ध्येयIAS®
most trusted since 2003

परफेक्ट 7

यूपीएससी व पीसीएस परीक्षाओं के लिए संपूर्ण पाक्षिक

वर्ष 5 | अंक 04 | फरवरी 2023 / Issue 02 | मूल्य ₹ 55

dhyeyaias.com

भारत की नौसेना को मजबूती देने पर बन रही रणनीतियां

भारत में आय की विषमता का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

सिंधु जल समझौते की प्रासंगिकता और भारत का दृष्टिकोण

स्वदेशी टीकों को विकसित करने की दिशा में बढ़ता भारत

भारत में सहकारी समितियों के प्रबंधन और प्रशासन में सुधार की आवश्यकता

शहरी विकास परियोजनाओं में पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन की जरूरत

पूर्वोत्तर भारत के बहुआयामी विकास के चलते उग्रवाद में बड़े पैमाने पर कमी

प्रीलिम्स स्पेशल 2023: अन्तर्राष्ट्रीय संबंध

परफेक्ट-7

करेंट अफेयर्स मैगजीन ही क्यों?

1. सर्वप्रथम परफेक्ट-7 करेंट अफेयर्स मैगजीन, **प्रत्येक 15 दिन** में प्रकाशित होती है जिससे छात्र करेंट अफेयर्स से अप-टू-डेट रहते हैं, वहीं अन्य कोचिंग संस्थानों की पत्रिकाएं मासिक होती हैं जिससे महीने भर की करेंट अफेयर्स एक साथ एकत्र हो जाती हैं। अधिक करेंट अफेयर्स होने के कारण छात्र प्राय: सभी लेखों को पढ़ नहीं पाते। अंतत: वे वार्षिकी और अर्द्धवार्षिक मैगजीन पर निर्भर हो जाते हैं।
2. परफेक्ट-7 मैगजीन **आईएएस और पीसीएस केंद्रित परीक्षा** को ध्यान में रखकर बनाई गई है, वहीं अन्य कोचिंग संस्थानों की पत्रिकाओं में आईएएस और पीसीएस परीक्षा के नाम पर अनावश्यक एवं अतिरिक्त सामग्री शामिल कर देते हैं, जिससे छात्रों में कन्फ्यूजन हो जाता है।
3. परफेक्ट-7 मैगजीन में 15 दिन के दौरान महत्त्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी घटनाओं पर **विषय विशेषज्ञों द्वारा 7 संपादकीय लेख, महत्त्वपूर्ण घटनाओं और सूचनाओं पर 42 लेख, रचनात्मक शैली में 7 ब्रेन-बूस्टर, करेंट अफेयर्स, वन लाइनर, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा संबंधित प्रश्न** आदि दिए जाते हैं। इसके साथ व्यक्ति विशेष नाम का एक खंड भी है जो ऐतिहासिक व्यक्तित्व के देश और समाज के प्रति योगदान को दर्शाता है। इस तरह 15 दिन की अवधि में आईएएस, पीसीएस परीक्षा केंद्रित कोई भी महत्त्वपूर्ण सूचना और खबर नहीं छूटती।
4. इसके साथ ही **केस स्टडी खंड** के माध्यम से छात्र यह सीखते हैं कि एक अधिकारी को अपने कार्यकाल के दौरान कैसी परिस्थितियों का सामना करना होता है और उसका क्या समाधान हो सकता है?
5. परफेक्ट-7 करेंट अफेयर्स मैगजीन के माध्यम से Dhyeya IAS के सबसे महत्त्वपूर्ण परीक्षा कार्यक्रम **PMI (Pre + Mains + Interview)** की अच्छे से तैयारी हो जाती है।
6. करेंट अफेयर्स आधारित कक्षाओं में परफेक्ट-7 के माध्यम से तैयारी कराई जाती है जिससे छात्रों की गुणवत्तापूर्ण तैयारी हो पाती है।
7. परफेक्ट-7 मैगजीन **प्रत्येक माह की 10 और 25 तारीख** को छात्रों के लिए उपलब्ध हो जाती है, वहीं अन्य संस्थानों की मैगजीन में करेंट अफेयर्स पिछले महीने का होता है और पत्रिका में आगे का अगला महीना अंकित होता है, अर्थात करेंट अफेयर्स लगभग 1 माह पुराना होता है।
8. परफेक्ट-7 मैगजीन में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा केंद्रित मॉक टेस्ट रहते हैं जिसके माध्यम से छात्र अपनी तैयारी को और भी सटीक बना सकते हैं।

-: For any feedback Contact us :-

+91 6393005298

perfect7magazine@gmail.com

OUR OTHER INITIATIVES

DHYEYA TV
Current affairs Programmes hosted by Mr. Qurban Ali Ex. Editor RSTV) & by Dhyeya Team Broadcasted on YouTube & Dhyeya TV

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...
Hindi & English Current Affairs Monthly News Paper

पहला पन्ना

करेंट अफेयर्स संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों की ओर से आयोजित परीक्षाओं की तैयारी में अति महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के मुद्दों पर प्रासंगिक सूचनाओं से जुड़ाव होना अभ्यर्थियों के लिए काफी जरूरी समझा गया है। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए परफेक्ट-7 पत्रिका का पाक्षिक प्रकाशन किया जा रहा है। आईएएस और पीसीएस की तैयारी तभी पूर्ण मानी जाती है जब प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू स्तर की गतिशील प्रकृति के राज्यों और विश्लेषणों को आप सभी तक समावेशी रूप में रखा जाये। परफेक्ट-7 मैगजीन इसी विजन और दृष्टिकोण को ध्यान में रखती है और विद्यार्थियों की कटेंट के स्तर पर बहुआयामी जरूरतों को समझती है। इसीलिए इस मैगजीन को करेंट अफेयर्स के साथ-साथ सामान्य अध्ययन के महत्त्वपूर्ण खंडों से जुड़े अति प्रासंगिक कटेंट के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। एक तरफ जहां करेंट अफेयर्स के स्तर पर सबसे पहले मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 7 ज्वलंत विषयों पर समसामयिक लेखों को, स्वतंत्रता आंदोलन और अन्य क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तित्व की जीवनी और भूमिकाओं को, सामान्य अध्ययन के विविध खंडों के सर्वाधिक उपयोगी विषयों पर मुख्य परीक्षा के स्तर पर कवरेज दिया जा रहा है, वहीं प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर 15 दिन पर सबसे महत्त्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के मुद्दों को कवर किया जा रहा है जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र, लोक प्रशासन, कला-संस्कृति, विज्ञान-प्रौद्योगिकी, राजव्यवस्था और अर्थव्यवस्था के मुद्दों पर जोर दिया जाता है।

विद्यार्थियों की संकल्पना के स्तर पर समझ को बढ़ने के लिए ब्रेन-बूस्टर सेक्शन में 7 ग्राफिक्स के जरिये विषय को संक्षेप और सारगर्भित रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके अलावा सिविल सर्विसेज की परीक्षा में प्रमुखता से पूछे जाने वाले ग्लोबल इनिशिएटिव्स, वैधिक संस्थाओं, संगठनों की संरचना, कार्यप्रणाली, महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट्स, सूचकांकों पर अपडेटेड जानकारी इस पत्रिका में शामिल रहती है। इस मैगजीन को केवल बच्चों व केवल एनालिसिस पर जोर देते हुए नहीं बनाया गया है बल्कि इस मैगजीन का ध्येय यह है कि सिविल सेवा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के उभरते हुए ट्रेंड्स और प्रश्नों की नई प्रकृति को देखते हुए अभ्यर्थियों को एक ऐसी समावेशी मैगजीन उपलब्ध कराई जाए, जिससे वे सिविल सेवा एग्जाम की नई जरूरतों को समझते हुए अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकें। पत्रिका के प्रारूप में अभ्यर्थियों की तथ्यात्मक आवश्यकताओं, मानसिक विकास, लेखन प्रविधि विकसित करने जैसे विषयों को ध्यान में रखते हुये स्तंभ शामिल किये गये हैं। इसके साथ ही हम अभ्यर्थियों की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप नये स्तंभ शुरू करते रहे हैं और आगे भी यह क्रम जारी रहेगा। आशा है कि आप सभी के लिये यह अंक उपयोगी सिद्ध होगा। हमें आपके सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी।

शुभकामनाओं के साथ।

विनय कुमार सिंह
संस्थापक
ध्येय IAS

ध्येयIAS most trusted since 2003

परफेक्ट 7

इस अंक में...

प्रबंध संपादक : विजय सिंह
: बाघेन्द्र सिंह
संपादक : विवेक ओझा
सह-संपादक : आशुतोष मिश्र
: सौरभ चक्रवर्ती
उप-संपादक : अमन कुमार
प्रकाशन प्रबंधन : डॉ.एस.एम. खालिद
संपादकीय सहयोग : हरि ओम पाण्डेय
: भानू प्रताप
: ऋषिका, नितिन
: ऋतु, प्रत्यूषा
: नीरज, अदनान
: सल्तनत, लोकेश
मुख्य समीक्षक : ए.के. श्रीवास्तव
शोध एवं समीक्षा सहयोग : शशांक शेखर त्रिपाठी
आवरण सज्जा एवं विकास : अरूण मिश्र
: पुनीष जैन
टंकण : सचिन, तरून
तकनीकी सहायक : मो. वसीफ खान
कार्यालय सहायक : राजू
: चंदन, गुड्डू
: अरूण, राहुल

समसामयिकी लेख 5-18

1. सिंधु जल समझौते की प्रासंगिकता और भारत का दृष्टिकोण
2. भारत में आय की विषमता का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव
3. भारत की नौसेना को मजबूती देने पर बन रही रणनीतियां
4. स्वदेशी टीकों को विकसित करने की दिशा में बढ़ता भारत
5. भारत में सहकारी समितियों के प्रबंधन और प्रशासन में सुधार की आवश्यकता
6. पूर्वोत्तर भारत के बहुआयामी विकास के चलते उग्रवाद में बड़े पैमाने पर कमी
7. शहरी विकास परियोजनाओं में पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन की जरूरत

राष्ट्रीय 19-22
अंतर्राष्ट्रीय 23-26
पर्यावरण 27-30
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 31-35
आर्थिकी 36-40
विविध 41-44
राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की महत्त्वपूर्ण खबरें 45-48
समसामयिक घटनाएं एक नजर में ... 49
ब्रेन-बूस्टर 50-56

प्रीलिम्स स्पेशल 2023

- अन्तर्राष्ट्रीय संबंध 57-72
- प्रीलिम्स आधारित बहु-विकल्पीय प्रश्न 73-78

समसामयिकी आधारित बहु-विकल्पीय प्रश्न 79-81
व्यक्तित्व 82

आगामी अंक में

- भारत के विकास में सहायक बनता लिथियम
- ऑपरेशन दोस्त: भारत की प्रोएक्टिव सॉफ्ट डिप्लोमेसी
- कौशल विकास से सशक्त होता भारत
- वित्तीय समावेशन में भुगतान एग्रीगेटर्स की भूमिका
- पीएम पीवीटीजी मिशन: आदिवासी विकास के लिए साबित हो सकता है मील का पत्थर
- राज्यपाल की नियुक्ति और उनकी कार्यवाही पर उठता विवाद
- एसएसएलवी की सफलता: भारतीय अन्तरिक्ष क्षेत्र में नए युग की शुरुआत

सिंधु जल समझौते की प्रासंगिकता और भारत का दृष्टिकोण

वर्ष 2016 में पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा जम्मू-कश्मीर के उरी पर किए गए आतंकी हमले के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंधु जलसंधि और आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया था कि भारत जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलेगा तथा कश्मीर में या तो जल बहेगा या रक्त। इसका मतलब था कि पाकिस्तान अगर भारत पर आतंकी हमले बंद नहीं करता तो झेलम, चिनाब, सिंधु का पानी उस तक नही पहुँचेगा, भारत कुछ ऐसी कार्यवाही करेगा। भारत ने हाल ही में तकरीबन 62 साल के इतिहास में पहली बार सिंधु जल समझौते में संशोधन की मांग कर दी है। भारत ने पाकिस्तान को सिंधु जल समझौते की शर्त बदलने का नोटिस दे दिया है। इस तरह केंद्र सरकार ने फिर से सिंधु जल समझौते पर विचार करने के संकेत दिये हैं। भारत ने पाकिस्तान को 90 दिनों में सरकारी स्तर पर बातचीत करने का मौका भी दिया है। चूंकि पाकिस्तान आदतन सिंधु जल समझौते के मुद्दे पर भारत से सीधी बात न करके बार-बार वर्ल्ड बैंक के पास पहुंच जाता है। इसलिए भारत ने पाकिस्तान को नोटिस के जरिए सिंधु जल संधि के उल्लंघन की प्रवृत्ति को सुधारने के लिए 90 दिनों में इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन (अंतरसरकारी वार्ता) करने का मौका दिया है। अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान के नजरिए में कुछ भी बदलाव आता है? सिंधु जल संधि को लेकर भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट है। भारत का कहना है कि विश्व बैंक को अधिकार नहीं है कि सिंधु नदी जल बंटवारे के मुद्दे पर न्यूट्रल एक्सपर्ट नियुक्त करे और कोर्ट ऑफ आरबिट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय ले। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कुछ ही समय पूर्व स्पष्ट रूप से कहा था कि भारत को लगता है कि विश्व बैंक इस स्थिति में नहीं है कि वह भारत के लिये सिंधु जल संधि की व्याख्या कर सकें। यह संधि दो देशों के बीच हुई है और इस संधि के बारे में भारत की समझ यह है कि इसमें श्रेणीबद्ध प्रावधान हैं। इसी को ध्यान में रखकर भारत ने सितंबर 1960 की सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए इस साल 25 जनवरी को पाकिस्तान को नोटिस भेजा था। पाकिस्तान को पहली बार यह नोटिस छह दशक पुराने इस संधि को लागू करने से जुड़े विवाद निपटारा तंत्र के अनुपालन को लेकर अपने रुख पर अड़े रहने के कारण भेजा गया है। इसके साथ ही जब भारत ने यह भी समझ लिया है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के निर्णयों का भारत के हितों के खिलाफ असर पड़ सकता है, या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन पाकिस्तान का समर्थन बिना किसी ठोस आधार पर करता है तो भारत उसकी रूलिंग मानने के लिए बाध्य नहीं है। भारत ने वर्ल्ड बैंक जैसे संगठन की मध्यस्थता इसलिए नहीं अपनाई थी कि भारत सही होते हुए भी कोई गलत बात या निर्णय सुने।

एक ऐसे समय में जब पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बदहाल है, महंगाई, बेरोजगारी, निर्धनता, आतंकी हमले, साम्प्रदायिक तनाव, राजनीतिक अस्थिरता चरम पर है और वह भारत से संबंध सुधारने का अनुरोध कर रहा है, भारत में इस साल होने वाले शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लेने के लिए पाकिस्तानी विदेश मंत्री को आमंत्रण भी भेजा गया है, ऐसे में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि भारत ने पाकिस्तान को सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए नोटिस क्यों दिया है? वास्तव में प्रश्न यह होना चाहिए कि यह काम पहले क्यों नहीं किया गया? दोनों देशों के बीच तनाव, विवादों और यहां तक कि युद्धों के बीच भी यह संधि जारी रही तो भारत की उदारता और अंतर्राष्ट्रीय समझौते के प्रति प्रतिबद्धता के कारण। पाकिस्तान ने भारत की इस उदारता को न केवल हल्के में लिया, बल्कि वह इस संधि के प्रावधानों की अनदेखी करके अनावश्यक आपत्तियां भी जताता रहा।

पाकिस्तान भारत पर सिंधु जल संधि के उल्लंघन का लगाता है आरोप:

- भारत ने जब-जब जम्मू-कश्मीर क्षेत्र के विकास के लिए, वहां ऊर्जा सुरक्षा के लिए झेलम, चेनाब या सिंधु नदियों पर पनबिजली परियोजनाओं को मूर्तिमान बनाने की कोशिश की तो, पाकिस्तान ने बिना किसी न्यायपूर्ण आधार के उस पर अपना विरोध दर्ज किया। पाकिस्तान अक्सर यह आरोप लगाता है कि सिंधु जल तंत्र के पश्चिमी नदियों पर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के लिए भारत जो बांध या बैराज बनाता है, उसकी डिजाइन त्रुटिपूर्ण है, जिसका पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसी आधार पर पाकिस्तान पाकल दुल (1000 मेगावाट), रैटल (850 मेगावाट), किशनगंगा (330 मेगावाट), मियार (120 मेगावाट) और लोअर कलनई (48 मेगावाट) जैसी भारतीय पनबिजली परियोजनाओं पर आपत्ति करता है और वहीं चीन के साथ मिलकर सिंधु नदी पर बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं के लिए समझौता करने से नहीं हिचकता।
- पाकिस्तान भारत पर वॉटर टेरोरिज्म का आरोप लगाकर कहता रहा है कि भारत के हाथ में सिंधु जल तंत्र यानी झेलम, चेनाब, सिंधु, रावी, सतलज और व्यास का पानी पाकिस्तान के खिलाफ एक हथियार के रूप में है और भारत जब चाहे तब पाकिस्तान में बाढ़ ला सकता है या वहां सूखे की स्थिति पैदा कर सकता है। पाकिस्तान यह भूल गया है कि 1960 के दशक में भारत की यह सोच थी कि पाकिस्तान किसी जल संकट के चलते मानवीय त्रासदी का शिकार न बने, इसलिए भारत ने वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में इस बात को स्वीकार कर लिया था कि भारत सिंधु जल तंत्र के पानी को अपने क्षेत्रों से पाकिस्तान प्रवाहित होने देगा। भारत के इतने बड़े उपकार के बदले में भी पाकिस्तान ने भारत को प्रतिकार ही दिया जो यह दर्शाता है कि पाकिस्तान कितना कृतघ्न देश है। पाकिस्तान भारत के किसी भी पनबिजली परियोजना में खलल डालने के लिए छोटी सी छोटी बात को मुद्दा बनाता रहा है। जैसे कि हाइड्रो पॉवर प्लांट लगाने के क्रम में बने डैम अथवा बैराज की ऊंचाई ज्यादा है और उसमें कमी किया जाए। बैराज में वाटर स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा है, उसको घटाया जाए। दरअसल पाकिस्तान जानता है कि भारत वैध रूप से सिंधु जल संधि के प्रावधानों के हिसाब से पनबिजली परियोजनाएं चलाने और जल का अन्य उपयोग भी करने का अधिकार रखता है, लेकिन पाकिस्तान

चाहता है कि वह सिंधु, झेलम और चेनाब के जल को भारत से साझा न होने दे।

भारत-पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौते का इतिहास:

- सिंधु नदी के जल बटवारें से जुड़ा विवाद 1947 में भारत के विभाजन के समय ही शुरू हो गया था। उस समय भारत और पाकिस्तान के इंजीनियरों ने मिलकर भारत से पाकिस्तान की तरफ बहने वाली दो प्रमुख नदियों पर स्टैंडस्टिल समझौता किया था। इसके अनुसार पाकिस्तान को लगातार पानी मिलता रहे जो 31 मार्च 1948 तक लागू था। हालांकि, पाकिस्तान का आरोप था कि 1 अप्रैल 1948 को समझौता लागू नहीं रहा और भारत ने दो प्रमुख नदियों का पानी रोक दिया।
- इसके बाद दोनों पक्षों में टकराव हुए क्योंकि कोई भी इस मुद्दे पर वार्ता को तैयार नहीं था। 1951 में 'टेनेसी वैली अथॉरिटी' और 'यू.एस. एटॉमिक एनर्जी कमीशन' दोनों के पूर्व प्रमुख डेविड लिलिएंथल ने एक कोलियर मैग्जीन के लिए लिखे जाने वाले लेखों पर शोध करने के उद्देश्य से इस क्षेत्र का दौरा किया। इसके बाद सुझाव दिया कि भारत-पाकिस्तान को संभवतः विश्व बैंक से सलाह और वित्त पोषण के साथ सिंधु नदी प्रणाली को संयुक्त रूप से विकसित तथा प्रशासित करने के लिए एक समझौते की दिशा में काम करना चाहिए जिस पर उस वक्त के विश्व बैंक के अध्यक्ष यूजीन ब्लैक भी सहमत हुए। इसके बाद ब्लैक ने साल 1954 में भारत और पाकिस्तान के प्रमुखों से इस बारे में संपर्क किया। छह साल की बातचीत के बाद, भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान ने सितंबर 1960 में सिंधु जल समझौता पर हस्ताक्षर किये।
- इस समझौते में मुश्किलें तब शुरू हुई जब भारत ने पश्चिमी नदियों पर जलविद्युत परियोजनाओं का निर्माण शुरू किया। पाकिस्तान को इस बात की चिंता थी कि इन परियोजनाओं से पाकिस्तान के लिए पानी का प्रवाह कम हो जाएगा। दोनों देशों के विशेषज्ञों ने 1978 में सलाल बांध विवाद को बातचीत से सुलझाया। फिर आया बगलिहार बांध का मुद्दा जिसे 2007 में विश्व बैंक के एक तटस्थ मध्यस्थ की मदद से सुलझाया गया था। किशन गंगा परियोजना भी एक विवादास्पद परियोजना थी। यह मामला अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में पहुँच गया था, जिसका निर्णय 2013 में किया गया था। सिंधु आयोग की बैठकों ने इन विवादों को सुलझाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

सिंधु नदी तंत्र के बारे में जरूरी बातें:

- सिन्धु तंत्र विश्व के विशालतम नदी तंत्रों में से एक है। इसके अंतर्गत सिन्धु तथा उसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, जास्कर, काबुल तथा गिलगिट सम्मिलित हैं। सिन्धु नदी तिब्बत के निकट मानसरोवर झील के समीप बोखर चू हिमानी से निकलती है। इसकी लंबाई 2880 किमी है। यह नदी पहले उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हैं, फिर यह हिमालय पर्वत को काट कर दमचौक के निकट भारत में प्रवेश करती है।
- सिन्धु नदी भारतीय केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख के दो जिलों लेह एवं कारगिल में प्रवाहित होने के पश्चात पाक अधिकृत कश्मीर में बहती है। सिन्धु नदी एक पूर्ववर्ती नदी है जो नंगा पर्वत के उत्तर बुंजी नामक स्थल पर लद्दाख श्रेणी को काटकर गार्ज का निर्माण करती है। सिन्धु नदी के बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में पंजाब की पांच नदियां सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम (दक्षिण से उत्तर इसी क्रम में) सबसे प्रमुख हैं, वहीं दाई ओर से मिलने वाली नदियों में काबुल, कुर्रम, गोमल आदि प्रमुख है। सिन्धु नदी दक्षिण-पश्चिम की ओर बढ़ते हुए कराची के पूर्व में अरब सागर में मिल जाती है।
- भारत-पाकिस्तान के बीच हुए सिंधु जल समझौता 1960 के अंतर्गत भारत सिन्धु व उसकी सहायक नदियों के 20 प्रतिशत जल का उपयोग कर सकता है, वहीं पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चेनाब के जल का उपयोग करने का एक्सक्लुसिव राइट (80 %) दिया गया था। भारत को पश्चिमी नदियों पर हाइड्रो पॉवर प्रोजेक्ट चलाने की भी अनुमति मिली थी।
- पुलवामा हमले के बाद भारत के तत्कालीन परिवहन और जल मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट करते हुए कहा था कि भारत सरकार ने पाकिस्तान जाने वाले अपने हिस्से के पानी को रोकने का फैसला किया है। ऐसा ही कुछ स्टैंड भारत फिर से इस समय ले रहा है। पारस्परिक रूप से बीच का रास्ता निकालने के लिए भारत की ओर से बार-बार प्रयास करने के बावजूद पाकिस्तान ने 2017 से 2022 तक स्थायी सिंधु आयोग की पांच बैठकों में इस पर चर्चा करने से इनकार कर दिया। इस तरह से पाकिस्तान की ओर से सिंधु जल संधि के प्रावधानों के लगातार उल्लंघन ने भारत को सिंधु जल समझौते में संशोधन को लेकर नोटिस जारी करने के लिए मजबूर कर दिया।
- भारत को सिंधु जल संधि के तहत अपने हिस्से के जल का पूरा प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि पश्चिमी नदियों के अपने हिस्से के जल का भारत पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं कर सका है। इसके साथ ही भारत को इस संधि के तहत जल के अधिक हिस्से की मांग करनी चाहिए। उरी आतंकी हमले के बाद भारत ने स्पष्ट रूप से सिंधु जल संधि की समीक्षा के मुद्दे को सीमा पार आतंकवाद के प्रश्न से जोड़ दिया था जिसके बाद कालांतर में पूर्वी नदियों विशेषकर रावी नदी पर शाहपुर कंडी में बांध बनाने का निर्माण भी शुरू हुआ। इसके साथ ही इस प्रोजेक्ट के तहत भारतीय हिस्से का पानी जम्मू-कश्मीर के लोग प्रयोग करेंगे। ऐसी प्लानिंग की गई और शेष पानी रावी व्यास लिंक से होकर प्रवाहित होगा जिसे अन्य बेसिन स्टेट्स को उपलब्ध कराने का निर्णय भारत सरकार ने किया था। रावी नदी के माध्यम से पाकिस्तान जा रहे उझ नदी के पानी को रोकने के लिए मकोड़ा पत्तन पर भी बैराज बनाने की बात हो चुकी है। ऐसा करके पंजाब में पानी का इस्तेमाल किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि गुरदासपुर में स्थित मकोड़ा पत्तन पर ही उझ नदी आकर मिलती है। इस तरह भारत जो पहले अपने हिस्से के जल को ढंग से उपयोग करने के बारे में नहीं सोचता था अब इस दिशा में जरूरी कदम उठा रहा है।

भारत में आय की विषमता का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

सन्दर्भः

हाल ही में आक्सफैम द्वारा जारी 'सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्टः द इंडिया स्टोरी' ने भारत में व्यापक आर्थिक असमानता के आकड़ों को प्रस्तुत किया है। यह आर्थिक विषमता देश में सामाजिक-आर्थिक न्याय की प्रगति में बाधक का कार्य कर रही है।

परिचयः

स्विट्ज़रलैंड के दावोस में इस वर्ष विश्व आर्थिक मंच की बैठक के पहले दिन ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। ध्यातव्य है कि प्रतिवर्ष जनवरी में दावोस बैठक के समय ऑक्सफैम इंटरनेशनल अपनी रिपोर्ट जारी करता है। इस रिपोर्ट में मुख्य रूप से भारत सहित सम्पूर्ण विश्व में व्याप्त आर्थिक असमानता के कारकों, उनके कारणों तथा प्रभावों पर चर्चा की जाती है।

सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्टः द इंडिया स्टोरी

ऑक्सफैम ने भारत पर केंद्रित एक खास रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्टः द इंडिया स्टोरी शीर्षक से जारी की गई है जिसके मुख्य बिन्दु निम्नवत हैंः

- भारत की कुल संपत्ति के 60% भाग पर 5% धनाढ्य लोगों का अधिकार है तथा भारत के गरीबतम 50% की जनसँख्या के पास मात्र 3% संपत्ति है।
- भारत के केवल 21 सबसे बड़े अरबपतियों के पास देश के 70 करोड़ लोगों की सम्पत्ति से भी ज्यादा संपत्ति है।
- भारत में जहां वर्ष 2020 में अरबपतियों की संख्या 102 थी, वहीं 2022 में यह आंकड़ा 166 पर पहुंच गया है अर्थात दो वर्ष में अरबपतियों की संख्या में 64 की वृद्धि हुई है।
- 2020 में कोरोना महामारी शुरू होने के बाद से नवंबर 2021 तक जहां अधिकतर भारतीयों को नौकरी संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा तथा उन्हें बचत संकट का सामना करना पड़ा, वहीं इसी समयांतराल में भारतीय अरबपतियों की संपत्ति में 121 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी के इस दौर में भी भारत के अरबपतियों की संपत्ति में प्रतिदिन 3 हजार 608 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।
- 2012-2021 के दौरान 1% लोगों ने संपत्ति सृजन में 40% का प्रतिनिधित्व किया, वहीं 50 फीसदी जनता ने महज 3% संपत्ति का सृजन किया है।
- वर्ष 2021 के बाद भारत के 10 सबसे अमीर लोगों में 32% की वृद्धि देखी गई।
- इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि भारत में न सिर्फ अमीर लोगों की संपत्ति में वृद्धि हुई है, बल्कि अमीर-गरीब में व्यापक असमानता बढ़ी है।

बढ़ती आय असमानता में सरकारी नीतियों की भूमिकाः

विगत वर्ष ऑक्सफैम की रिपोर्ट 'इनक्वॉलिटी किल्स' ने यह बताया था कि भारत सरकार की नीतियां पूंजीपतियों को समर्थन दे रही हैं।

- **कारपोरेट टैक्स को कम करनाः** वर्ष 2019 में सरकार ने निगम कर को 30% से कम करके 22% कर दिया, वहीं नवगठित कंपनियों के लिए यह मात्र 15% रखा गया। कराधान में हुई इस कमी के कारण लगभग 1.84 लाख करोड़ की राजस्व हानि हुई।
- **जीएसटी तथा उत्पाद कर में वृद्धिः** निगम कर से हुई हानि को कम करने के लिए पेट्रोल व डीजल पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि की गई जिसका बोझ आम जनता पर पड़ा। इन नीतियों के फलस्वरूप देश की 50% गरीब जनता, देश के 10% अमीरों की तुलना में 6 गुना अधिक अप्रत्यक्ष कर प्रदान कर रही है। यदि 2022 के जीएसटी की बात करें तो, देश की 50% गरीब जनता द्वारा दो-तिहाई जीएसटी का भुगतान किया गया, वहीं 10% अमीर लोग मात्र 4% जीएसटी का भुगतान कर रहे हैं।
- **मौद्रिक नीति तथा मुद्रास्फीतिः** जहाँ एक तरफ रेपो दर में वृद्धि से ईएमआई की दर अधिक हुई, वहीं पिछले 6 वर्षों में सार्वजनिक बैंको के लगभग 11 लाख करोड़ रुपये को एनपीए घोषित किया गया। इसके परिणामस्वरूप कार्पोरेट्स के लाभ में 70% की वृद्धि हुई, वहीं 84% हाउसहोल्ड्स की आय में कमी आई है।

आर्थिक असमानता के प्रभावः

- **सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना में विलंबः** भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय की कल्पना की गई है, परंतु इस प्रकार की बढ़ती हुई असमानता सामाजिक तथा आर्थिक न्याय की स्थापना में बाधक बन रही है। ध्यातव्य है कि सामाजिक न्याय तथा आर्थिक न्याय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जिससे आर्थिक असमानता दोनों को प्रभावित करती है।
- **लैंगिक असमानता में वृद्धिः** व्यापक आर्थिक असमानता ने लैंगिक असमानता को भी बढ़ाया है। रिपोर्ट यह बताती है कि पुरुष श्रमिक द्वारा अर्जित 1 रुपए की तुलना में महिला श्रमिकों को मात्र 63 पैसे मिलते हैं। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत का उल्लंघन है।
- **अपराध में वृद्धिः** अपराध मुख्य रूप से सामाजिक, नैतिक तथा विधिक आदेशों की अवज्ञा होती है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री हिली के अनुसार अपराध सामाजिक वातावरण का परिणाम है तथा समाज में विषमता अपराध को बढ़ावा देने हेतु एक उर्वर भूमि का कार्य करती है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि आर्थिक विषमता भी कहीं न कहीं अपराध को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
- **निजी कंपनियों तथा जनता के मध्य विश्वास संकटः** यही स्थिति भारत में निजी कंपनियों तथा जनता के बीच विश्वास संकट को जन्म देता है। यह कहीं न कहीं आगे चलकर उत्पादकता तथा आर्थिक विकास में बाधक के रूप में कार्य करेगा।
- **सतत विकास में अवरोधः** यह सत्य है कि कारपोरेट कंपनियों की वृद्धि देश की आर्थिक संवृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है, परंतु यह आर्थिक संवृद्धि यदि गरीब जनता के हितों के मूल्य पर होगी

तो यह न सिर्फ कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रभावित करेगी बल्कि विकास तथा असमानता में द्वंद की स्थिति उत्पन्न करके, सतत विकास के मार्ग में बाधक बनेगी।

- इन प्रभाव के अतिरिक्त आर्थिक असमानता भ्रष्टाचार, क्रोनी कैपिटलिज्म, चुनाव में धनबल इत्यादि का कारण बन सकती है जो भारत के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक ताने-बाने को प्रभावित करेगी।

इन दुष्प्रभावों को कम करने हेतु किये जाने वाले उपाय:

- भारत के 100 सबसे अमीर लोगों के पास 54 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति है जो भारत सरकार के बजट को लगभग 18 माह तक वित्तपोषित कर सकती है। विश्लेषण के अनुसार यदि भारतीय अरबपतियों की कुल संपत्ति पर सिर्फ 2 फीसदी टैक्स ही लगाया जाए तो इससे अगले 3 साल तक कुपोषण के शिकार बच्चों के लिए सभी जरूरतों को पूरा किया जा सकता है।
- यदि भारत के द्वारा 100 अरबपतियों पर 2.5% का कर अथवा 10 अरबपतियों पर 5% का कर लगाया जाता है तो उससे 1.4 लाख करोड़ रुपए का लाभ होगा जिससे वंचित बच्चों की शिक्षा का प्रबंधन किया जा सकेगा।
- सरकार को विंडफाल टैक्स लगाना चाहिए जिससे कोरोना महामारी से हुए आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने में सहायता मिल सके। ध्यातव्य है कि विंडफाल टैक्स अप्रत्याशित या असाधारण लाभ पर लगाए गए कर होते हैं जो आर्थिक संकट युद्ध या प्राकृतिक आपदाओं के समय प्राप्त किए गए हैं।
- इसके अतिरिक्त सरकार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में परिकल्पित स्वास्थ्य क्षेत्र के बजटीय आवंटन को सकल घरेलू उत्पाद के 2.5% तक तथा शिक्षा के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 6% बेंच मार्क तक बजटीय व्यय बढ़ाना चाहिए।

अन्य उपाय:

- सरकार को कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के उचित क्रियान्वयन पर ध्यान देना चाहिए।
- कारपोरेट कंपनियां जिन्हें भारत की जनता द्वारा ही लाभ प्राप्त हो रहा है उन्हें नैतिक रूप से आगे आकर देश के वंचित वर्ग के विकास में अपना योगदान देना चाहिए।

निष्कर्ष:

आर्थिक असमानता न सिर्फ संवैधानिक लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधक है बल्कि यह अराजकता तथा अपराध के बढ़ने का एक प्रमुख माध्यम बन सकता है। अराजकता तथा अपराध बढ़ने की स्थिति में न सिर्फ सामाजिक आर्थिक ताना-बाना प्रभावित होगा, बल्कि कारपोरेट कंपनियों सहित देश के आर्थिक उत्पादन पर भी व्यापक प्रभाव पड़ेगा। स्थितियों के निदान हेतु यह आवश्यक है कि भारत सरकार अपनी कल्याणकारी राज्य के उद्देश्यों पर खरा उतरे तथा वंचित वर्ग को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए यथासंभव प्रयास करें।

ध्येयIAS®
most trusted since 2003
DHYEYA IAS®
most trusted since 2003
NEW BATCH - FACE TO FACE
सामान्य अध्ययन
UP-PCS
PRE-CUM-MAINS
22 FEB.
BPSC
MAINS SPECIAL
20 FEB.
PRE-CUM-MAINS
15 MAR.
A 12, 13, ANSAL BUILDING, DR. MUKHERJEE NAGAR, DELHI 110009
9205274741 / 42, 9289580074 / 75

भारत की नौसेना को मजबूती देने पर बन रही रणनीतियां

सन्दर्भ:

हाल ही में भारतीय नौसेना को मजबूत करने की प्रतिबद्धता के साथ ही 2047 तक आत्मनिर्भर सैन्यबल बनाने के उद्देश्य से, 5वीं स्कारपियन श्रेणी की पारंपरिक पनडुब्बी को 23 जनवरी, 2023 को नवल डॉकयार्ड, मुंबई में आईएनएस वीएजीआईआर के रूप में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया।

परिचय:

- अक्टूबर 2005 में हस्ताक्षरित 3.75 बिलियन डॉलर के सौदे के तहत फ्रांस से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हेतु मझगाँव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा प्रोजेक्ट-75 हेतु 6 स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। पहली पनडुब्बी आईएनएस कलवरी को दिसंबर 2017 में, दूसरी आईएनएस खंडेरी को सितंबर 2019 में, तीसरी आईएनएस करंज को मार्च 2019 में और नवंबर 2021 में चौथी आईएनएस वेला को कमीशन किया गया था।
- इसके साथ, नौसेना के पास अब 16 पारंपरिक और एक परमाणु पनडुब्बी है। इसमें सात रूसी किलो वर्ग की पनडुब्बी, चार जर्मन एचडीडब्ल्यू पनडुब्बी, पांच फ्रेंच स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बी और स्वदेशी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत शामिल हैं।

भारत की समुद्री स्थिति और इसका महत्त्व:

- भारत के पास हिन्द महासागर में लगभग 1100 द्वीपों और लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर के अनन्य आर्थिक क्षेत्रों (ईईजेड) के साथ लगभग 7500 किलोमीटर की लंबी तटरेखा है। भारत 7 देशों (पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया) के साथ अपनी समुद्री सीमा साझा करता है।
- मलक्का जलडमरूमध्य को लाल सागर, फारस की खाड़ी और बाब-अल-मंडेब से जोड़ने वाली संचार की प्रमुख समुद्री मार्ग हिंद महासागर से होकर गुजरते हैं जो इसे वैश्विक व्यापार का रणनीतिक केंद्र बिंदु बनाती हैं। हिंद महासागर क्षेत्र दुनिया के समुद्री व्यापार में 75% की भागीदारी रखता है।
- हिंद महासागर बहुत महत्त्वपूर्ण खनिजों से संपन्न है जिन्हें पॉलीमेटैलिक नोड्यूल कहा जाता है। उनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, स्मार्ट फोन, बैटरी और सौर पैनलों में किया जाता है। इन खनिजों का पता लगाने के लिए भारत ने 'डीप ओशन मिशन' लॉन्च किया है।
- यह हिंद महासागर को ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि के दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण बनाता है और भारतीय नौसेना को रसद (लॉजिस्टिक) सहायता प्रदान करने में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है।

हिंद महासागर में चीन का आक्रामक तेवर:

- चीन ने हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में 'मोतियों की माला' (स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स) नामक कूटनीति तथा चीन द्वारा अपने आर्थिक, सैन्य और रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए बनाए गए रणनीतिक नौसैनिक/सैन्य ठिकानों के नेटवर्क के तहत अपने रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए क्षेत्र में आक्रामक कदम उठाए हैं। श्रीलंका के हंबनटोटा पोर्ट को 99 वर्ष के लीज पर, पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को 40 वर्ष के लीज पर ऑपरेशनल कंट्रोल हासिल करना और जिबूती में मिलिट्री बेस बनाना इसी रणनीति का हिस्सा माना जाता है।
- दिसंबर 2022 में, चीनी उपग्रह ट्रैकिंग और सी बेड मैपिंग जहाज युआन वांग 5 ने हिंद महासागर में प्रवेश किया। 2018 में भी भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी पनडुब्बी को देखा था।

चीन की काउंटर बैलेंस रणनीतिक भूमिका पर भारत की प्रतिक्रिया:

- 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' रणनीति के तहत चीन की बढ़ती घुसपैठ तथा हस्तक्षेप के बारे में चिंताओं ने भारत को चीनी तैनाती का मुकाबला करने के लिए अपनी समुद्री और नौसैनिक क्षमता को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया है।
- भारत ने इंडोनेशिया के रणनीतिक गहरे समुद्र सबंग पोर्ट और ओमान के डुक्म पोर्ट तक पहुंच प्राप्त की है। भारत ने फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ रसद समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं, जो भारत को डिएगो गार्सिया में अमेरिकी आधार और रीयूनियन द्वीप में फ्रांसीसी आधार पर बंदरगाह सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करता है।
- हिंद-प्रशांत चीन और भारत के लिए एक भू-रणनीतिक केंद्र बिंदु के रूप में उभरा है। चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए फ्रांस और जर्मनी के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी इंडो-पैसिफिक रणनीति को उजागर किया है, जिसमें भारत एक महत्त्वपूर्ण घटक है।
- हिन्द-प्रशांत रणनीति के तहत भारत अनौपचारिक चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (क्वाड) के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी जुड़ा हुआ है। क्वाड की समुद्री रणनीति, इंडो-पैसिफिक डेमोक्रेटिक एलायंस, चीन के उदय को रोकने के लिए मुख्य रूप से मजबूत और जीवंत भारतीय नौसेना पर टिकी हुई है। क्वाड समूह के अंतर्गत हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में चार लोकतांत्रिक शक्तियों के एक साथ आने से इस क्षेत्र में भारतीय नौसेना की प्रोफाइल और कद में वृद्धि हुई है। चीन के समुद्री क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करने के साथ, भारत की नौसैनिक शक्ति को प्रमुख प्रतिसंतुलन के रूप में देखा जा रहा है।

भारत की समुद्री रणनीति और नौसेना की बढ़ती प्रासंगिकता:

- भारतीय नौसेना को केंद्र में रखते हुए भारत ने अपने 2015 के दस्तावेज में 'समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु, भारत समुद्री सुरक्षा रणनीति' नामक अपनी समुद्री रणनीति को प्रतिपादित किया है। इसका उद्देश्य अपने स्वयं के राष्ट्रीय हित पर ध्यान देने के साथ समुद्री सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना था।
- रणनीति के अनुसरण के रूप में, भारतीय नौसेना ने हाल के वर्षों में महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्गों के साथ जहाजों और विमानों को तैनात करके 'मिशन-आधारित तैनाती' के माध्यम से अपनी उपस्थिति तथा परिचालन पहुंच में विस्तार किया है। अदन की खाड़ी, अरब सागर, लक्षद्वीप, मालदीव, सेशेल्स, मॉरीशस, बंगाल की खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा मलक्का जलडमरूमध्य को 15 युद्धपोतों व टोही विमान द्वारा साल भर की गश्त के लिए सात क्षेत्रों के रूप में पहचाना गया है। मालाबार, मिलन, रिमपैक (रिम ऑफ पैसिफिक), कॉर्पेट, सिम्बेक्स, ऑस-इंडेक्स आदि जैसे नौसैनिक अभ्यासों में भाग लेने के लिए तैनात किए जा रहे जहाजों के साथ भारत की परिचालन पहुंच का भी विस्तार हुआ है।
- 'हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी' तथा 'हिंद महासागर रिम एसोसिएशन' जैसे अंतर-सरकारी संगठनों ने भारतीय नौसेना की सामरिक प्रासंगिकता को और बढ़ा दिया है।
- मिशन सागर, प्रोजेक्ट मौसम, प्रोजेक्ट सागरमाला, एक्ट ईस्ट और भारत के रूप में 'शुद्ध सुरक्षा प्रदाता' जैसी रणनीतिक नीतियां-वैश्विक स्तर पर भारत के आर्थिक विकास के लिए महासागरों तथा भारतीय नौसेना की केंद्रीयता को सामने लाती हैं।

भारतीय नौसेना को मजबूत करने के लिए उठाए जा रहे कदम:

- नौसेना की बढ़ती सामरिक प्रासंगिकता ने इसके तात्कालिक उन्नयन को आवश्यक बना दिया है। भारतीय नौसेना को विश्वस्तरीय बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
- प्रोजेक्ट सी बर्ड (Sea Bird) के तहत भारत का सबसे बड़ा नौसैनिक बुनियादी ढांचा आईएनएस कदंब, जिसका उद्देश्य बेड़े का समर्थन और युद्धपोत रखरखाव प्रदान करना है, जो 2012 से कर्नाटक के कारवार नौसेना बेस में निर्माणधीन है। रूस द्वारा निर्मित विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य कारवार में स्थित है।
- सितंबर 2022 में फिर से भारतीय नौसेना ने स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत विक्रांत को शामिल किया। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, चीन और जापान के बाद भारत सातवां ऐसा देश बन गया है जो विमानवाहक पोत बना सकता है।
- प्रोजेक्ट-15ए और 15बी के तहत, चार स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक-विशाखापत्तनम, मोरमुगाओ, इंफाल और सूरत के नाम से मझगाँव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड में बनाए जाने हैं। आईएनएस विशाखापत्तनम और आईएनएस मोरमुगाओ को हाल ही में कमीशन किया जा चुका है।
- मझगाँव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा प्रोजेक्ट-75 के तहत स्कॉर्पीन श्रेणी की छह पारंपरिक पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही भारतीय नौसेना पहले से ही परमाणु संचालित पनडुब्बी अरिहंत से लैस हैं एवं दो अन्य परमाणु पनडुब्बियां निर्माणाधीन हैं।
- भारतीय नौसेना ने मार्च 2022 में गोवा में लंबी दूरी के समुद्री टोही विमान पी-8आई के साथ आईएनएस हंसा को कमीशन किया है। इसे 'सबमरीन हंटर्स' भी कहा जाता है, जो हिंद महासागर क्षेत्र में नौसेना की निगरानी क्षमताओं को बढ़ावा देगा।
- दिसंबर 2022 में भारतीय नौसेना ने 8 एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट (एएसडब्लू-एसडब्लूसी) में से पहला 'अर्नला' लॉन्च किया, जो वर्तमान में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई) कोलकाता द्वारा बनाया जा रहा है। इन जहाजों को तटीय जल में पनडुब्बी रोधी संचालन करने के लिए डिजाइन किया गया है।
- इन कार्यों से नौसेना ने अपनी समुद्री नियंत्रण क्षमताओं में काफी वृद्धि की है। ऊंचे समुद्रों पर ऐसी क्षमता होने वाली दुनिया की पांच प्रमुख नौसैनिक शक्तियों में गिना जाता है। भारत ने किसी भी नौसैनिक शक्ति को चुनौती देने के लिए पर्याप्त निवारक क्षमता हासिल कर ली है।

निष्कर्ष:

- नौसेना दिवस (4 दिसंबर, 2022) की पूर्व संध्या पर, नौसेना प्रमुख एडमिरल हरि कुमार ने जोर देकर कहा कि जब भारत अपनी स्वतंत्रता का शताब्दी वर्ष मना रहा होगा, भारतीय नौसेना 2047 तक पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगी। उन्नत विमान वाहक, पनडुब्बियों और युद्धपोतों के साथ सशस्त्र भारतीय नौसेना ने उभरती हुयी सुरक्षा चुनौतियों के लिए त्वरित प्रतिक्रिया को सक्षम करते हुए पूरे क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ायी है। बड़ी शक्तियों के बीच सामरिक प्रतिस्पर्धा पहले ही समुद्री क्षेत्र में स्थानांतरित हो चुकी है, जिसके लिए भारतीय नौसेना को पर्याप्त रूप से तैयार करने की आवश्यकता है।
- हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में अपनी केंद्रीय स्थिति के कारण भारत का रणनीतिक महत्त्व संतुलित विश्व व्यवस्था के पक्ष में बढ़ रहा है। भारत को अपने राष्ट्रीय हितों को संरक्षित करने के लिए, इस क्षेत्र में एक शुद्ध सुरक्षा प्रदाता की भूमिका निभाना आवश्यक है जिसके लिए उसके पास मजबूत और तकनीकी रूप से आधुनिक नौसेना होनी चाहिए।
- अल्फ्रेड थायर महान ने 21 वीं सदी को 'समुद्रों की सदी' कहा है। उनका विचार था कि साम्राज्य निर्माण का रहस्य समुद्री शक्ति या किसी राष्ट्र की नौसैनिक शक्ति थी। समुद्र का महत्त्व बार-बार साबित हुआ है जो वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है, विशेष रूप से भारत जैसे देश के लिए, जिसके पास 7516.6 किमी लम्बी तटरेखा मौजूद है जो दुनिया के दूसरे सबसे बड़े प्रायद्वीपीय क्षेत्र (2.07 मिलियन वर्ग किमी) के साथ बहुत महत्त्वपूर्ण समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित करता है।

स्वदेशी टीकों को विकसित करने की दिशा में बढ़ता भारत

सन्दर्भ:

हाल ही में केंद्रीयमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) ने 'मिशन कोविड सुरक्षा' के माध्यम से चार टीके विकसित किए हैं और कोवैक्सिन के निर्माण को बढ़ाने की पहल की है। यह निश्चित रूप से भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है।

परिचय:

कोरोना महामारी के दौरान वैक्सीन निर्माण हेतु जब सम्पूर्ण विश्व आशंकित था, तभी भारत के वैज्ञानिकों को दो वर्षों के अल्प कालखंड में कोविड-19 के चार स्वदेशी वैक्सीन विकसित करने में सफलता मिली है। इनमें विश्व का पहला व भारत का स्वदेशी रूप से विकसित डीएनए टीका जायकोव-डी (ZyCoV-D), भारत का पहला प्रोटीन सबयूनिट टीका कॉर्बेवैक्स (Corbevax), विश्व का पहला एवं भारत का स्वदेशी रूप से विकसित एमआरएनए टीका जेमकोवैक-19 (Gemcovac) और विश्व का पहला तथा भारत में स्वदेशी रूप से विकसित इंट्रानेजल (नाक के माध्यम से) कोविड-19 टीका इन्कोवैक (iNCOVACC) शामिल है। यह न सिर्फ भारत में बढ़ते अनुसन्धान का प्रदर्शन करता है बल्कि भारत के फार्मास्यूटिकल उद्योग की परिपक्वता को भी प्रदर्शित करता है।

भारत में वैक्सीन निर्माण परिदृश्य:

- कोरोना महामारी के प्रभावों को निष्प्रभावी करने हेतु त्वरित कार्यवाही की गई। जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) ने 'मिशन कोविड सुरक्षा' के माध्यम से वैक्सीन के विकास पर अत्यधिक जोर दिया। वैक्सीन के लिए सरकारी तथा निजी संस्थानों ने तत्परता दिखाई जिसके फलस्वरूप भारत 2 वर्षों में 4 टीकों का निर्माण करने में सक्षम रहा।
- महामारी संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने कोविड-19 टीके के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जिसके अनुरूप भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत 3.0 पैकेज के तहत 'मिशन कोविड सुरक्षा' की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य त्वरित तरीके से सुरक्षित, प्रभावी, सस्ते और स्वदेशी कोविड-19 टीकों के विकास को सक्षम बनाना था।
- 'मिशन कोविड सुरक्षा' के तहत समर्थित चिकित्सीय परीक्षण स्थलों में जायकोव-डी, कोवोवैक्स, जेमकोवैक-19, कॉर्बेवैक्स, कोवैक्सिन बूस्टर, आरबीसीजी (सीरम इंस्टीट्यूट) और जेएंडजे के कोविड टीकों के चिकित्सीय परीक्षणों की सुविधा प्रदान की गई। यहां लगभग 1.5 लाख लोगों के एक इलेक्ट्रॉनिक स्वयंसेवी डेटाबेस को भी तैयार किया गया है।
- हाल ही में भारत बायोटेक द्वारा निर्मित इंट्रानेजल कोविड-19 टीका-इन्कोवैक को लॉन्च किया गया है। इस इंट्रानेजल टीके की खुराक बूँदों के रूप में नाक के माध्यम से दी जाती है। यह वैक्सीन श्वासनली के ऊपरी भाग को अतिरिक्त प्रतिरक्षा प्रदान करती है तथा वायरस को शरीर में पहुंचने से पहले ही निष्प्रभावी करने का प्रयास करती है।
- भारत ने न सिर्फ अपने देश के लोगों का कोविड टीकाकरण किया है, बल्कि जुलाई 2022 तक 101 देशों व 2 यूएन इंटिटी को करीब 25 करोड़ वैक्सीन दी है। भारत का वैक्सीन निर्यातक बनना निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि है।

वैक्सीन निर्माण की प्रक्रिया:

किसी भी वैक्सीन को तैयार करने में कई चरण शामिल होते हैं जो शोध एवं अनुसंधान से प्रारंभ होकर विनिर्माण, गुणवत्ता नियंत्रण और वितरण तक विस्तृत है। वैक्सीन निर्माण के निम्नलिखित चरण होते हैं-

- **शोध एवं अन्वेषण (EXploratory stage):** इस प्रक्रिया में वैज्ञानिक बीमारी का निदान करने वाले प्राकृतिक और कृत्रिम एंटीजन (Antigen) की पहचान करते हैं। एंटीजन की पहचान सुनिश्चित करने के बाद शोध द्वारा एंटीजन को प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया हेतु प्रेरित किया जाता है। इस चरण में रोगाणुओं की वृद्धि ,संग्रह तथा रिकंम्बिनेंट प्रोटीन का निर्माण किया जाता है।
- **नैदानिक पूर्व (Pre Clinical):** इस चरण में एंटीजन का कोशिका संवर्धन करके जन्तुओं पर परीक्षण किया जाता है। यह चरण वैक्सीन की प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। इस चरण में प्रायः चूहों, बंदरों और खरगोश इत्यादि पर टीके का प्रयोग किया जाता है। वैक्सीन में प्रतिरोधी तंत्र विकसित होने के सत्यापन हेतु किया जाता है।
- **नैदानिक परीक्षण (Clinical Trial):** यह चरण सर्वाधिक महत्त्व पूर्ण है। इसमें कोशिका संवर्धन प्रणाली के माध्यम से जंतु या पौधों में उत्पन्न प्रतिरोधी क्षमता का परीक्षण मानव शरीर पर किया जाता है। यह चरण तीन उपचरणों में पूर्ण होता है:
  - **फेज 1-** लोगों के छोटे समूह (लगभग 20 से 80 लोग) पर वैक्सीन का परीक्षण किया जाता है। इसमें मानव शरीर पर वैक्सीन के प्रभाव का अवलोकन किया जाता है। पर्यवेक्षण की इस अवधि में वैक्सीन की मात्रा (Doses) व समय का विशेष ध्यान रखा जाता है।
  - **फेज 2-** इसमें सैंकड़ो लोगों पर परीक्षण किया जाता है। यहाँ वैक्सीन की मात्रा (Doses), समय इत्यादि में परिवर्तन करके वैक्सीन की सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावों अथवा साइड इफेक्ट्स का विश्लेषण किया जाता है। इस अवस्था में सभी आयुवर्ग के लोगों को शामिल करने का प्रयास किया जाता है। इसमें औसतन 8 से 12 माह का समय लगता है।
  - **फेज 3-** इस अवस्था में हजारों की संख्या में लोगों पर परीक्षण किया जाता है तथा बड़ी जनसँख्या पर वैक्सीन के प्रभाव का परीक्षण किया जाता है। इसमें वैक्सीन के दीर्घकालिक प्रभावों की जांच की जाती है। जब यह सिद्ध हो जाता है कि परीक्षण के सभी उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया गया है तो इसे नियामकीय समीक्षा हेतु आगे बढ़ा दिया जाता है।
- **नियामकीय समीक्षा व अनुमोदन (Regulatory review and Approval):** इस चरण में 'ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया' विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर वैक्सीन का परीक्षण करता है। इसमें अनुमति प्राप्त होने के बाद वैक्सीन के निर्माण का कार्य आरम्भ किया जाता है।

- **विनिर्माण और गुणवत्ता नियंत्रण (Manufacturing and quality control):** इस अवस्था में बेहतर अवसंरचना के साथ वैक्सीन के विनिर्माण का कार्य प्रारंभ किया जाता है। वैक्सीन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु समय-समय पर नियामकीय परीक्षण किये जाते हैं।

कोविड-19 वैक्सीन विकास के सरकारी प्रयास:

भारत सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन के विकास हेतु कई प्रयास किए हैं:

- जैव प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Biotechnology &DBT) द्वारा शैक्षणिक जगत और उद्योग जगत दोनों में ही अब तक कुल 10 वैक्सीन कैंडिडेट्स को समर्थन दिया गया है।
- वर्तमान में, रूसी वैक्सीन स्पुतनिक-वी समेत 5 वैक्सीन कैंडिडेट्स मानव परीक्षण की अवस्था में हैं, जबकि 3 अन्य पूर्व-नैदानिक के अग्रिम चरण में हैं, जो शीघ्र ही मानव परीक्षण की शुरुआत करेंगे।
- **'मिशन कोविड सुरक्षा'**- भारतीय कोविड-19 वैक्सीन विकास मिशन'(Mission COVID Suraksha-The Indian COVID-19 Vaccine Development Mission) को प्रारंभ किया गया है। यह पूर्व-क्लिनिकल विकास (preclinical development) के साथ त्वरित उत्पाद विकास के लिए सभी उपलब्ध और वित्त पोषित संसाधनों को समेकित करेगा।

भारत में नैदानिक परीक्षण की चुनौतियाँ:

भारत में नैदानिक परीक्षण से सम्बंधित स्पष्ट नीति के अभाव में कई चुनौतियाँ देखने को मिलती हैं जिनका वर्णन निम्नवत है:

- **नैदानिक परीक्षण में होने वाली मृत्यु:** वर्ष 2007 से 2019 के बीचे पूरे देश में लगभग 4800 लोगों की मृत्यु नैदानिक परीक्षण के कारण हुई। यह न सिर्फ नैदानिक परीक्षण पर प्रश्नचिन्ह आरोपित करता है, बल्कि अनुच्छेद-21 में वर्णित जीवन के अधिकार का भी उलंघन करता है।
- **नियामकीय विफलता:** भारत में प्राय: वालंटियर आय की समस्या को कम करने के लिए बड़ी संख्या में स्वेच्छा से नैदानिक परीक्षणों में भाग लेते हैं। एक बेहतर नियामकीय ढाँचे के अभाव में वालंटियरों के स्वास्थ्य से सम्बंधित आंकड़ों की अवहेलना करते हुए मानकों का पालन नहीं किया जाता।
- **अनैतिक नैदानिक परीक्षण:** अनैतिक नैदानिक परीक्षण भारत में एक बड़ी समस्या है। डाक्टर, वैज्ञानिक तथा परीक्षण हेतु वित्तीयन करने वाली कम्पनियाँ आपस में नेक्सस करके जिसमें नकली दवाओं व उपकरणों की जाँच के लिये वालंटियरों से सच छुपाती हैं, लोगों पर नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभाव देखे जा सकते हैं।
- **आर्थिक असमानता:** वालन्टियर के आर्थिक जोखिमों का लाभ उठाकर कई बार नैदानिक शोध संस्थानों (CROs) द्वारा लोगों का शोषण किया जाता है। ध्यातव्य है कि वर्ष 2009 में एच.पी.वी. टीके के लिये 24000 लड़कियों को नामांकित किया गया था, परन्तु जांच में पता चला की इन्हें झूठी जानकारियां दी गई थीं।
- **वित्तीयन की समस्या:** परीक्षण के सभी चरणों को नियमानुसार पालन करने में बहुत अधिक व्यय होता है। अत: निजी कम्पनियाँ इस व्यय को कम करने हेतु परीक्षण के सभी चरणों का पालन नहीं करतीं।

भारत के वैक्सीन हब बनने से लाभ:

- भारत में वैक्सीन के निर्माण में तीव्रता आने से भारत की पश्चिमी देशों पर निर्भरता कम होगी।
- भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को बढ़ावा मिलेगा।
- अपने देश में बनी हुई वैक्सीन विभिन्न प्रकार की अफवाहों तथा अनिश्चितताओं को कम करेगी जिससे वैक्सीन के प्रति होने वाले विश्वास संकट को कम करके अराजकता को कम किया जा सकेगा।
- भारत ने विगत 2 वर्षों में कोरोना से संबंधित चार वैक्सीन का निर्माण किया है जो भारत की मजबूत फार्मास्यूटिकल अवसंरचना को प्रदर्शित कर रहा है।
- भारत का फार्मास्युटिकल्स हब बनना, भारत से डॉक्टरों, नर्सों के होने वाले ब्रेन ड्रेन को रोकेगा तथा भारत की उन्नति में सहायक होगा।

अन्य तथ्य:

मिशन कोविड सुरक्षा:

- भारत सरकार के कोविड-19 वैक्सीन विकास मिशन का पूरा नाम 'मिशन कोविड सुरक्षा-भारतीय कोविड-19 वैक्सीन विकास मिशन' (Mission COVID Suraksha-The Indian COVID-19 Vaccine Development Mission) है।
- इस मिशन को भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Biotechnology-DBT) के नेतृत्व में लागू किया जा रहा है।
- यह मिशन पूर्व क्लिनिकल विकास (preclinical development) के साथ त्वरित उत्पाद विकास के लिए सभी उपलब्ध और वित्त पोषित संसाधनों को समेकित करेगा।
- हाल ही में इस मिशन के चरण-I को 12 महीनों की अवधि के लिए 900 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- यह मिशन कोविड सुरक्षा भारत के लिए स्वदेशी, किफायती और सुलभ वैक्सीन के विकास के लिए लक्षित प्रयास है जो आत्मनिर्भर भारत राष्ट्रीय मिशन के लिए पूरक सिद्ध होगा।
- इससे 5-6 वैक्सीन कैंडिडेट (vaccine candidates) के विकास में मदद मिलेगी तथा लाइसेंस प्राप्ति और बाजार तक पहुँच सुनिश्चित होगी।
- भारत वैक्सीन निर्माण में एक शक्तिशाली राष्ट्र है और इस राष्ट्रीय कोविड वैक्सीन मिशन के माध्यम से हमारे वैक्सीन निर्माता न केवल भारत बल्कि दुनिया के लिए किफायती और सुलभ वैक्सीन विकसित करेंगे।

निष्कर्ष:

वैक्सीन निर्माण में भारत द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धि निश्चित ही प्रशंसा योग्य है। हालाँकि नैदानिक परीक्षण में होने वाली चुनौतियों को कम करना आवश्यक है। वैक्सीन निर्माण तथा उसका अनुप्रयोग न सिर्फ आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहायक है, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम की भारत की परम्परा को भी आगे बढ़ा रहा है। हालाँकि भारत को अन्य रोगों के वैक्सीनाइजेशन पर भी ध्यान देना होगा तभी वास्तव में आत्मनिर्भर भारत का निर्माण किया जा सकेगा।

भारत में सहकारी समितियों के प्रबंधन और प्रशासन में सुधार की आवश्यकता

जनवरी 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 के तहत एक राष्ट्रीय स्तर की बहु-राज्यीय बीज सहकारी समिति की स्थापना हेतु ऐतिहासिक निर्णय को मंजूरी दी।

इन बहु राज्यीय सहकारी समितियों की भूमिका:

- गुणवत्तापूर्ण बीजों का उत्पादन, खरीद, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, भंडारण, विपणन और वितरण।
- सामरिक अनुसंधान एवं विकास।
- स्वदेशी प्राकृतिक बीजों के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक प्रणाली विकसित करना।

यह संबंधित मंत्रालयों, विशेष रूप से कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), राष्ट्रीय बीज निगम (एनएससी) के समर्थन से देश भर में विभिन्न सहकारी समितियों के माध्यम से उनकी योजनाओं तथा एजेंसियों के माध्यम से किया जाएगा।

प्रस्तावित सोसायटी द्वारा की जाने वाली सहायता:

- बीज प्रतिस्थापन दर (एसआरआर) तथा प्रजाति प्रतिस्थापन दर (वीआरआर) को बढ़ाना।
- सहकारी समितियों के सभी स्तरों के नेटवर्क का उपयोग करके गुणवत्तापूर्ण बीज की खेती और बीज किस्म के परीक्षण, एकल ब्रांड नाम के साथ प्रमाणित बीजों के उत्पादन एवं वितरण में किसानों की भूमिका सुनिश्चित करना।
- गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता से कृषि उत्पादकता में वृद्धि।
- खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना।
- किसानों की आय में वृद्धि करना।
- सदस्यों को एक ओर गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन से बेहतर कीमतों की प्राप्ति होगी, वहीं दूसरी ओर उच्च उपज वाली किस्म (एचवाईवी) के बीजों के उपयोग से फसलों का उच्च उत्पादन सुनिश्चित होगा, जिसका लाभ अंततः समाज को होगा।
- देश में कृषि उत्पादन बढ़ने से कृषि व सहकारी क्षेत्र में अधिक रोजगार सृजित होना।
- आयातित बीजों पर निर्भरता कम करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर होना।
- मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 के तहत राष्ट्रीय स्तर की बहु-राज्यीय बीज सहकारी समिति, भारत में सहकारी समितियों के प्रबंधन और प्रशासन में सुधार, भारत में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए सरकार का एक सराहनीय प्रयास है।

भारत में सहकारी आंदोलन:

- अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (आईसीए) सहकारिता को 'संयुक्त स्वामित्व वाले, लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित उद्यम के माध्यम से अपनी सामान्य आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से एकजुट व्यक्तियों को एक स्वायत्त संघ' के रूप में परिभाषित करता है।
- सहकारी समितियाँ स्व-वित्तपोषित, आत्मनिर्भर और स्वायत्त हैं। ये सदस्यों के स्वैच्छिक संगठन हैं जो मूल्यों के आधार पर अपने सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एकजुट होते हैं न कि केवल लाभ के आधार पर। सहकारिता आंदोलन को चलाने वाले मुख्य मूल्य स्वयं सहायता, स्व-जिम्मेदारी, लोकतंत्र, समानता, इक्विटी और सामूहिकता है। सहकारी समितियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में समावेशी विकास (विशेष रूप से खाद्य सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन) का एक महत्त्वपूर्ण आधार हैं। वे एक लोकतांत्रिक व्यापार मॉडल प्रस्तुत करते हैं जिसमें लोग पूर्ण समानता के साथ एक साथ आते हैं। इसे निजी पूंजीवाद का मुकाबला करने के लिए लोगों का पूंजीवाद कहा जाता है जो धन के संकेद्रण का कारण बनता है।
- भारत में सहकारिता आंदोलन का जन्म 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में व्याप्त आर्थिक संकट और उथल-पुथल से हुआ था।
- कानून के माध्यम से औपचारिक सहकारी संरचनाओं के अस्तित्व में आने से पहले भी भारत के कई भागों में सहयोग और सहकारी गतिविधियों की अवधारणा प्रचलित थी। उनमें से कुछ को देवरई या वानरई, चिट फंड, कुरी, भिशी, फड़ के नाम से जाना जाता था।
- ब्रिटिश भारत ने भारतीय अकाल आयोग (1901) की सिफारिश पर पहला सहकारी साख समिति अधिनियम, 1904 अधिनियमित किया। 1919 में सहकारिता राज्य सूची का विषय बन गया और प्रांतों को मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के अंतर्गत अपने सहकारी कानून बनाने के लिए अधिकृत किया गया। 1942 में ब्रिटिश सरकार ने बहु-इकाई सहकारी समिति अधिनियम बनाया, जिसका उद्देश्य उन समाजों को शामिल करना था जिनके संचालन एक से अधिक राज्यों तक विस्तारित थे।
- 1958 में, राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) ने सहकारी समितियों पर एक राष्ट्रीय नीति की सिफारिश की। भारत सरकार ने 1984 में बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम बनाया और 2002 में सहकारिता पर राष्ट्रीय नीति अपनाई गई। सहकारी समितियों के तेजी से प्रचार और विकास के लिए 1984 के अधिनियम को एक नए बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
- 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 ने भारत में कार्यरत सहकारी समितियों के संबंध में भाग-IXA (नगरपालिकाओं) के बाद एक नया भाग-IXB जोड़कर सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। 'सहकारिता' शब्द को संविधान के भाग-3 के अनुच्छेद-19(1)(सी) में जोड़ा गया था, इसे नागरिकों के मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है। 'सहकारी समितियों के प्रचार' के संबंध में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (भाग-IV) में एक नया अनुच्छेद-43बी जोड़ा गया था।
- पिछले कुछ वर्षों में सहकारी समितियों ने व्यापार की दुनिया

में पर्याप्त स्थान प्राप्त किया है। भारत में लगभग दस लाख सहकारी समितियाँ हैं। इनका गठन या तो सहकारी समिति अधिनियम, 1912 या केंद्रीय बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम या संबंधित राज्य कानूनों के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है।

- कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड (इफको), अमूल और सहकारी ग्रामीण विकास ट्रस्ट (कॉर्डेट), बैंकिंग क्षेत्र में भारत सहकारी बैंक, सारस्वत सहकारी बैंक, सहकारी भंडार, खुदरा दुकानों की एक सहकारी श्रृंखला व अपना बाजार, सबसे बड़ी तथा सबसे पुरानी बहु-राज्य सहकारी समितियों में से एक हैं। ये भारत में सहकारी समितियों की सफलता की कुछ कहानियाँ हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, ग्रामीण और कृषि ऋण के लिए सहकारी वित्तपोषण संस्थानों का योगदान 1951 में 3.1 प्रतिशत से प्रभावशाली रूप से बढ़कर 2002 में 27.3 प्रतिशत हो गया है।
- वर्ष 2019 में सहकार से समृद्धि की दृष्टि को साकार करने और सहकारिता आंदोलन को एक नया पुश देने के लिए एक अलग 'सहकारिता मंत्रालय' बनाया गया है। सरकार ने समुदाय आधारित विकास साझेदारी के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता को भी दर्शाया है। इन प्रयासों के बावजूद सहकारिता आंदोलन अपने समक्ष उपस्थित कई समस्याओं के कारण अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाया है।

सहकारी क्षेत्र द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दे:

- **टॉप टू बॉटम दृष्टिकोण-** भारत में सहकारिता आंदोलन के संबंध में इस विश्वास का अभाव है कि यह स्वयं लोगों से उत्पन्न नहीं हुआ है।
- **अत्यधिक सहकारी विधान-** भारत में सहकारी समितियाँ विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करती हैं। राज्य का विषय होने के नाते राज्य के सहकारी कानून और उनके कार्यान्वयन के स्तर पर राज्यों में काफी भिन्नता पायी जाती है।
- मुख्य रूप से सहकारी अधिनियमों में खामियां और प्रतिबंधात्मक प्रावधानों से उत्पन्न राजनीतिकरण तथा सरकार का अत्यधिक हस्तक्षेप।
- **गैर-जिम्मेदारी और गैर-जवाबदेही-** बोर्ड की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से संबंधित शासन में गंभीर अनियमितताएं हैं। कई असुविधाओं के लिए बोर्ड के सदस्यों की जवाबदेही का अभाव उत्तरदायी है।
- सक्षम पेशेवरों को आकर्षित करने और बनाए रखने में असमर्थता, एक बड़ी समस्या है।
- **पूंजी निर्माण की कमी-** पूंजी निर्माण के लिए प्रयासों की कमी विशेष रूप से सदस्यों में इक्विटी और सदस्यों की भागीदारी बढ़ाने की चुनौती।
- **जागरूकता की कमी-** लोगों को सहकारी संस्थाओं के नियमों और विनियमों के बारे में समुचित जानकारी का अभाव है।
- **कुप्रबंधन और हेराफेरी-** एक बड़ी समस्या सदस्यों द्वारा किये जाने वाले कुप्रबंधन की है। शासी निकायों के चुनावों में धन तथा बाहुबल के माध्यम से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जैसे शीर्ष पदों पर नियुक्त होना चंद शक्तिशाली लोगों का धंधा बन गया है।
- **प्रतिबंधित कवरेज-** इनमें से अधिकांश समितियां कुछ सदस्यों तक ही सीमित हैं और उनका संचालन केवल एक या दो गाँवों तक फैला हुआ है।
- ओवरस्टाफिंग और भारतीय बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश के कारण, समग्र प्रतिस्पर्धात्मकता जैसे मुद्दों से उत्पन्न लागत में कमी सहकारी समितियों के विकास के मार्ग में बाधक है।
- सहकारी बैंकों की खराब स्थिति जो सहकारी वित्त प्रणाली की एक महत्त्वपूर्ण कड़ी है, वे ठीक से संचालित करने के लिए अत्यंत छोटे हैं और उनमें से कुछ केवल कागजों पर मौजूद हैं:
  - सहकारी बैंकों के एनपीए वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में अधिक हैं- पीएमसी संकट।
  - कामकाज में शेयरधारकों की उम्मीद से कम भागीदारी, ढांचागत कमजोरियां, जिससे सहकारी समितियों के समग्र कामकाज में बाधा आ रही है।
- **सहकारी आंदोलन में क्षेत्रीय विविधताएं-** कुछ सबसे उपजाऊ और आबादी वाले क्षेत्रों में सहकारी समितियों की सीमित सफलता जनसांख्यिकीय और सांस्कृतिक कारकों के साथ संबंध की ओर इशारा करती है।

सहकारी समितियों की स्वायत्तता, स्वतंत्रता और प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए-

- सहकारिता के एक सदस्य द्वारा वार्षिक रूप से आवश्यक भागीदारी के न्यूनतम स्तर को निर्धारित करने वाले प्रावधानों को कानून में शामिल करने की आवश्यकता है।
- सदस्यों द्वारा लोकतांत्रिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना व प्रभावी नेतृत्व विकसित करना जो सहकारी समितियों के अनुकूल सरकार द्वारा नीति निर्माण को भी प्रभावित कर सके।
- विचारों/नीतियों को मूर्त परिणामों में बदलने के लिए व्यावसायिकता का संचार करना महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है।
- सहकारी समितियों में भर्ती, प्रशिक्षण, सामाजिक सुरक्षा आदि जैसे ठोस मानव संसाधन प्रबंधन प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था को मजबूत करना।
- सहकारी उद्यमों को अधिक प्रतिस्पर्धी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र तथा राज्य दोनों कानूनों को फिर से तैयार करना।
- विभिन्न वित्तीय, वाणिज्यिक और कर कानूनों के तहत सहकारी समितियों की मान्यता सुनिश्चित करना, केंद्रीय और राज्य सहकारी कानूनों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है।
- सहकारिता आन्दोलन का सिद्धांत, गुमनाम रहते हुए भी सबको एक करना है। सहकारी आंदोलन में लोगों की समस्याओं को हल करने की क्षमता है। हालांकि सहकारी समितियों में अनियमितताएं हैं और उन्हें रोकने के लिए नियम और सख्त कार्यान्वयन की आवश्यकता है। सहकारिता आन्दोलन को मजबूत करते समय यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि सहकारी समितियों जैसे सामाजिक संगठनों के एक बड़े नेटवर्क की उपस्थिति से सामाजिक पूंजी के उत्पादन और उपयोग में सहायता मिलेगी।

पूर्वोत्तर भारत के बहुआयामी विकास के चलते उग्रवाद में बड़े पैमाने पर कमी

पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद, अलगाववाद, विप्लवकारी गतिविधियां और नृजातीय संघर्ष पूर्वोत्तर के शांति, सुरक्षा तथा समृद्धि के समक्ष एक बड़े खतरे के रूप में मौजूद रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का यह प्रयास रहा है कि प्रभावी रणनीतियों के जरिए उग्रवाद मुक्त पूर्वोत्तर भारत का निर्माण किया जाए जिससे भारत के विकास में पूर्वोत्तर भारत और मुखर रूप में अपनी भूमिका निभा सके। इस दिशा में अपनी एक उपलब्धि को साझा करते हुए भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने हाल ही में पूर्वोत्तर में उग्रवाद में आई कमी से जुड़े आंकड़ें साझा किए हैं। गृह मंत्रालय के आकड़ों के अनुसार पूर्वोत्तर में उग्रवाद से जुड़ी घटनाओं में 89 प्रतिशत की कमी आई है। सुरक्षा बलों पर हमलों में 90 प्रतिशत और आम नागरिकों की मौत के मामलों में 89 प्रतिशत की कमी देखी गई है। ये कमी केंद्र सरकार की नीतियों और इस क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों का ही परिणाम है। यहां उग्रवादी समूहों से जुड़े करीब 8,000 युवा आत्मसमर्पण करके मुख्यधारा में शामिल हो गये हैं।

पूर्वोत्तर में वर्तमान सुरक्षा स्थितिः

2014 के बाद से उत्तर-पूर्वी राज्यों में सुरक्षा की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। वर्ष 2019 से 2020 में पिछले दो दशकों के दौरान सबसे कम उग्रवाद से हताहत होने की घटनाएं हुई हैं। वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2020 में उग्रवाद की घटनाओं में 80 प्रतिशत की कमी आई। इसी तरह इस अवधि के दौरान, सुरक्षा बलों में हताहतों की संख्या में 75 प्रतिशत की कमी आई तथा नागरिक हताहतों की संख्या में 99 प्रतिशत की कमी आई। जहां 2014 में पूर्वोत्तर में हिंसा की 824 घटनाएं हुई जिनमें 212 निर्दोष नागरिक मारे गए, वहीं 2020 में ऐसी घटनाओं की संख्या घटकर 162 रह गई, जिनमें केवल तीन नागरिक मारे गए।

पूर्वोत्तर में शांति और समृद्धि लाने के लिए हाल के समय के प्रमुख समझौतेः

- पूर्वोत्तर में विभिन्न राज्यों के बीच लंबे समय से लंबित सीमा-विवाद क्षेत्र के विकास में एक प्रमुख चिंता का विषय रहे हैं। केंद्र सरकार के सक्रिय प्रयासों से कई दशकों से चले आ रहे विवाद आखिरकार स्थायी रूप से सुलझने लगे हैं। इसने एकीकरण व विश्वास को बढ़ावा दिया है तथा दीर्घकालिक शांति और प्रगति के लिए आगे का मार्ग प्रशस्त किया है। इस दिशा में ऐतिहासिक बोडो शांति समझौते का उल्लेख किया जा सकता है।
- **बोडो पीस एकार्डः** 1960 के दशक के दौरान, असम के बोडो और अन्य जनजातियों ने उदयचल के अलग राज्य का आह्वान किया। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में, बोडो-बोडोलैंड के लिए एक अलग राज्य और असम को '50-50' विभाजित करने की मांग की। इन निरंतर मांगों के परिणामस्वरूप, वर्षों से हिंसा की व्यापक घटनाएं हुई हैं। असम में पांच दशक पुराने बोडो मुद्दे को हल करने के लिए 27 जनवरी, 2020 को बोडो समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके परिणामस्वरूप 1615 कैडरों ने भारी मात्रा में हथियारों और गोला-बारूद के साथ गुवाहाटी में आत्मसमर्पण किया। बोडो पीस एकार्ड में बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट्स (BTAD) के बाहर रहने वाले बोडो लोगों से संबंधित मुद्दों को हल करना, बोडो की सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई तथा जातीय पहचान को बढ़ावा देना और उसकी रक्षा करना, आदिवासियों के भूमि अधिकारों के लिए विधायी संरक्षण प्रदान करना, जनजातीय क्षेत्रों का त्वरित विकास सुनिश्चित करना और एनडीएफबी गुटों के सदस्यों का पुनर्वास करने जैसे प्रावधान किए गए हैं। बोडो इलाके के आर्थिक विकास के लिए सरकार ने 1500 करोड़ रुपये का प्रारंभिक बजट बनाया है। इस इलाके के विकास कार्य की निगरानी एक कमेटी करेगी।
- **ब्रू-रियांग समझौताः** अक्टूबर 1997 में मिजोरम के पश्चिमी भाग में नृजातीय हिंसा के कारण 37,000 से अधिक अल्पसंख्यक ब्रू (रियांग) परिवार 1997-1998 में उत्तरी त्रिपुरा में चले गए। 23 साल पुराने ब्रू-रियांग शरणार्थी संकट को हल करने के लिए 16 जनवरी, 2020 को एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके द्वारा 37,000 से अधिक आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों को त्रिपुरा में बसाया जा रहा है। नई व्यवस्था के अंतर्गत विस्थापित परिवारों को 40X30 फुट का आवासीय प्लॉट, आर्थिक सहायता के रूप में प्रत्येक परिवार को पहले समझौते के अनुसार 4 लाख रुपए फिक्स्ड डिपॉजिट, दो साल तक 5 हजार रुपए प्रतिमाह नकद सहायता, दो साल तक फ्री राशन व मकान बनाने के लिये 1.5 लाख रुपए दिये जाएंगे। इस नए समझौते से करीब 23 वर्षों से चल रही बड़ी मानव समस्या का स्थायी समाधान किया गया है। भारत सरकार, त्रिपुरा, मिजोरम सरकार और ब्रू-रियांग प्रतिनिधियों के बीच हुए समझौते में यह तय हुआ है कि करीब 600 करोड़ रुपये की सहायता केंद्र द्वारा दी जाएगी जिससे ब्रू लोगों का पुनर्वास सुविधाजनक ढंग से हो।
- **नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा समझौताः** 1989 में गठित नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एनएलएफटी) हिंसा में शामिल रहा, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा-पार से सक्रिय है। भारत सरकार और असम सरकार के साथ कई वर्षों की बातचीत के बाद, अगस्त 2019 में नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके परिणामस्वरूप 44 हथियारों के साथ 88 कैडरों का आत्मसमर्पण हुआ।
- एनएलएफटी के कैडर ने साल 1989 से फिर से विद्रोह शुरू किया। हाल के दिनों में राज्य के सुरक्षा उपायों तथा केंद्र सरकार की एजेंसियों की सतर्कता के बाद विद्रोही समूहों, विशेष रूप से एनएलएफटी (बीएम) के सदस्यों का विद्रोह से मोहभंग हो गया और इन्होंने मुख्यधारा में शामिल होने के संकेत देना शुरू कर दिया।
- **कार्बी आंगलोंग समझौताः** कार्बी असम का एक प्रमुख जातीय समूह है, जिसका इतिहास 1980 के दशक के अंत से हत्याओं, नृजातीय हिंसा, अपहरण और कराधान द्वारा चिह्नित किया गया है। असम के कार्बी क्षेत्रों में लंबे समय से चल रहे विवाद को हल करने के लिए 4 सितंबर, 2021 को कार्बी आंगलोंग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें 1000 से अधिक सशस्त्र कैडरों ने हिंसा को त्याग दिया और समाज की मुख्यधारा में शामिल हो गए। हथियार डालने वाले इन उग्रवादी संगठनों के नाम हैं-कार्बी लोंगरी नार्थ कछार हिल्स लिबरेशन फ्रंट, पीपुल्स डेमोक्रेटिक काउंसिल ऑफ कार्बी लोंगरी,

यूनाइटेड पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, कार्बी पीपुल्स लिबरेशन टाइगर्स, कार्बी पीपुल्स लिबरेशन टाइगर्स (आर) और कार्बी पीपुल्स लिबरेशन टाइगर्स (एम)। समझौते में इनके कैडरों के पुनर्वास का प्रावधान भी किया गया है। असम सरकार कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद क्षेत्र से बाहर रहने वाले कार्बी लोगों के विकास के लिए भी कदम उठाने पर सहमत हुई है। इसके लिए वह कार्बी कल्याण परिषद की स्थापना करेगी। कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाया जाएगा। क्षेत्र में विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए अगले पांच वर्षों में 1000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद को और अधिक विधायी, कार्यकारी, प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियां देने का भी प्रस्ताव है।

- **असम-मेघालय अंतर्राज्यीय सीमा समझौता:** असम और मेघालय राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के कुल बारह क्षेत्रों में से छह क्षेत्रों पर विवाद को निपटाने के लिए 29 मार्च, 2022 को एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। अकेले इस समझौते से दोनों राज्यों के बीच लगभग 65 प्रतिशत सीमा विवाद हल हो गए।

अशांत क्षेत्र से आकांक्षी क्षेत्र तक:

- सीमा विवाद समाधान समझौतों और शांति समझौते के परिणामस्वरूप पूर्वोत्तर की सुरक्षा स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पूर्वोत्तर राज्यों की लंबे समय से चली आ रही भावुक मांग को पूरा करते हुए, सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) को उत्तर-पूर्व के एक बड़े हिस्से से कम कर दिया गया है। असम का 60% हिस्सा अब AFSPA से मुक्त हो गया है, वहीं मणिपुर के छह जिलों के 15 पुलिस थानों को अशांत क्षेत्र से बाहर किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में अब केवल तीन जिलों में AFSPA और एक जिले में दो पुलिस थाने रह गए हैं।
- जबकि नागालैंड के सात जिलों के 15 थानों से अशांत क्षेत्र की अधिसूचना हटाई गई है। त्रिपुरा और मेघालय से यह पूरी तरह से वापस ले लिया गया।

पूर्वोत्तर को भारत का आर्थिक हब बनाना:

- सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास और इसे दक्षिण-पूर्व एशिया को जोड़ने वाला एक आर्थिक केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर-पूर्व में विकास कार्यों पर खर्च के लिए 54 केंद्रीय मंत्रालयों से 10% सकल बजटीय सहायता के तहत कुल निर्धारित धनराशि को 2014-15 में 36,108 करोड़ रुपये से 110% बढ़ाकर 2022-23 में 76,040 करोड़ रुपये कर दिया गया है। केंद्रीय बजट 2022-23 में 1,500 करोड़ रुपये के प्रारंभिक आवंटन के साथ एक नई योजना, पूर्वोत्तर के लिए प्रधान मंत्री की विकास पहल (पीएम-डिवाइन) की घोषणा की गई थी।

एक्ट ईस्ट नीति के बारे में:

- नवंबर 2014 में घोषित 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' 'लुक ईस्ट पॉलिसी' का अपग्रेड है जिसे 1992 में प्रख्यापित किया गया था। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय स्तरों पर निरंतर जुड़ाव के माध्यम से हिंद-प्रशांत क्षेत्र जिससे हमारे पड़ोस के अन्य देशों के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके। एक्ट ईस्ट पॉलिसी उत्तर-पूर्व क्षेत्र की संभावित भूमिका में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव लाने में प्रमुख भूमिका निभा रही है।
- अतीत में, सरकार की नीतियां और उनका कार्यान्वयन उत्तर-पूर्व क्षेत्र की विशाल अंतर्निहित क्षमता को आकार देने के लिए अपर्याप्त साबित हुआ था। पिछले आठ वर्षों में केंद्र सरकार इस क्षेत्र की जरूरतों के प्रति अत्यंत संवेदनशील रही है। इसके मुख्य विकास एजेंडे में बेहतर कनेक्टिविटी, बेहतर बुनियादी ढांचा और लोगों के कल्याण का हिस्सा शामिल है।

पूर्वोत्तर भारत में उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस:

- केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 191 नए संस्थान स्थापित किए हैं। उच्च शिक्षा के केंद्रीय संस्थानों की स्थापना में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप, उच्च शिक्षा में कुल छात्र नामांकन में 29 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य की दृष्टि से अकेले कैंसर योजना के तृतीयक स्तर की देखभाल के सुदृढ़ीकरण के तहत 19 राज्य कैंसर संस्थान और 20 तृतीयक स्तर की देखभाल कैंसर केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। इससे कैंसर मरीजों को इलाज के लिए पूर्वोत्तर में ही सारी सहूलियत उपलब्ध होगी।
- केंद्र सरकार ने इस क्षेत्र के लिए 77,930 करोड़ रुपये की 19 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। सरकार अगले तीन साल में यहां 9,476 किमी सड़कों का निर्माण करेगी। देश में 9,265 करोड़ रुपये की नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड (NEGG) परियोजना पर काम चल रहा है। साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र में 18 राष्ट्रीय जलमार्ग आरंभ किए गए हैं।

पूर्वोत्तर के समावेशी विकास के लिए नीति मंच का गठन:

- पूर्वोत्तर के लिए नीति मंच का गठन फरवरी 2018 में किया गया था, ताकि हमारे देश के पूर्वोत्तर-क्षेत्र में त्वरित, समावेशी व सतत आर्थिक विकास में विभिन्न बाधाओं की पहचान की जा सके और पहचान की गई बाधाओं को दूर करने के लिए उपयुक्त अंत:क्षेपों की सिफारिश की जा सके। यह नीति आयोग द्वारा गठित पहला क्षेत्रीय मंच है।
- इस मंच की सह-अध्यक्षता उपाध्यक्ष, नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री द्वारा की जाती है। पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) मंच के सचिवालय के रूप में काम करती है। इसमें सभी पूर्वोत्तर राज्यों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों का प्रतिनिधित्व है। इसके सदस्यों में पूर्वोत्तर के प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे आईआईटी गुवाहाटी, आईआईएम शिलांग, एनईआरआईएसटी, आरआईएस, आरएफआरआई आदि के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ और प्रतिनिधि शामिल हैं।

पूर्वोत्तर में लघु सूक्ष्म मध्यम उपक्रम पर बल:

- हाल के समय में पूर्वोत्तर क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के सतत विकास पर क्षेत्रीय सम्मेलन का अगरतला (त्रिपुरा) में आयोजन किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में एमएसएमई को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने अनेक पहल की हैं। 'पूर्वोत्तर और सिक्किम में एमएसएमई को प्रोत्साहन' एक समर्पित योजना है, जो एमएसएमई के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। अब तक 140 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत 1.14 लाख सूक्ष्म इकाइयों को सहायता दी गई है जिससे 7.6 लाख रोजगार जुटाए गए हैं।

शहरी विकास परियोजनाओं में पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन की जरूरत

सतत विकास अथवा धारणीय विकास आज विश्व के जिम्मेदार देशों में एक प्रमुख एजेंडा और लक्ष्य बन चुका है। भारत में भी पर्यावरण और विकास के बीच सही संतुलन बनाने के लिए सतत विकास के एक साधन के रूप में पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन को अनिवार्य बनाने तथा किसी क्षेत्र को पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने का कार्य किया जा रहा है। इस दिशा में भारत के सर्वोच्च न्यायालय और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की भूमिका हाल के समय में काफी सराहनीय रही है। दोनों ने ही अपने-अपने निर्णयों में एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट और इको-सेंसिटिव जोन के संबंध में महत्त्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र के साथ-साथ राज्य स्तर पर विधायिका, कार्यपालिका और नीति निर्माताओं द्वारा शहरी विकास की अनुमति देने से पहले पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अध्ययन करने के लिए आवश्यक प्रावधान किया जाए।

सर्वोच्च न्यायालय ने एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की जरूरत को बेंगलुरु का उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया और कहा कि जो कभी भारत के सबसे अच्छे शहरों में से एक माना जाता था, लेकिन अब इस तरह के अव्यवस्थित और विचारहीन शहर नियोजन के कारण भारी बाढ़, जलभराव, पीने योग्य पानी की कमी, भयानक ट्रैफिक जाम, खराब कचरा निपटान, तेजी से सिकुड़ते जल निकाय की समस्याओं से जूझ रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि बेंगलुरू शहर द्वारा मिल रही पर्यावरणीय चेतावनी पर विधायिका, कार्यपालिका और नीति निर्माताओं द्वारा उचित ध्यान देने की आवश्यकता है। यह सही समय है कि शहरी विकास की अनुमति देने से पहले इस तरह के विकास का ईआईए करने की आवश्यकता है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने 'कार्बुसियर' चंडीगढ़ की विरासत को संरक्षित करने के निर्देश जारी करते हुए केंद्र तथा राज्यों के विधायिका और कार्यकारी अंगों से आग्रह किया था कि वे बेतरतीब शहरी नियोजन के हानिकारक प्रभावों पर विचार करें। विकास की वेदी पर पर्यावरण की बलि नहीं चढ़ाई जाती और इसलिए एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट जैसे प्रावधानों का गंभीरता से इस्तेमाल किया जाना जरूरी हो जाता है।

इसी प्रकार हाल के समय में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने बडगाम में एनकेसी परियोजनाओं को माइनर मिनरल के खनन के लिए दी गई तीन पर्यावरणीय मंजूरियों को रद्द कर दिया है। गौरतलब है कि इस मामले में जम्मू-कश्मीर राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) द्वारा 19 अप्रैल, 2022 को मेसर्स एनकेसी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में दी गई पर्यावरण मंजूरी को कोर्ट में चुनौती दी गई थी। एनजीटी के इस निर्णय से भी पर्यावरण प्रभाव आंकलन की महत्ता समझ में आती है। चूंकि एनजीटी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के तहत कार्य करता है, इसलिए विकास परियोजनाओं का पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा उसकी एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है और एनजीटी ने अपनी इस भूमिका का निर्वहन लगातार किया है। कुछ समय पूर्व ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तराखंड राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण द्वारा दी गई एक पर्यावरणीय मंजूरी पर भी रोक लगा दिया था। यह मामला उत्तराखंड के बागेश्वर जिले से जुड़ा था जहां साबुन पत्थर खनन के लिए उत्तराखंड राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) द्वारा पर्यावरण मंजूरी गई थी। इस मामले में आवेदक का तर्क था कि इस पर्यावरण मंजूरी में 14 सितंबर, 2006 की ईआईए अधिसूचना का उल्लंघन किया गया है। एनजीटी को दिए अपने आवेदन में याचिकाकर्ता द्वारा कहा गया था कि इसमें वन्यजीवों के आवासों को होते नुकसान को नजरअंदाज कर दिया गया है और ऐसी गतिविधियां भूकंप क्षेत्र में व्यवहार्य नहीं हैं। 'ऐसे में एनजीटी ने परियोजना प्रस्तावक को राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण के समक्ष दो महीने के अंदर भूकंपीयता पर खनन के प्रभावों और वन एवं वन्यजीवों पर इसके प्रभाव पर अध्ययन करने तथा रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया जिससे एसईआईएए उस पर विचार कर सके। पर्यावरण मंजूरी देने से पहले सभी महत्त्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करते हुए एक उचित आदेश पारित करना आवश्यक होता है।'

भारत में क्यों जरूरी है पर्यावरण प्रभाव आंकलन?

- भारत के विभिन्न क्षेत्रों की संवेदनशील भौगोलिक स्थिति इस बात की अपेक्षा करती है कि ऐसे क्षेत्रों में अंधाधुंध तरीके से वाणिज्यिक लाभ के लिए विकास परियोजनाएं न चलाई जाए। हर क्षेत्र की अपनी एक कैरेइंग कैपेसिटी होती है। पहाड़, पठार, नदी क्षेत्र, वेटलैंड एरिया की विकास कार्यों को बर्दाश्त करने की एक हद तक ही क्षमता होती है जिसको ध्यान में रखकर ही प्रोजेक्ट्स को शुरू करना चाहिए। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने से भारी नुकसान की खबरों के बीच सरकारी आंकड़ों से खुलासा हुआ है कि 2015 से 2022 के बीच देश के विभिन्न हिस्सों में भूस्खलन की कुल 3782 घटनाएं हुई, जिससे जनजीवन और बुनियादी ढांचा प्रभावित हुआ है।
- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार, लगभग 0.42 मिलियन वर्ग किमी या 12.6 प्रतिशत भूमि क्षेत्र, बर्फ से ढके क्षेत्र को छोड़कर भारत भूस्खलन के खतरे से ग्रस्त है। इसमें से 0.18 मिलियन वर्ग किमी उत्तर-पूर्व हिमालय में पड़ता है, जिसमें दार्जिलिंग और सिक्किम शामिल हैं। 0.14 मिलियन वर्ग किमी उत्तर-पश्चिम हिमालय (उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर) में पड़ता है, पश्चिमी घाटों और कोंकण पहाड़ियों (तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा तथा महाराष्ट्र) में 0.09 मिलियन वर्ग किमी व आंध्र प्रदेश में अरुकु क्षेत्र के पूर्वी घाटों में 0.01 मिलियन वर्ग किमी।
- भूस्खलन-प्रवण हिमालय क्षेत्र अधिकतम भूकंप-प्रवण क्षेत्रों में आता है। ऐसे में इन क्षेत्रों में पर्यावरण प्रभाव आंकलन की

अनिवार्यता आवश्यक हो जाती है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) भी कहता है कि भूस्खलन और हिमस्खलन प्रमुख हाइड्रो-जियोलॉजिकल खतरों में से एक हैं, जो हिमालय, पूर्वोत्तर पहाड़ी शृंखला, पश्चिमी घाट, नीलगिरि, पूर्वी घाट तथा विंध्य के अलावा भारत के बड़े हिस्से को प्रभावित करते हैं जो लगभग 15 फीसदी भूभाग को कवर करता है।

- भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री द्वारा हाल ही में लोकसभा में हिमालयी क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं की स्थिति के बारे में जानकारी दी गई है जिसके आधार पर भी पर्यावरण प्रभाव आंकलन की गंभीर जरूरत समझ में आती है। वर्तमान में, 11137.50 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता वाली 30 बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं (एचईपी) जो 25 मेगावाट स्थापित क्षमता से ऊपर हैं। देश के विभिन्न राज्यों में हिमालयी इलाकों में विकसित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं में से कुल 10381.5 मेगावाट की 23 जलविद्युत परियोजनाएं सक्रिय निर्माणाधीन हैं और कुल 756 मेगावाट की सात जल विद्युत परियोजनाओं का काम रुका हुआ है।
- इसके साथ ही ट्रांस-हिमालयी क्षेत्र में विकासात्मक गतिविधियों के पर्यावरणीय प्रभाव के मापन की जरूरत पर भी हाल के समय में बल दिया गया है। पर्यावरण मंत्रालय ने संशोधित पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना, 2006 में परियोजना के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों के व्यापक मूल्यांकन के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया का वर्णन किया है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ ट्रांस-हिमालयी इलाकों में स्थित परियोजना के स्थान को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण और सामाजिक प्रभावों के आंकलन के लिए विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) द्वारा विचार प्रक्रिया के चार चरणों अर्थात जांच, दायरे, सार्वजनिक परामर्श व मूल्यांकन को शामिल किया गया है।

पर्यावरण प्रभाव आंकलन क्या होता है?

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम पर्यावरण प्रभाव आंकलन को एक ऐसे उपकरण के रूप में परिभाषित करता है जिसके तहत किसी विकास परियोजना या ऐसी गतिविधि पर निर्णय लेने से पूर्व किसी परियोजना के पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों की पहचान की जाती है।
- पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन (EIA) पर्यावरणीय नीति निर्माताओं के पास उपलब्ध एक ऐसा उपकरण है जो विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में पर्यावरणीय चिंताओं के साथ विकासीय गतिविधियों के साथ सामंजस्य को स्थापित करता है। ईआईए को भारत में पहली बार 1978 में नदी घाटी परियोजनाओं के संबंध में पेश किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत ईआईए को अनिवार्य किया गया है। पहली पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना वर्ष 1994 में तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (वर्तमान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय) द्वारा प्रख्यापित की गई थी।
- पर्यावरण प्रभाव आंकलन इस अवधारणा पर आधारित है कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के धारणीय विकास पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों का आंकलन किए बिना कार्यवाही न हो। यह अवधारणा हरित विकास को बढ़ावा देती है। पर्यावरण मूल्यांकन (ईए) प्रस्तावित कार्यवाही के साथ आगे बढ़ने के फैसले से पहले योजना, नीति, कार्यक्रम या वास्तविक परियोजनाओं के पर्यावरणीय परिणामों (सकारात्मक और नकारात्मक) का मूल्यांकन है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परियोजना को प्रस्तावित किया जा सकता है या नहीं। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन एक विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) द्वारा किया जाता है, जिसमें वैज्ञानिक और परियोजना प्रबंधन विशेषज्ञ शामिल होते हैं। विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ईआईए अध्ययन का एक फ्रेमवर्क तैयार करती है और एक प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।

राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण का महत्त्व:

- राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) राज्य स्तर पर ईआईए अधिसूचना के कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय का बहुत महत्त्वपूर्ण संगठन है जिसे श्रेणी-बी के तहत सभी प्रस्तावों के लिए पर्यावरण संबंधी मंजूरी (ईसी) पर विचार करने तथा प्रावधान तैयार करने की शक्तियां दी गई हैं। भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरण संबंधी मंजूरी की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और मंजूरी देने में लगने वाले अनुचित समय को कम करने के लिए कई पहलें की हैं, जैसे ईसी प्रस्ताव को पूरी तरह ऑनलाइन दाखिल करना और प्रक्रिया चलाना, सभी विस्तार प्रस्तावों के लिए मानक टीओआर, एक बार में सभी प्रश्नों को उठाकर कई ईडीएस/एडीएस से बचाव करना, पाक्षिक ईसी बैठकें आयोजित करना आदि।
- अगले कदम के रूप में एसईआईएए के कामकाज में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रोत्साहित करने के लिए एसईआईएए की नई रेटिंग शुरू की गई है। रैंकिंग प्रणाली ईआईए अधिसूचना 2006 के प्रावधानों और मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विभिन्न दिशानिर्देशों पर आधारित है और किसी भी नियामक सुरक्षा उपायों को कमजोर किए बिना ईआईए अधिसूचना 2006 के प्रावधानों के अनुसार सख्ती से निर्णय लेने में अपनी दक्षता बढ़ाने के लिए एसईआईएए को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह ध्यान देने योग्य है कि ईआईए अधिसूचना पहले से ही सभी ईसी प्रक्रियाओं के लिए समय-सीमा प्रदान करती है।
- संयुक्त राष्ट्र की एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में विश्व की आधी आबादी शहरों में रहने लगी है तथा 2050 तक भारत की आधी आबादी महानगरों और शहरों में रहने लगेगी। भारत में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है और वैश्विक स्तर पर भी तब तक कुल आबादी का 70% हिस्सा शहरों में रह रहा होगा। ऐसे में संसाधनों पर बोझ बढ़ना स्वाभाविक है, इसलिए शहरी विकास परियोजनाओं में पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन की जरूरत का प्रचार प्रसार करना भी आवश्यक हो जाता है।

1 एनुअल डेथ पेनल्टी इन इंडिया रिपोर्ट, 2022

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLU) के प्रोजेक्ट-39A द्वारा 'एनुअल डेथ पेनल्टी इन इंडिया रिपोर्ट, 2022' नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई।

रिपोर्ट के प्रमुख बिन्दु:

- देश भर की ट्रायल कोर्ट ने 2022 में 165 कैदियों को मौत की सजा दी, जो पिछले दो दशकों में एक साल में सबसे ज्यादा है। साथ ही, 2022 के अंत तक 539 कैदियों को मौत की सजा सुनाई जा चुकी थी, जो 2016 के बाद से सबसे अधिक था और 2015 के बाद से मौत की सजा के तहत रहने वाले कैदियों की संख्या में 40% की वृद्धि देखी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए 11 मामलों में (जिसमें 15 कैदी शामिल थे) अदालत ने पांच कैदियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया। आठ कैदियों की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया और दो कैदियों की मौत की सजा की पुष्टि की।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि बड़ी संख्या में मौत की सजा पाए हुए लोगों की लंबी कतार निचली अदालतों द्वारा उच्च संख्या में मौत की सजा जारी रखने और अपीलीय अदालतों द्वारा निपटान की कम दर का संकेत देती है। 50 प्रतिशत से अधिक (51.28 प्रतिशत) मामले (जिनमें मृत्युदंड दिया गया था) यौन अपराधों से संबंधित थे।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 में सबसे ज्यादा मौत की सजा अहमदाबाद में एक बम विस्फोट मामले में 38 लोगों को मौत की सजा दी गई। यह 2016 के बाद से एक ही मामले में मौत की सजा पाने वाले लोगों की सबसे बड़ी संख्या है।
- सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने क्रमशः मृत्युदंड से संबंधित 11 और 68 मामलों का फैसला किया।
- रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि उच्च न्यायालयों द्वारा तय किए गए 68 मामलों में से (जिसमें 101 कैदी शामिल थे) तीन कैदियों की मौत की सजा की पुष्टि हुई तथा 48 की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया एवं 43 को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया तथा छह के मामले ट्रायल कोर्ट, एनएलयू को भेज दिए गए थे। बंबई उच्च न्यायालय ने डकैती और हत्या के एक मामले में एक कैदी की आजीवन कारावास की सजा को बढ़ाकर मृत्युदंड कर दिया।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए 11 मामलों में (जिसमें 15 कैदी शामिल थे) अदालत ने पांच कैदियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया। आठ कैदियों की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया और दो कैदियों की मौत की सजा की पुष्टि की। शीर्ष अदालत के बरी किए गए फैसलों में पुलिस, अभियोजन और निचली अदालतों द्वारा जांच की अनुचित प्रकृति तथा प्रक्रियात्मक विफलताओं का उल्लेख है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि अपीलीय अदालतों ने अधिकांश मौत की सजाओं को कम करना जारी रखा है, लेकिन चिंता की बात यह है कि इन कमियों के परिणामस्वरूप आजीवन कारावास की सजा में कमी आई है।

आगे की राह:

बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1979 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि मृत्युदण्ड/कैपिटल पनिशमेंट/ डेथ पेनाल्टी को केवल दुर्लभतम या Rarest of the rare मामलों में देना चाहिए जिसको ध्यान रखना आवश्यक है ताकि कानून में विश्वास बना रहे।

2 ओबीसी उप-वर्गीकरण पैनल को मिला 14वां विस्तार

चर्चा में क्यों?

अन्य पिछड़ा वर्ग के उप-वर्गीकरण हेतु दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी की अध्यक्षता में बने आयोग को राष्ट्रपति द्वारा 14वां विस्तार दिया गया है। उल्लेखनीय है कि पहले इस आयोग को 31 जनवरी, 2023 तक रिपोर्ट देनी थी जिसे अब 31 जुलाई तक विस्तारित किया गया है।

आयोग के बारे में:

- इस आयोग का गठन 2 अक्टूबर, 2017 को संविधान के अनुच्छेद-340 के तहत 12 सप्ताह में 02 जनवरी, 2018 तक रिपोर्ट देने के लिए किया गया था।
- इस आयोग को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उप-वर्गीकरण और उनके लिए आरक्षित लाभों के समान वितरण का काम सौंपा गया था।
- 2015 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) ने सिफारिश की थी कि OBC को अति पिछड़ा वर्ग, अधिक पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।
- एनसीबीसी के पास सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के संबंध में शिकायतों तथा कल्याणकारी उपायों की जांच करने का अधिकार है।
- इसमें राज्य सरकारों से भी सुझाव लेने एवं कोविड महामारी ने जमीनी रिपोर्ट एकत्रित करने में विलम्ब किया है।

भारत में ओबीसी आरक्षण की स्थिति:

- वर्ष 1953 में स्थापित कालेलकर आयोग अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के अलावा अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान करने वाला पहला आयोग था।
- मंडल आयोग(1980) की रिपोर्ट में ओबीसी आबादी का 52% अनुमान लगाया गया था तथा 1,257 समुदायों को पिछड़े के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इस आयोग ने ओबीसी को शामिल करने के लिए मौजूदा कोटा (जो केवल एससी/एसटी के लिए था) को 22.5% से 27% बढ़ाकर 49.5% करने की सिफारिश की थी।
- संविधान के अनुच्छेद-15(4), 16(4) और 340(1) में 'पिछड़ा वर्ग' शब्द का उल्लेख है। अनुच्छेद-15(4) और 16(4) राज्य को

किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है।

- 2008 में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ओबीसी के बीच क्रीमी लेयर (उन्नत वर्ग) को बाहर करने का निर्देश दिया।
- 102वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2018 ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, जो पहले सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय था।

उप-वर्गीकरण करने की आवश्यकता:

- एक तरफ जाट, यादव, कुर्मी जैसे शक्तिशाली कृषक समुदाय हैं, जो विभिन्न प्रकार का लाभ उठा रहे हैं और दूसरी ओर बड़ी संख्या में छोटे किसान तथा संबद्ध समुदाय जैसे मछली श्रमिक व चरवाहे हैं, जो इससे वंचित है।
- नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में ओबीसी कोटा लागू करने के पांच साल के आंकड़ों से पता चलता है कि एक बहुत छोटे वर्ग ने बड़े हिस्से का लाभ उठाया है।
- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 2011 में उप-वर्गीकरण हेतु स्थायी समिति की सिफारिश की थी क्योंकि उप-वर्गीकरण ओबीसी के भीतर असमानता को दूर करने का एक बहुत ही सरल तरीका है।

आगे की राह:

सरकार को चाहिए कि इस मुद्दे को गंभीरता से हल करे क्योंकि बार-बार एक्सटेंसन देने से लोगों का विश्वास कानून प्रणाली में कम होता है, इसलिए समयबद्ध तरीके से सुझाव देना जरुरी हो जाता है।

3 दो सीटों पर एक साथ चुनाव लड़ने पर कोई रोक नहीं

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने लोकसभा या विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों को एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने से रोकने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। माननीय न्यायालय ने कहा कि यह कार्य संसद की संप्रभुता व राजनीतिक लोकतंत्र के अंतर्गत आता है।

दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने का प्रावधान:

- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951 की धारा-33(7) एक उम्मीदवार को अधिकतम दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव (संसदीय, राज्य विधानसभा या उपचुनाव) लड़ने की अनुमति देती है।
- यह प्रावधान 1996 में संशोधित किया गया था। इससे पहले निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या पर कोई रोक नहीं थी, जहां से एक उम्मीदवार चुनाव लड़ सकता था।
- आरपीए की धारा-70 में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन में या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन में एक से अधिक सीटों के लिए चुना जाता है, ऐसी स्थिति में वह निर्धारित समय के भीतर एक सीट को छोड़कर, अन्य सभी से इस्तीफा दे देता है।

धारा-33(7) की वैधता पर सरकार का दृष्टिकोण:

- सरकार का मत है कि कानून, चुनाव लड़ने के उम्मीदवार के अधिकार को कम नहीं कर सकता है, साथ ही उम्मीदवारों की राजनीतिक पसंद को कम नहीं कर सकता है।
- सरकार ने कहा कि दो निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रतिबंध काफी उचित था, इसलिए अब कानून को बदलने की कोई जरूरत नहीं है।

धारा-33(7) पर भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) का दृष्टिकोण:

- चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने 2004, 2010, 2016 व 2018 में धारा-33 (7) में संशोधन का प्रस्ताव दिया था।
- चुनाव आयोग ने कहा कि जब कोई व्यक्ति दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है और दोनों से जीतता है, तो उसे दो निर्वाचन क्षेत्रों में से एक सीट खाली करनी होती है जिसके लिए उपचुनाव की आवश्यकता होगी।
- चुनाव आयोग ने यह भी सुझाव दिया था कि एक उम्मीदवार को विधानसभा चुनाव में दो निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ने के लिए 5 लाख रूपये व लोकसभा चुनाव में 10 लाख रूपये की राशि जमा करनी चाहिए ताकि इस राशि का उपयोग उपचुनाव के खर्च को कवर करने के लिए किया जा सके।

आगे की राह:

आज जब देश में एक व्यक्ति, एक वोट की अवधारणा लागू है, ऐसे में यह समय की मांग है कि एक व्यक्ति को एक ही निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहिए। इससे लोगों में लोकतंत्र के प्रति विश्वास तो बढ़ेगा ही, साथ में समय की बचत होगी और संसाधनों का दुरूपयोग कम किया जा सकेगा।

4 राज्यपाल ने डोमिसाइल विधेयक को किया वापस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में झारखंड के राज्यपाल ने डोमिसाइल विधेयक राज्य सरकार को लौटा दिया क्योंकि यह विधेयक 1932 के भूमि रिकॉर्ड के आधार पर राज्य में 'स्थानीय' को परिभाषित करता है, जिसमें 'गंभीरता से समीक्षा' करने की आवश्यकता है। उल्लेखनीय है कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच संबंध काफी दिनों से तनावपूर्ण रहे हैं।

विधेयक के बारे में राज्यपाल का तर्क:

- राज्यपाल ने विधेयक को वापस करते हुए तर्क दिया कि विधेयक में केवल स्थानीय व्यक्ति (जैसा कि इसके तहत पहचाना गया है) को राज्य सरकार के वर्ग-3 और 4 के पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र माना गया है। यह संविधान के अनुच्छेद-16 के अनुरूप नहीं है, जो रोजगार में समानता की गारंटी देता है। राज्यपाल ने यह भी कहा कि रोजगार के मामलों में किसी भी तरह की शर्तें लगाने का अधिकार सिर्फ संसद को है, राज्य विधानमंडल के पास यह शक्ति नहीं है।
- राज्यपाल ने एवीएस नरसिम्हा राव और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश के मामले का हवाला देते हुए कहा कि यह विधेयक शीर्ष अदालत के आदेशों के खिलाफ है, जो नॉन-डोमिसाइल व्यक्तियों को नौकरी

देने के बारे में था। इसमें माननीय न्यायालय ने कहा था कि मुक्त किए गए सभी नॉन-डोमिसाइल कर्मचारियों को आंध्र क्षेत्र में सेवा में बिना किसी रुकावट के और यदि आवश्यक हो तो अधिसंख्य पद सृजित करके रोजगार प्रदान किया जाए।

- ध्यातव्य है कि झारखंड के विभिन्न क्षेत्र पांचवीं अनुसूची (अनुसूचित जनजातियों के प्रावधानों से निपटने) के तहत आते हैं। सत्यजीत कुमार बनाम झारखंड राज्य के मामले का उदाहरण देते हुए राज्यपाल ने कहा कि 100 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान स्पष्ट रूप से असंगत प्रतीत होता है, जो मौलिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसलिए जब राज्य विधानमंडल के पास ऐसे मामलों में विधेयक पारित करने की शक्ति नहीं है, तो इस विधेयक की वैधता पर एक गंभीर सवाल उठता है।

आगे की राह:

संविधान की नौवीं अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची है, जिन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। हालांकि अतीत में अदालतों ने कहा है कि अगर कानून मौलिक अधिकारों या संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करते हैं तो कानूनों की समीक्षा की जा सकती है। इसलिए राज्य सरकार को संविधान के अंतर्गत निहित प्रावधानों को ध्यान रखकर कानून बनाना चाहिए।

5 लद्दाख ने संविधान के अनुच्छेद-244 के तहत छठी अनुसूची के दर्जे की मांग की

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, लद्दाख के इनोवेटर तथा सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने लद्दाख की नाजुक पारिस्थितिकी की ओर ध्यान आकर्षित करने और संविधान के अनुच्छेद-244 के तहत छठी अनुसूची के तहत इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 5 दिवसीय 'जलवायु उपवास' किया।

छठी अनुसूची क्या है?

- संविधान के भाग-X में अनुच्छेद-244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। अनुच्छेद-244(2) के तहत छठी अनुसूची का प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन पर लागू होता है।
- छठी अनुसूची स्वायत्त जिला और क्षेत्रीय परिषदों के सृजन के माध्यम से जनजातीय समुदायों को स्वायत्तता प्रदान करती है। वे भूमि, वन, स्थानांतरण खेती, ग्राम प्रशासन, संपत्ति की विरासत, सामाजिक रीति-रिवाजों आदि जैसे मामलों पर कानून (जिसे आगे राज्यपाल की सहमति की आवश्यकता होती है) बना सकते हैं।
- वे जनजातियों के बीच मामलों की सुनवाई के लिए ग्राम परिषदों या अदालतों का गठन कर सकते हैं। वे प्राथमिक विद्यालयों, औषधालयों की स्थापना और प्रबंधन कर सकते हैं। वे भूमि राजस्व एकत्र कर सकते हैं और कुछ कर लगा सकते हैं।

यह मांग क्यों?

- लद्दाख को 1995 से एक स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद द्वारा प्रशासित किया जाता रहा है। अनुच्छेद-370 के निरस्त होने के साथ, लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और वास्तविक शक्ति स्वायत्त पहाड़ी परिषदों से उपराज्यपाल के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत नौकरशाही को स्थानांतरित हो गई। लद्दाख के लोगों को लोकतांत्रिक विकल्प बनाने और अपने स्वयं के पार्षदों का चुनाव करने से वंचित कर दिया गया।
- जम्मू-कश्मीर में बदली निवास नीति ने लद्दाख में अपनी भूमि, रोजगार, जनसांख्यिकी और सांस्कृतिक पहचान के बारे में आशंकाएं पैदा कर दी हैं। औद्योगिक और पर्यटन उद्देश्य के विकास के लिए लद्दाख को खोलने के कारण, पूरे क्षेत्र में बड़ी आबादी तथा उद्योगों का निवास होगा। यह उनकी स्थानीय संस्कृतियों और सामाजिक रीति-रिवाजों को खतरे में डाल सकता है।

आगे की राह :

लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता है। अनुच्छेद-244(2) के तहत 6वीं अनुसूची के रूप में केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल हैं। देश के अन्य जनजातीय बहुल क्षेत्रों के लिए, 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों का प्रावधान है। सितंबर 2019 में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने सिफारिश की है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को 6वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। लद्दाख की 90% से अधिक आबादी आदिवासी है और ब्रोकपा, चांगपा, बाल्टी आदि जैसे समुदाय विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत संरक्षित करते हैं जिन्हें सुरक्षा देने की आवश्यकता है।

6 ऑपरेशन सद्भावना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, भारतीय सेना ने लद्दाख के दूरदराज के क्षेत्रों में महिलाओं, बच्चों और युवाओं को सहायता देने के उद्देश्य से ऑपरेशन सद्भावना शुरू किया है।

ऑपरेशन सद्भावना क्या है?

'ऑपरेशन सद्भावना' के तहत, भारतीय सेना केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के दूरदराज के क्षेत्रों के महिलाओं, बच्चों तथा कमजोर वर्गों के लिए सेना सद्भावना स्कूलों, मानव संसाधन/कौशल विकास, बुनियादी ढांचे की विकास परियोजनाओं, राष्ट्रीय एकता, शैक्षिक भ्रमण आदि जैसे कई कल्याणकारी गतिविधियों का संचालन करेगी।

उद्देश्य:

ऑपरेशन सद्भावना का फोकस सामुदायिक/बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से, क्षमता निर्माण वाली शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल, महिला तथा युवा सशक्तीकरण के समग्र मुख्य सामाजिक सूचकांकों में सुधार करना है। इसका मूल विषय पाकिस्तान प्रायोजित भारत विरोधी भावनाओं के प्रचार का मुकाबला करना, स्थानीय लोगों, सेना और नागरिक प्रशासन को शामिल करने वाले एक सहभागी मॉडल के आधार पर क्षेत्र के चहुमुखी विकास की सुविधा प्रदान करना है।

विशेषताएं:

- सामुदायिक विकास परियोजनाओं में सामुदायिक हॉल का निर्माण, नवीनीकरण व उपकरणों की व्यवस्था करना, जल आपूर्ति योजनाएं,

जनरेटर के प्रावधान, सौर प्रकाश व्यवस्था करना, वृक्षारोपण, बोरवेल की स्थापना, ग्रामीण सड़कों और शौचालयों के निर्माण का प्रावधान शामिल है।

- बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में कंप्यूटर प्रयोगशाला की स्थापना शामिल है। साथ ही स्टेडियम/खेल परिसर का निर्माण, सामुदायिक हॉल, सभागार का निर्माण और युवा सशक्तीकरण नोड का निर्माण आदि। उपकरण, खेल किट प्रदान करके और विभिन्न खेल कार्यक्रमों का आयोजन करके खेलों को भी गति प्रदान की जा रही है।
- व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों, महिला सशक्तीकरण केन्द्रों और कम्प्यूटर केन्द्रों में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है। इसके अलावा, विभिन्न गतिविधियों जैसे पश्मीना शॉल बुनाई, ऊन बुनाई, खुबानी के तेल का निष्कर्षण करने आदि के लिए महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कक्षाएं भी आयोजित की जा रही हैं।
- इसके अलावा, भारत में विभिन्न व्यावसायिक कॉलेजों और संस्थानों में प्रवेश के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेष रूप से कारगिल की छात्राओं के लिए एक पहल 'कारगिल इग्नाइटेड माइंड्स' शुरू की गई है।
- क्षमता निर्माण पर्यटन, विशेष रूप से महिलाओं और छात्राओं सहित छात्रों के लिए आयोजित किए जाते हैं, जिसमें उन्हें दिल्ली में भारत के राष्ट्रपति से मिलने तथा बातचीत करने का अवसर मिलता है।

आगे की राह:

'ऑपरेशन सद्भावना' राष्ट्रीय एकता यात्राओं, महिला सशक्तीकरण, रोजगार सृजन, शिक्षा और राष्ट्र निर्माण की दिशा में विकास गतिविधियों के माध्यम से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहा है। ऑपरेशन सद्भावना परियोजनाओं का चयन स्थानीय नागरिक प्रशासन के साथ मिलकर स्थानीय आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। यह पहल राष्ट्रीय एकीकरण और क्षेत्र के लोगों को भारत की मुख्यधारा के साथ जोड़ने के दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण है। इससे क्षेत्र में कट्टरपंथ और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का मुकाबला करने में भी मदद मिलेगी।

7 आंध्र प्रदेश की गारंटीड पेंशन योजना मॉडल

चर्चा में क्यों?

आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित नए पेंशन मॉडल ने केन्द्र सरकार के अतिरिक्त कई राज्य सरकारों को प्रभावित किया है।

आंध्र प्रदेश सरकार का प्रस्तावित पेंशन मॉडल क्या है?

- इसे आकर्षक रूप से 'गारंटीड पेंशन स्कीम' या जीपीएस कहा जाता है।
- यदि कर्मचारी हर महीने अपने मूल वेतन का 10 प्रतिशत योगदान करते हैं, तो वे अपने अंतिम आहरित वेतन के 33 प्रतिशत की गारंटीकृत पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।
- यदि कर्मचारी हर महीने अपने वेतन का 14 प्रतिशत अंशदान करने के इच्छुक हैं, तो अपने अंतिम आहरित वेतन के 40 प्रतिशत की गारंटीकृत पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।

पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के बारे में:

- ओपीएस सरकारी कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करता था जो अंतिम आहरित मूल वेतन के 50% या रोजगार के पिछले दस महीनों में उनके औसत वेतन पर तय किया गया था, जो भी उनके लिए अधिक अनुकूल हो।
- ओपीएस के तहत कर्मचारियों को पेंशन अंशदान करने से छूट प्राप्त है।
- 1 अप्रैल, 2004 से ओपीएस को केंद्र सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था।

ओपीएस के साथ मुद्दे:

- जैसे-जैसे जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है, ओपीएस सरकारों के लिए अस्थिर हो गया है।
- सरकार द्वारा सेवारत कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते या (डीए) में वृद्धि के साथ सरकारी कर्मचारियों के वेतन की तरह पेंशनभोगियों के मासिक भुगतान में भी वृद्धि हुई है।
- 'एज-यू-गो' योजना ने अंतर-पीढ़ीगत इक्विटी मुद्दों का निर्माण किया।
- कुछ राज्यों ने इसे एक प्रमुख वित्तीय चिंता माना।

नई पेंशन योजना (एनपीएस) क्या है?

- केंद्र सरकार ने अप्रैल, 2004 में ओपीएस के विकल्प के रूप में एनपीएस की शुरुआत की थी।
- एनपीएस के तहत, जो लोग सरकार के लिए काम करते हैं, वे अपने मूल वेतन का 10% योगदान करते हैं, जबकि उनके नियोक्ता 14% तक योगदान कर सकते हैं।
- सशस्त्र बलों के कर्मचारियों को छोड़कर सार्वजनिक, निजी और असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों को पेंशन कार्यक्रम के लिए खोला गया है।
- कोष का कुछ प्रतिशत अंशदान सेवानिवृत्ति के बाद अभिदाताओं द्वारा निकाला जा सकता है।

एनपीएस और ओपीएस में क्या अंतर है?

- ओपीएस में पेंशन राशि स्थिर और गारंटीकृत है। दूसरी ओर, एनपीएस फिक्स रिटर्न की गारंटी नहीं देता है।
- ओपीएस में कोई कर लाभ नहीं था जहां एनपीएस में कर्मचारी आयकर की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये और 80सीसीडी (1बी) के तहत अन्य निवेश पर 50,000 रुपये तक की कर कटौती का दावा कर सकता है।
- ओपीएस में पेंशन पर कोई कर नहीं है, जबकि एनपीएस में 40% कर योग्य है जबकि एनपीएस कोष का शेष 60% कर-मुक्त है।

आगे की राह:

भारत में पेंशन प्रणाली पर पुनर्विचार की आवश्यकता है जिससे एक कर्मचारी बिना भविष्य की चिंता किये वर्तमान में अपना बेहतर इनपुट दे सके। पेंशन प्रणाली अच्छी राजनीति और अर्थशास्त्र दोनों के दृष्टिकोण से टिकाऊ होनी चाहिए।

1 भारत-मिस्र 'रणनीतिक साझेदारी'

चर्चा में क्यों?

मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी 24-27 जनवरी 2023 तक भारत की राजकीय यात्रा पर रहे। वे भारत के गणतंत्र दिवस 2023 में मुख्य अतिथि भी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी ने रक्षा और सुरक्षा, व्यापार तथा आतंकवाद-रोधी सहयोग के क्षेत्रों में संबंधों का विस्तार करने का संकल्प लेते हुए अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया।

भारत-मिस्र द्विपक्षीय संबंध:

भारत और मिस्र का प्राचीन काल से निकट संबंधों का इतिहास रहा है। भारत, मिस्र को यूरोपीय और अफ्रीकी देशों के प्रवेश द्वार के रूप में देखता है। अशोक के अभिलेखों में टॉलेमी-द्वितीय के तहत मिस्र के साथ उसके संबंधों का उल्लेख है।

- राष्ट्रपति नासिर और पीएम नेहरू के बीच घनिष्ठ मित्रता के कारण 1955 में दोनों देशों के बीच मैत्री संधि हुई।
- वर्ष 2022 का भारत और मिस्र के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है।
- G-20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान मिस्र को एक अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है।
- 2021-22 में द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष की तुलना में 75% की वृद्धि दर्ज करते हुए 7.26 बिलियन डॉलर हो गया है।
- लगभग 50 भारतीय कंपनियों ने मिस्र में 3.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के संयुक्त निवेश के साथ विभिन्न क्षेत्रों में निवेश किया है। भारत में मिस्र का निवेश लगभग 37 मिलियन अमेरिकी डॉलर है।
- भारत ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध होने के बावजूद मिस्र को 61,500 टन निर्यात की अनुमति दी।

मिस्र के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के महत्त्वपूर्ण बिंदु:

- दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में अपग्रेड किया गया।
- दोनों पक्षों ने राजनीतिक, सुरक्षा, रक्षा, ऊर्जा और आर्थिक क्षेत्रों को शामिल करते हुए संबंधों को सामरिक भागीदारी तक बढ़ाने का निर्णय लिया।
- भारत-मिस्र संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्मारक डाक टिकटों का आदान-प्रदान किया।
- साइबर सुरक्षा, आईटी, संस्कृति, युवा मामलों में सहयोग के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।
- आतंकवाद के मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए दोनो देशों ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सतर्क करने की कोशिश पर बल दिया। आतंकवाद मानवता के लिए सबसे गंभीर सुरक्षा खतरा है और वे इस बात पर सहमत हुए कि सीमा पार आतंकवाद को समाप्त करने के लिए ठोस उपायों की आवश्यकता है।
- दोनों पक्षों ने अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को 12 अरब डॉलर तक ले जाने का फैसला किया है।
- छोटे और मध्यम स्तर के उद्योगों के बीच डिजिटल कनेक्शन बढ़ाने के लिए स्थायी चैनल बनाने का अनुरोध किया।

आगे की राह:

मिस्र अफ्रीका और अरब दुनिया की राजनीति में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। इसे अफ्रीका और यूरोप के बाजारों के लिए एक प्रमुख प्रवेश द्वार के रूप में भी देखा जाता है। यह समझौता भविष्य में न केवल दोनों पक्षों के सांस्कृतिक, आईटी, साइबर सुरक्षा, युवा मामलों और प्रसारण के क्षेत्रों में सहयोग प्रदान करेगा बल्कि इससे आतंकवाद तथा उग्रवाद से निपटने में भी सहायता मिलेगी।

2 चाड झील बेसिन में जलवायु परिवर्तन बढ़ा रहा संघर्ष व पलायन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक मानवाधिकार समूह रिफ्यूजीज इंटरनेशनल ने नाइजर की राजधानी नियामे में चाड झील बेसिन की बदलती स्थिति पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय कार्ययोजना बनाने का आह्वान किया। जलवायु परिवर्तन के कारण सूखा, बाढ़ और चाड झील का सिकुड़ना इस क्षेत्र में संघर्ष व पलायन को बढ़ावा दे रहा है जिस पर बेहतर ध्यान देने की जरूरत है।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु:

- रिपोर्ट में पाया गया कि प्रतिकूल मौसम के कारण सिकुड़ते प्राकृतिक संसाधन, समुदायों में तनाव बढ़ा रहे हैं और लोग विस्थापित होने पर मजबूर हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार, अब तक लगभग 3 मिलियन लोग विस्थापित हुए हैं और यदि 11 मिलियन लोगों को समय पर मानवीय सहायता नहीं मिली, तो इसी श्रेणी में आ सकते हैं।
- बोको हराम चरमपंथी समूह और अन्य उग्रवादी समूहों के 13 साल के विद्रोह ने चाड झील बेसिन तथा साहेल क्षेत्र को अस्थिर कर दिया है। यह बेसिन कैमरून, चाड, नाइजर और नाइजीरिया के बीच स्थित है।
- संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या एजेंसी के अनुसार, चाड झील बेसिन जलवायु और पारिस्थितिक संकट से कहीं अधिक शांति तथा क्षेत्रीय विकास से जुड़ा एक मानवीय मुद्दा है।
- संयुक्त राष्ट्र की मौसम एजेंसी ने भी चेतावनी दी कि चाड बेसिन जलवायु परिवर्तन से संबंधित चरम घटनाओं जैसे बाढ़ और सूखे के लिए विशेष रूप से कमजोर है तथा भविष्य में चरम घटनाएं बढ़ने से, खाद्य असुरक्षा बढ़ सकती है।
- चाड बेसिन आयोग के आंकड़ों के अनुसार, पश्चिम और मध्य अफ्रीका में चाड बेसिन अफ्रीकी महाद्वीप के 8% हिस्से को कवर करता है, जबकि 42 मिलियन लोगों का घर है, जिनकी आजीविका ग्रामीण गतिविधि मछली पकड़ने और खेती पर निर्भर करती है।
- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एजेंसी ने नोट किया कि चाड झील 60 वर्षों में 90% संकुचित हुई है, जिसमें जलवायु परिवर्तन का महत्त्वपूर्ण योगदान है। सिंचाई, बांधों का निर्माण और जनसंख्या

वृद्धि भी इसके लिए जिम्मेदार थे।

आगे की राह:

दिन-प्रतिदिन बढ़ रही जलवायुविक घटनाएं विश्व समुदाय को यह संकेत दे रही हैं कि अब केवल मीटिंग और कांफ्रेंस के माध्यम से स्थिति को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। विकसित देशों और अमीर लोगों को उन लोगों के हितों का भी ख्याल रखना होगा जिनके संसाधनों का प्रयोग करके उन्होंने खुद को स्थापित किया है। अन्यथा प्रकृति के कहर से किसी का भी बचना मुश्किल होगा।

3 कराची परमाणु ऊर्जा संयंत्र की यूनिट-3 का उद्घाटन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने कराची परमाणु ऊर्जा संयंत्र (कनुप-3) की तीसरी यूनिट का उद्घाटन किया जो राष्ट्रीय ग्रिड में 1,100 मेगावाट विद्युत क्षमता का विस्तार करेगा।

कनुप-3 क्या है?

- KANUPP-3 चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के तहत महत्त्वाकांक्षी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) का एक हिस्सा है। दोनों देशों के बीच परमाणु सहयोग 1986 से चला आ रहा है, जब 'परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग के लिए समझौते' पर हस्ताक्षर हुए थे।
- वर्ष 1991 में पंजाब के चश्मा में प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर (PWR) की पहली 325 मेगावाट क्षमता स्थापित की गई थी। इसके बाद चश्मा में तीन और संयंत्र स्थापित किए गए। कराची में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण के लिए 2013 में एक अलग अनुबंध पर हस्ताक्षर हुआ, जिसका नाम K-2 और K-3 था, जिसमें प्रत्येक की क्षमता 1100 मेगावाट थी।
- इन दोनों का निर्माण क्रमश: 2015 और 2016 में शुरू हुआ और K-2 परमाणु संयंत्र ने मई 2021 में अपना संचालन शुरू किया। ये Hualong One रिएक्टर, या HPR1000 पर आधारित हैं जो चीन द्वारा डिजाइन किया गया जेनरेशन III + थ्री-लूप प्रेशराइज्ड वॉटर रिएक्टर है।
- KANUPP-1 को 1972 में चालू किया गया था जो 137-मेगावाट क्षमतायुक्त कनाडा ड्यूटेरियम यूरेनियम, या CANDU इकाई थी। 30 साल के डिजाइन किए गए समय को पूरा करने के बाद 2002 में इसे सेवामुक्त कर दिया गया था।

कनुप-3 के उद्घाटन का आशय:

- इसके संचालन के साथ पाकिस्तान के ऊर्जा मिश्रण में परमाणु ऊर्जा का हिस्सा 10% से अधिक हो जाएगा। वर्तमान में, जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत उत्पादन का हिस्सा सबसे अधिक है जो पाकिस्तान की कुल जरूरतों के 60% से अधिक की आपूर्ति करता है। बढ़ते ऊर्जा संकट और विद्युत कटौती की चिंताओं के बीच, परमाणु ऊर्जा क्षमता का विस्तार ऊर्जा का अतिरिक्त स्रोत प्रदान कर सकता है।
- इसके अलावा, यह पाकिस्तान के आयात बिल को कम करेगा जो मौजूदा आर्थिक संकट के चलते 27 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। यहां तक कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी 2014 के बाद से निम्नतम स्तर पर है। नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश करने से मूल्यवान विदेशी मुद्रा बचाने में मदद मिल सकती है।
- वैश्विक पटल पर यह चीन-पाकिस्तान संबंधों को मजबूत करता है और दोनों देशों के बीच विश्वास बढ़ाता है। हालाँकि, भारत को इससे सावधान रहना चाहिए क्योंकि CPEC की बढ़ती ताकत भारत के राष्ट्रीय हितों हेतु अच्छा संकेत नहीं है।

आगे की राह:

पाकिस्तान कराची तथा चश्मा में ऐसे और रिएक्टर लगाने की योजना बना रहा है ताकि जल विद्युत उत्पादन की पूरी क्षमता का दोहन किया जा सके। इस तरह के कदम न केवल पाकिस्तान में ऊर्जा संकट को कम करेगा, बल्कि जलवायु परिवर्तन से निपटने में भी मदद करेगा।

4 चीन-रूस संबंध

चर्चा में क्यों?

हाल ही में चीनी कंपनियों ने मास्को को जेट लड़ाकू विमानों, पनडुब्बियों और सैनिकों को लैस करने में सहायता किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगे कई प्रतिबंधों के बावजूद चीन, रूस को आवश्यक तकनीक प्रदान कर रहा है जो मॉस्को की सैन्य जरूरतों को पूरा करता है।

चीन-रूस गठबंधन के निहितार्थ:

- पिछले साल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक नए चीन-रूस गठबंधन का अनावरण करते हुए बीजिंग का दौरा किया था, जो 'बिना किसी सीमा के' और 'कोई वर्जित क्षेत्र नहीं' द्वारा परिभाषित किया गया था। हालाँकि, इस गठबंधन की घोषणा से पहले दोनों देश लंबे समय तक (सोवियत युग के दौरान 1950 के दशक में) रणनीतिक साझेदार रहे थे जिसे पुन: शुरू किया गया है।
- चीन और रूस के बीच यह गठजोड़ अंतर्राष्ट्रीय मामलों में संयुक्त राज्य अमेरिका और नाटो के प्रभाव का मुकाबला करने में एक साझा हित से प्रेरित है क्योंकि पूर्व में दोनों देश अमेरिका के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखना चाहते थे। हालाँकि, रूस की बढ़ती शिकायतों और एशिया की प्रमुख शक्ति के रूप में चीन की बढ़ती महत्त्वाकांक्षा ने इन दोनों ताकतों को एक साथ लाया है।
- हाल के वर्षों में, दोनों देशों के संयुक्त सैन्य अभ्यास, आर्थिक सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर समन्वय के साथ चीन-रूस गठबंधन मजबूत हुआ है।

ऐसे गठबंधन के प्रभाव:

- यूरोप में पश्चिम के साथ युद्ध के समय चीन के सहयोग ने चीन-रूस गठजोड़ बढ़ाया है। विभिन्न सैन्य प्रयासों के माध्यम से रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया और लगभग 1 वर्ष के बाद भी यह युद्ध किसी संतुलित समाधान पर नहीं पहुंचा है।
- इसके अलावा यूक्रेन पर आक्रमण ने अमेरिका को नाटो की उपस्थिति का विस्तार करने और ऑस्ट्रेलिया तथा जापान के साथ अमेरिकी द्विपक्षीय गठबंधन को मजबूत करने में मदद की।
- अमेरिका ने ताइवान के लिए अपने सैन्य और राजनीतिक समर्थन में उल्लेखनीय वृद्धि की है जिससे ताइवान पर आक्रमण करना, शी जिनपिंग के लिए आसान नहीं होगा।

- पश्चिम और मास्को-बीजिंग धुरी के बीच तथाकथित सहसंबंध ने दुनिया के अन्य देशों को अपने सुरक्षा-व्यवस्था के लिए अलग तरह से सोचने पर मजबूर किया है।

भारत के लिए निहितार्थ:

- यूक्रेन युद्ध ने अमेरिका के साथ पश्चिमी एकता को सुविधाजनक बनाया है जिसने चीन और रूस दोनों पर एक साथ दबाव बनाने का अवसर दिया है। जैसे-जैसे चीन-रूस गठबंधन मजबूत होता जा रहा है, भारत को दोनों देशों से बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिमी गठबंधन और चीन पर उसका दबाव भारत के पक्ष में काम कर सकता है।
- चीन-ऐसे गठजोड़ में और अधिक विश्वास प्राप्त कर रहा है तथा भारत के साथ सीमा पर अपना सैन्य दबाव बढ़ा रहा है। पीएलए की चुनौती से निपटने के लिए रूसी सैन्य आपूर्ति पर भारत की निर्भरता देश को एक कठिन स्थिति में डाल सकती है। इसके अलावा रूसी सैन्य आपूर्ति पर भारत की निर्भरता ने यूरोप और अमेरिका के साथ जुड़ाव पर अपनी स्थिति को सीमित कर दिया है, जिससे भारत को सजग रहने की आवश्यकता है।

5 महत्त्वपूर्ण उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहल (iCET)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और उनके अमेरिकी समकक्ष जेक सुलिवन ने औपचारिक रूप से वाशिंगटन में क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी (iCET) पहल की शुरुआत की।

आईसीईटी क्या है?

- आईसीईटी का विचार पहली बार मई 2022 में टोक्यो शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा पेश किया गया था जिसका उद्देश्य नए डोमेन में सहयोग को बढ़ावा देकर भारत-अमेरिका के बीच रणनीतिक और तकनीकी साझेदारी को बढ़ाना है।
- इसमें साझा लोकतांत्रिक मूल्यों तथा सार्वभौमिक मानवाधिकारों के प्रति सम्मान के आधार पर सह-विकास और सह-उत्पादन को बढ़ावा देने वाले सहयोग के क्षेत्रों की पहचान की गई है। सहयोग के इन क्षेत्रों को 6 प्रमुख शीर्षकों (वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास, क्वांटम व कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रक्षा नवाचार, अंतरिक्ष, उन्नत दूरसंचार तथा अर्धचालक) के तहत विभाजित किया गया है। यह एक्सपो, हैकथॉन और पिच (Pitch) सत्रों के माध्यम से प्रमुख क्षेत्रों में इनोवेशन ब्रिज के द्वारा स्थापित किया जाएगा।
- इसका लक्ष्य भारत-अमेरिका दोनों में नवीन पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम प्रौद्योगिकियों और उन्नत वायरलेस प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन तथा भारतीय विज्ञान एजेंसियों के बीच साझेदारी की परिकल्पना करता है। इसका उद्देश्य रेस्पोंसिबल एआई और अन्य तकनीकों के लिए सामान्य मानक तथा बेंचमार्क विकसित करना है।
- रक्षा मोर्चे पर, आईसीईटी ने एक नए द्विपक्षीय रक्षा औद्योगिक सहयोग रोडमैप की घोषणा की जिसमें जेट इंजन से संबंधित अन्वेषण पर प्रारंभिक ध्यान दिया गया तथा अधिक कंपनियों को मान्य अंतिम उपयोगकर्ता (वीईयू) का दर्जा दिया गया।
- इसने नासा जॉनसन स्पेस सेंटर में संयुक्त वाणिज्यिक अंतरिक्ष अन्वेषण और भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के उन्नत प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करके अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग की वकालत की। इसके अलावा, अमेरिका ने आपूर्ति शृंखलाओं में विविधता लाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर आयोग की स्थापना की सराहना की है जो अमेरिका द्वारा शुरू किए गए चिप कार्यक्रम का पूरक होगा।

इस पहल का महत्त्व:

- महत्त्वपूर्ण उभरती प्रौद्योगिकियों में सह-विकास और सह-उत्पादन के अलावा, यह राजनयिक चैनलों के माध्यम से व्यापार बाधाओं, नियामक तंत्रों तथा निर्यात नियंत्रणों को संबोधित करेगा। चीन की बढ़ती महत्त्वाकांक्षाओं को देखते हुए यह दोनों देशों को रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी सुरक्षा प्रदान करेगा।
- जहां तक भारत के लिए लाभ का संबंध है, यह आर्थिक विकास सुनिश्चित करते हुए उसकी तकनीकी क्षमताओं में वृद्धि करेगा। इसके अलावा, यह उसकी सौदेबाजी की शक्ति को बढ़ाते हुए रूसी सैन्य उपकरणों पर भारत की निर्भरता को कम करेगा। साथ ही अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग, अंतरिक्ष क्षेत्र के व्यावसायीकरण के लिए भारत की योजना का पूरक होगा।

आगे की राह:

आज के आधुनिक युग में प्रौद्योगिकी का उपयोग नए-नए स्वरूपों में हो रहा है। आईसीईटी को बढ़ावा देकर पूरे विश्व समुदाय को लाभान्वित करते हुए भारत-अमेरिका तकनीकी साझेदारी में क्रांति लाने की क्षमता है।

6 क्वाड नेशंस ने क्वाड साइबर चैलेंज किया लॉन्च

चर्चा में क्यों?

हाल ही में क्वाड राष्ट्रों (भारत, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान) ने साइबर सुरक्षा में सुधार के लिए क्वाड साइबर चैलेंज लॉन्च किया। इंडो-पैसिफिक में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को क्वाड साइबर चैलेंज का हिस्सा बनने और 'सुरक्षित तथा जिम्मेदार' साइबर आदतों का अभ्यास करने के लिए आमंत्रित किया। भारत में कार्यवाही का समन्वय राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक के कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के साथ किया जा रहा है।

- जनवरी 2023 में दिल्ली में क्वाड साइबर सिक्योरिटी ग्रुप की मीटिंग हुई। समूह ने क्वाड सदस्यों और हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में भागीदारों के लिए साइबर सुरक्षा क्षमता निर्माण पर चर्चा की। भारतीय पक्ष का नेतृत्व देश के राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत ने किया।

क्या है क्वाड साइबर चैलेंज?

- क्वाड साइबर चैलेंज इंडो-पैसिफिक और उसके बाहर सुरक्षित तथा जिम्मेदार साइबर आदतों को अपनाने के लिए इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को प्रोत्साहित करने का एक सार्वजनिक अभियान है।
- इस पहल का फोकस लोगों के साइबर सुरक्षा ज्ञान और व्यवहार में सुधार के साथ-साथ दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं तथा उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए एक सुरक्षित व लचीले साइबर वातावरण को बढ़ावा देना है।

प्रासंगिकता:

- साइबर सुरक्षा उन प्रमुख क्षेत्रों में से एक है जिसकी पहचान क्वाड नेताओं ने एक स्वतंत्र और खुले हिन्द-प्रशांत क्षेत्र को आगे बढ़ाने में की है। चीन और उत्तर कोरिया से साइबर खतरे चार देशों तथा उनके सहयोगियों के लिए संभावित चुनौती हैं।
- राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सचिवालय के अनुसार, दुनिया भर में इंटरनेट उपयोगकर्ता साइबर अपराध और अन्य दुर्भावनापूर्ण साइबर खतरों के लक्ष्य हैं, जो हर साल खरबों डॉलर खर्च कर सकते हैं। ये संवेदनशील और व्यक्तिगत डेटा से समझौता कर सकते हैं।
- सरल निवारक उपायों से कई साइबर हमलों से बचा जा सकता है। साइबर सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण सुधार के लिए इंटरनेट उपयोगकर्ता और प्रदाता इन उपायों का पालन कर सकते हैं। इन चरणों में नियमित रूप से सुरक्षा अद्यतन स्थापित करना, बहु-कारक प्रमाणीकरण के माध्यम से बढ़ी हुई पहचान जांच को सक्षम करना, मजबूत और नियमित रूप से बदल कर पासवर्ड का उपयोग करना तथा फिशिंग जैसे सामान्य ऑनलाइन घोटालों की पहचान करना शामिल है।
- QUAD साइबर सिक्योरिटी चैलेंज निगमों से लेकर शैक्षणिक संस्थानों, छोटे व्यवसायों व स्कूल के छात्रों से लेकर बुजुर्गों तक सभी उपयोगकर्ताओं के लिए बुनियादी साइबर सुरक्षा जानकारी और प्रशिक्षण जैसे संसाधन प्रदान करता है।

आगे की राह:

यह चुनौती व्यक्तियों तथा समुदायों की साइबर सुरक्षा जागरूकता को मजबूत करने, एक अधिक सुरक्षित और लचीला साइबर पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए निरंतर क्वाड प्रयासों को दर्शाती है। इसके अलावा, ऐसी पहलें साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए एक उपकरण साबित हो सकती हैं, जिससे चीन और उत्तर कोरिया जैसे देशों से साइबर सुरक्षा खतरों का मुकाबला किया जा सके।

7 विश्व की दुग्ध राजधानी बनता भारत

चर्चा में क्यों?

भारत ने वर्ष 2021-22 में वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 24% का भारी योगदान करते हुए, दुनिया के शीर्ष दूध उत्पादक देश के रूप में स्थिति मजबूती की। खाद्य और कृषि कॉर्पोरेट सांख्यिकीय डेटाबेस (FAOSTAT) के अनुसार, भारत ने पिछले आठ वर्षों में दूध उत्पादन में 51% की वृद्धि दर्ज की है।

भारत के डेयरी क्षेत्र के बारे में:

- भारत में शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्य हैं:
  - उत्तर प्रदेश (14.9% या 31.4 एमएमटी)
  - राजस्थान (14.6% या 30.7 एमएमटी)
  - गुजरात (7.6% या 15.9 एमएमटी)
  - आंध्र प्रदेश (7.0% या 14.7 एमएमटी)
- भारत में हर साल दूध उत्पादन में 6% की वृद्धि दर देखी जाती है।
- अधिकांश श्रम शक्ति में महिला श्रमिक शामिल हैं।

भारत में डेयरी क्षेत्र का महत्त्व:

- **रोजगार**- यह देश में 8 करोड़ से अधिक परिवारों को रोजगार देता है।
- डेयरी क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है और भारत की अर्थव्यवस्था के सबसे महत्त्वपूर्ण उद्योगों में से एक है।
- अमूल, मदर डेयरी, क्वालिटी लिमिटेड जैसी कंपनियां उत्पादन बढ़ाने में सहायक रही हैं।
- पिछले वर्ष 2020-21 में महामारी के कारण VAPs (मूल्य वर्धित उत्पाद) की बिक्री भी घटी थी।

डेयरी उद्योग से जुड़ी योजनाएं:

- डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीडीडी)-2014 में पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा दूध व दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने, संगठित खरीद, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन तथा विपणन की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था।
- राष्ट्रीय पशुधन मिशन, फीड और चारा विकास पर उप-मिशन- जिसका उद्देश्य भारत के पशुधन के लिए फीड तथा चारे की उपलब्धता में वृद्धि करना है।
- **राष्ट्रीय गोकुल मिशन**- यह वैज्ञानिक तरीके से स्वदेशी पशुपालन और संरक्षण को बढ़ावा देता है।
- **राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम**- इसका उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाले बीज के साथ दुधारू पशुओं की आनुवंशिक योग्यता में सुधार करना है।

आगे की राह:

दुनिया के अग्रणी दुग्ध उत्पादक के रूप में भारत का शीर्ष पर पहुंचना अपने किसानों की कड़ी मेहनत, समर्पण और सरकार द्वारा अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदान की गई सहायता का एक जीवंत उदाहरण है। आगे एक आशाजनक भविष्य के साथ, भारत खुद को डेयरी महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की राह पर अग्रसर है।

पर्यावरणीय मुद्दे

1 केरल के 'डूबते' द्वीप को बचाने के उपाय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में शोधकर्ताओं ने मुनरो थुरुथु (Munroe Thuruthu) को बचाने के लिए आवश्यक समाधान सुझाए हैं। इस द्वीप को स्थिर भूमि अवतलन, ज्वारीय बाढ़ और कम कृषि उत्पादकता का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण इस क्षेत्र से बड़े पैमाने पर पलायन हुआ है।

इस स्थिति का कारण:

- हालांकि इसमें गिरावट 1980 के दशक में शुरू हुई थी लेकिन इसकी गंभीरता 2000 के दशक में ही महसूस की गई। अब तक इस द्वीप का लगभग 39% क्षेत्र की हानि हुई है जिसमें पेरिंगलम और चेरियाकाडावु को क्रमश: 12% और 47% के उच्चतम गिरावट का सामना करना पड़ा है।
- नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज (एनसीईएसएस) द्वारा किए गए अध्ययन में भूमि क्षरण के पीछे मुख्य कारण के रूप में मानवजनित गतिविधियों का हवाला दिया गया है। अध्ययन ने द्वीप के रूपात्मक परिवर्तनों का विश्लेषण करने के लिए उपलब्ध रिमोट सेंसिंग डेटा और भूमि सर्वेक्षण रिकॉर्ड का उपयोग किया है। इसने भूमि क्षेत्र के उप-सतह भूविज्ञान को निर्धारित करने के लिए कल्लदा नदी के विद्युत प्रतिरोधकता मीटर सर्वेक्षण और बाथीमेट्री सर्वेक्षण भी किया है।
- इस क्षेत्र में भूमि की कमी का मुख्य कारण अनियमित रेत खनन है, जिसके परिणामस्वरूप कल्लदा नदी में नदी के ताल का निर्माण होता है। इसके अलावा, थेनमाला बांध के निर्माण के बाद नदी द्वारा तलछट की आपूर्ति अवरुद्ध हो गई थी। अनियमित रेत खनन के कारण बने खारे जलाशयों ने भूजल की गुणवत्ता और मिट्टी की उर्वरता को खराब कर दिया है। इन दो मापदंडों के गिरते स्तर ने कृषि कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है जिससे द्वीपवासियों का बड़े पैमाने पर पलायन हुआ है।

आवश्यक समाधान:

- सबसे पहले, रिवर्स भूनिर्माण होना चाहिए जो पृथ्वी और सामाजिक विज्ञान के सभी पहलुओं को एकीकृत करेगा।
- कल्लदा नदी में रेत खनन को नियंत्रित करने और द्वीप पर भूमि उपयोग को विनियमित करने के लिए कड़े उपाय अपनाए जाने चाहिए।
- द्वीप में सभी मौजूदा निर्माण विधियों को अच्छी तरह से अध्ययन की गई इंजीनियरिंग तकनीकों से बदला जाना चाहिए।
- इसके अलावा, अध्ययन में नदी तल के पूलों के किनारों को मिटाने के लिए एक कृत्रिम अवसादन प्रक्रिया का प्रस्ताव किया गया है। इस प्रयोजन के लिए तेनमाला जलाशय में निक्षेपित तलछट का उपयोग किया जा सकता है।
- अनुसंधान ने एक महत्वपूर्ण रामसर स्थल व अष्टमुडी झील के संरक्षण के लिए स्थायी प्रबंधन योजनाओं की आवश्यकता पर बल दिया है।

आगे की राह:

भारत ने UNCCD के तहत 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को बहाल करने का संकल्प लिया है। इसे प्राप्त करने के लिए एक कड़े नियामक तंत्र, उन्नत तकनीकी समाधान और उपयुक्त नीतिगत ढांचे की आवश्यकता होगी।

2 जलवायु परिवर्तन के कारण अंडर वाटर केल्प वन के अस्तित्व को खतरा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नेचर जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला है कि अंडर वाटर केल्प वन पारिस्थितिक तंत्र को जलवायु परिवर्तन के कारण नुकसान हो रहा हैं।

अध्ययन के निष्कर्ष:

- विषुवतीय रेखा के किनारों पर, केल्प वन विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है क्योंकि ये स्थान थर्मल टॉलरेंस थ्रेसहोल्ड पर या उससे परे गर्म हो रहे हैं।
- एक्लोनिया रेडिएट, दक्षिणी गोलार्ध में प्रमुख केल्प प्रजाति, विशेष रूप से भूमध्य रेखा के पास के क्षेत्रों में, जलवायु परिवर्तन के लिए संवेदनशील है।
- नई आबादी, लगभग 200^{0} C तापमान वाले उथले और ठंडे सर्दियों के महीनों में पाई गई।

केल्प वनों के बारे में:

- ये पानी के नीचे के पारिस्थितिक तंत्र हैं जो उथले पानी में कई अलग-अलग प्रजातियों के सघन विकास से बनते हैं जिन्हें केल्प्स के रूप में जाना जाता है।
- केल्प्स बड़े भूरे रंग के शैवाल होते हैं जो तट के करीब ठंडे, अपेक्षाकृत उथले पानी में रहते हैं जो समुद्रतल से जुड़े रहते हैं।
- वे अंतत: पानी की सतह तक बढ़ते हैं। ये भोजन और ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए सूर्य के प्रकाश पर निर्भर होते हैं।
- सिवार के जंगल अकशेरूकीय, मछलियों और अन्य शैवाल की सैकड़ों प्रजातियों के लिए पानी के नीचे आवास प्रदान करते हैं जिनका महान पारिस्थितिक और आर्थिक मूल्य है।

वितरण:

- आर्कटिक क्षेत्र में।
- अकेले कैनेडियन आर्कटिक दुनिया के 10% समुद्र तटों का प्रतिनिधित्व करता है।
- एलेस्मेरे द्वीप और लैब्राडोर के बीच, साथ ही लैंकेस्टर साउंड, उनगावा बे, हडसन बे, बाफिन बे रेसोल्यूट बे और पूर्वी कनाडा के तटों के साथ, केल्प वनों को वैज्ञानिक रूप से प्रलेखित किया गया है।

केल्प का महत्त्व:

- ये कीस्टोन प्रजातियाँ हैं जो पर्यावरण की संरचना में बड़े बदलाव का संकेत देती हैं।
- यह विभिन्न प्रकार के समुद्री जीवों के लिए एक महत्त्वपूर्ण खाद्य

स्रोत के रूप में कार्य करता है। केल्प्स तटीय अकशेरूकीय में पाए जाने वाले 60% तक कार्बन का उत्पादन करते हैं।

- वे पक्षियों और चारे के आवास के रूप में काम करते हैं।
- वे प्राकृतिक बैकवाटर के रूप में काम करते हैं और तटीय कटाव को रोकते हैं।
- यह आयोडीन और पोटाश का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है।

आगे की राह:

केल्प वनों के नुकसान से अद्वितीय जैव विविधता में कमी आएगी जिसका वे समर्थन करते हैं। ऐसे क्षेत्रों की पहचान यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि महत्त्वपूर्ण आनुवंशिक विविधता संरक्षित है। यह जलवायु प्रजातियों के वितरण और विकासवादी विविधता को समझने के लिए भी आवश्यक है।

3 पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के विस्थापित होते किनारे

चर्चा में क्यों?

पश्चिम बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों में गंगा नदी के किनारे हुए भीषण कटाव ने हजारों लोगों के आवास को क्षति पहुँचाया है। विशेषज्ञों के अनुसार, कई ब्लॉकों में कटाव से घर, मंदिर, कृषि भूमि आदि बह गए हैं जिससे हावड़ा में भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान भी खतरे में है।

जिम्मेदार कारक:

- विशेषज्ञों ने इसे मानवजनित कारकों से प्रेरित क्षरण माना है। गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना डेल्टा की नदियों में दोलन करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार नदी का कटाव और स्थानांतरण मार्ग इस बेसिन में बार-बार होने वाली घटनाएं हैं।
- फरक्का बैराज के निर्माण से भी नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हुआ है जिससे पार-अनुभागीय क्षेत्र और जल धारण क्षमता कम हुई है। कोलकाता बंदरगाह के रखरखाव और संरक्षण के लिए फीडर नहर के माध्यम से गंगा से भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली में पानी की पर्याप्त मात्रा को मोड़ने के लिए इसका निर्माण किया गया था।
- मालदा में फरक्का के ऊपर तलछट जमाव से नदी द्वीप जैसी आकृति बन गई है। मालदा में यह नदी बाएं किनारे पर कटाव कर रही है, जबकि अपेक्षाकृत तलछट मुक्त पानी फरक्का के निचले हिस्से से मुर्शिदाबाद के दाहिने किनारे को काट रहा है।
- इसके अलावा बैराज की धारण क्षमता हाल के दिनों में काफी कम हो गई है, जिसके परिणामस्वरूप उत्तर बंगाल में भारी वर्षा के दौरान अनियंत्रित पानी छोड़ा जाता है जिससे नीचे की ओर कटाव तेज हो गया है। साथ ही इससे रेत खनन, वनों की कटाई, बंदरगाह निर्माण, जलीय कृषि, जलवायु परिवर्तन आदि भी प्रभावित हो रहे हैं।

समाधान की जरूरत:

- स्थानीय प्रशासन ने बांस और सैंडबैग का उपयोग करके कटाव को रोकने की कोशिश की है लेकिन ये कदम पर्याप्त नहीं होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में मानिकचक ब्लॉक में बड़े पैमाने पर कटाव के बारे में चिंता व्यक्त की।
- नदी के कटाव को रोकने के लिए तटबंधों का निर्माण किया जाना चाहिए और नदी के किनारों पर मैंग्रोव लगाए जाने चाहिए। संवेदनशील जिलों का जोखिम क्षेत्र मानचित्रण किया जाना चाहिए और स्थानीय लोगों को समय-समय पर सतर्क करके, पुनर्वास प्रक्रिया को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- विभिन्न राज्य विभागों, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने दीर्घकालिक समाधानों को लागू करने के लिए धन की कमी को दोहराया है। केंद्र सरकार को स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, उसके अनुसार डेल्टा प्रबंधन योजना तैयार करनी चाहिए।

आगे की राह:

नदी को स्वतंत्र प्रवाह के लिए 3-5 किमी के क्षेत्र की आवश्यकता होती है। नदी विज्ञान को समग्र रूप से समझने और सिविल इंजीनियरिंग से सामाजिक इंजीनियरिंग समाधानों में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है।

4 पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में डिस्टर्बेंस और एवियन वैग्रेंसी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित एक नए शोध से पता चला है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में डिस्टर्बेंस और प्रवासी पक्षियों के भटकने (Astray) के बीच एक संभावित लिंक है। इस घटना को एवियन वैग्रेंसी के रूप में जाना जाता है।

चुंबकीय क्षेत्र में एवियन वैग्रेंसी और डिस्टर्बेंस के बीच संबंध:

- यह लंबे समय से स्थापित है कि खराब मौसम प्रवासी पक्षियों को अस्त-व्यस्त बना सकता है, जिससे वे अपरिचित प्रदेशों में चले जाते हैं, जिसके बारे में कुछ जानकारी नहीं होती है। हालाँकि, हाल के एक अध्ययन से पता चला है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में डिस्टर्बेंस भी पक्षियों को प्रवास के दौरान भ्रमित करता है।
- इसके लिए, वैज्ञानिकों ने 152 प्रजातियों में से 2.2 मिलियन पक्षियों के रिकॉर्ड का विश्लेषण किया है जिन्हें 1960 और 2019 के बीच अध्ययन के लिए पकड़ा गया। चूंकि, पक्षी अपनी आंखों में मैग्नेटो रिसेप्टर्स का उपयोग करके चुंबकीय क्षेत्र को महसूस कर सकते हैं, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र में इन विकृतियों से अत्यधिक प्रभावित होते हैं। पक्षी परिचित क्षेत्रों में नेविगेट कर सकते हैं, लेकिन कुछ मामलों में वे भू-चुंबकत्व पर निर्भर होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी परिवर्तन उनके प्रवासी अनुभव की परवाह किए बिना कम या अधिक उम्र दोनों पक्षियों को प्रभावित करता है।
- पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र या भू-चुंबकीय क्षेत्र एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती है और इसे विभिन्न आंतरिक व बाहरी कारकों द्वारा आकार दिया जाता है। उदाहरण के

लिए सौर हवाएँ या सनस्पॉट। ये डिस्टर्बेंस पक्षियों को विकृत नक्शे प्रदान करती है जिससे वे अपना रास्ता खो देते हैं। नए स्थान में, उन्हें उपयुक्त भोजन और आवास खोजने में कठिनाई हो सकती है, या यह नया स्थान जलवायु परिवर्तन के कारण पारंपरिक निवास स्थान के विनाश के कारण अधिक अनुकूल हो सकता है।

- हालांकि, अध्ययन से पता चला है कि उच्च सौर गतिविधि के कारण भू-चुंबकीय डिस्टर्बेंस बढ़ी है। यह सौर गतिविधि द्वारा उत्पन्न रेडियोफ्रीक्वेंसी का कारण हो सकता है जो पक्षियों में मैग्नेटो रिसेप्टर्स को प्रभावित कर सकता है तथा अन्य उपलब्ध संकेतों के माध्यम से नेविगेट करने के लिए बाध्य करता है।

आगे की राह:

प्रवासी पक्षियों द्वारा सामना किए जाने वाले खतरों का विश्लेषण करने और उनके संरक्षण में मदद करने के लिए यह अध्ययन एक पथप्रवर्तक रहस्योद्घाटन है। इसके अलावा, यह वैज्ञानिकों को व्हेल जैसी अन्य प्रवासी प्रजातियों को समझने में भी मदद कर सकता है।

5 बजट में पर्यावरण संरक्षण पहल

चर्चा में क्यों?

बजट 2023-24 में, भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े 'ग्रीन पुश' के रूप में मिष्टी (समुद्री आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल), पीएम प्रणाम, अमृत धरोहर जैसी कई योजनाओं और पहलों को शुरू करने का निर्णय लिया है।

मिष्टी (समुद्री आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल):

इस नए कार्यक्रम का उद्देश्य समुद्र तट के किनारे लवणीय भूमि पर तटीय मैंग्रोव वनों के सघन वनीकरण की सुविधा प्रदान करना। इस कार्यक्रम का खर्च MGNREGS, CAMPA फंड और अन्य स्रोतों के माध्यम से पूरा किया जाएगा।

पहल का महत्त्व:

- पृथ्वी पर अधिकांश जैव-विविधता समृद्ध क्षेत्रों के लिए संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देना और अधिक पारिस्थितिक उत्तोलन (Leverages) प्रदान करना।
- स्थानीय लोगों को व्यावसायिक अवसर प्रदान करना क्योंकि मैंग्रोव विभिन्न समुद्री प्रजातियों और मत्स्य पालन के लिए आवास प्रदान करते हैं।
- खराब मौसम की क्षति से तटरेखा का संरक्षण।
- मैंग्रोव वन चक्रवातों के लिए इकोलॉजिकल-शॉक ऑब्जर्वर और बफर के रूप में काम करता है। वे तटीय भूमि को अधिक लचीला बनाने, भूमि के कटाव और बाढ़ को रोकने की भी क्षमता रखते हैं। उनके पास उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की तुलना में कार्बन पृथक्करण की चार गुना अधिक क्षमता है।
- इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार, भारत में दक्षिण एशिया के कुल मैंग्रोव फॉरेस्ट का 3% हिस्सा है जो दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव फॉरेस्ट यानी सुंदरबन डेल्टा (पश्चिम बंगाल) का घर है।

पीएम प्रणाम (पृथ्वी मां के पोषण की बहाली, जागरूकता और सुधार के लिए पीएम कार्यक्रम):

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य वैकल्पिक उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग तथा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने वाले राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करना।
- यह कदम सरकार के सब्सिडी बोझ को भी कम करेगा और देश में आदर्श N:P:K अनुपात को बहाल करेगा। 2021 से उर्वरकों पर सरकारी सब्सिडी लगभग 40% बढ़ गई है।
- 3 वर्षों में 10,000 भारतीय प्राकृतिक जैव-इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये केंद्र सूक्ष्म उर्वरकों के वितरण और कीटनाशक निर्माण के लिए नेटवर्क के रूप में कार्य करेंगे।

इस योजना का महत्त्व:

- यह कदम रासायनिक उर्वरकों के नकारात्मक प्रभावों की जांच करने के लिए चल रहे निवारण तंत्र को सशक्त करेगा। इससे जल प्रदूषण व जलीय जीवन को खतरे में डालने वाला यूट्रोफिकेशन, लंबे समय तक मौजूद रहने से अम्लीकरण और भूमि की उत्पादकता में गिरावट शामिल है। वैज्ञानिक अध्ययनों ने किसानों में कैंसर और रासायनिक उर्वरकों के बीच संबंध भी पाया है।

अमृत धरोहर:

- इस योजना का उद्देश्य आर्द्रभूमि के इष्टतम उपयोग को एक दृष्टिकोण के साथ संरक्षित करके प्रोत्साहित करना है जिसमें स्थानीय समुदायों को इन पारिस्थितिक तंत्रों के देखभालकर्ता के रूप में शामिल किया गया है।

इस योजना का महत्त्व:

- यह योजना जैव विविधता समृद्ध क्षेत्रों और कार्बन स्टॉक के संरक्षण को प्रोत्साहित करेगी। आर्द्रभूमि स्थल जलीय जीवन और अन्य विविध वनस्पतियों व जीवों के समुदाय को बनाए रखते हैं। यह कदम पर्यावरण-पर्यटन के अवसरों को बढ़ाने और तटीय क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने का भी प्रयास करता है।
- यह प्रकृति आधारित समाधानों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के साथ नए हरित रोजगार के अवसरों का पता लगाएगा।

आगे की राह:

भारत का केंद्रीय बजट देश के समग्र विकास पथ को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह स्थानीय समुदायों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ देश के पारिस्थितिक स्वास्थ्य की बहाली को बढ़ावा देता है ताकि 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

6 नोबल्स हेलेन या पैपिलियो नोबली तितली

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के नामदफा नेशनल पार्क में पहली बार एक अत्यंत दुर्लभ नोबल्स हेलेन तितली पाई गई है। यह पहचान तितली के जानकारों के समूह द्वारा की गई है।

नोबल्स हेलेन तितली (Noble's Helen Butterfly):

- इस अत्यंत दुर्लभ तितली का वैज्ञानिक नाम पैपिलियो नोबली है।
- यह 100-120 मिमी के पंखों वाली एक तितली है।
- इसमें अग्रभाग के पृष्ठ भाग में एक अतिरिक्त सफेद धब्बा होता है।
- नोबल्स हेलेन फिलिपाइन के पैपिलियो-एंटोनियो की तरह है।
- यह अपनी पहले से ज्ञात श्रेणियों में बहुत दुर्लभ होने के लिए भी जानी जाती है।

इस प्रजाति का वितरण:

- यह तितली म्यांमार और दक्षिणी चीन से लेकर वियतनाम तक अपनी पहले से ज्ञात क्षेत्र से गायब हो रही है।
- यह उत्तरी थाईलैंड में मध्यम ऊंचाई पर मोंटेन जंगल में पाए जाने के लिए भी जानी जाती थी। म्यांमार, चीन के युन्नान और हुबई क्षेत्रों, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम आदि में भी यह देखी गई है।

इकोसिस्टम में एक तितली का महत्त्व:

- किसी भी क्षेत्र में तितलियों की बहुतायत, समृद्ध जैव विविधता का प्रतिनिधित्व करती है। तितली एक संकेतक प्रजाति के रूप में भी कार्य करती है।
- संकेतक प्रजाति पारिस्थितिकी तंत्र की समग्र स्थिति और उस पारिस्थितिकी तंत्र में अन्य प्रजातियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। वे पर्यावरणीय परिस्थितियों के साथ-साथ सामुदायिक संरचना के पहलुओं में गुणवत्ता और परिवर्तन को दर्शाते हैं।
- यह एक परागणक के रूप में भी कार्य करती है।

नामदफा राष्ट्रीय उद्यान:

- यह अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले के भीतर भारत और म्यांमार के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है।
- यह भारत-चीन-म्यांमार सीमा के ट्राई-जंक्शन के करीब स्थित है। नामदफा संरक्षित क्षेत्र का भौगोलिक विस्तार पूर्वोत्तर हिमालय और पटकाई पर्वतमाला के मिश्मी पहाड़ियों के दाफा बम रिज के बीच स्थित है।
- यह पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है।
- नामदफा राष्ट्रीय उद्यान गंभीर रूप से लुप्तप्राय नामदफा उड़ने वाली गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। यह दुनिया का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और क्लाउडेड तेंदुए जैसी बड़ी बिल्ली की चार प्रजातियां हैं।

आगे की राह:

नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में इस नई सफलता ने प्रकृति प्रेमियों को प्रोत्साहित किया है और पूर्वी जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र में विभिन्न एजेंसियों द्वारा उठाए गए बहाली के कदमों पर भी जोर दिया है।

7 भारत से लगभग 20,000 टन लाल चंदन की तस्करी हुई: रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में TRAFFIC और WWF-I द्वारा जारी एक रिपोर्ट 'रेड सैंडर्स: फैक्टशीट ऑन इंडियाज रेड सैंडर्स इन इल्लीगल वाइल्डलाइफ ट्रेड' शीर्षक में, 19,049 टन से अधिक रेड सैंडर्स लकड़ियों की पकड़ और जब्ती की 28 घटनाओं की सूचना दी गई थी। इन्हें अवैध रूप से जंगल से निकाले जाने के बाद 2016 से 2020 के बीच भारत से निर्यात किया गया था। यह रिपोर्ट सीआईटीईएस (वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन) व्यापार डेटाबेस पर आधारित है।

रेड सैंडर्स के बारे में प्रमुख तथ्य:

- Red Sanders या Pterocarpus Santalinus, जिसे लाल चन्दन भी कहा जाता है, भारत में पूर्वी घाटों के दक्षिणी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में पाई जाने वाली एक स्थानिक प्रजाति है।
- इसे IUCN रेड लिस्ट द्वारा 'लुप्तप्राय' के रूप में सूचीबद्ध किया गया है जो CITES के परिशिष्ट-II में आती है। भारत में, इसे वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-IV के तहत सूचीबद्ध किया गया है।
- चीन और जापान में फर्नीचर, हस्तशिल्प तथा संगीत वाद्ययंत्र बनाने के लिए रेड सैंडर्स की हर्टवुड की मांग है। लकड़ी से प्राप्त लाल रंग का उपयोग कपड़ा, दवा और खाद्य उद्योगों में रंगीन एजेंट के रूप में किया जाता है।

चिंता का कारण:

- रेड सैंडर्स की अवैध कटाई के कारण यह भारत की सबसे अधिक शोषित वृक्ष प्रजातियों में से एक है। भारत की विदेश व्यापार नीति के तहत लाल चंदन का आयात और निर्यात प्रतिबंधित है। चीन 13,618 टन से अधिक उत्पादों के साथ सबसे बड़ा आयातक बना हुआ है, जिसके बाद हांगकांग 5,215 टन और सिंगापुर 216 टन स्थान है।

आगे की राह:

प्रजातियों के और अधिक शोषण को रोकने के लिए कानूनी उपायों के सख्त प्रवर्तन के साथ-साथ संरक्षण प्रयासों तथा जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आंध्र प्रदेश सरकार ने लाल चंदन को विशेष संरक्षण का दर्जा दिया है। लाल चंदन के अपराधों को संज्ञेय और गैर-जमानती बनाया गया तथा इससे संबंधित दंडों में वृद्धि की गई। इसके अलावा, लाल चंदन के जंगलों को 'उच्च संरक्षण क्षेत्र' के रूप में घोषित किया जाना चाहिए, ताकि प्रजातियों और इसके आवास की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कानूनी ढांचा प्रदान किया जा सके। हॉटस्पॉट तथा पारगमन मार्गों और लाल चंदन की तस्करी से संबंधित वास्तविक समय की जानकारी साझा करके, वन विभागों, सीमा शुल्क, रेलवे, राजस्व खुफिया निदेशालय व तट रक्षकों जैसी प्रवर्तन एजेंसियों को लाल चंदन की तस्करी पर अंकुश लगाने के प्रयासों का समन्वय करना चाहिए।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

1 नासा-इसरो ज्वाइंट सैटेलाइट 'निसार'

चर्चा में क्यों?

नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित पृथ्वी-अवलोकन उपग्रह निसार जो पृथ्वी की भूमि और बर्फ की सतहों का अधिक विस्तार से अध्ययन करने में मदद करेगा, को विशेष कंटेनर द्वारा अमेरिका से भारत भेजने पर सहमति बनी। निसार को अब जनवरी, 2024 में सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च करने की संभावना है।

निसार उपग्रह के बारे में:

- इसरो और नासा ने पृथ्वी अवलोकन के लिए 2,800 किग्रा वजनी उपग्रह बनाने के लिए 2014 में हस्ताक्षर किया था।
- इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार (Synthetic Aperture Radar) है जो पृथ्वी की सतह में परिवर्तन को मापने के लिए उपयोग करेगा।
- SAR सटीकता के साथ रडार द्वारा बादलों की तथा अंधेरे में हाई-रिजॉल्यूशन वाली छवियां लेने की तकनीक है, जिसका अर्थ है कि यह किसी भी मौसम में दिन और रात डेटा एकत्र कर सकता है।
- निसार लगभग 12 मीटर व्यास वाले ड्रम के आकार के रिफ्लेक्टर एंटीना के साथ रडार डेटा एकत्र करेगा।
- यह पृथ्वी की भूमि और बर्फ की सतहों में परिवर्तन का निरीक्षण करने के लिए इंटरफेरोमेट्रिक सिंथेटिक एपर्चर रडार या इनएसएआर नामक एक सिग्नल-प्रोसेसिंग तकनीक का उपयोग करेगा।

नासा की भूमिका:

नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) उपग्रह के लिए एक रडार, विज्ञान डेटा के लिए एक उच्च-दर संचार उपप्रणाली, जीपीएस रिसीवर, एक पेलोड डेटा सबसिस्टम और एल-बैंड पेलोड प्रदान करेगा। निसार नासा द्वारा लॉन्च किए गए अब तक के सबसे बड़े रिफ्लेक्टर एंटीना से सुसज्जित होगा।

इसरो की भूमिका:

इसरो अंतरिक्ष यान बस, दूसरे प्रकार का रडार (जिसे एस-बैंड रडार कहा जाता है) और लॉन्च वाहन से संबंधित सेवाएं प्रदान करेगा।

उपग्रह के कार्य और उपयोगिताएँ:

- यह अभूतपूर्व दृश्य देने के लिए पृथ्वी की भूमि, बर्फ की चादरों और समुद्री बर्फ की इमेजिंग के अपने तीन साल के मिशन के दौरान हर 12 दिनों में ग्लोब को स्कैन करेगा।
- यह टेनिस कोर्ट के लगभग आधे आकार के क्षेत्रों में 0.4 इंच जितनी छोटी ग्रह की सतह की हलचल का पता लगा सकता है।
- यह शोधकर्ताओं को भूमि की सतह की धीमी गति से चलने वाली विविधताओं का पता लगाने में भी मदद करेगा जो भूकंप, भूस्खलन और ज्वालामुखी विस्फोट की पूर्व जानकारी दे सकता है।
- समुद्री बर्फ और बर्फ की चादरों के पिघलने के मापन से समुद्र के स्तर में वृद्धि सहित जलवायु परिवर्तन की गति और प्रभावों की समझ में सुधार होगा। यह भूजल आपूर्ति की निगरानी करने में मदद कर सकता है।

आगे की राह:

निसार का डेटा दुनिया भर में लोगों को प्राकृतिक संसाधनों और खतरों का बेहतर प्रबंधन करने में मदद कर सकता है जिसकी छवियां स्थानीय परिवर्तनों को दिखाने के लिए विस्तृत होंगी तथा क्षेत्रीय प्रवृत्तियों को मापने के लिए पर्याप्त व्यापक होंगी। यह हमारे ग्रह की कठोर बाहरी परत, जिसे क्रस्ट कहा जाता है, के बारे में समझ को भी बढ़ाएगा।

2 जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार ने जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकियों के उद्भव और शिक्षा, विनिर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, वित्त जैसे अन्य क्षेत्रों में उनके तेजी से प्रसार को संज्ञान में लिया। सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को डिजिटल अर्थव्यवस्था, निवेश और नौकरियों के विकास के लिए एक अवसर के रूप में भी मानती है।

जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है?

- जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नई सामग्री बनाने के लिए मौजूदा टेक्स्ट, ऑडियो फाइलों या छवियों का उपयोग करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-सक्षम मशीनों की क्षमता को संदर्भित करता है। जैसे-चैटजीपीटी, डीप-फेक (Deep-Fakes) आदि।
- जनरेटिव एआई बड़े डेटासेट पर एक मॉडल को प्रशिक्षित करके काम करता है और फिर उस मॉडल का उपयोग करके प्रशिक्षण डेटा के समान नई (जो पहले अनदेखी सामग्री थी) सामग्री उत्पन्न करता है।

जनरेटिव एआई के अनुप्रयोग क्या हो सकते हैं?

कला, संगीत, छवि और वीडियो निर्माण:

- डीपड्रीम जेनरेटर-एक ओपन-सोर्स प्लेटफॉर्म जो यथार्थपरक (surrealistic) या ड्रीम जैसी छवियां बनाने के लिए डीप लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करता है।
- DALL-E2 -OpenAI का यह मॉडल पाठ विवरण से नई छवियां उत्पन्न करता है।
- एम्पर म्यूजिक - पहले से रिकॉर्ड किए गए नमूनों से म्यूजिकल ट्रैक बनाना।
- AIVA - विभिन्न शैलियों में मूल संगीत की रचना करने के लिए AI एल्गोरिदम का उपयोग करना।

भाषा और सामग्री:

- चैटजीपीटी समाचार लेख, कविता और यहां तक कि कोड उत्पन्न करने के लिए।
- चैट-बॉट और भाषा अनुवाद मॉडल।
- ड्रग डिस्कवरी- जनरेटिव एआई मॉडल का उपयोग नई दवाओं की खोज करने और उनकी संभावित प्रभावकारिता का अनुमान लगाने के लिए किया जा सकता है।

- सीखने हेतु एआई के लिए सामग्री तैयार करके रोबोटिक और मशीन लर्निंग में आगे इस्तेमाल किया जा सकता है।

भारत के लिए महत्त्व:

- नैसकॉम के आंकड़ों के अनुसार, भारत में कुल एआई पेशेवरों का लगभग 416,000 रोजगार अनुमानित है।
- इस क्षेत्र के लिए विकास दर 20-25% अनुमानित है। इसके अलावा, एआई से 2035 तक भारत की अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त 957 बिलियन अमरीकी डॉलर का योगदान करने की क्षमता है।

भारतीय पहलें क्या हैं?

- **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए राष्ट्रीय रणनीति-** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुसंधान करने और बढ़ावा देने हेतु एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना।
- **अंत:विषय साइबर**-भौतिक प्रणालियों पर राष्ट्रीय मिशन।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च, एनालिटिक्स और नॉलेज एसिमिलेशन प्लेटफॉर्म।

जनरेटिव एआई से जुड़े मुद्दे क्या हैं?

- नौकरी का विस्थापन।
- मानव संज्ञान को कम करना।
- **पूर्वाग्रह और निष्पक्षता-** एआई मॉडल समाज में मौजूदा पूर्वाग्रहों को स्थायी रूप से बढ़ा सकते हैं, जिससे कुछ समूहों के साथ भेदभावपूर्ण अनुचित व्यवहार हो सकता है।
- **नैतिक चिंताएं-** इसका उपयोग दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जैसे-प्रचार या गलत सूचना अभियान, नकली सामग्री आदि।
- **बौद्धिक संपदा-** जनरेटिव एआई मॉडल रचनात्मक कार्यों का उत्पादन कर सकते हैं जो मौजूदा कॉपीराइट या ट्रेडमार्क कानूनों का उल्लंघन करते हैं, जिससे कानूनी विवाद होते हैं।
- कुछ बड़ी तकनीकी कंपनियों और देशों में शक्ति के संकेन्द्रण की संभावना।

आगे की राह:

अभी तक हुए महत्त्वपूर्ण प्रगति के बावजूद, जनरेटिव एआई को और भी तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे-आउटपुट की गुणवत्ता में सुधार करना और प्रशिक्षण डेटा में पक्षपात से बचना। इसलिए पारदर्शिता, जवाबदेही तथा गोपनीयता के सिद्धांतों के आधार पर किसी भी नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक व अनपेक्षित दोनों तरह के जनरेटिव एआई मॉडल के संभावित परिणामों का लगातार आकलन और समायोजन करने की आवश्यकता है।

3 मनुष्यों के लिए बर्ड फ्लू वेक्टर बन सकते हैं मिंक्स (Minks)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में स्पेन में 50,000 मिंक मारे गए हैं जिसका कारण बर्ड फ्लू माना जा रहा है। इसने वायरस के जीनोम में कम से कम एक उत्परिवर्तन का संकेत दिया, जो स्तनपायी-से-स्तनपायी संक्रमण को आसान बना सकता है।

बर्ड फ्लू के बारे में:

- इसे एवियन इन्फ्लुएंजा (एआई) के रूप में भी जाना जाता है, बर्ड फ्लू अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग है जो खाद्य उत्पादक पक्षियों (मुर्गियां, पक्षी) की कई प्रजातियों के साथ-साथ पालतू पक्षियों और जंगली पक्षियों को प्रभावित करता है।
- इन्फ्लुएंजा वायरस का वर्गीकरण-
  - निम्न रोगजनक एआई (LPAI)
  - अत्यधिक रोगजनक एआई (एचपीएआई), जैसे-H5N1 स्ट्रेन
- बर्ड फ्लू दुनिया भर में जंगली पक्षियों में स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाले एवियन इन्फ्लूएंजा टाइप-ए वायरस के कारण होता है।
- टाइप-ए वायरस को उनकी सतहों पर दो प्रोटीनों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है- हेमाग्लगुटिनिन (एचए) और न्यूरोमिनिडेस (एनए)।
  1. 18 ज्ञात एचए उपप्रकार और 11 ज्ञात एनए उपप्रकार
  2. इन दो प्रोटीनों का विभिन्न संयोजन संभव है, उदाहरण- एच5एन1, एच7एन2, एच9एन6, एच17एन10 आदि।

मनुष्यों में संक्रमण:

- सबसे अधिक संक्रमण की संभावना सीधा संपर्क है। यह संक्रमित मुर्गे के पास दूषित सतहों या हवा के संपर्क में आने पर भी फैल सकता है।
- आम जनता के लिए जोखिम बहुत कम है। हालांकि, मानव संक्रमण की रिपोर्ट मिली है।
- यह संक्रमण घातक है क्योंकि इसकी मृत्यु दर लगभग 60% अधिक है।
- मानव से मानव में H5N1 का संचरण बहुत दुर्लभ है।

प्रभाव:

- बर्ड फ्लू का प्रकोप किसी भी देश, विशेष रूप से पोल्ट्री उद्योग के लिए विनाशकारी परिणाम पैदा कर सकता है।
- यह किसानों को उनके पक्षियों के झुंड में उच्च स्तर की मृत्यु दर से प्रभावित करता है, जिसकी दर अक्सर 45% से अधिक होती है।

भारत में बर्ड फ्लू की स्थिति:

- 2019 में, भारत को एवियन इन्फ्लुएंजा (H5N1) से मुक्त घोषित किया गया था, जिसे विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (OIE) को भी अधिसूचित किया गया था।
- OIE एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसका मुख्यालय पेरिस (फ्रांस) में है, जो दुनिया भर में जानवरों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए जिम्मेदार है।

नियंत्रण के उपाय:

- जानवरों में संक्रमण का पता चलने पर जानवरों को मारने का काम किया जाता है जिसके बाद मारे गए जानवरों का सुरक्षित निपटान किया जाता है।
- WHO की वैश्विक प्रयोगशाला प्रणाली, वैश्विक इन्फ्लुएंजा निगरानी और प्रतिक्रिया प्रणाली (GIRSRS), इन्फ्लूएंजा वायरस प्रसार के स्ट्रेन की पहचान, निगरानी और सरकारों को सलाह देती है।

आगे की राह:

मिंक के बीच संक्रमण दुनिया भर में एक ताजा चिंता का विषय है।

वायरस के संभावित स्ट्रेन के आगमन की प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में कार्य करने के लिए जंगली पक्षियों और स्तनधारियों की निगरानी बढ़ाने की आवश्यकता है।

4 जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने वर्चुअल रूप से जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया।

जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन:

- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स (एनआईबी) यह सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है कि केवल गुणवत्ता वाले जैविक उत्पाद ही स्वास्थ्य प्रणाली तक पहुंचें।
- राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन जैविकों के गुणवत्ता आश्वासन के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत के लिए हितधारकों, नियामक प्राधिकरणों और शिक्षाविदों को एक मंच प्रदान करने के रूप में कार्य करेगा।
- ये बातचीत सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, उसकी सुरक्षा के लिए क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी वृद्धि और नए जैविक विकास का नेतृत्व करेगी, जिससे 'स्वस्थ भारत' सुनिश्चित होगा।

राष्ट्रीय जैविक संस्थान (एनआईबी) के बारे में:

- इसकी स्थापना 1992 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक शीर्ष स्वायत्त संस्थान के रूप में की गई थी।
- एनआईबी जैविक के गुणवत्ता नियंत्रण के प्राथमिक वैधानिक कार्य करने के लिए जिम्मेदार है। उदाहरण के लिए इंसुलिन, एरिथ्रोप्रोटीन, रक्त उत्पाद, डायग्नोस्टिक किट आदि।

जैविक क्या हैं?

- बायोलॉजिकल दवाओं का विविध समूह है जिसमें टीके, वृद्धि कारक, प्रतिरक्षा न्यूनाधिक, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, साथ ही मानव रक्त और प्लाज्मा से प्राप्त उत्पाद शामिल हैं।
- जैविक पदार्थों को अन्य दवाओं से अलग माना जाता है क्योंकि ये आम तौर पर जीवित संस्कृति प्रणालियों से शुद्ध किए गए प्रोटीन होते हैं, जबकि अन्य दवाओं को 'छोटे अणु' माना जाता है जो कृत्रिम रूप से बनाई जाती हैं या पौधों से बनाई जाती हैं।
- जैविक चिकित्सीय में वे दवाएं शामिल हैं जो बैक्टीरिया या खमीर, या पौधे या पशु कोशिकाओं के बड़े पैमाने पर सेल कल्चर से उगाई जाती हैं और फिर शुद्ध की जाती हैं।

जैविक के लाभ:

- पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाता है।
- जड़ विकास में सुधार करता है।
- रोगों और कीटों को दबाता है।
- आनुवंशिक क्षमता को अधिकतम करता है।
- स्थिरता को बढ़ावा देता है।

आगे की राह:

यह शिखर सम्मेलन भारत में प्रचलित गुणवत्ता आश्वासन दृष्टिकोणों में अंतर विश्लेषण के लिए एक आधार प्रदान करेगा। यह देश के बायोफार्मास्यूटिकल्स और इन-विट्रो डायग्नोस्टिक्स उद्योग के बुनियादी ढांचे तथा प्रौद्योगिकियों को अपग्रेड करने में मदद करेगा। यह विश्व स्तरीय उत्पादों को विकसित करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की इसकी क्षमता को भी बढ़ाएगा।

5 लैब में बने हीरे को विकसित करने की पहल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बजट भाषण के दौरान, वित्त मंत्री ने प्रयोगशाला में विकसित हीरों (LGD) पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सरकार के कदम की घोषणा की। प्रयोगशाला में विकसित हीरे के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले बीजों पर कस्टम ड्यूटी कम की जाएगी। भारत में एलजीडी के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए आईआईटी को अनुदान दिया जाएगा।

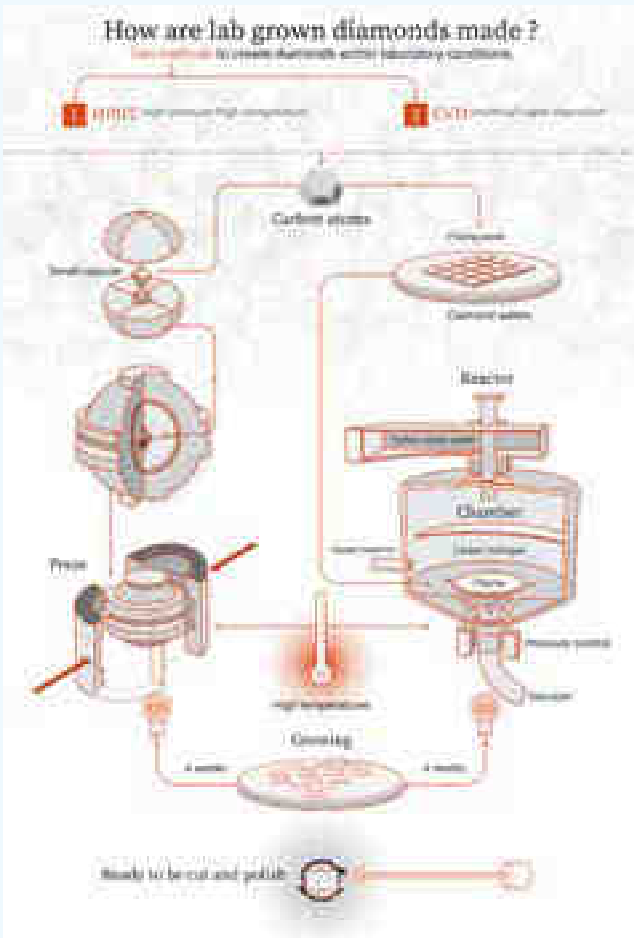

प्रयोगशाला में विकसित हीरे (एलडीजी) क्या हैं?

- एलडीजी वे हीरे हैं जिन्हें विशिष्ट तकनीक का उपयोग करके घटाया जाता है जो प्राकृतिक हीरे उगाने वाली भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं

की नकल करते हैं।

- विश्व का पहला LGD 1954 में न्यूयॉर्क में वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया था।
- एलडीजी रासायनिक, भौतिक और वैकल्पिक रूप से हीरे हैं।
- ये मोइसेनाइट, क्यूबिक जिरकोनिया (CZ), सफेद नीलम, YAG, आदि जैसे 'हीरा उत्तेजक' के समान नहीं हैं, जो केवल हीरे की तरह दिखने का प्रयास करते हैं। उनमें हीरे की चमक और स्थायित्व की कमी होती है जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है।

LGDs की उत्पादन प्रक्रियाएं:

उच्च दबाव, उच्च तापमान (एचपीएचटी) विधि:

- इस विधि के लिए अत्यधिक भारी दबावों की आवश्यकता होती है जो अत्यधिक उच्च तापमान (कम से कम 1500^0 सेल्सियस) के तहत 730,000 पीएसआई तक दबाव उत्पन्न कर सकता है।
- आमतौर पर, ग्रेफाइट का उपयोग 'हीरे के बीज' के रूप में किया जाता है। जब इन चरम स्थितियों के अधीन होता है, तो कार्बन का अपेक्षाकृत सस्ता रूप, कार्बन के सबसे महंगे रूपों में से एक में बदल जाता है।
- रासायनिक वाष्प जमाव (सीवीडी) 'डेटोनेशन नैनोडायमंड्स' के रूप में जाना जाता है।

अनुप्रयोग:

- उनके गुण प्राकृतिक हीरे के समान हैं, जिसमें उनके ऑप्टिकल फैलाव शामिल हैं, जो उन्हें विशेष हीरे की चमक प्रदान करते हैं।
- चूंकि वे नियंत्रित वातावरण में बनाए जाते हैं, इसलिए उनके कई गुणों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए बढ़ाया जा सकता है।
- **औद्योगिक उद्देश्य:** उदाहरण के लिए, एलजीडी का उपयोग अक्सर मशीनों और उपकरणों में औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है।
- कठोरता और अतिरिक्त ताकत उन्हें कटर के रूप में उपयोग करने के लिए आदर्श बनाती है।
- इसके अलावा, शुद्ध सिंथेटिक हीरे में उच्च तापीय चालकता होती है, लेकिन विद्युत चालकता नगण्य होती है।
- **इलेक्ट्रॉनिक्स:** एलजीडी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अमूल्य हैं जहां ऐसे हीरों का उपयोग उच्च-शक्ति वाले लेजर डायोड, लेजर सरणी और उच्च-शक्ति ट्रांजिस्टर के लिए गर्मी फैलाने वाले के रूप में किया जा सकता है।
- **आभूषण:** जैसे-जैसे पृथ्वी के प्राकृतिक हीरे के भंडार कम होते जा रहे हैं, एलजीडी धीरे-धीरे रत्न की जगह ले रहे हैं।

आगे की राह:

भारत हीरों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा कटिंग और पॉलिशिंग केंद्र है, जो वैश्विक स्तर पर पॉलिश किए गए हीरों के निर्माण का 90% से अधिक हिस्सा है। LGDs पर सरकार के ध्यान के साथ, भारत में हीरा उद्योग में वृद्धि होने की संभावना है।

6 भारतीय गायों की जीनोम सीक्वेंसिंग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल के शोधकर्ताओं ने चार देशी भारतीय गाय नस्लों (कासरगोड बौना, कासरगोड कपिला, वेचुर और ओंगोल) के आनुवंशिक मेकअप को सफलतापूर्वक सुलझाया। यह पहली बार है कि इन भारतीय गायों के लिए जीनोम अनुक्रमित किया गया है।

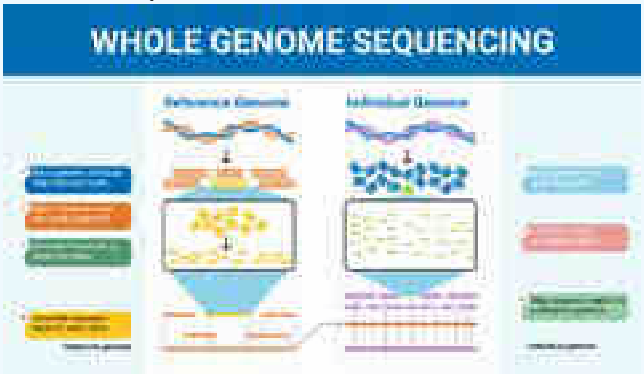

जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है?

- जीनोम किसी पौधे या जानवर की तरह किसी जीव के निर्माण और चलाने के लिए एक ब्लूप्रिंट या निर्देशों के एक सेट की तरह है।
- यह जीन नामक छोटी इकाईयों से बना होता है जिसमें जीव के बढ़ने, विकसित होने और ठीक से काम करने के लिए आवश्यक जानकारी होती है।
- जैसे किसी भवन के ब्लूप्रिंट में यह जानकारी होती है कि इसे कैसे बनाया जाए? जीनोम में वह जानकारी होती है जिसकी एक जीव को जीवित रहने और जीवित रहने के लिए आवश्यकता होती है।
- सीक्वेंसिंग चार न्यूक्लियोटाइड बेसों के अनुक्रम को दर्शाता है, जैसे एडेनाइन(ए), साइटोसिन(सी), गुआनिन(जी) और थाइमिन(टी)।
- मानव जीनोम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड (डीएनए) से बने होते हैं जबकि एक वायरस जीनोम या तो डीएनए या आरएनए (राइबोन्यूक्लिक एसिड) से बना हो सकता है।
- मानव जीनोम 23 गुणसूत्र जोड़े से बना है जिसमें कुल लगभग 3 बिलियन डीएनए बेस जोड़े हैं।
- जीनोम सीक्वेंसिंग एक ऐसी तकनीक है जो डीएनए या आरएनए के भीतर पाई जाने वाली आनुवंशिक जानकारी को पढ़ती है और उसकी व्याख्या करती है।

देशी भारतीय गाय:

- उनके पास विशेष क्षमताएं हैं जो उन्हें भारत में कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने में मदद करती हैं, जैसे खराब गुणवत्ता वाले भोजन खाने में सक्षम होना और कुछ बीमारियों के लिए प्रतिरोधी होना।
- पूर्ण जीनोम अनुक्रमण उन कारणों को समझने में मदद करेगा कि क्यों भारतीय गायों में गर्म मौसम, उनके आकार और दूध के प्रकार

को अपनाने जैसे कुछ विशेष गुण होते हैं?

- वेचुर दुनिया की सबसे छोटी गाय की नस्ल है।

जीनोम सीक्वेंसिंग का महत्त्व:

- जीनोम अनुक्रमण आसानी से और जल्दी जीन खोजने के लिए एक मूल्यवान शॉर्टकट प्रस्तुत करता है।
- जीनोम अनुक्रम की पूरी समझ से यह समझने में मदद मिलेगी कि कैसे एक जीनोम समग्र रूप से एक संपूर्ण जीव के विकास और रखरखाव को निर्देशित करता है?
- वैज्ञानिक जीव के बारे में महत्त्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि यह कुछ बीमारियों या लक्षणों से कैसे संबंधित हो सकता है?
- जीनोम अनुक्रमण इन देशी नस्लों की आनुवंशिक विविधता को संरक्षित करने में मदद कर सकता है, जो एक स्वस्थ और लचीले झुंड को बनाए रखने के लिए महत्त्वपूर्ण है।

आगे की राह:

इन गायों के प्रजनन और प्रबंधन में सुधार के लिए जीनोम संरचना का उपयोग किया जा सकता है, जिससे भारतीय मवेशी उद्योग में उत्पादकता और स्थिरता में वृद्धि हो सकती है। यह उनके और अन्य नस्लों के बीच आनुवंशिक अंतर को समझने में भी मदद करेगा, जो आगे आनुवंशिक सुधार के लिए मूल्यवान हैं।

7 सिकल सेल एनीमिया

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय बजट 2023-24 में सरकार ने 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए एक मिशन की घोषणा की है। यह जागरूकता अभियान प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों में 0-40 वर्ष की आयु के सात करोड़ लोगों की सार्वभौमिक स्क्रीनिंग, केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से परामर्श पर ध्यान केंद्रित करेगा।

सिकल सेल एनीमिया क्या है?

- सिकल सेल रोग (SCD) रक्त विकारों का एक वंशानुगत समूह है जो प्रकृति में आनुवंशिक है। यह आमतौर पर जन्म के दौरान माता-पिता से बच्चे में स्थानांतरित हो जाता है यानी माता-पिता दोनों एससीडी के वाहक हो सकते हैं।
- स्वस्थ आरबीसी आकार में गोल होते हैं, इसलिए एससीडी वाले व्यक्ति में आरबीसी चिपचिपा (sticky) और कठोर हो जाता है जो कृषि उपकरण 'सिकल' के समान सी-आकार ग्रहण कर लेता है।

क्या लक्षण हैं?

- **क्रोनिक एनीमिया-** सिकल सेल समय से पहले मर जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप लाल रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाती है, जिससे थकान, कमजोरी और शरीर पर पीलापन हो जाता है।
- दर्दनाक एपिसोड (सिकल सेल संकट के रूप में भी जाना जाता है) - जैसे ही सिकल सेल छोटी रक्त धमनियों से गुजरता है, वे फंस जाते हैं और रक्त प्रवाह में बाधा डालते हैं।
- इसके परिणामस्वरूप हड्डियों, छाती, पीठ, बाहों, पैरों में अचानक और तीव्र दर्द जैसी परेशानी हो सकती है जिसके अन्य खतरनाक परिणाम (स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं) जैसे संक्रमण, तीव्र छाती सिंड्रोम (Acute chest Syndrome) और स्ट्रोक हो सकते हैं।
- विलंबित विकास और यौवन।

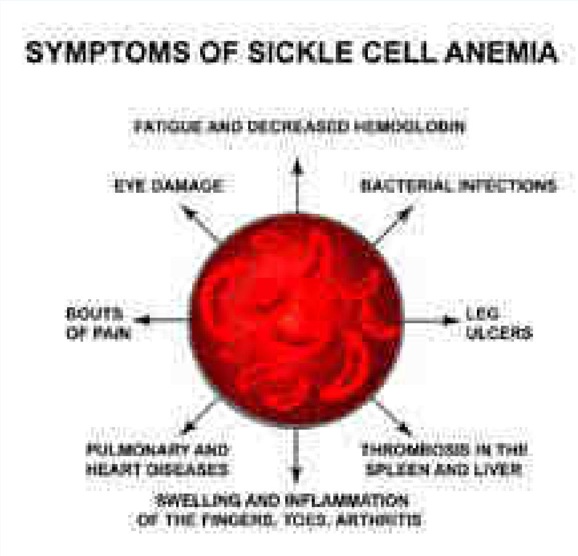

उपचार क्या हैं?

- **रक्ताधान** (Blood Transfusions)- रक्ताल्पता दूर करने और दर्द संकट के जोखिम को कम करने के लिए।
- **हाइड्रोक्सीयूरिया-** यह एक ऐसी दवा है जो दर्दनाक एपिसोड की आवृत्ति को कम करने और रोग की दीर्घकालिक जटिलताओं को रोकने में मदद कर सकती है।
- अस्थि मज्जा या स्टेम सेल प्रत्यारोपण।

सिकल सेल रोग (SCD) के निदान की प्रक्रिया क्या है?

- रक्त परीक्षण।
- बच्चे के जन्म से पहले एमनियोटिक द्रव या अपरा ऊतक के नमूने से भी एससीडी का निदान किया जा सकता है।

आगे की राह:

सिकल सेल लक्षण विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले समुदायों में जांच करने की आवश्यकता है। सिकल सेल विशेषता वाले व्यक्तियों को एक दूसरे से शादी करने से रोकना। सिकल सेल रोग के लिए भ्रूण की जांच करना और माता-पिता की इच्छा होने पर गर्भावस्था को समाप्त करना। सिकल सेल रोग का उन्मूलन एक 'साहसिक कदम' है जिसे समावेशी विकास पर फोकस के साथकम किया जा सकता है।

आर्थिक मुद्दे

1 औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-दिसंबर 2022

चर्चा में क्यों?

दिसंबर, 2022 का अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक श्रमिक) 0.2 अंक घटकर 132.3 अंकों के स्तर पर संकलित हुआ। सूचकांक में पिछले माह की तुलना में 0.15 प्रतिशत की वृद्धि रही जबकि एक वर्ष पूर्व इन्हीं दो महीनों के बीच 0.24 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी।

दिसंबर 2022 इंडेक्स के प्रमुख बिन्दु:

- वर्तमान सूचकांक में अधिकतम गिरावट खाद्य और पेय पदार्थ समूह से आया है, जो कुल परिवर्तन में 0.52 प्रतिशत अंकों का योगदान देता है।
- हालांकि इस कमी को चावल, गेहूं, आंटा, गाय के दूध आदि द्वारा सूचकांक को बढ़ाकर नियंत्रित किया गया।
- साल-दर-साल मुद्रास्फीति, पिछले महीने के 5.4% और एक साल पहले इसी महीने के दौरान 5.56% की तुलना में इस महीने के लिए 5.50% रही।
- इसी तरह, खाद्य मुद्रास्फीति पिछले महीने के 4.30% और एक साल पहले इसी महीने के दौरान 5.93% के मुकाबले 4.10% रही।

औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW):

- इसे श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय द्वारा संकलित किया गया है।
- इसे हर महीने देश के 88 केंद्रों में फैले 317 बाजारों से एकत्रित खुदरा कीमतों के आधार पर जारी किया जाता है।
- CPI-IW का उपयोग मुख्य रूप से खुदरा कीमतों में मुद्रास्फीति को मापने के अलावा औद्योगिक क्षेत्रों में केंद्रीय/राज्य सरकार के कर्मचारियों और श्रमिकों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते (DA) के निर्धारण के लिए किया जाता है।
- इसका आधार वर्ष 2016 है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के बारे में:

- यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा प्रकाशित, खुदरा खरीददार के दृष्टिकोण से कीमतों में बदलाव को मापता है।
- यह भारतीय उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग के लिए खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में अंतर की गणना करता है, जैसे-भोजन, चिकित्सा देखभाल, शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि।
- सीपीआई को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है-
  1. सीपीआई- औद्योगिक श्रमिक।
  2. सीपीआई- कृषि मजदूर।
  3. सीपीआई- ग्रामीण मजदूर।
  4. सीपीआई शहरी/ग्रामीण/संयुक्त।
- पहले तीन को श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित किया जाता है, जबकि सीपीआई शहरी/ग्रामीण/संयुक्त को एनएसओ द्वारा संकलित किया जाता है।

आगे की राह:

दिसंबर 2022 के लिए CPI-IW देश में मुद्रास्फीति की वर्तमान स्थिति को दर्शाता है। यह देश में मुद्रास्फीति के स्तर को नियंत्रित करने के लिए नीति निर्माताओं और आरबीआई को तदानुसार कार्य करने के लिए मार्गदर्शन करता है।

2 विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जनवरी-2023

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने विश्व आर्थिक आउटलुक जनवरी 2023 अपडेट जारी किया है।

भारतीय परिदृश्य:

- आउटलुक के अनुसार, भारत वित्तीय वर्ष 2023 और 2024 में दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा।
- वित्त वर्ष 2023 में मामूली गिरावट के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था 6.1% की दर से बढ़ेगी, लेकिन 2024 में यह 6.8% की दर से मजबूत वृद्धि करेगी।
- मुद्रास्फीति की दर वित्त वर्ष 2022 में 6.8% से वित्त वर्ष 2023 में 5% पर आने की उम्मीद है जबकि वित्त वर्ष 2024 में यह और घटकर 4% तक हो सकती है।

वैश्विक परिदृश्य:

- आईएमएफ के अनुसार 2024 में वैश्विक विकास वृद्धि 3.1% रहेगी, जबकि इस वर्ष यह 2.7% से 2.9% तक रह सकती है।
- वैश्विक विकास दर में यह पूर्वानुमानित उन्नयन चीन की शून्य-कोविड प्रतिबंध नीति को हटाने का परिणाम है। यह भी अनुमान लगाया गया है कि भारत और चीन 2023 में वैश्विक विकास के 50% से अधिक की आपूर्ति करेंगे।
- रिपोर्ट में उम्मीद है कि जर्मनी और इटली मंदी के प्रभाव में नहीं होंगे। विशेष रूप से यूक्रेन युद्ध के बावजूद यूरोप का विकास अपेक्षा से अधिक लचीला साबित हुआ।
- आईएमएफ को उम्मीद है कि फेडरल रिजर्व और प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा आक्रामक ब्याज (Aggressive interest) दरों में बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप इस वर्ष मुद्रास्फीति कम होगी। वैश्विक खपत (Consumption) मुद्रास्फीति की दर 2022 में 8.8% से गिरकर 2023 में 6.6% और 2024 में 4.3% तक रहने की उम्मीद है।
- मध्यम रूप से बेहतर दृष्टिकोण उच्च मुद्रास्फीति, उच्च ब्याज दरों और यूक्रेन के खिलाफ चल रहे युद्ध के कारण विश्व अर्थव्यवस्था के लचीलेपन में वृद्धि का परिणाम है। यह आउटलुक 2023 में वैश्विक मंदी की आशंकाओं को देखते हुए राहत प्रदान करता है।
- आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री पियरे-ओलिवर गौरिनचास ने कहा कि मंदी के जोखिम कम हो गए हैं और केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में प्रगति कर रहे हैं, लेकिन कीमतों पर अंकुश

लगाने तथा अप्रत्याशित की उम्मीद करने के लिए और अधिक काम करने की जरूरत है।

- विश्व आर्थिक आउटलुक आईएमएफ द्वारा सर्वेक्षण है जो आम तौर पर अप्रैल-अक्टूबर के महीनों में साल में दो बार प्रकाशित किया जाता है, यह वैश्विक आर्थिक विकास का विश्लेषण और भविष्यवाणी करता है।
- इसके अतिरिक्त डब्ल्यूईओ अपडेट दो मुख्य प्रकाशनों के बीच जनवरी और जुलाई में प्रकाशित किया जाता है। WEO के अलावा, IMF वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट और विश्व आर्थिक रिपोर्ट भी प्रकाशित करता है।

आगे की राह:

इस हालिया दृष्टिकोण ने आगामी वित्तीय वर्षों के लिए अपेक्षित मंदी से राहत का अनुमान लगाया है, लेकिन संभावित विपरीत परिस्थितियों के खिलाफ विश्व अर्थव्यवस्था को अग्रिम और उभरती अर्थव्यवस्थाओं हेतु सहयोगात्मक रूप से कदम उठाने होंगे। इसमें भू-राजनीतिक तनावों के निवारण से लेकर सरकारी हस्तक्षेपों के माध्यम से अर्थव्यवस्थाओं की उत्पादकता को बढ़ावा देना शामिल होगा।

3 विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2023 रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट, 2023 के अनुसार, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 2022 में 3% से गिरकर 2023 में 1.9% रहने का अनुमान है।

रिपोर्ट की प्रमुख बातें:

- रिपोर्ट के अनुसार, इसका कारण खाद्य तथा ऊर्जा संकट है, जिसने 2022 में COVID-19 और यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि में अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया।
- युद्ध की स्थिति में बदलाव और आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के अधीन, दुनिया की उत्पादन वृद्धि 2024 में 2.7% तक वापस आ सकती है।
- **मुद्रास्फीति-** 2022 में दुनिया की औसत मुद्रास्फीति दर 9% थी, जिसके कारण कई विकसित और विकासशील देशों में बजटीय बाधा उत्पन्न हुई।
- **गरीबी-** विश्व बैंक के अनुसार, कई वैश्विक संकटों ने महामारी पूर्व अनुमानों की तुलना में 2022 में अतिरिक्त 75 से 95 मिलियन लोगों को अत्यधिक गरीबी में धकेल दिया।
- **आय असमानताएं-** विश्व स्तर पर, नीचे के 40% लोगों की औसत आय में 2019 की तुलना में 2021 में थोड़ी गिरावट आई, जबकि यह शीर्ष 10% लोगों की आय बढ़ी है, जो आय असमानता के बढ़ने का संकेत है।

दक्षिण एशिया:

- उच्च खाद्य और ऊर्जा की कीमतों, मौद्रिक तंगी तथा राजकोषीय कमजोरियों के कारण आर्थिक दृष्टिकोण काफी बिगड़ गया है।
- औसत जीडीपी वृद्धि 2022 में 5.6% से मध्यम होकर 2023 में 4.8% होने का अनुमान है।

भारत-विशिष्ट हाइलाइट्स:

- भारत में विकास दर 5.8% पर मजबूत रहने की उम्मीद है। हालांकि 2022 में अनुमानित 6.4% की तुलना में थोड़ा कम है, क्योंकि उच्च ब्याज दरें, वैश्विक मंदी, निवेश और निर्यात पर भारित है।
- रिपोर्ट ने संकेत दिया कि भारत की खाद्य और ऊर्जा सब्सिडी ने अर्थव्यवस्था में एक बड़ी गिरावट को रोका है।
- बेरोजगारी दर-2022 में, यह शहरी और ग्रामीण रोजगार में वृद्धि के माध्यम से पूर्व-महामारी स्तर तक गिर गई। हालाँकि, युवा रोजगार पूर्व-महामारी के स्तर से नीचे रहा, विशेषकर महिलाओं में।

सिफारिशें:

- रिपोर्ट में डिजिटल बुनियादी ढांचे, जलवायु परिवर्तन और नई तकनीकों में निवेश करने की सलाह दी गई है।
- सरकारों को राजकोषीय मितव्ययिता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो कि खर्च में कटौती और कर वृद्धि को रोकने वाले उपाय हैं।
- सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करना और अस्थायी सब्सिडी का प्रावधान।

विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट के बारे में:

- यूएनडीईएसए (संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग) द्वारा जारी किया गया।
- मुख्यालय न्यूयॉर्क (अमेरिका) में स्थित है।
- UNDESA दुनिया भर के देशों को उनकी आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय चुनौतियों को बनाने के लक्ष्य के साथ एजेंडा-सेटिंग और निर्णय लेने में सहायता करता है।

आगे की राह:

रिपोर्ट ने उत्तेजक उत्पादन और उम्मीदों को कम करने के बीच संतुलन बनाने के लिए व्यापक आर्थिक नीतियों को कैलिब्रेट करने की सिफारिश की। वित्तीय सहायता तक पहुंच बढ़ाने और एसडीजी वित्तपोषण को बढ़ाने के लिए मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की तत्काल आवश्यकता है।

4 रिवर्स-फ्लिपिंग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 ने सुझाव दिया है कि भारत सरकार को ईएसओपी कराधान (कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजना) को सरल बनाने और स्टार्टअप के बीच रिवर्स-फ्लिपिंग में तेजी लाने के लिए कॉर्पोरेट कानूनों को आसान बनाने की आवश्यकता है।

फ्लिपिंग और रिवर्स फ्लिपिंग क्या होता है?

- फ्लिपिंग एक भारतीय कंपनी के पूरे स्वामित्व को एक विदेशी इकाई को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है।
- रिवर्स फ्लिपिंग, उन कंपनियों के स्वामित्व को भारत में वापस स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है जो पहले फ्लिप या शिफ्ट हो गए थे।

ऐसा क्यों होता है?

- स्टार्टअप के शुरुआती चरण में फ्लिपिंग होती है, जो संस्थापकों और निवेशकों की वाणिज्यिक, कराधान और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं से

प्रेरित होती है। प्रमुख कंपनियां फ्लिप करने का फैसला करती हैं क्योंकि उनके उत्पाद का बाजार अलग होता है।

- निजी इक्विटी तथा उद्यम पूंजी तक आसान पहुंच, राउंड-ट्रिपिंग के बारे में नियमों में बदलाव और भारत के पूंजी बाजार की बढ़ती परिपक्वता के कारण कंपनियां रिवर्स फ्लिप करती हैं।
- कई स्टार्ट-अप ने अपने व्यवसाय को विदेशों में स्थानांतरित कर दिया है, विशेष रूप से अनुकूल कानूनी वातावरण और कराधान नीतियों (फ्लिपिंग के रूप में जाना जाता है) वाले गंतव्यों में। इस प्रक्रिया में एक भारतीय कंपनी के पूरे स्वामित्व को एक विदेशी इकाई में स्थानांतरित करना भी शामिल है, जिसमें भारतीय कंपनी के स्वामित्व वाली सभी बौद्धिक संपदा और डेटा का हस्तांतरण शामिल होता है। यह आमतौर पर स्टार्टअप के शुरुआती चरण में होता है।
- विभिन्न कारकों, जैसे स्टार्टअप को बढ़ावा देने तथा कर संबंधी नियमों में ढील देने के लिए विभिन्न सरकारी पहल के कारण भारत सरकार मूल्य शृंखला में विघटनकारी नवप्रवर्तकों के साथ काम करने और सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार के लिए उनके नवाचारों का उपयोग करने के मूल्य को समझ रही है। भारत सरकार एक स्टार्टअप और नवाचार अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है।
- आर्थिक सर्वेक्षण ने कई मोर्चों पर प्रकाश डाला है जहां पर्याप्त सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता है। जैसे:
  - कई कर दरों को सरल बनाना।
  - कर मुकदमेबाजी के कारण कर अनिश्चितता को हल करना। विशेष रूप से कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजनाओं के बारे में।
  - सामाजिक नवाचार और प्रभाव निवेश जैसे उभरते क्षेत्रों में स्टार्ट-अप के लिए इनक्यूबेशन और वित्त पोषण परिदृश्य की खोज करना।
  - स्थापित निजी संस्थाओं के साथ साझेदारी के माध्यम से मेंटरशिप कार्यक्रमों को सुविधाजनक बनाना और स्टार्टअप के लिए 'अंतर मंत्रालयी बोर्ड' प्रमाणन प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल बनाना।
  - अन्य चुनौतियों जैसे फंडिंग बाधाओं, राजस्व सृजन संघर्ष, सहायक बुनियादी ढांचे तक आसान पहुंच की कमी और एक जटिल नियामक कर वातावरण को भी संबोधित करने की आवश्यकता है।

स्टार्टअप भारत के लिए इतने महत्त्वपूर्ण क्यों हैं?

- आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप (स्व-रिपोर्ट) द्वारा लगभग 9 लाख प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा की गई हैं, जिसमें पिछले 3 वर्षों में 64% की वृद्धि हुई है।
- लगभग 48% भारतीय स्टार्टअप टियर-2 और 3 शहरों से हैं, जो जमीनी स्तर का प्रदर्शन करते हैं। स्टार्टअप देश के हर वर्ग की बेहतर भागीदारी सुनिश्चित करता है और भारत की विकास की कहानी को समावेशी व टिकाऊ बनाता है।
- भारत सरकार को भारतीय युवा श्रम शक्ति की पूरी क्षमता का एहसास करने के लिए, भारत को अपने अमृतकाल में आत्मनिर्भर और एक विकसित देश बनाने के लिए इन सभी चुनौतियों पर विशेष ध्यान देना होगा।

5 पेरिस क्लब द्वारा श्रीलंका के ऋण पर आईएमएफ को वित्तीय आश्वासन प्रदान करने की संभावना

चर्चा में क्यों?

पेरिस क्लब (जो लेनदार देशों का एक अनौपचारिक समूह है) श्रीलंका के ऋण पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को वित्तीय आश्वासन प्रदान करेगा।

पेरिस क्लब के बारे में:

- पेरिस क्लब में 22 स्थायी सदस्य हैं, जिसमें ज्यादातर पश्चिमी लेनदार देश हैं।
- इसकी शुरुआत 1956 में अर्जेंटीना और उसके सार्वजनिक लेनदारों के बीच पेरिस में हुई बैठक से हुई थी।
- **उद्देश्य:** अपने द्विपक्षीय ऋण चुकाने में असमर्थ देशों के लिए स्थायी ऋण-राहत समाधान खोजना।
- प्रत्येक ऋणी राष्ट्र के साथ आम सहमति, एकजुटता, शर्त और उपचार की तुलनीयता के साथ व्यवहार किया जाना है। देनदार देश के साथ किया गया कोई भी समझौता क्लब के सभी सदस्यों पर समान रूप से लागू होता है।
- सदस्य फरवरी और अगस्त को छोड़कर महीने में एक बार पेरिस में मिलते हैं।

पेरिस क्लब का महत्त्व:

- श्रीलंका के मामले में चीन, जापान और भारत सबसे बड़े द्विपक्षीय लेनदार हैं। श्रीलंका को चीन और भारत से भी आश्वासन चाहिए था। चीन के लिए श्रीलंका का कर्ज उसके द्विपक्षीय ऋण का 52 प्रतिशत, जापान का 19.5 प्रतिशत और भारत का 12 प्रतिशत है। जापान पेरिस क्लब का सदस्य है।
- भारत ने जनवरी 2023 में श्रीलंका के साथ अपनी स्वयं की

द्विपक्षीय वार्ता शुरू की।

- हाल के 20 वर्षों में, चीन ने पेरिस समूह के देशों को दुनिया के सबसे बड़े द्विपक्षीय ऋणदाता के रूप में पीछे छोड़ दिया है।

श्रीलंका के वित्तीय संकट के बारे में:

- आर्थिक कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और कृषि संकट के कारण श्रीलंका एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है।

- खराब मौद्रिक नीतियों के कारण मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई है जिसने देश में अशांति और विरोध को जन्म दिया है।
- श्रीलंका का बचा हुआ विदेशी मुद्रा उसके कर्ज का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
- श्रीलंका अपनी विभिन्न आवश्यकताओं जैसे परिवहन उपकरण, चीनी, दाल, दवाईयां, भोजन, कागज और अन्य आवश्यक वस्तुओं को पूरा करने के लिए अपने आयात पर बहुत अधिक निर्भर करता है।

आगे की राह:

ऋण समझौतों में पेरिस क्लब की भूमिका महत्त्वपूर्ण रही है। चीन की पेशकश को अभी भी अपर्याप्त माना जाता है क्योंकि श्रीलंका के ऋण के संबंध में आईएमएफ को पेरिस क्लब का आश्वासन 2.9 अरब डॉलर के राहत पैकेज के वितरण की दिशा में एक कदम है।

6 NSE ने अडानी समूह की फर्मों को 'अतिरिक्त निगरानी तंत्र' के तहत रखा

चर्चा में क्यों?

रॉयटर्स ने बताया कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने अतिरिक्त निगरानी तंत्र (एएसएम) के तहत अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स और अंबुजा सीमेंट्स को रखा है। इसका मतलब है कि उनके शेयरों में ट्रेडिंग के लिए 100% मार्जिन की आवश्यकता होगी, जिसका उद्देश्य अटकलों और शॉर्टसेलिंग पर अंकुश लगाना है।

अतिरिक्त निगरानी तंत्र (एएसएम) क्या है?

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने निवेशकों को बाजार की अस्थिरता और शेयर की कीमत में असामान्य परिवर्तन से बचाने के इरादे से 2018 में एएसएम पेश किया था।
- एएसएम में रखने के लिए प्रतिभूतियों की शॉर्टलिस्टिंग उन मानदंडों पर आधारित होती है जो सेबी द्वारा संयुक्त रूप से तय किए गए हैं, जिसमें निम्नलिखित पैरामीटर शामिल हैं:
  - उच्च निम्न भिन्नता।
  - ग्राहक एकाग्रता।
  - मूल्य भिन्नता खोने के करीब।
  - बाजार पूंजीकरण।
  - मात्रा भिन्नता।
  - मूल्य-आय अनुपात।
  - वितरण प्रतिशत।
  - अद्वितीय पैन की संख्या।
- अन्य शब्दों में कहें तो एएसएम शॉर्टलिस्टिंग निवेशकों को संकेत देता है कि शेयरों में असामान्य गतिविधि देखी गई है।
- एएसएम के तहत प्रतिभूतियों की शॉर्टलिस्टिंग विशुद्ध रूप से अकाउंट मार्केट सर्विलांस पर आधारित है जिसे संबंधित कंपनी/संस्था के खिलाफ प्रतिकूल कार्यवाही के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।
- सट्टेबाजों और इंट्रा-डे ट्रेडर्स को शेयरों में भारी पोजीशन लेने से हतोत्साहित करने के लिए उन शेयरों पर कड़े उपाय लगाए जाते हैं।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के बारे में:

- एनएसई एक भारतीय स्टॉक एक्सचेंज है जिसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है।
- यह 1992 में स्थापित भारत का सबसे बड़ा वित्तीय बाजार है, जिसने सेबी (1993) द्वारा नामित किए जाने के बाद 1994 में अपना परिचालन शुरू किया।
- एनएसई बाजार पूंजीकरण के हिसाब से दुनिया का ग्यारहवां सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है।
- एस एंड पी सीएनएक्स निफ्टी, जिसे अक्सर एनएसई निफ्टी (नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सिटी) के रूप में जाना जाता है। पचास बड़े शेयरों का बाजार पूंजीकरण-भारित सूचकांक है।
- यह हमेशा पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज रहा है, जो पेपरलेस लेनदेन को बढ़ावा देता है।
- विनिमय पर उत्पादों को व्यापार के लिए 3 परिसंपत्ति वर्गों में व्यवस्थित किया जाता है:
  - इक्विटी की लिस्टिंग और ट्रेडिंग के लिए पूंजी बाजार।
  - निश्चित आय प्रतिभूतियां।
  - डेरिवेटिव बाजार।

आगे की राह:

एएसएम उन प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करता है जो वर्तमान में अवलोकन के अधीन हैं, जो निवेशकों को स्टॉक द्वारा अप्रत्याशित मूल्य में उतार-

चढ़ाव के बारे में सचेत करती हैं। एएसएम सूची के तहत अडानी समूह विभिन्न व्यापारिक प्रतिबंधों के अधीन होगा।

7 प्रयोज्य आय में गिरावट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रकाशित YouGov की रिपोर्ट के अनुसार, 'एक तिहाई से अधिक शहरी भारतीयों ने दावा किया है कि पिछले 12 महीनों में उनकी प्रयोज्य आय में कमी आई है।' YouGov एक अंतर्राष्ट्रीय डेटा एनालिटिक्स फर्म है, जो यूके में स्थित है और डिस्पोजेबल आय रिसर्च करती है।

प्रयोज्य आय (Disposable) क्या है?

- यह वह धनराशि है जो किसी व्यक्ति या परिवार को आयकर काटने के बाद खर्च या बचत करनी पड़ती है।
- प्रयोज्य आय = व्यक्तिगत आय – व्यक्तिगत आय कर
- वृहत स्तर पर ये संख्या दर्शाती है कि उपभोक्ता कैसे बचत करते हैं, खर्च करते हैं और उधार लेते हैं।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु:

- भारत में पिछले 12 महीनों में लोगों की प्रयोज्य आय में वृद्धि की तुलना में कमी देखी गयी है।
- भविष्य में प्रयोज्य आय पर कम निराशावादी दृष्टिकोण है। विगत वर्ष (31 प्रतिशत) की तुलना में अगले वर्ष में डिस्पोजेबल आय में गिरावट की उम्मीद कम है।
- रिपोर्ट में पिछले 12 महीनों में की गई शीर्ष तीन वित्तीय गतिविधियों पर प्रकाश डाला गया है:
  - बचत में पैसा लगाना (33 प्रतिशत)
  - स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान (26 प्रतिशत)
  - स्टॉक और शेयरों में निवेश (21 प्रतिशत)
- **बचत पर-** 36 प्रतिशत शहरी भारतीयों का इरादा अगले 12 महीनों में नियमित रूप से अपनी बचत में पैसा लगाने का है।
- 18 बाजारों में, ब्रिटेन की प्रयोज्य आय में सबसे अधिक गिरावट आई है। लगभग दो-तिहाई (64 प्रतिशत) लोगों ने कहा कि पिछले 12 महीनों में उनकी प्रयोज्य आय में कमी आई है। इसके बाद इटली और पोलैंड (दोनों 57 प्रतिशत) का स्थान है।

भारत में प्रयोज्य आय में गिरावट के संभावित कारण:

- कोविड संबंधित आर्थिक संकट और यूक्रेन-रूस युद्ध संबंधी आर्थिक संकट के प्रभाव।
- रोजगार हानि।
- आर्थिक मंदी को रोकना, क्योंकि इससे सरकार का राजस्व घटता है। स्थिति को संभालने के लिए सरकार करों में वृद्धि करती है जिससे प्रयोज्य आय में कमी आती है।

आगे की राह:

डिस्पोजेबल आय एक महत्त्वपूर्ण संकेतक है जो अर्थव्यवस्था में मांग का निर्धारण करने और देश की अर्थव्यवस्था की समग्र स्थिति का अनुमान लगाने में मदद करता है। सामान्य तौर पर, उच्च प्रयोज्य आय होना फायदेमंद होता है क्योंकि यह व्यक्तियों को अधिक वित्तीय स्वतंत्रता और लचीलापन प्रदान करता है। हालांकि मुद्रास्फीति, रहने की लागत में वृद्धि और अप्रत्याशित व्यय जैसे कारक भी उपलब्ध डिस्पोजेबल आय की मात्रा को प्रभावित कर सकते हैं। व्यक्तियों के लिए यह महत्त्वपूर्ण है कि वे अपने वित्तीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिए अपनी प्रयोज्य आय और बजट की निगरानी करें।

1 अनिवार्य न्यूनतम सजा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली बेंच ने भारतीय दंड संहिता की धारा-376D की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली एक याचिका की जांच करने का फैसला किया। आईपीसी की इस धारा में 12 साल से कम उम्र की नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के लिए 'अनिवार्य न्यूनतम सजा' का प्रावधान करता है, वहीं धारा-376DB में 12 साल से कम उम्र की महिला से सामूहिक बलात्कार होने पर, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा का प्रावधान है।

अनिवार्य न्यूनतम सजा क्या है?

- मोहम्मद हाशिम बनाम यूपी राज्य और अन्य 2016 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय दिया गया था कि अनिवार्य न्यूनतम सजा का अर्थ ऐसी सजा से है जिसे अदालत में विवेक (Discretion) पर छोड़े बिना लगाया जाना चाहिए अर्थात सजा की मात्रा निर्धारित अवधि से कम न की जाये।
- अनिवार्य न्यूनतम सजा की अवधारणा मुख्य रूप से कनाडाई और अमेरिकी कानूनी प्रणालियों की देन है। भारत में इसे पहली बार 1983 के आपराधिक संशोधन अधिनियम द्वारा वर्णित किया गया था।
- भारत में यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम (POCSO) अधिनियम 2012 के तहत यौन उत्पीड़न के अपराध को छोड़कर सभी यौन अपराधों के लिए इस तरह की सजा निर्धारित है।
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 2019 के मध्य प्रदेश बनाम विक्रम दास मामले में कहा कि जब विधायिका ने विवेक के बिना न्यूनतम सजा निर्धारित की है तो न्यायपालिका इसे कम नहीं कर सकती है, चाहे वह कारावास हो या जुर्माना, यह अनिवार्य है।

न्यूनतम अनिवार्य सजा क्यों जरूरी है?

- इस अवधारणा के पक्ष में दिए गए तर्कों में कहा गया है कि यह न्यायिक विवेक और मनमानी के दायरे को सीमित करता है, जिससे न्याय के उद्देश्य में वृद्धि होती है तथा गंभीर अपराधों के अपराधी को सजा नहीं मिलती है।
- यह उन प्रावधानों को भी स्थापित करता है जो समाज में निवारक के रूप में कार्य करते हैं। यह देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में नैतिक विश्वास को भी बढ़ाता है।
- इसके विपरीत, कई कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इससे जेलों में क्षमता से अधिक भीड़ हो जाती है और एक अपराधी (यदि वे पहली बार अपराधी हैं या परिवार के एकमात्र कमाने वाले हैं) की कमजोर करने वाली परिस्थितियों पर भी भारी पड़ता है।
- इस तरह के प्रावधानों के अक्सर अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं क्योंकि न्यायाधीशों द्वारा उस मामले में निर्धारित सजा अत्यधिक कठोर होने के कारण अभियुक्तों को पूरी तरह से बरी कर दिया जाता है।
- इससे पहले तुकाराम और एएनआर बनाम महाराष्ट्र राज्य 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल की लड़की के सामूहिक बलात्कार में दो पुलिसकर्मियों को बरी कर दिया था।
- 2013 का आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, जिसने बलात्कार की परिभाषा का विस्तार किया जिसका अर्थ है अपराधी के पूरे शेष जीवन या 20 साल की न्यूनतम सजा होनी चाहिए।

आगे की राह:

धारा-376DB की समीक्षा में SC का निर्णय निश्चित रूप से देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करेगा लेकिन विलंबित परीक्षणों, अनैतिक जांच प्रथाओं और पीड़ितों की विनम्रता व गोपनीयता बनाए रखने के लिए गंभीर मामलों की संवेदनशील हैंडलिंग जैसे मुद्दों के समाधान के लिए न्यायपालिका को अन्य उपायों पर भी विचार करना चाहिए।

2 बच्चों और किशोरों में शारीरिक निष्क्रियता

चर्चा में क्यों?

हाल के एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि बच्चे और किशोर पर्याप्त शारीरिक गतिविधि नहीं कर रहे हैं। शारीरिक निष्क्रियता जो पुरानी बीमारी और विकलांगता की ओर ले जाती है, दुनिया भर में होने वाली मौतों का चौथा प्रमुख कारण है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें:

- अध्ययन में बताया गया है कि शारीरिक निष्क्रियता के कारण दुनिया में 2030 तक क्रोनिक इलनेस (Chronic illnesses) के लगभग आधे अरब नए मामले सामने आ सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने 5-17 वर्ष के बच्चों और किशोरों के लिए प्रति दिन औसतन 60 मिनट की मध्यम से तेज (Moderate to vigorous) शारीरिक गतिविधि की सिफारिश की है तथा मनोरंजक स्क्रीन (Recreational screen) समय 2 घंटे/दिन से अधिक नहीं बढ़ाया जाना चाहिए।
- शोध में चार अफ्रीकी देशों बोत्सवाना, इथियोपिया, दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे से डेटा एकत्र किया गया है। यह पाया गया है कि चार अफ्रीकी देशों के बच्चे और किशोर दुनिया के बाकी हिस्सों से थोड़ा अधिक शारीरिक रूप से सक्रिय थे। अफ्रीकी देशों के अधिक बच्चे तथा किशोर बाकी दुनिया की तुलना में अधिक शारीरिक रूप से फिट और सक्रिय थे। इसका कारण यह भी हो सकता है कि सस्ती परिवहन व्यवस्था के अभाव में बच्चे पैदल स्कूल जाने को मजबूर हों। यह बच्चों और किशोरों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे की कमी, सामुदायिक सुरक्षा व अपर्याप्त धन से संबंधित चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। उल्लेखनीय है कि यह डेटा इन देशों में सभी बच्चों और किशोरों का अध्ययन नहीं करता है।

कोविड-19 का प्रभाव:

- महामारी से पहले ही बच्चों और किशोरों के बीच शारीरिक गतिविधि अनुशंसित स्तरों से नीचे थी। 2016 में, 11-17 वर्ष की आयु के 81% किशोरों को शारीरिक रूप से निष्क्रिय (Inactive) माना गया था जिसमें लड़कियों की स्थिति चिंताजनक थी। महामारी ने स्थिति को और भी खराब कर दिया है। लॉकडाउन के कारण स्कूलों और सार्वजनिक पार्कों को बंद करने से बच्चों में शारीरिक गतिविधियों का स्तर बाधित हुआ है। शोध में पाया गया है कि महामारी के दौरान बच्चों के बीच शारीरिक गतिविधि में 17 मिनट/दिन की कमी आई है।

आगे की राह:

बच्चों के बीच शारीरिक गतिविधियों का स्तर कम होना एक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता है जो WHO की वैश्विक कार्य योजना में भी शामिल है। बच्चों को शारीरिक गतिविधियों में शामिल होने के समान अवसर प्रदान करने के लिए एक समग्र पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए। इसके अलावा सुरक्षित और मुफ्त पहुंच सुनिश्चित करने के लिए हरित स्थान, सार्वजनिक पार्क, खेल सुविधाएं विकसित की जानी चाहिए।

3 बिना सलाखों वाली जेलें

चर्चा में क्यों?

हाल ही में लगभग 40 ओपन एयर कैम्प्स के साथ राजस्थान सरकार ने सुधारात्मक न्याय की दिशा में एक अच्छा कार्य किया है।

ओपन एयर कैम्प्स क्या हैं?

- ओपन एयर कैम्प्स या खुली जेलों की अवधारणा कोई नई नहीं है। यह पहली बार 1955 में अपराध की रोकथाम और अपराधियों के उपचार पर संयुक्त राष्ट्र कांग्रेस में चर्चा की गई थी। इसके बाद, कैदियों के उपचार के लिए संयुक्त राष्ट्र मानक न्यूनतम नियमों में खुली जेलों के गठन का प्रावधान था जो कैदियों के आत्म-अनुशासन के आधार पर कार्य करे।
- बाद में, जेल सुधार पर अखिल भारतीय समिति ने प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में खुली जेलों की स्थापना की सिफारिश की।
- खुली जेल न्यूनतम संयम के साथ एक दंड प्रतिष्ठान है जो स्व-शासन और आत्म-अनुशासन के सिद्धांत पर काम करता है। इसके पात्रता मानदंड राज्यों द्वारा परिभाषित किए जाते हैं। राजस्थान में दोषी जिन्होंने अच्छे आचरण और कुछ अपवादों जैसे महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगों आदि के अधीन अपनी सजा का 1/3 पूर्ण किया है, वे इसके पात्र होंगे।
- दोषियों को अपने परिवार के साथ रहने और अपनी आजीविका कमाने की अनुमति होती है। ऐसी जेलों के आंतरिक प्रबंधन के लिए 'कैदी पंचायत', कार्य, अनुशासन समिति और कैदी सहकारी समितियां होती हैं।

उपयोगिता:

- प्रिजन स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया 2020 के अनुसार, भारतीय जेलों में 76% विचाराधीन कैदी हैं। इसके अलावा, देश की जेलों में उनकी क्षमता का 118% भीड़ है, जिसमें 3.81 लाख से कम क्षमता के मुकाबले 4.33 लाख कैदी हैं। ऐसे परिदृश्य में, खुली जेलों से भीड़भाड़ वाली जेलों के बोझ को कम करने में मदद मिलती है।
- यह प्रति कैदी 500 रुपये प्रति माह की न्यूनतम लागत के साथ अत्यधिक लागत प्रभावी है। यह बंद जेलों की तुलना में 78 गुना सस्ता है। इसके अलावा, इन्हें स्थापित करना आसान है क्योंकि इसके लिए विशाल परिसर क्षेत्र की आवश्यकता नहीं होती है। इन्हें बंद जेल या 'कैदी गांव' की चारदीवारी से जुड़े छोटे समूहों के रूप में भी बनाया जा सकता है।
- परिवार के साथ रहना सुधार की प्रक्रिया में सहायता करता है, उन्हें अधिक नियम का पालन करने और उनकी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को संबोधित करने में मदद करता है। उनकी आजीविका कमाने से उनमें विश्वास पैदा होता है और उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाती है।
- यह प्रणाली विशेष मामलों जैसे गर्भवती महिलाओं या छोटे बच्चों, वृद्धों, दिव्यांगों और छोटे अपराधियों वाली महिलाओं में अत्यधिक प्रभावी है।

आगे की राह:

खुली जेलें 'हाफ वे होम्स' की तरह हैं जिनका उद्देश्य प्रतिशोधी और सुधारात्मक न्याय के बीच संतुलन बनाना है। इस प्रणाली को पूरे देश में विस्तारित किया जाना चाहिए और जेल सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए विचाराधीन कैदियों पर भी लागू किया जाना चाहिए।

4 माइक्रोसॉफ्ट का प्रोजेक्ट एलोरा

चर्चा में क्यों?

इस परियोजना के तहत माइक्रोसॉफ्ट के शोधकर्ता उन भारतीय भाषाओं के लिए डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं जिनकी ऑनलाइन उपस्थिति पर्याप्त नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च ने तीन भाषाओं (गोंडी, मुंडारी और इदु मिश्मी) को चयनित किया है। माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च भारत में अपने प्रोजेक्ट एलोरा के साथ 'दुर्लभ' भारतीय भाषाओं को संरक्षित करने में मदद कर रहा है।

प्रोजेक्ट एलोरा (Ellora):

- 'दुर्लभ' भारतीय भाषाओं को ऑनलाइन लाने के लिए, माइक्रोसॉफ्ट ने 2015 में प्रोजेक्ट एलोरा या कम संसाधन भाषाओं को सक्षम करने की शुरुआत की। इस परियोजना के तहत शोधकर्ता भाषाओं के डिजिटल संसाधनों का निर्माण कर रहे हैं। उनका उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों के लिए एक भाषा को संरक्षित करना है ताकि इन भाषाओं के उपयोगकर्ता डिजिटल दुनिया में भाग ले सकें और बातचीत कर सकें।
- वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के पूर्वी भारतीय राज्यों में फैले लगभग दस लाख लोगों के मुंडा समुदाय के साथ काम कर रहा है।

एलोरा भाषा डेटासेट की प्रक्रिया:

- शोधकर्ता अपने एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने में डेटासेट बनाने के लिए मुद्रित साहित्य सहित संसाधनों की मैपिंग कर रहे हैं।
- टीम इन समुदायों के साथ परियोजना पर भी काम कर रही है।
- डेटा संग्रह प्रक्रिया में समुदाय को शामिल करके, शोधकर्ता एक ऐसा डेटासेट बनाने की उम्मीद करते हैं जो सटीक और सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक दोनों हो।

प्रोजेक्ट एलोरा का मुख्य उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य आर्थिक अवसरों का निर्माण करना, तकनीकी कौशल का निर्माण करना, शिक्षा को बढ़ाना और भावी पीढ़ियों के लिए स्थानीय भाषाओं और संस्कृतियों को संरक्षित करना भाषा प्रौद्योगिकी को सक्षम करके वंचित समुदायों को प्रभावित करना है।

आगे की राह:

माइक्रोसॉफ्ट का प्रोजेक्ट एलोरा गोंडी, मुंडारी जैसी छोटी भाषाओं को डिजिटल दुनिया में वाक्पटु बनने में मदद करना, स्वागत योग्य है। हालांकि स्कूलों में बच्चों को केवल बंगाली, हिंदी और उड़िया जैसी प्रमुख भाषाएं सिखाई जाती हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट से न केवल स्थानीय भाषाओं का विस्तार होगा बल्कि यह भविष्य के लिए संस्कृतियों को संरक्षित करने में भी मदद करेगा।

5 मुगल उद्यान का नया नाम अमृत उद्यान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रपति भवन उद्यान जिसे मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता था, का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत गार्डन का नाम बदला गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर, भारत के राष्ट्रपति भवन उद्यान को अमृत उद्यान के रूप में नाम दिया हैं। हर साल मुगल गार्डेन आम लोगों के लिए खोला जाता है। इस बार यह 31 जनवरी से 26 मार्च तक दो माह तक के लिए खुला रहेगा।

मुगल उद्यान से संबंधित महत्त्वपूर्ण बिंदु:

- एडविन लुटियंस ने 1917 में मुगल गार्डन को डिजाइन दिया था, लेकिन 1928-1929 के दौरान इसे अंतिम रूप दिया गया। लुटियंस, ने उद्यानों के लिए दो अलग-अलग बागवानी परंपराओं (मुगल शैली और अंग्रेजी फूलों का बगीचा शैली) को एक साथ लाए।
- इसके चार दीवारों में छज्जा (ड्रिपस्टोन), छतरी (गुंबददार खोखा), जाली (छिद्रित स्क्रीन) और कई अन्य भारतीय स्थापत्य का अच्छा इस्तेमाल किया गया है।
- मुगल नहरों, छतों और फूलों की झाड़ियों को यूरोपीय फूलों की क्यारियों, लॉन तथा निजी हेजेज के साथ खूबसूरती से मिश्रित किया गया है।
- प्रतिष्ठित उद्यान 15-एकड़ में फैला हुआ है। मुख्य उद्यान में दो चैनल हैं जो समकोण पर मिलते हैं और बगीचे वर्गों के ग्रिड में विभाजित हैं। चारबाग (चार कोनों वाला बगीचा) मुगल भूनिर्माण की एक विशिष्ट शैली थी। इन नहरों के चौराहे पर 12 फीट की ऊंचाई तक छह कमल के आकार के फव्वारे हैं। उद्यान में डहलिया की लगभग 2500 किस्में और गुलाब की 120 किस्में हैं।
- 1911 में, अंग्रेजों ने भारतीय राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली में स्थानांतरित करने का फैसला किया जिसमें एक पूरे नए शहर (नई दिल्ली) का निर्माण शामिल था।
- वायसराय हाउस के निर्माण के लिए लगभग 4,000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था, जिसमें सर एडविन लुटियंस को रायसीना हिल पर इमारत को डिजाइन करने का काम दिया गया था। लुटियंस के डिजाइन में भारतीय शैलियों के साथ शास्त्रीय यूरोपीय वास्तुकला के संयुक्त तत्व शामिल थे।
- इसी योजना के तहत पारंपरिक ब्रिटिश संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए मुगल गार्डन बनाया गया था।

6 हैदराबाद में ACIC-CBIT रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप फाउंडेशन का उद्घाटन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में डॉ. चिंतन वैष्णव (जो अटल इनोवेशन मिशन के निदेशक हैं) ने हैदराबाद में ACIC-CBIT केंद्र का उद्घाटन किया। इस केन्द्र ने इंफ्रास्ट्रक्चर, मानसिक स्वास्थ्य, बाजरा निर्माण और अपस्किलिंग रूरल इनोवेटर्स जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे चार स्टार्टअप फाउंडर्स से बातचीत के रूप में पहले स्टार्टअप 20एक्स कार्यक्रम की मेजबानी की।

एसीआईसी-सीबीआईटी के बारे में:

उद्देश्य-

- ACIC-CBIT की स्थापना एक सामुदायिक नवाचार तथा उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के उद्देश्य से की गई है ताकि नवप्रवर्तकों, असेवित और कम सेवा वाले क्षेत्रों के स्टार्ट-अप का पोषण किया जा सके।
- एसीआईसी का मानना है कि एक मजबूत सामुदायिक नवाचार

पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में विशेषज्ञ सलाहकारों को शामिल करना, ढांचागत समर्थन जैसे- निर्माता स्थान, वित्त पोषण सुविधा, प्रशिक्षण और परामर्श शामिल है।

सेक्टोरल फोकस क्षेत्र-

- हेल्थ-टेक।
- एआई/एमएल/आईओटी आधारित स्मार्ट इंजीनियरिंग उत्पाद।
- नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरणीय स्थिरता।

लक्षित एसडीजी-

- अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण (SDG3)
- उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा (SDG9)
- सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज (SDG1)

अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) के बारे में:

- AIM नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग का प्रयास है।
- इसकी शुरुआत नीति आयोग द्वारा 2016 में की गई थी।
- **उद्देश्य-** विशेष रूप से प्रौद्योगिकी संचालित क्षेत्रों में विश्व स्तरीय नवाचार केंद्रों, भव्य चुनौतियों, स्टार्ट-अप व्यवसायों और अन्य स्वरोजगार गतिविधियों के प्रचार के लिए एक मंच के रूप में सेवा प्रदान करना।
- एआईएम के तहत स्कूलों में रचनात्मक, नवोन्मेषी मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की गई है।
- एआईएम द्वारा विश्वविद्यालयों में अटल इन्क्यूबेशन केंद्रों की स्थापना की गई है ताकि स्टार्ट-अप और उद्यमियों का एक सतत विकसित पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया जा सके।

नीति आयोग के बारे में:

- 2015 में तत्कालीन योजना आयोग को नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (NITI Aayog) द्वारा बदल दिया गया था।
- यह सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है जिसके गवर्निंग काउंसिल में केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर और राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं।
- यह प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देता है। नीति आयोग ने ऑनलाइन डैशबोर्ड तैयार किए हैं जो राज्यों को एसडीजी इंडिया इंडेक्स, हेल्थ इंडेक्स इत्यादि जैसे विकास के विभिन्न संकेतकों पर रैंक करते हैं।

आगे की राह:

कोई भी समुदाय समाज में बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जमीनी स्तर से नवप्रवर्तकों को प्रेरित करना देश भर में एक समावेशी स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का एक अनिवार्य हिस्सा है। नए केंद्र के खुलने से युवाओं को अपने उद्यमिता कौशल को निखारने में मदद मिलेगी।

7 कीलाडी उत्खनन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कीलाडी में खुदाई से पता चला है कि संगम युग 800 ईसा पूर्व से भी पहले का था, जो पहले माना जाता था कि यह 300 ईसा पूर्व का है। कीलाडी में खुदाई से साबित होता है कि वैगई नदी के तट पर संगम युग में तमिलनाडु में एक शहरी सभ्यता मौजूद थी।

कीलाडी उत्खननः संगम युग 800 ईसा से भी पुराना

- उत्खनन में प्राप्त हुए पुरावशेष छठी शताब्दी ईसा पूर्व से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व और उसके बाद के सांस्कृतिक विकास के लिए लौह युग (12 वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6 वीं शताब्दी ईसा पूर्व) के महत्त्वपूर्ण कड़ी उपलब्ध कराते हैं।
- नई रिपोर्ट इसे 800 ईसा पूर्व और 300 सीई के बीच संगम युग को पुनर्स्थापित करती है। इस काल को भी तीन कालों में वर्गीकृत किया गया है। 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच पूर्व-प्रारंभिक ऐतिहासिक काल, 500 ईसा पूर्व से पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत तक प्रारंभिक इतिहास और पहली शताब्दी ईसा पूर्व से 300 सीई के प्रारंभिक इतिहास के बाद का इतिहास।
- कीलाडी के स्थलों में मिले भित्ति चित्र सिंधु घाटी सभ्यता और दक्षिण भारत के बीच एकमात्र अवशिष्ट कड़ी के रूप में काम करते हैं। कीलाडी के बर्तनों में पाए गए कुछ प्रतीकों में सिंधु घाटी के संकेतों के समान समानता है।

महत्त्वपूर्ण बिंदुः

- **साक्षर समाजः** तमिल ब्राह्मी लिपि उत्खनन में प्राप्त हुए बर्तनों पर पाए गए हैं जो बर्तन के गीले होने पर या बर्तन के सूख जाने के बाद खुदे हुए थे।
- **व्यापारी वर्गः** रिपोर्ट के अनुसार, क्षेत्र की उपजाऊ प्रकृति तथा पशुपालन ने इसके विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे चावल के अधिक उत्पादन और निवासियों के समुद्री व्यापार का मार्ग प्रशस्त हुआ।
- **कृषि समाजः** उत्खनन में गाय/बैल, भैंस, भेड़, बकरी, नीलगाय, काला हिरण, जंगली सूअर और मोर के कंकाल के टुकड़े आदि पाए गए।
- **उच्च जीवन स्तरः** लंबी दीवारें, टूटी हुई अवस्था में छत की टाइलों के साथ अच्छी तरह से बिछाए गए फर्श, खंभों पर लोहे की कीलें और छतें संगम युग के दौरान उच्च जीवन स्तर को साबित करती हैं।
- **मिली वस्तुएँः** ईंट की संरचनाएँ, टेराकोटा रिंग कुएँ, टाइलों के साथ गिरी हुई छत, सोने के आभूषण, तांबे की सुई, तांबे की वस्तुओं के टूटे हुए हिस्से, लोहे के औजार, टेराकोटा शतरंज के टुकड़े, कान के गहने, तकली की फुहारें, मूर्तियाँ, काले तथा लाल बर्तन, रूलेट वाले बर्तन और कुछ टुकड़े कांच, टेराकोटा, अर्ध-कीमती पत्थरों से बने मनकों के अलावा अरेटिन के बर्तन।
- **भित्तिचित्रों के निशानः** मिट्टी के बर्तनों, गुफाओं और चट्टानों में या उत्खनन स्थलों के पास पाए गए हैं।

राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की महत्त्वपूर्ण खबरें

1. ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला पहला सिविक बॉडी बना इंदौर

हाल ही में, इंदौर नगर निगम, (लगातार छह वर्षों तक स्वच्छता सर्वेक्षण में शीर्ष स्थान) अपने जल पम्पिंग स्टेशन पर 60 मेगावाट सौर संयंत्र के लिए 244 करोड़ रुपये जुटाने की मांग करते हुए ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय बन गया है।

ग्रीन बांड का क्या अर्थ है?

ग्रीन बांड एक प्रमुख अंतर के साथ नियमित बांड की तरह काम करते हैं: निवेशकों से जुटाई गई धनराशि का उपयोग विशेष रूप से उन परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाता है जिनका सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव होता है, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा और हरित भवन। ग्रीन बॉन्ड फंड का उपयोग जलवायु पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं और वित्त पोषण के लिए किया जाता है।

2. बार हेडेड गूज

बार-हेडेड गूज, जिसे जुलाई 2014 में मंगोलिया में टैग किया गया था, को तिरुनेलवेली जिले के कुंथनकुलम - कदनकुलम पक्षी अभयारण्य में देखा गया है।

मुख्य विशेषताएं:

- यह इस अभयारण्य में नियमित रूप से आने वाले शीतकालीन प्रवासी पक्षी प्रजातियों में से एक है।
- इसकी विशिष्ट काली पट्टियों के साथ सफेद और भूरे रंग के पंखों, सिर और नारंगी-पीली चोंच और पैर से इसकी पहचान की जा सकती है।
- बार-हेडेड गूज एक दिन में 1,600 किमी से अधिक की दूरी तय कर सकता है।
- यह हिमालय में दो बार वार्षिक प्रवास के दौरान 29,500 फीट की चरम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए जाना जाता है।
- यह मध्य एशिया में पहाड़ी झीलों के पास हजारों की कॉलोनियों में और दक्षिण एशिया में सर्दियों में, प्रायद्वीपीय भारत में प्रजनन करती है।
- यह एक बार में तीन से आठ अंडे देती है।
- संरक्षण स्थिति: आईयूसीएन लाल सूची- लीस्ट कंसर्न

3. बर्फ का एक नया प्रकार

वैज्ञानिकों ने एक नए प्रकार की बर्फ बनाई है जो घनत्व और संरचना में जल के समान है। यह खोज जल के रहस्यमय गुणों का अध्ययन करने का मार्ग प्रशस्त करेगी।

मुख्य बिंदु:

- इस बर्फ को मध्यम-घनत्व वाली आकृतिहीन बर्फ कहा गया है।
- वैज्ञानिको ने इस वैरिएंट को तैयार करने के लिए (-) 200 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर स्टेनलेस स्टील की गेंदों वाले एक छोटे कंटेनर में रखा, फिर सामान्य बर्फ की तरह हिलाया। इस कंटेनटर में बर्फ एक सफेद दानेदार पाउडर के रूप में दिखाई दी जो धातु के गोले से चिपक गई।
- आम तौर पर, जब पानी जमता है, यह क्रिस्टलीकृत होता है और इसके अणु हेक्सागोनल के ठोस संरचना में व्यवस्थित होते है जिसे बर्फ कहा जाता है।
- बर्फ अपने तरल रूप से कम घनी होती है, जो क्रिस्टल के लिए एक असामान्य गुण है। दबाव और जमने की गति जैसी स्थितियों के आधार पर, पानी दो दर्जन अन्य नियमित व्यवस्थाओं में से किसी में भी जम सकता है।
- आकृतिहीन बर्फ में क्रम की अनुपस्थिति होने के कारण यह सामान्य बर्फ से अलग मानी गई है।

4. ग्रीन डील औद्योगिक योजना

हाल ही में यूरोपीय संघ ने अपने हरित उद्योग का समर्थन और विस्तार करने के लिए, 'ग्रीन डील औद्योगिक योजना' की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु:

- ग्रीन डील इंडस्ट्रियल प्लान का उद्देश्य लालफीताशाही में कटौती कर बड़े पैमाने पर सब्सिडी प्रदान करना है।
- यह कदम संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रास्फीति में कमी अधिनियम (IRA) घोषणा के कुछ महीने बाद आया है ।
- IRA, यूएस-आधारित विनिर्माण के लिए प्रोत्साहन के साथ स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन कार्यक्रमों के लिए अरबों डॉलर की कर कटौती का प्रावधान करता है।

ग्रीन डील औद्योगिक योजना:

- प्रस्ताव में एक सरल नियामक ढांचा का निर्माण शामिल है।
- योजना 'नेट-जीरो इंडस्ट्री एक्ट' तैयार करना चाहती है।
- यह नियमों को सरल करेगा और हरित परियोजनाओं के लिए परमिट जारी करने में तीव्रता लाएगा।
- इसमें एक 'महत्त्वपूर्ण रॉ मटेरियल एक्ट' शामिल है, जो शुद्ध-शून्य प्रौद्योगिकी के विकास के लिए महत्त्वपूर्ण रेयर अर्थ जैसी सामग्री तक पहुंच प्रदान करेगा।
- यूरोपीय संघ की 27 सरकारों को स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश करने में मदद करने के लिए राज्य सहायता नियमों को लचीला किया जाएगा।
- इस योजना का उद्देश्य 'नेट-जीरो उद्योग अकादमियों' की स्थापना करना है जो रणनीतिक उद्योगों में अप-स्किलिंग और री-स्किलिंग कार्यक्रम प्रदान करना भी है।
- यह 'यूरोपीय संघ के मुक्त व्यापार समझौतों के नेटवर्क को विकसित करने और हरित संक्रमण का समर्थन करने के लिए भागीदारों के साथ सहयोग के अन्य रूपों को विकसित करेगा।

5. भारत ऊर्जा सप्ताह 2023

हाल ही में प्रधानमंत्री ने E20 ईंधन लॉन्च किया तथा ग्रीन मोबिलिटी रैली को हरी झंडी दिखाई।

मुख्य बिंदु:

- प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु, कर्नाटक में भारत ऊर्जा सप्ताह (IEW) 2023 का उद्घाटन किया।
- आईईडब्ल्यू का उद्देश्य एक ऊर्जा परिवर्तन महाशक्ति के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति को प्रदर्शित करना है।
- कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, उन्होंने तेल और गैस पीएसयू और पीएलएल की ओर से हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा आयोजित ई20 ईंधन का शुभारंभ किया और ग्रीन मोबिलिटी रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया।

E-20 ईंधन:

- इथेनॉल सम्मिश्रण रोडमैप के अनुरूप, प्रधानमंत्री ने 11 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में तेल विपणन कंपनियों के 84 रिटेल आउटलेट्स पर E20 ईंधन लॉन्च किया। E20 पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल का मिश्रण है।
- सरकार का लक्ष्य 2025 तक इथेनॉल के पूर्ण 20% सम्मिश्रण को प्राप्त करना है।
- इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम और जैव ईंधन कार्यक्रम ने न केवल भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाया है बल्कि इसके परिणामस्वरूप 318 लाख मीट्रिक टन CO2 उत्सर्जन में कमी आई है।

6. याया त्सो झील

हाल ही में, याया त्सो झील को लद्दाख की पहली जैव विविधता विरासत स्थल (बीएचएस) के रूप में प्रस्तावित किया गया है।

मुख्य विशेषताएं:

- याया त्सो, 4,820 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है।
- याया त्सो, पक्षियों और जानवरों की एक बड़ी संख्या के लिए आवास है, जैसे कि बार हेडेड गूज, ब्लैक नेक्ड क्रेन और बत्तख।
- इसे भारत में काली गर्दन वाले क्रेन के उच्चतम प्रजनन स्थलों में से एक होने का गौरव भी प्राप्त है।

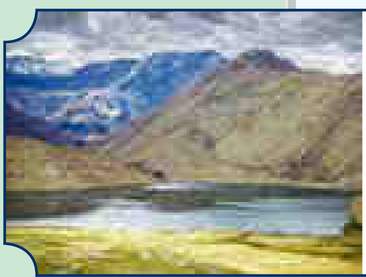

7. आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD)

हाल ही में, गुजरात सरकार ने सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन (PISA) परीक्षा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

मुख्य विशेषताएं:

- पीआईएसए वास्तविक जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए, गणित और विज्ञान के ज्ञान और कौशल का उपयोग करने की 15 वर्षीय बच्चों की क्षमता का मापन करता है।
- यह इस आयु वर्ग के छात्रों को 'महत्वपूर्ण सोच, समस्या समाधान और प्रभावी संचार' का भी परीक्षण करता है।
- इस तरह के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला गुजरात, देश का पहला राज्य है।

ओईसीडी के बारे में:

- OECD की स्थापना 14 दिसंबर, 1960 को 18 यूरोपीय देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा द्वारा की गई थी।
- इसका मुख्यालय पेरिस (फ्रांस) में स्थित है।
- यह 38 सदस्य देशों का एक समूह है जो आर्थिक और सामाजिक नीति पर चर्चा और विकास करता है।
- ओईसीडी के सदस्य आमतौर पर लोकतांत्रिक देश हैं जो मुक्त बाजार अर्थव्यवस्थाओं का समर्थन करते हैं।
- अधिकांश ओईसीडी सदस्य उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनका मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) बहुत अधिक है और उन्हें विकसित देश माना जाता है।
- 2017 में OECD के सदस्य देशों में सामूहिक रूप से वैश्विक नाममात्र GDP का 62.2% (US$49.6 ट्रिलियन) और वैश्विक वास्तविक GDP का 42.8% ($54.2 ट्रिलियन) का प्रतिनिधित्व करते थे।
- OECD का घोषित लक्ष्य उन नीतियों को आकार देना है जो सभी के लिए समृद्धि, समानता, अवसर और कल्याण को बढ़ावा देती हैं।
- ओईसीडी संयुक्त राष्ट्र का एक आधिकारिक स्थायी पर्यवेक्षक है और इसे थिंक-टैंक या निगरानी समूह के रूप में संदर्भित किया जाता है।
- भारत उन कई गैर-सदस्य अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जिनके साथ ओईसीडी के कार्यकारी संबंध हैं।

8. लाल सिर वाला गिद्ध (रेड हेडेड वल्चर)

हाल ही में, 2017 के बाद पहली बार, दिल्ली के भट्टी खदान क्षेत्र में एक लाल सिर वाले गिद्ध (Sarcogyps Calvus) को देखा गया।

मुख्य विशेषताएं:

- ध्यातव्य है कि इसी सप्ताह गुरुग्राम के चंदू बुधेरा में एक 'दुर्लभतम' काला गिद्ध (कोराजिप्स एट्रेटस) देखा गया था।
- असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य (एबीडब्ल्यूएस) में हर साल बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (बीएनएचएस) द्वारा किए जाने वाले चल रहे शीतकालीन रैप्टर सर्वेक्षण के दौरान इस पक्षी को देखा गया था।
- मध्य, उत्तरी और पूर्वी भारत के 13 राज्यों में लंबे समय तक गिद्धों की आबादी के सर्वेक्षण से पता चलता है कि डाइक्लोफेनाक पर प्रतिबंध लगने के बाद से पक्षी की आबादी में कमी स्थिर हो गई है।
- डिक्लोफेनाक इन पक्षियों के लिए जहरीली दवा है जिसे 2006 में पशु चिकित्सा उपयोग के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था।

लाल सिर वाला गिद्ध (रेड हेडेड वल्चर):

- लाल सिर वाले गिद्ध को एशियाई राजा गिद्ध, भारतीय काले गिद्ध या पांडिचेरी गिद्ध के रूप में भी जाना जाता है।
- यह एक पूर्व काल से पाया जाने वाले का गिद्ध है जो दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में छोटी अलग आबादी के साथ, मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है।
- इसकी संख्या 10,000 से कम है।

संरक्षण की स्थिति:

- IUCN रेड लिस्ट- गंभीर रूप से संकटग्रस्त।
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972- अनुसूची 1।

9. आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट कार्यक्रम

हाल ही में आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की गई है।

मुख्य विशेषताएं:

- भारत केला, आम, अनार और पपीता जैसे कई फलों का शीर्ष उत्पादक है, परन्तु उपज की खराब गुणवत्ता के कारण निर्यात में इनकी भागीदारी नगण्य है। उदाहरण के लिए वैश्विक केले के उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 27 प्रतिशत है, लेकिन निर्यात में हिस्सेदारी लगभग 1 प्रतिशत ही है।
- अब बागवानी फसलों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली और रोगमुक्त सामग्री तैयार करने के लिए वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर स्वच्छ पौधा कार्यक्रम की घोषणा की।
- कार्यक्रम राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा आयोजित किया जाएगा जो बदले में देश भर में क्लीन प्लांट केंद्र स्थापित करेगा।
- ये केंद्र भारतीय बागवानी क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए रोग मुक्त बागवानी रोपण सामग्री तक पहुंच सुनिश्चित करेंगे।
- स्वच्छ पौधा कार्यक्रम का उद्देश्य बागवानी फसलों की उपज में वृद्धि करना, जलवायु अनुकूल किस्मों का प्रसार और अपनाना, सक्रिय वायरस और रोग नियंत्रण उपायों के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना है।

10. यंत्रीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना (नमस्ते)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE) ने 'यंत्रीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना' (NAMASTE) एक योजना तैयार की है।

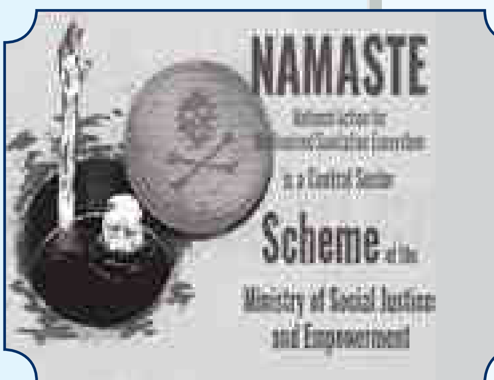

National Action for Mechanized Sanitation Ecosystem (NAMASTE) के बारे में:

सभी यूएलबी में लागू की जाने वाली योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

- नमस्ते योजना के अंतर्गत सीवर/सेप्टिक टैंक श्रमिकों (एसएसडब्ल्यू) की पहचान करने की योजना है जिसमें एसएसडब्ल्यू को व्यावसायिक प्रशिक्षण और पीपीई किट का वितरण भी शामिल है।
- स्वच्छता प्रतिक्रिया इकाइयों (एसआरयू) को सुरक्षा उपकरणों के लिए सहायता प्रदान करना।
- आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत चिन्हित एसएसडब्ल्यू और उनके परिवारों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देना।
- सफाई कर्मचारियों को, स्वच्छता संबंधी उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता और सब्सिडी (पूंजी) प्रदान करके मशीनीकरण और उद्यम विकास को बढ़ावा देना।

यह पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय का एक संयुक्त उद्यम है।

महत्व:

- यह योजना विशेष रूप से सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों (एसएसडब्ल्यू) की मृत्यु को रोकने के लिए है। यह सफाई में जोखिमों को कम करने और स्वच्छता कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से सफाई कार्यों के मशीनीकरण को बढ़ावा देगा।

11. ऑपरेशन 'नार्कोस' और ऑपरेशन एएएचटी

- रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने जनवरी 2023 के में एक माह तक देशव्यापी अभियान ऑपरेशन 'नारकोस' और ऑपरेशन आहट चलाया।
- ऑपरेशन आहट के तहत, तस्करों के चंगुल से पीड़ितों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों को बचाने पर ध्यान देने के साथ सभी लंबी दूरी की ट्रेनों/मार्गों पर विशेष टीमों को तैनात किया गया है।
- इसके अतिरिक्त, बल के बुनियादी ढांचे और खुफिया नेटवर्क का उपयोग पीड़ितों, स्रोत, मार्ग, गंतव्य, संदिग्धों द्वारा उपयोग की जाने वाली लोकप्रिय ट्रेनों, वाहकों/एजेंटों की पहचान, किंगपिन आदि पर सुराग एकत्र करने, तुलना करने और उनका विश्लेषण करने के लिए किया जाता है, जो फिर अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साझा किया जाता है।
- ऑपरेशन नारकोस -मादक पदार्थों और मनोसक्रिय पदार्थों के खतरे की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए, रेल के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान इस कोड नाम के तहत शुरू किया गया था।

समसामयिकी घटनाएं एक नजर में

1. वरिष्ठ पत्रकार डॉ. ऐनी भवानी कोटेश्वर प्रसाद को प्रतिष्ठित पीसीआई के राजा राम मोहन रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है।
2. इंडिया हेल्थ लिंक ने हेल्थ एटीएम स्थापित करने के लिए अपने इन्वेस्टअप कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
3. स्थायी खाद्य उत्पादन के हिस्से के रूप में दालों के पोषण और पर्यावरणीय लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया।
4. स्काई एयर ने भारत में 'स्काई यूटीएम' नामक एक ड्रोन-आधारित यातायात प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया।
5. नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) द्वारा रिपोर्ट 'मेकिंग इंडिया ए ग्लोबल पावर हाउस ऑन फार्म मशीनरी इंडस्ट्री' शीर्षक के साथ जारी की गई। इस रिपोर्ट का उद्देश्य नीति निर्माताओं को भारत में गैर-ट्रैक्टर कृषि मशीनरी उद्योग के विकास को बढ़ावा देना है।
6. तेलंगाना सरकार ने मोबिलिटी नेक्स्ट हैदराबाद समिट 2023, तेलंगाना के पहले संस्करण के दौरान भारत का पहला मोबिलिटी-केंद्रित क्लस्टर, तेलंगाना मोबिलिटी वैली (TMV) लॉन्च किया।
7. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और उनके अमेरिकी समकक्ष जेक सुलिवन ने क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी (iCET) और इनोवेशन ब्रिज पर यूएस-इंडिया पहल की शुरुआत की।
8. अडानी समूह ने 1.2 बिलियन अमरीकी डालर में के इजराइल के रणनीतिक हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है।
9. पूर्व पीएम डॉ मनमोहन सिंह (भारत) को लंदन में इंडिया-यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफटाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया।
10. इक्वेटोरियल गिनी के राष्ट्रपति, तियोदोरो ओबियांग न्गुएमा माबासोगो ने मैनुएला रोका बोटे को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है।
11. विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया गया जिसकी थीम 'इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन' थी।
12. जैविक विविधता अधिनियम के तहत याया त्सो झील को लद्दाख की पहली जैव विविधता विरासत स्थल (बीएचएस) के रूप में प्रस्तावित किया गया है।
13. इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार विकास प्रतिष्ठान (एलआरडीई) ने अंतरिक्ष रडार के लिए एक प्रमुख उपप्रणाली विकसित की है, जजो इसरो और सेना के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
14. सरकार ने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है। पीएम कुसुम योजना को सौर पंपों और ग्रिड से जुड़े सौर और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा ऊर्जा संयंत्रों (आरईपीपी) की स्थापना के उद्देश्य से शुरू किया गया है।
15. दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (DCPCR) ने 'बाल मित्र' नाम से अपना व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया।
16. विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को कैंसर के बारे में जागरूकता पैदा करने और इसकी पहचान, रोकथाम और उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया गया जिसकी थीम 'Uniting our Voices and taking Action' थी।
17. 6 फरवरी 2023 को लखनऊ में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा 6वीं शंघाई सहयोग संगठन (SCO), सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस (SAI) नेताओं की बैठक की मेजबानी की गई।
18. रिलायंस रिटेल, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसे डिजिटल रुपी के नाम से भी जाना जाता है, पेश करने वाला पहला भारतीय रिटेलर बन गया है।
19. भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने रक्षा, परमाणु ऊर्जा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में एक औपचारिक त्रिपक्षीय सहयोग पहल की घोषणा की।
20. विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा। इसमें पीवीटीजी परिवारों और पर्यावासों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, सड़क तथा दूरसंचार संपर्कता और संधारणीय आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह उपलब्ध कराई जाएंगी।

1. आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में

- केंद्रीय बजट से पहले संसद में पेश किया गया आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय का प्रमुख दस्तावेज है।
- आर्थिक सर्वेक्षण में पिछले एक साल में भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है।
- आर्थिक सर्वेक्षण अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति की झलक भी प्रदान करता है, और कभी-कभी आर्थिक दृष्टिकोण में अंतर्दृष्टि भी प्रदान करता है।
- हालांकि संविधान, सरकार को आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने के लिए बाध्य नहीं करता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में, हर सरकार के लिए केंद्रीय बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश करना आम बात हो गई है।

2. आर्थिक सर्वेक्षण के लेखक

आर्थिक सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है और केंद्रीय बजट की घोषणा से एक दिन पहले संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाता है।

3. आर्थिक सर्वेक्षण का महत्व

- आर्थिक सर्वेक्षण का महत्व इसलिए है क्योंकि यह आम लोगों को देश के आर्थिक मामलों की स्थिति से परिचय के साथ उन्हें सरकार के प्रमुख आर्थिक निर्णयों से भी अवगत कराता है जो उनके जीवन को काफी हद तक प्रभावित करते हैं।
- आर्थिक सर्वेक्षण सरकार को नीतिगत बदलावों की भी सिफारिश करता है, जो हालांकि, बाध्यकारी नहीं हैं बल्कि राष्ट्रीय नीतियों को तैयार करने में केवल एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं।
- इसमें देश के आर्थिक विकास और प्रक्षेपण को रेखांकित करने वाले कारणों के बारे में पूर्वानुमान शामिल हैं।

आर्थिक सर्वेक्षण

4. अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण का एक संक्षिप्त इतिहास

- पहला आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था।
- 1964 तक, इसे केंद्रीय बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन बाद में बजट प्रस्तावों की बेहतर समझ देने के लिए इसे केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया।
- जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण में देश के आर्थिक विकास का विस्तृत विश्लेषण और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित बहुत सारे डेटा शामिल हैं, यह पृष्ठभूमि ज्ञान प्रदान करने वाले एक उपयोगी उपकरण के रूप में काम करता है।
- पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने 2018 में पहली बार गुलाबी रंग में दस्तावेज जारी किया था।
- यह विचार उन महिलाओं का समर्थन करने के लिए था जो हिंसा का शिकार होती हैं। जिसका उद्देश्य लैंगिक समानता के लिए जोर देना था।
- केवल दस्तावेज का रंग ही नहीं, उसने उद्धरण और अतिरिक्त जानकारी के साथ इसे और अधिक रोचक बनाकर पूरे दस्तावेज को नया रूप दिया गया है।

- यह पहली बार था कि आर्थिक सर्वेक्षण ने भारत के भीतर राज्यों में माल और लोगों के प्रवाह को देखने के लिए जीएसटी नेटवर्क और भारतीय रेलवे द्वारा उत्पन्न डेटा का उपयोग किया।

1. आर्थिक हालात 2022-23:कोविड पूर्व स्थिति की पुनः प्राप्ति

- महामारी की वजह से दर्ज की गई गिरावट, रूस-यूक्रेन युद्ध के प्रतिकूल असर और महंगाई से उबरने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में अब समस्त क्षेत्रों में उल्लेखनीय बेहतरी देखने को मिल रही है, जिससे यह वित्त वर्ष 2023 में महामारी पूर्व विकास पथ पर अग्रसर हो रही है।
- भारत में जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2024 में भी अच्छी रहने की आशा है। वित्त वर्ष 2024 में जीडीपी वृद्धि दर 6-6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
- वित्त वर्ष 2015 से लेकर अब तक प्रथम छमाही में निजी खपत सर्वाधिक रही है और इससे उत्पादन संबंधी गतिविधियों को काफी बढ़ावा मिला है जिससे समस्त क्षेत्रों में क्षमता उपयोग बढ़ गया है।
- केन्द्र सरकार का पूंजीगत व्यय और अब कंपनियों की मजबूत बैलेंस शीट की अगुवाई में निजी पूंजीगत व्यय चालू वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में काफी मददगार साबित हो रहा है।
- एमएसएमई क्षेत्र के लिए कुल ऋणों में वृद्धि जनवरी-नवम्बर 2022 के दौरान औसतन 30.6 प्रतिशत से भी अधिक रही।
- खुदरा महंगाई नवम्बर 2022 में घटकर फिर से आरबीआई के लक्षित दायरे में आ गई है।
- भारतीय रुपये का प्रदर्शन अप्रैल-दिसम्बर 2022 के दौरान अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी बेहतर रहा।
- प्रत्यक्ष कर संग्रह अप्रैल-नवम्बर 2022 के दौरान भी दमदार रहा।
- घटती शहरी बेरोजगारी दर और कर्मचारी भविष्य निधि में तेजी से हो रहे कुल पंजीकरण में बेहतर रोजगार सृजन नजर आ रहा है।
- सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्मों के विस्तारीकरण और विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के उपायों से आर्थिक विकास की गति तेज हो जाएगी।

आर्थिक समीक्षा 2022-23
भाग 1

2. भारत का मध्यम अवधि का विकास दृष्टिकोण: उम्मीदों और उम्मीदों के साथ

- भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यापक संरचनात्मक और शासन सुधार लागू किए गए, जिससे अर्थव्यवस्था के मूल तत्व मजबूत हुए हैं, वर्ष 2014-22 के दौरान इसकी समग्र दक्षता में वृद्धि हुई है।
- 2014 के बाद लागू किए गए सुधारों के परिणामस्वरूप सार्वजनिक वस्तुओं के निर्माण, विश्वास-आधारित शासन को अपनाने, विकास के लिए निजी क्षेत्र के साथ सह-साझेदारी और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के आधार पर जीवनयापन और व्यापार करने में आसानी पर विशेष जोर दिया गया।
- 2014-2022 की अवधि में भी पिछले वर्षों में क्रेडिट बूम और गंभीर वैश्विक झटके के कारण बैलेंस शीट पर दबाव देखा गया। इसके कारण, इस अवधि के दौरान ऋण वृद्धि, पूंजी निर्माण और इस प्रकार आर्थिक विकास जैसे प्रमुख व्यापक आर्थिक घटक गंभीर रूप से प्रभावित हुए।
- यह स्थिति वास्तव में 1998-2002 की अवधि के समान ही है जब सरकार द्वारा लागू परिवर्तनकारी सुधारों के कारण अर्थव्यवस्था में अस्थायी झटकों के कारण विकास की गति धीमी हो गई थी। जब ये झटके थम गए, तो लागू किए गए संरचनात्मक सुधारों का व्यापक लाभ वर्ष 2003 से मिलना शुरू हुआ।
- इसी तरह साल 2022 में महामारी के वैश्विक झटकों का असर कम होगा और महंगाई कम होगी तो अगले दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से काफी ऊपर उठेगी।
- बैंकिंग, गैर-बैंकिंग और कॉर्पोरेट क्षेत्रों में स्वस्थ बैलेंस शीट के दम पर एक नया क्रेडिट चक्र अभी शुरू हुआ है, जो पिछले महीनों के दौरान बैंक क्रेडिट में दर्ज दो अंकों की वृद्धि दर से स्पष्ट है।
- भारतीय अर्थव्यवस्था भी अधिक औपचारिकता, वित्तीय समावेशन की पीठ पर बढ़ी हुई दक्षता और डिजिटल प्रौद्योगिकी संचालित आर्थिक सुधारों द्वारा बनाए गए आर्थिक अवसरों से लाभान्वित होने लगी है।
- इस प्रकार, आर्थिक सर्वेक्षण के अध्याय 2 से पता चलता है कि भारत का विकास दृष्टिकोण अब महामारी से पहले के वर्षों की तुलना में बेहतर दिख रहा है और भारतीय अर्थव्यवस्था आने वाले वर्षों में अपनी पूरी क्षमता तक बढ़ने के लिए तैयार है।

1. वित्तीय घटनाएँ: राजस्व में तीव्र वृद्धि

- वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति काफी मजबूत हुई है, जो कि बढ़ती आर्थिक गतिविधियों, प्रत्यक्ष करों और जीएसटी से राजस्व में तेज उछाल और बजट में वास्तविक अनुमानों के कारण ही संभव हो पाया है।
- अप्रैल-नवंबर 2022 के दौरान सकल कर राजस्व में 15.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई, जो प्रत्यक्ष करों और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में मजबूत वृद्धि से संभव हुआ है।
- चालू वित्त वर्ष के पहले आठ महीनों के दौरान प्रत्यक्ष करों में वृद्धि वास्तव में उनके दीर्घकालिक औसत से कहीं अधिक रही है।
- GST अब केंद्र और राज्य सरकारों के लिए एक महत्त्वपूर्ण राजस्व स्रोत बन गया है। अप्रैल-दिसंबर 2022 के दौरान सकल जीएसटी संग्रह में सालाना आधार पर 24.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
- उच्च राजस्व व्यय की आवश्यकता के बावजूद केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) पर विशेष जोर देना जारी रखा है। वित्त वर्ष 2022 में केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय को दीर्घकालिक वार्षिक औसत (वित्त वर्ष 2009 से वित्त वर्ष 2020 तक) के सकल घरेलू उत्पाद के 1.7 प्रतिशत से बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद के 2.5 प्रतिशत तक लगातार बढ़ाया गया है।
- केंद्र सरकार ने पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता देने के लिए राज्य सरकारों को ब्याज मुक्त ऋण और बढ़ी हुई उधार सीमा के माध्यम से भी प्रोत्साहित किया है।

आर्थिक समीक्षा 2022-23
भाग 2

2. मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता: एक अच्छा वर्ष साबित हुआ

- आरबीआई ने अप्रैल 2022 में अपनी मौद्रिक नीति को कड़ा करना शुरू किया और तब से रेपो दर में 225 आधार अंकों की वृद्धि की है, जिससे अधिशेष तरलता में कमी आई है।
- बैलेंस शीट में सुधार से वित्तीय संस्थानों को ऋण में वृद्धि हुई है।
- ऋण लेने में रिकॉर्ड वृद्धि आगे भी जारी रहने की उम्मीद है, जिससे निजी पूंजीगत व्यय में तेजी आने से एक अच्छा निवेश चक्र शुरू हो रहा है।
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का गैर-खाद्य ऋण अप्रैल 2022 से लगातार दो अंकों में बढ़ रहा है।
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का ऋण वितरण भी बढ़ रहा है।
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल गैर-निष्पादित आस्तियां (जीएनपीए) अनुपात घटकर सात साल के निचले स्तर 5.0 पर आ गया।
- पूंजी-से-जोखिम भारित संपत्ति अनुपात (CRAR) अभी भी 16.0 के उच्च स्तर पर बना हुआ है।
- इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) के माध्यम से SCBs के लिए रिकवरी दर अन्य चैनलों की तुलना में FY22 में सबसे अधिक थी।

3. उद्योग: निरंतर सुधार

- औद्योगिक क्षेत्र द्वारा समग्र सकल मूल्य संवर्धन (जीवीडब्ल्यू) में 3.7 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई (वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली छमाही के लिए), जो पिछले दशक के पूर्वाद्ध के दौरान हासिल की गई 2.8 प्रतिशत की औसत वृद्धि से अधिक है।
- बढ़ी हुई मांग के प्रति उद्योग की आपूर्ति प्रतिक्रिया मजबूत रही है।
- जुलाई 2021 से 18 महीनों के लिए पीएमआई विनिर्माण विस्तार क्षेत्र में कायम रहा है। औद्योगिक विस्तार सूचकांक में उत्साहवर्धक वृद्धि हुई है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्यात में वित्त वर्ष 2019 में 4.4 बिलियन डॉलर से वित्त वर्ष 2022 में 11.6 बिलियन तक लगभग तीन गुणा वृद्धि हुई है।
- भारत वैश्विक स्तर पर मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है। यहां हैंडसेट का उत्पादन वित्त वर्ष 2015 में 6 करोड़ यूनिट से बढ़कर वित्त वर्ष 2021 में 29 करोड़ तक पहुंच गया।
- फार्मा उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में चार गुणा वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2019 में 180 मिलियन डॉलर से बढ़कर यह वित्त वर्ष 2022 में 699 मिलियन डॉलर हो गया।
- जनवरी 2023 तक 39,000 से अधिक अनुपालनों में कमी आई है और 3500 से अधिक प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से हटाया गया है।

आर्थिक समीक्षा 2022-23 भाग 3

1. कीमतें एवं महंगाई: सफलतापूर्वक संतुलन स्थापित किया

- जहां एक ओर तीन से चार दशकों के लंबे अंतराल के बाद विकसित देशों में आसमान छूती महंगाई की वापसी देखने को मिली, वहीं दूसरी ओर भारत में मूल्यवृद्धि एक सीमा में बनी रही।
- वैसे तो भारत में खुदरा महंगाई दर अप्रैल 2022 में बढ़कर 7.8 प्रतिशत के शिखर पर पहुंच गई जो कि आरबीआई की 6 प्रतिशत की ऊपरी सीमा से अधिक थी, लेकिन भारत में लक्षित सीमा से बढ़ी हुई महंगाई इसके बावजूद पूरी दुनिया में न्यूनतम में से एक रही।
- सरकार ने मूल्य वृद्धि को एक दायरे में रखने के लिए एक बहुआयामी रणनीति अपनाई:
  - पेट्रोल और डीजल पर निर्यात शुल्क में कई चरणों में कटौती की गई।
  - प्रमुख कच्चे माल पर आयात शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया गया, जबकि लौह अयस्क एवं सांद्र के निर्यात पर देय कर को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया।
  - कपास के आयात पर देय सीमा शुल्क को 14 अप्रैल 2022 से लेकर 30 सितम्बर 2022 तक माफ कर दिया गया।
  - एचएस कोड 1101 के तहत गेहूं उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया और चावल पर निर्यात शुल्क लगाया गया।
  - कच्चे एवं परिशोधित पाम ऑयल, कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल पर देय बुनियादी शुल्क में कमी की गई।
- आरबीआई द्वारा अग्रिम तौर पर गाइडेंस जारी करके अपेक्षित महंगाई अनुमानों को नियंत्रण में रखने और इसके साथ ही उचित मौद्रिक नीति अपनाने से देश में महंगाई को सही दिशा में रखने में मदद मिली।
- कारोबारियों और परिवारों दोनों के ही आने वाले वर्ष के लिए महंगाई अनुमान चालू वित्त वर्ष में कम हो गए हैं।
- सरकार द्वारा आवास क्षेत्र में समय पर नीतिगत उपाय करने और इसके साथ ही आवास ऋणों पर ब्याज दरों को कम रखने से आवास क्षेत्र में मांग को बढ़ाने में काफी मदद मिली और बड़ी संख्या में खरीदार वित्त वर्ष 2023 के दौरान किफायती आवास की ओर आकर्षित हुए।
- संयोजित आवास मूल्य सूचकांकों (एचपीआई) के आकलन में समग्र रूप से हुई वृद्धि और आवास मूल्य सूचकांकों से संबंधित बाजार मूल्यों से आवास वित्त क्षेत्र में फिर से तेज गति आने के संकेत मिलते हैं। एचपीआई में स्थिर से लेकर मामूली वृद्धि होने से परिसंपत्ति का मूल्य बने रहने की दृष्टि से गृह मालिकों और आवास ऋण प्रदाताओं का विश्वास बढ़ जाता है।
- भारत का महंगाई प्रबंधन विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा है, जो कि विकसित देशों की मौजूदा हालत के ठीक विपरीत है क्योंकि वे अब भी ऊंची महंगाई दर से जूझ रहे हैं।

2. बाहरी क्षेत्र

- अप्रैल-दिसम्बर 2022 के दौरान व्यापार निर्यात 332.8 बिलियन डॉलर रहा।
- भारत ने अपने बाजार को विभिन्न वर्गों में विविधिकृत किया और ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब के लिए अपने निर्यात में बढ़ोतरी की।
- बाजार के विस्तार और बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, 2022 में यूएई के साथ सीईपीए और ऑस्ट्रेलिया के साथ ईसीटीए लागू हुआ।
- भारत, 2022 में 100 बिलियन डॉलर प्राप्त करने के द्वारा विश्व में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा। सेवा निर्यात के बाद प्रेषण बाह्य वित्त पोषण का दूसरा सबसे बड़ा प्रमुख स्रोत है।
- दिसम्बर, 2022 तक विदेशी मुद्रा भंडार 9.3 महीनों के आयात को कवर करते हुए 563 बिलियन डॉलर पर रहा।
- नवम्बर, 2022 के अंत तक भारत विश्व में छठा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक है।
- बाह्य ऋण का वर्तमान स्टॉक विदेशी मुद्रा भंडार के आरामदायक स्तर से अच्छी तरह सुरक्षित है।
- भारत का सकल राष्ट्रीय आय की प्रतिशतता के रूप में कुल ऋण का अपेक्षाकृत निम्न स्तर तथा कुल ऋण की प्रतिशतता के रूप में अल्प अवधि ऋण है।

आर्थिक समीक्षा 2022-23 भाग 4

1. सामाजिक अवसंरचना और रोजगार पर विशेष जोर

- सामाजिक क्षेत्र पर सरकारी खर्च में व्यापक वृद्धि देखने को मिली।
- स्वास्थ्य क्षेत्र पर केन्द्र एवं राज्य सरकारों का अनुमानित व्यय बढ़कर वित्त वर्ष 2023 (बीई) में जीडीपी का 2.1 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2022 (आरई) में जीडीपी का 2.2 प्रतिशत हो गया, जो कि वित्त वर्ष 2021 में जीडीपी का 1.6 प्रतिशत ही था।
- सामाजिक क्षेत्र पर व्यय वित्त वर्ष 2016 के 9.1 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 (बीई) में 21.3 लाख करोड़ रुपये हो गया है।
- आर्थिक समीक्षा में बहुआयामी गरीबी सूचकांक पर यूएनडीपी की रिपोर्ट 2022 के निष्कर्षों पर प्रकाश डाला गया है जिनमें कहा गया है कि भारत में 41.5 करोड़ लोग वर्ष 2005-06 और वर्ष 2019-20 के बीच गरीबी से उबर गए।
- आकांक्षी जिला कार्यक्रम विशेषकर सुदूर एवं दुर्गम क्षेत्रों में सुशासन के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में सामने आया है।
- असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए ई-श्रम पोर्टल विकसित किया गया जिसका सत्यापन 'आधार' से होता है। 31 दिसम्बर, 2022 तक कुल मिलाकर 28.5 करोड़ से भी अधिक असंगठित कामगारों ने ई-श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है।
- जैम (जन-धन, आधार, एवं मोबाइल) के साथ-साथ डीबीटी ने समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ दिया है जिससे लोगों को सशक्त करते हुए पारदर्शी एवं उत्तरदायी गवर्नेंस के मार्ग में क्रांति आ गई है।
- 'आधार' ने को-विन प्लेटफॉर्म को विकसित करने और टीके की 2 अरब से भी अधिक खुराक लोगों को पारदर्शी ढंग से देने में अहम भूमिका निभाई है।
- शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में श्रम बाजार मुश्किलों से उबर कर कोविड पूर्व स्तर से ऊपर चला गया है। यही नहीं, बेरोजगारी दर वर्ष 2018-19 के 5.8 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2020-21 में 4.2 प्रतिशत रह गई है।
- स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार द्वारा उठाए गए अनेक कदमों की वजह से कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में व्यक्ति की जेब से होने वाला खर्च वित्त वर्ष 2014 के 64.2 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 2019 में 48.2 प्रतिशत रह गया।
- बाल मृत्यु दर (आईएमआर), 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर (यू5एमआर) और नवजात शिशु मृत्यु दर (एनएमआर) में निरंतर गिरावट दर्ज की गई है।
- 6 जनवरी, 2023 तक कोविड टीके की 220 करोड़ से भी अधिक खुराक लोगों को दी गई हैं।
- 4 जनवरी, 2023 तक आयुष्मान भारत योजना के तहत लगभग 22 करोड़ लाभार्थियों का सत्यापन किया गया है। आयुष्मान भारत के तहत देश भर में 1.54 लाख से भी अधिक स्वास्थ्य एवं वेलनेस केन्द्रों को चालू किया गया है।

2. सेवाएं- सुदृढ़ता का स्त्रोत

- वित्त वर्ष 2022 में 8.4 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) की तुलना में वित्त वर्ष 2023 में सेवा क्षेत्र के 9.1 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है।
- जुलाई 2022 से पीएमआई सेवाओं, जोकि सेवा क्षेत्र की गतिविधियों का संकेतक है, में जबरदस्त विस्तार देखा गया।
- भारत 2021 में शीर्ष दस सेवा निर्यात करने वाले देशों में शामिल था, विश्व वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में इसकी हिस्सेदारी 2015 में 3 प्रतिशत से बढ़कर 2021 में 4 प्रतिशत हो गई।
- जुलाई 2022 से सेवा क्षेत्र के लिए ऋण में 16 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है।
- वित्त वर्ष 2022 में सेवा क्षेत्र में 7.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी का प्रवाह।
- वित्त वर्ष 2023 में संपर्क-गहन सेवाएं महामारी से पहले के स्तर की वृद्धि दर को पुनः हासिल करने के लिए तैयार हैं।
- रियल एस्टेट क्षेत्र में निरंतर वृद्धि 2021 और 2022 के बीच 50 प्रतिशत की वृद्धि के साथ, आवास की बिक्री को महामारी के पूर्व-स्तर पर ले जा रही है।
- होटल ऑक्यूपेंसी दर अप्रैल 2021 में 30-32 प्रतिशत से बढ़कर नवंबर 2022 में 68-70 प्रतिशत हो गई है।
- वित्त वर्ष 2023 में भारत में विदेश पर्यटकों के आगमन के साथ-साथ निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की बहाली और कोविड-19 नियमों में ढील के साथ पर्यटन क्षेत्र के पुनर्जीवित होने के संकेत मिल रहे हैं।
- डिजिटल प्लेटफॉर्म भारत की वित्तीय सेवाओं में बदलाव ला रहे हैं।
- भारत का ई-कॉमर्स बाजार 2025 तक सालाना 18 फीसदी की दर से बढ़ने का अनुमान है।

आर्थिक समीक्षा 2022-23 भाग 5

1. अवसंरचना विकास के लिए सरकार का दृष्टिकोण

सार्वजनिक निजी भागीदारीः

- वीजीएफ योजना के लिए 2014-15 से 2022-23 के दौरान 56 परियोजनाओं को सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी दी गई, जिनकी कुल परियोजना लागत 57,870.1 करोड़ रुपये है।
- वित्त वर्ष 2023-25 के लिए, 150 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ आईआईपीडीएफ को केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रुप में अधिसूचित किया गया।

राष्ट्रीय अवंसरचना पाइपलाइनः

- कुल 141.4 लाख करोड़ रुपये की 89,151 परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है।
- 5.5 लाख करोड़ रुपये की 1009 परियोजनाएं पूरी की गई।
- एनआईपी और परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) पॉर्टल को आपस में जोड़ने से परियोजनाओं की मंजूरी/स्वीकृति में तेजी आई।

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइनः

- 9.0 लाख करोड़ रुपये की संचयी निवेश क्षमता का निर्माण हुआ।
- वित्त वर्ष 2022 के दौरान 0.8 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 0.9 लाख करोड़ रुपये के मुद्रीकरण का लक्ष्य हासिल किया गया।
- वित्त वर्ष 2023 के लिए लक्ष्य 1.6 लाख करोड़ रुपये (कुल एनएमपी लक्ष्य का 27 प्रतिशत)।

गतिशक्तिः

- पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लिए एकीकृत योजना निर्माण और तालमेल आधारित कार्यान्वयन के संदर्भ में व्यापक डेटाबेस का निर्माण करता है।
- लोगों और सामानों के निर्बाध आवागमन की कमियों को दूर करते हुए मल्टीमोडल परिवहन और लॉजिस्टिक कार्यकुशलता को बेहतर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

2. भारतीय लॉजिस्टिक क्षेत्र को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना

- तेज और समावेशी विकास के लिए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति देश में एक तकनीक सक्षम, एकीकृत, किफायती, लचीली, सतत और विश्वसनीय लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को विकसित करने की परिकल्पना करती है।
- राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़कों के निर्माण में तेजी; वित्त वर्ष 2016 के 6061 किलोमीटर की तुलना में वित्त वर्ष 2022 के दौरान 10,457 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों/सड़कों का निर्माण किया गया।
- वित्त वर्ष 2020 के 1.4 लाख करोड़ रुपये की तुलना में बजट परिव्यय बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में 2.4 लाख करोड़ रुपये हो गया। इस प्रकार पूंजीगत व्यय में वृद्धि हुई।
- अक्टूबर 2022 तक 2359 किसान रेलों ने लगभग 7.91 लाख टन सब्जियों/फलों का परिवहन किया।
- 2016 में शुरु होने के बाद, एक करोड़ से ज्यादा हवाई यात्रियों ने उड़ान स्कीम का लाभ प्राप्त किया है।
- आठ वर्षों में प्रमुख पत्तनों की क्षमता दोगुनी हुई।
- सौ साल पुराने अधिनियम के स्थान पर अंतरदेशीय पोत अधिनियम 2021 लागू किया गया, ताकि अंतरदेशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के साथ पत्तनों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित की जा सके।

3. भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना

एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई):

- 2019-22 के दौरान यूपीआई आधारित लेन-देन के लिए मूल्य के संदर्भ में 121 प्रतिशत की वृद्धि और मात्रा के संदर्भ में 115 प्रतिशत की वृद्धि, इससे यूपीआई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाए जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

टेलीफोन और रेडिया डिजिटल सशक्तीकरणः

- भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या 117.8 करोड़ (सितम्बर 2022 तक) है, 44.3 प्रतिशत उपभोक्ता ग्रामीण क्षेत्रों में है।
- कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं में से 98 प्रतिशत मोबाइल फोन द्वारा जुड़े हुए हैं।
- मार्च 2022 में भारत का कुल टेली घनत्व 84.8 प्रतिशत है।
- 2015 से 2021 के दौरान ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में 200 प्रतिशत की वृद्धि।

डिजिटल रूप से सार्वजनिक कल्याणः

- 2009 में आधार के शुभारंभ के साथ कम खर्च पर पहुंच हासिल की गई।
- मेरी योजना, टीआरएडीएस, जेम, ई-नाम, उमंग से मार्किट प्लेस में बदलाव आया है और नागरिक विभिन्न क्षेत्र में सेवाओं तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम हुए हैं।
- अनुमति आधारित डेटा साझाकरण रूपरेखा वर्तमान में 110 करोड़ बैंक खातों में संचालित की जा रही है।
- ओपन डिजिटल एनेबलमेंट नेटवर्क, डिजिटल ऋण आवेदनों को शुरु से अंत तक अनुमति देने के साथ ऋण प्रक्रियाओं के लोकतंत्रीककरण का लक्ष्य रखता है।

1. जलवायु परिवर्तन व पर्यावरणः भावी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करना

- भारत ने वर्ष 2070 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए 'नेट जीरो' का संकल्प व्यक्त किया।
- भारत ने गैर-जीवाश्म ईंधनों से 40 प्रतिशत अधिष्ठापित बिजली क्षमता का अपना लक्ष्य वर्ष 2030 से पहले ही हासिल कर लिया।
- गैर-जीवाश्म ईंधनों से संभावित अधिष्ठापित क्षमता वर्ष 2030 तक 500 जीडब्ल्यू से भी अधिक हो जाएगी जिससे वर्ष 2014-15 की तुलना में वर्ष 2029-30 तक औसत उत्सर्जन दर में लगभग 29 प्रतिशत की कमी आ जाएगी।
- भारत अपनी जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक 45 प्रतिशत कम कर देगा।
- वर्ष 2030 तक लगभग 50 प्रतिशत संचयी बिजली अधिष्ठापित क्षमता गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों से हासिल होगी।
- पर्यावरण के लिए जीवन शैली 'लाइफ' के रूप में जन आंदोलन शुरू किया गया।
- सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फ्रेमवर्क (एसजीआरबी) नवम्बर 2022 में जारी किया गया।
- आरबीआई ने 4000 करोड़ रुपये के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फ्रेमवर्क (एसजीआरबी) की दो किस्तों की नीलामी की।
- राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत वर्ष 2047 तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा।
- वर्ष 2030 तक कम से कम 5 एमएमटी (मिलियन मीट्रिक टन) की वार्षिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित कर ली जाएगी। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत वर्ष 2030 तक जीवाश्म ईंधन के आयात में 1 लाख करोड़ रुपये से भी अधिक की संचयी कटौती की जाएगी और 6 लाख से भी अधिक रोजगार सृजित किए जाएंगे। वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में लगभग 125 जीडब्लयू की वृद्धि की जाएगी और जीएचजी के वार्षिक उत्सर्जन में लगभग 50 एमएमटी की कमी की जाएगी।
- आर्थिक समीक्षा में सीसी पर एनएपी के तहत आठ मिशनों की दिशा में हुई प्रगति पर प्रकाश डाला गया है, ताकि जलवायु से जुड़ी चिंताओं को दूर किया जा सके और सतत विकास को बढ़ावा दिया जा सके।
- अधिष्ठापित सौर ऊर्जा क्षमता, जो कि राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत एक अहम पैमाना है, अक्टूबर 2022 में 61.6 जीडब्ल्यू दर्ज की गई।
- भारत नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एक पसंदीदा देश बनता जा रहा है; सात वर्षों में कुल निवेश 78.1 अरब अमेरिकी डॉलर आंका गया है।
- सतत पर्यावास पर राष्ट्रीय मिशन के तहत 62.8 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों और 6.2 लाख सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण (अगस्त 2022) किया गया।

आर्थिक समीक्षा 2022-23 भाग 6

2. कृषि एवं खाद्य प्रबंधन

- कृषि और संबंधित क्षेत्र का प्रदर्शन पिछले कुछ वर्षों से मजबूत रहा है।
- वर्ष 2020-21 में कृषि क्षेत्र में निजी निवेश 9.3 प्रतिशत बढ़ा।
- वर्ष 2018 से अनिवार्य सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, पूरे भारत में उत्पादन की औसत लागत का 1.5 गुणा निर्धारित किया गया।
- वर्ष 2021-22 में कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण लगातार बढ़कर 18.6 लाख करोड़ हो गया।
- भारत में खाद्यान्न उत्पादन में निरंतर वृद्धि देखी गई और वर्ष 2021-22 में यह बढ़कर 315.7 मिलियन टन हो गया।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 1 जनवरी, 2023 से एक वर्ष के लिए लगभग 81.4 करोड़ लाभार्थियों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की योजना है।
- योजना के अंतर्गत अप्रैल-जुलाई 2022-23 भुगतान चक्र में लगभग 11.3 करोड़ किसानों को कवर किया गया।
- कृषि अवसंरचना निधि के तहत फसल पश्चात समर्थन और सामुदायिक खेती के लिए 13,681 करोड़ रुपये मंजूर।
- राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना (ई-नाम) के तहत 1.74 करोड़ किसानों और 2.39 लाख व्यापारियों के साथ ऑनलाइन, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी निविदा प्रणाली लागू।
- परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के तहत किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के माध्यम से जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष पहल के माध्यम से भारत मोटे अनाजों को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

भारत-बांग्लादेश संबंध

चर्चा में क्यों: बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने सितंबर, 2022 में भारत का दौरा किया।

आर्थिक संबंध:

- भारत बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
- भारत ने 2011 से दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (SAFTA) के तहत तंबाकू और शराब को छोड़कर सभी टैरिफ लाइनों पर बांग्लादेश को शुल्क मुक्त कोटा मुक्त पहुंच प्रदान की है।
- दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2020-21 में 10.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 2021-22 में 18.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया।

दो देशों के बीच नदी समझौता:

- भारत और बांग्लादेश 54 साझा नदियों को साझा करते हैं। लीन सीजन के दौरान गंगा नदी के पानी के बंटवारे हेतु 1996 में गंगा जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- हाल ही में, दोनों देशों ने कुशियारा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे दक्षिणी असम और बांग्लादेश के सिलहट क्षेत्र के लोगों को लाभ होगा।

दो देशों के बीच कनेक्टिविटी:

- भारत और बांग्लादेश 4096.7 किमी लंबी सीमा साझा करते हैं, जो असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और पश्चिम बंगाल राज्यों को छूती है।
- अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से पारगमन और व्यापार बांग्लादेश-भारत के बीच लंबे समय से चले आ रहे समय-परीक्षणित प्रोटोकॉल द्वारा नियंत्रित होते हैं।
- अगरतला-अखौरा रेल-लिंक पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश के बीच पहला रेल मार्ग होगा।

बिजली और ऊर्जा क्षेत्र सहयोग:

- 2018 में हस्ताक्षरित भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन परियोजना, भारत में पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी और बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले के पारबतीपुर को जोड़ेगी।
- भारत और बांग्लादेश ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन (MOU) पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

बिम्सटेक

चर्चा में क्यों: भारत ने केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में दूसरी बिम्सटेक कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। 5वां बिम्सटेक शिखर सम्मेलन मार्च, 2022 में कोलंबो में हुआ था।

बैठक के मुख्य बिंदु:

- दूसरी बिम्सटेक कृषि मंत्रिस्तरीय बैठक ने बिम्सटेक कृषि सहयोग (2023-2027) को मजबूत करने के लिए कार्य योजना को अपनाया।
- बिम्सटेक सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आईएफपीआरआई) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिसमें कृषि कार्य समूह के तहत मत्स्य पालन और पशुधन उप-क्षेत्रों को लाने के लिए मंजूरी दी गई है।
- बिम्सटेक सदस्य देशों ने कृषि अनुसंधान और विकास में सहयोग को मजबूत करने, कृषि में स्नातकोत्तर और पीएचडी कार्यक्रमों के लिए छह-छह छात्रवृत्ति देने के लिए भारत के प्रयासों की सराहना की।

बिम्सटेक के बारे में:

- बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी-सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन (बिम्सटेक) की स्थपना 1997 में हुई थी जिसका मुख्यालय ढाका (बंग्लादेश) में स्थित है। इसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। यह दुनिया की आबादी के 1.73 बिलियन और 4.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की संयुक्त जीडीपी का एक क्षेत्रीय संगठन है। बिम्सटेक का उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में आम हित के मामलों पर सक्रिय सहयोग तथा पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देने के लिए समानता व साझेदारी की भावना में संयुक्त प्रयासों के माध्यम से बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति को गति देना है।

पूर्वी आर्थिक मंच

चर्चा में क्यों: रूस ने व्लादिवोस्तोक में 7वें पूर्वी आर्थिक मंच (EEF) की मेजबानी की। यह फोरम रूसी सुदूर पूर्व (RFE) क्षेत्र में अपने व्यवसाय का विस्तार करने के इच्छुक उद्यमियों के लिए एक मंच है।

पूर्वी आर्थिक मंच के बारे में:

- रूस के सुदूर पूर्व में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 2015 में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की स्थापना की गई थी। 2022 तक, इस क्षेत्र में लगभग 2,729 निवेश परियोजनाओं की योजना बनाई गई है।
- चीन, दक्षिण कोरिया, जापान और भारत इस क्षेत्र के प्रमुख हितधारक हैं, जहां चीन सबसे बड़ा निवेशक है।
- भारत इस क्षेत्र में ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, समुद्री संपर्क, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, हीरा उद्योग में सहयोग का इच्छुक है।
- 2019 में, भारत ने इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सुविधा की पेशकश की।

भारत की 'एक्ट फार ईस्ट' नीति के बारे में:

- 2019 में व्लादिवोस्तोक में 5वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम (ईईएफ) के पूर्ण सत्र में, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के लिए 'एक्ट फॉर ईस्ट' नीति का अनावरण किया और घोषणा की कि भारत, रूसी सुदूर पूर्व के विकास के लिए $1 बिलियन की 'लाइन ऑफ क्रेडिट' का विस्तार करेगा।

यूएन में भारत

चर्चा में क्यों: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

भारत के लिए प्राथमिकता के मुद्दे:

- **दक्षिण-दक्षिण सहयोग:**
  1. भारत के पास द्विपक्षीय रूप से और साथ ही संयुक्त राष्ट्र के साथ सहयोग के माध्यम से दक्षिण-दक्षिण सहयोग को काफी प्राथमिकता दी है।
  2. भारत ने UNOSSC द्वारा प्रबंधित 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर के भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष की स्थापना की है। यह फंड एलडीसी, एलएलडीसी तथा एसआईडीएस पर ध्यान देने के साथ दक्षिण-स्वामित्व वाली और दक्षिण-नेतृत्व वाली सतत विकास परियोजनाओं का समर्थन करता है। चार वर्षों में, इस फंड ने 52 देशों में 66 परियोजनाओं का एक पोर्टफोलियो जमा किया है।
  3. गरीबी और भुखमरी के उन्मूलन के लिए IBSA (भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका) कोष भी UNOSSC में आयोजित किया गया, जो दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए एक अनूठा तंत्र है।
  4. मार्च 2023 में दोहा, कतर में आयोजित होने वाले एलडीसी पर 5वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भी भारत एक सक्रिय भागीदार होगा।
- सतत विकास, विकास के लिए वित्त पोषण, आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर अग्रणी आवाज के रूप में भारत की सक्रिय भागीदारी को बनाए रखना। समान रूप से और सस्ती पहुंच सुनिश्चित करना, टीके के उत्पादन को बनाए रखने के लिए लचीली वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं की आवश्यकता की वकालत करना।
- आतंकवाद का मुकाबला करने से संबंधित मुद्दों को अधिक प्रमुखता देना, सुरक्षा परिषद की स्वीकृति समितियों में संस्थाओं और व्यक्तियों को सूचीबद्ध करने तथा हटाने की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता पर जोर देना भारत की प्राथिमिकता में शामिल है।
- संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों के लिए शासनादेशों को अंतिम रूप देने में एक प्रमुख सैन्य योगदान देने वाले देश के रूप में शांति स्थापना से संबंधित मामलों में पर्याप्त रूप से संलग्न होना। सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2589 के अनुसार शांतिरक्षक मिशनों में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना, शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही की तलाश करना भी भारत की प्राथमिकता है।
- 77वें यूएनजीए में सार्थक परिणाम के लिए सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे को आगे बढ़ाना जारी रखना।

शंघाई सहयोग संगठन

चर्चा में क्यों: ऐतिहासिक शहर समरकंद में संपन्न हुए एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने भाग लिया। इस सम्मलेन में आदर्श विश्व व्यवस्था की बात की गई। अगला शिखर सम्मेलन 2023 में भारत में होगा।

सम्मेलन में भारत का रुख:

- यह युद्ध का युग नहीं है: भारत ने रूस से दो टूक कहा कि यह युद्ध का समय नहीं है, अत: रूस-यूक्रेन युद्ध अवश्य ही रुकना चाहिए।
- पाकिस्तान द्वारा भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए भूमि मार्ग से पारगमन व्यापार की पहुंच प्रदान की जानी चाहिए।

एससीओ के बारे में:

- शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 में हुई थी। यह एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है। यह भौगोलिक दायरे और जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है, जो यूरेशिया के लगभग 60% क्षेत्र, दुनिया की 40% आबादी और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 30% से अधिक को कवर करता है। चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, भारत, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान संगठन के सदस्य हैं।
- एससीओ 2005 से संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक रहा है।
- 2002 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हस्ताक्षरित एससीओ चार्टर में अंतरसरकारी संगठन के उद्देश्यों, सिद्धांतों, संरचनाओं और संचालन के रूपों को सूचीबद्ध किया गया था। इसके प्राथमिकता वाले क्षेत्र क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दे, आतंकवाद, जातीय अलगाववाद और धार्मिक उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई हैं।

अब्राहम समझौता

चर्चा में क्यों: हाल ही में अब्राहम एकॉर्ड के दो साल पुरे हुए जो मिडिल ईस्ट में शांति की बहाली के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है।

- संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मध्यस्थता के माध्यम से, अब्राहम एकॉर्ड औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच एक सामान्यीकरण समझौता है, जो बाद में बहरीन, सूडान और मोरक्को से जुड़ गया तथा बदले में इजराइल कब्जे वाले वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों को जोड़ने की अपनी योजना को निलंबित कर देगा। इजरायल के साथ राजनयिक और आर्थिक संबंध स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश यूएई है।
- यूएई अब्राहम एकॉर्ड पर हस्ताक्षर करने वाला तीसरा अरब देश बना था।

I2U2 शिखर सम्मेलन

चर्चा में क्यों: हाल ही में पहला I2U2 (भारत, इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात) नेताओं का शिखर सम्मेलन वर्चुअली आयोजित किया गया था।

शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताएं:

- संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने पूरे भारत में फूड पार्क विकसित करने के लिए भारत में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की घोषणा की।
- भारत परियोजना के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करेगा और किसानों को फूड पार्कों में शामिल करने की सुविधा प्रदान करेगा।
- इस समूह ने गुजरात में 300 मेगावाट (मेगावाट) पवन और सौर क्षमता वाली एक संकर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना का समर्थन करने की घोषणा की।

I2U2 के बारे में:

- I2U2 भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका से

मिलकर बना है जिसे पश्चिम एशियाई क्वाड के रूप में भी जाना जाता है।

- समुद्री सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और परिवहन से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए I2U2 की शुरुआत अक्टूबर, 2021 में अब्राहम समझौते के बाद की गई थी। अब्राहम समझौता 26 वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मध्यस्थता वाला पहला अरब-इजरायल शांति समझौता है।
- I2U2 का उद्देश्य आपसी हित के सामान्य क्षेत्रों पर चर्चा करना, संबंधित क्षेत्रों और उससे आगे व्यापार व निवेश में आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना शामिल है।
- I2U2 देशों द्वारा पारस्परिक रूप से सहयोग के छह क्षेत्रों की पहचान की गई है जिसका उद्देश्य जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा में संयुक्त निवेश को प्रोत्साहित करना है।

भारत तथा चीन ने एलएसी के पास हवाई क्षेत्र के उल्लंघन पर बातचीत की

चर्चा में क्यों: भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के साथ हवाई क्षेत्र के प्रबंधन और हवाई क्षेत्र के उल्लंघन से बचने के लिए बेहतर समझ स्थापित करने के तरीकों पर चर्चा की। पूर्वी लद्दाख में नियमित कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स (सीबीएम) वार्ता के दौरान इस पर चर्चा हुई।

हवाई क्षेत्र (Air space) के बारे में:

- हवाई क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय कानून में, एक विशेष राष्ट्रीय क्षेत्र के ऊपर का स्थान है, जिसे क्षेत्र को नियंत्रित करने वाली सरकार से संबंधित माना जाता है। इसमें बाहरी अंतरिक्ष शामिल नहीं है, जो बाहरी अंतरिक्ष संधि (1967) के तहत मुक्त घोषित किया गया है और राष्ट्रीय विनियोग के अधीन नहीं है। हालाँकि, संधि ने उस ऊँचाई को परिभाषित नहीं किया जिस पर बाहरी अंतरिक्ष शुरू होता है और वायु अंतरिक्ष समाप्त होता है।

शिकागो कन्वेंशन:

- 1944 में, शिकागो कन्वेंशन आयोजित किया गया था जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) का गठन हुआ। इस सम्मेलन ने हवाई मार्ग से अंतर्राष्ट्रीय परिवहन की अनुमति देने वाले मूल सिद्धांतों की स्थापना का भी नेतृत्व किया। भारत ICAO के संस्थापक सदस्यों में से एक है। ICAO का मुख्यालय मॉन्ट्रियल, कनाडा में स्थित है।

संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध शासन (UN sanction regime):

- भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध व्यवस्था की विश्वसनीयता सर्वकालिक निम्न स्तर पर है। दोहरे मानकों और निरंतर राजनीतिकरण ने प्रतिबंध व्यवस्था की विश्वसनीयता को अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा दिया है।

UNSC 1267 समिति:

- यह तालिबान-नियंत्रित अफगानिस्तान पर लगाए गए प्रतिबंधों के कार्यान्वयन की देखरेख के उद्देश्य से स्थापित किया गया था, लेकिन अंततः व्यक्तियों और संगठनों को शामिल करने के लिए इसका दायरा बढ़ा दिया गया है।

संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध शासन के बारे में:

- सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय-VII के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने या बहाल करने के लिए कार्यवाही कर सकती है। ये प्रतिबंध उपाय अनुच्छेद-41 के तहत, प्रवर्तन विकल्पों की एक विस्तृत शृंखला को शामिल करते हैं जिनमें सशस्त्र बल का उपयोग शामिल नहीं है। हालाँकि अनुच्छेद-42 के तहत सुरक्षा परिषद् द्वारा सैन्य कार्यवाही का भी आदेश जारी किया जा सकता है।

ट्रांस-हिमालयी नेटवर्क

चर्चा में क्यों: चीन और नेपाल ने हाल ही में ट्रांस-हिमालयन मल्टी-डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क के निर्माण के लिए अपनी सहमति दी है।

ट्रांस-हिमालयी नेटवर्क के बारे में:

- नेटवर्क को ट्रांस-हिमालयन नेटवर्क भी कहा जाता है। यह बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत नेपाल और चीन के बीच एक आर्थिक गलियारा है। इस नेटवर्क के निर्माण से नेपाल एक लैंडलॉक से लैंड-लिंक्ड देश में बदल गया। इस नेटवर्क में कई परिवहन अवसंरचना परियोजनाएं शामिल हैं।

भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक नियुक्त

चर्चा में क्यों: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अर्जेंटीना के रियर एडमिरल गुइलेर्मो पाब्लो रियोस को भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह (UNMOGIP) के मिशन प्रमुख व मुख्य सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

यूएनएमओजीआईपी के बारे में:

- UNMOGIP जनवरी 1948 के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प 39 के तहत भारत और पाकिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र आयोग (UNCIP) की स्थापना की गयी।
- भारत आधिकारिक तौर पर मानता है कि यूएनएमओजीआईपी की भूमिका 1972 के शिमला समझौते से समाप्त हो गयी जिसने नियंत्रण रेखा या एलओसी की स्थापना की थी, जिसमें मामूली विचलन के साथ पहले की संघर्ष विराम रेखा का पालन किया गया था।
- पाकिस्तान ने हालांकि भारतीय तर्क को स्वीकार नहीं किया और UNMOGIP से सहयोग मांगता रहा।
- भारत 1972 से पाकिस्तान के खिलाफ शिकायतों के साथ आधिकारिक तौर पर यूएनएमओजीआईपी की मीटिंग में नहीं गया है।

अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम (आईटीएफ)

चर्चा में क्यों: मंत्रिमंडल ने भारतीय परिवहन क्षेत्र पर अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम (ITF) की गतिविधियों का समर्थन करने के लिए भारत और फ्रांस के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर करने को अपनी मंजूरी दे दी है। इस अनुबंध पर 6 जुलाई, 2022 को हस्ताक्षर किए गए थे।

अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम (ITF) के बारे में:

- ओईसीडी में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम 64 सदस्य देशों वाला एक अंतर-सरकारी संगठन है। यह परिवहन नीति के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है और परिवहन मंत्रियों के वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन करता है। ITF एकमात्र वैश्विक निकाय है जो सभी परिवहन साधनों को कवर करता है। ITF प्रशासनिक रूप से OECD के साथ एकीकृत है।

भारत और मिस्र संबंध

चर्चा में क्यों: एक अनोखे कदम के तहत इजिप्ट पोस्ट ने मिस्र और भारत के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। मिस्र के राष्ट्रपति 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भारत आए।

भारत और मिस्र के संबंध के बारे में:

- भारत और मिस्र के बीच राजनयिक संबंध तब शुरू हुए, जब मिस्र ने भारत की स्वतंत्रता के तीन दिन बाद 18 अगस्त, 1947 को भारत की स्वतंत्रता को मान्यता दी। 1950 के दशक में दोनों देश और भी करीब आ गए, जिसके परिणामस्वरूप 1955 में एक ऐतिहासिक मित्रता संधि हुई।
- दोनों देशों ने बहुपक्षीय मंचों पर निकटता से सहयोग किया है और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य रहे।
- भारत-मिस्र द्विपक्षीय व्यापार समझौता मार्च 1978 से चल रहा है। यह मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज पर आधारित है और पिछले दस वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार पांच गुना से अधिक बढ़ गया है।

अभ्यास वज्र प्रहार

चर्चा में क्यों: भारत-अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार का 13वां संस्करण हिमाचल प्रदेश के बकलोह में संपन्न हुआ।

अभ्यास वज्र प्रहार के बारे में

- 'वज्र प्रहार' एक भारत-अमेरिका विशेष बल का संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है जो 2010 में वैकल्पिक रूप से शुरू हुआ था। अभ्यास का उद्देश्य विशेष बलों के बीच पारस्परिकता और रणनीतियों के पारस्परिक आदान-प्रदान को बढ़ाकर दोनों देशों के बीच सैन्य संबंधों को बढ़ावा देना है।

युद्ध अभ्यास

चर्चा में क्यों: भारत-अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास 'युद्ध अभ्यास' का 18वां संस्करण उत्तराखंड में वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगभग 100 किमी दूर आयोजित किया गया था।

युद्ध अभ्यास के बारे में:

- दोनों देशों की सेनाओं के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं, रणनीति, तकनीकों और प्रक्रियाओं का आदान-प्रदान करने के उद्देश्य से भारत-अमेरिका के बीच सालाना सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। अभ्यास 2004 से दोनों देशों द्वारा वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाता है।

एशियन पाम ऑयल एलायंस (APOA)

चर्चा में क्यों: एशियन पाम ऑयल एलायंस (APOA) को सितंबर 2022 में आगरा में ग्लोबल समिट के दौरान लॉन्च किया गया था।

गठबंधन के बारे में:

- द एशियन पाम ऑयल एलायंस (APOA) की शुरुआत पांच दक्षिण-एशियाई देशों-भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के एपेक्स सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन द्वारा की गई है।
- पूरे महाद्वीप में पाम ऑयल के उत्पादन या शोधन से जुड़े उद्योगों और कंपनियों को शामिल करने के लिए एपीओए की सदस्यता का विस्तार किया जाएगा।
- APOA सचिवालय का प्रबंधन शुरू में भारत के सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन (SEA) द्वारा किया जाएगा।
- इसकी पहली आम सभा की बैठक में, अडानी विल्मर लिमिटेड के निदेशक अध्यक्ष अतुल चतुर्वेदी को एपीओए के पहले अध्यक्ष के रूप में चुना गया।
- एपीओए की अगली बैठक अगले साल (2023) की शुरुआत में इंडोनेशिया में होने की उम्मीद है।
- इस एसोसिएशन से पाम ऑयल का उपभोग करने वाले देशों के आर्थिक और व्यावसायिक हितों की रक्षा करने तथा एशिया में भोजन, फीड और ऑयली-रसायनों में उपयोग किए जाने वाले सभी वसा व तेलों के लिए एक समान अवसर बनाने की उम्मीद है। यह सदस्य देशों में स्थायी पाम ऑयल की खपत को बढ़ाने के लिए भी काम करेगा।

आर्मेनिया, अजरबैजान के बीच सीमा संघर्ष

चर्चा में क्यों: अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच ताजा संघर्ष छिड़ गया। प्रत्येक पक्ष ने हताहतों की सूचना दी और हिंसा के लिए एक दूसरे को दोषी ठहराया।

संघर्ष के प्रमुख बिंदु:

- दोनों देशों के बीच नागोर्नो-काराबाख क्षेत्र को लेकर दशकों से संघर्ष चल रहा है, जो अजरबैजान के अंदर है लेकिन मुख्य रूप से जातीय अर्मेनियाई लोगों की आबादी है।
- 2020 में छह सप्ताह के युद्ध में 6,600 से अधिक लोग मारे गए। अजरबैजान ने इस क्षेत्र को पुन: प्राप्त किया।

आर्मेनिया के बारे में:

- राष्ट्रपति: वाहनन खाचतुर्यन
- राजधानी: येरेवन
- मुद्रा: अर्मेनियाई ड्राम

अजरबैजान के बारे में:

- राष्ट्रपति: इल्हाम अलीयेव
- राजधानी: बाकू
- मुद्रा: अजरबैजानी मानत

भारत-जापान 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद

चर्चा में क्यों: दूसरी भारत-जापान मंत्रिस्तरीय वार्ता टोक्यो में आयोजित

हुयी। इसके तहत विदेश तथा रक्षा मंत्री एक-दूसरे की रणनीतिक चिंताओं को समझने और मजबूत संबंध बनाने के लिए नियमित रूप से मिलते हैं।

संवाद के बारे में:

- 30 नवंबर, 2019 को भारत और जापान के बीच नई दिल्ली में पहली 2+2 बैठक आयोजित की गई थी।
- इस बैठक को चीन के साथ तनाव और न केवल अपने प्रभाव बल्कि क्षेत्रीय मुद्दों पर भी नियंत्रण बढ़ाने में चीन की हठधर्मिता के मद्देनजर भारत-जापान के बीच संबंधों के प्रगाढ़ होने के रूप में देखा गया।
- भारत के चार प्रमुख रणनीतिक साझेदारों के साथ 2+2 संवाद हैं: अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और रूस।

भारत-जापान संयुक्त पहल:

- क्वाड, सप्लाई चेन रेजिलिएंस इनिशिएटिव्स, एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई एग्रीमेंट (MLSA), धर्म गार्जियन (संयुक्त सैन्य अभ्यास), JIMEX (नौसेना) और मालाबार (भारत-अमेरिका-जापान-ऑस्ट्रेलिया समुद्री अभ्यास)

IPEF मंत्रिस्तरीय शिखर सम्मेलन

चर्चा में क्यों: हाल ही में इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (IPEF) मंत्रिस्तरीय शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ।

आईपीईएफ के बारे में:

- यह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में 14 देशों का अमेरिकी नेतृत्व वाला आर्थिक समूह है, जिसका उद्देश्य चीनी आक्रामकता व्यापार और आर्थिक नीतियों का मुकाबला करना है।
- **सदस्य:** अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई दारुस्सलाम, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम है।
- IPEF ढांचे के चार स्तंभ हैं:
  1. व्यापार।
  2. आपूर्ति शृंखला।
  3. स्वच्छ ऊर्जा, डीकार्बोनाइजेशन और इन्फ्रास्ट्रक्चर।
  4. कर और भ्रष्टाचार विरोधी।
- चार स्तंभों में, भारत व्यापार को छोड़कर केवल IPEF के तीन स्तंभों में शामिल है।

हिंद-प्रशांत त्रिपक्षीय विकास सहयोग कोष

चर्चा में क्यों: भारत और फ्रांस हिंद-प्रशांत त्रिपक्षीय विकास सहयोग की स्थापना की दिशा में काम करने पर सहमत हुए हैं।

फंड के बारे में:

- हिंद-प्रशांत त्रिपक्षीय विकास सहयोग विकास परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाएगा, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के क्षेत्र में।
- इंडो-पैसिफिक त्रिपक्षीय भारतीय नवाचारों और स्टार्टअप्स को अन्य समाजों की आवश्यकताओं के लिए उनकी प्रासंगिकता प्रदर्शित करने के लिए एक मंच भी प्रदान करेगा।

भारत और फ्रांस सहयोग:

- अभ्यास शक्ति (सेना), वरुण (नौसेना) और गरुड़ (वायु सेना) अभ्यास, भारत-फ्रांस के बीच संयुक्त अभ्यास हैं।
- भारत और फ्रांस ने गगनयान मिशन पर सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- 2008 में भारत और फ्रांस के बीच असैन्य परमाणु सहयोग पर हस्ताक्षर किए गए तथा 9,900 मेगावाट जैतापुर परमाणु ऊर्जा परियोजना (जेएनपीपी) पर फ्रांस सहयोग दे रहा है।

सीआईसीए शिखर सम्मेलन

चर्चा में क्यों: कजाकिस्तान ने भारतीय पीएम को CICA शिखर सम्मेलन (एशिया में बातचीत और विश्वास निर्माण उपायों पर सम्मेलन) के लिए आमंत्रित किया है जिसमें भारत की तरफ से मीनाक्षी लेखी ने भाग लिया।

सीआईसीए के बारे में:

- इसकी स्थापना 1999 में हुई थी जो एक बहु-राष्ट्रीय मंच है।
- भारत इसके 27 सदस्यों में से एक है।
- इसका उद्देश्य एशिया में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने की दिशा में विस्तृत बहुपक्षीय दृष्टिकोणों के माध्यम से सहयोग बढ़ाना है। साथ ही आर्थिक, पर्यावरण, नई चुनौतियों और खतरों, सैन्य आदि के क्षेत्र में विश्वास पैदा करने के लिए भी यह एक मंच है।

G4 देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार की मांग की

चर्चा में क्यों: ग्रुप ऑफ फोर (जी4) देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बैठक हुयी। वे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के सुधार से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के मौके पर मिले थे।

बैठक के मुख्य बिंदु:

- चार मंत्रियों द्वारा जारी संयुक्त बयान में सदस्यता की स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में सुरक्षा परिषद के विस्तार का आह्वान किया गया।
- यह सुरक्षा परिषद् को अधिक वैध और प्रभावी बनाएगा।
- मंत्रियों ने सुरक्षा परिषद (एससी) सुधार पर अंतरसरकारी वार्ता (आईजीएन) में सार्थक प्रगति की कमी पर प्रकाश डाला।

जी-4 देश:

- इसका गठन 2004 में भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के सदस्यों द्वारा किया गया था।
- समूह मुख्य रूप से यूएनएससी सुधारों और जी4 सदस्यों के लिए निकाय की स्थायी सदस्यता पर केंद्रित है।

अन्य समूह जो UNSC में सुधार चाहते हैं:

- अफ्रीकी संघ
- G4 राष्ट्र

- विकासशील देशों का L-69 समूह
- अरब लीग
- कैरेबियन समुदाय (CARICOM)

क्वाड ग्रुप

चर्चा में क्यों: मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) साझेदारी पर हस्ताक्षर करने के लिए क्वाड समूह के देशों के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त बैठक हुई।

क्वाड ग्रुप के बारे में:

- यह एक मुक्त, खुले, समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने तथा समर्थन करने के लिए भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता है। क्वाड का विचार पहली बार 2007 में जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा प्रस्तावित किया गया था, लेकिन 2017 में अस्तित्व में आया।
- QUAD की 3C रणनीति तीन स्तंभों पर आधारित है:
  - Covid-19 वैक्सीन साझेदारी।
  - जलवायु कार्य समूह।
  - क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग

चर्चा में क्यों: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ऑस्ट्रिया के वोल्कर तुर्क को मानवाधिकारों के लिए अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया। उन्होंने चिली के मिशेल बाचलेट का स्थान लिया, जिनका कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त हो गया था।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के बारे में:

- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) एक संयुक्त राष्ट्र निकाय है जो दुनिया भर में मानवाधिकारों को बढ़ावा देता है और उनकी रक्षा करता है।
- 15 मार्च 2006 को जिनेवा (स्विटजरलैंड) में स्थापित इस संगठन में 3 साल के लिए क्षेत्रीय आधार पर चुने गए 47 सदस्य हैं। परिषद के सदस्यों का कार्यकाल तीन साल के लिए होता है जो लगातार दो कार्यकालों के बाद पुनः चुनाव के लिए पात्र नहीं होंगे।
- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों में मानवाधिकारों के दुरुपयोग के आरोपों की जांच करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि मानवाधिकार मुद्दों को संबोधित किया जाए।

यूएस-इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम

चर्चा में क्यों: लॉस एंजिल्स में इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मिनिस्ट्रियल (IPEF) बैठक सम्पन्न हुई।

यूएस-इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के बारे में:

- यूएसआईएसपीएफ 2017 में स्थापित एक गैर-लाभकारी संगठन है।
- इसका उद्देश्य नीति समर्थन के माध्यम से दोनों देशों के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को मजबूत करना है जिससे अधिक समावेशी समाज बनाने के लिए आर्थिक विकास, उद्यमशीलता, रोजगार-सृजन तथा नवाचार को बढ़ावा मिल सके।
- साथ ही व्यापार और सरकारों को सहयोग करने तथा अर्थपूर्ण अवसरों का निर्माण करने में सक्षम बनाना जो नागरिकों के जीवन को सकारात्मक रूप से बदल सकते हैं।

क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल (CEM13) और मिशन इनोवेशन (MI-7)

चर्चा में क्यों: अमेरिका ने 21 से 23 सितंबर 2022 तक ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम के 13वें क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल (CEM 13) और 7वें मिशन इनोवेशन मिनिस्ट्रियल (MI-7) की संयुक्त बैठक की मेजबानी की।

क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल के बारे में:

- इसे दिसंबर 2009 में कोपेनहेगन में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पर संयुक्त राष्ट्र के फ्रेमवर्क कन्वेंशन में स्थापित किया गया था।
- CEM स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने वाली नीतियों और कार्यक्रमों को बढ़ावा देने, सीखे गए अनुभव व सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने तथा वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था में परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए एक उच्च-स्तरीय वैश्विक मंच है।
- CEM तीन वैश्विक जलवायु और ऊर्जा नीति लक्ष्यों पर केंद्रित है:
  1. दुनिया भर में ऊर्जा दक्षता में सुधार करना।
  2. स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति में वृद्धि करना।
  3. स्वच्छ ऊर्जा की पहुंच का विस्तार करना।
- 29 देश सीईएम का हिस्सा हैं।
- भारत भी एक सदस्य देश है।

मिशन इनोवेशन मंत्रिस्तरीय के बारे में:

- मिशन इनोवेशन (एमआई) एक वैश्विक पहल है जो स्वच्छ ऊर्जा को सस्ती, आकर्षक और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए अनुसंधान, विकास, प्रदर्शन में एक दशक की कार्यवाही तथा निवेश को उत्प्रेरित करती है। यह पेरिस समझौते के लक्ष्यों और शुद्ध शून्य के रास्ते की दिशा में प्रगति को गति देगा।

सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी)

चर्चा में क्यों: विश्व बैंक ने किशनगंगा और रातले पनबिजली संयंत्रों के संबंध में एक तटस्थ विशेषज्ञ (एनई) व कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन (सीओए) का अध्यक्ष नियुक्त किया है। दोनों बांध सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को आवंटित पश्चिमी नदियों पर बने हैं।

संधि के बारे में:

- यह 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता के माध्यम से लागू हुआ था।
- आईडब्ल्यूटी सिंधु नदियों पर पानी के उपयोग के लिए भारत-पाकिस्तान के अधिकारों और दायित्वों का परिसीमन करता है।
- भारत, पाकिस्तान और विश्व बैंक संधि के हस्ताक्षरकर्ता हैं। हालांकि सिंधु तिब्बत से निकलती है, परन्तु चीन को संधि से बाहर रखा गया है।
- विश्व बैंक तीसरा पक्ष गारंटर है।
- **पूर्वी नदियाँ:** रावी, व्यास और सतलज नदियों के 80 प्रतिशत पानी

उपयोग करने का अधिकार भारत को दिया गया।

- **पश्चिमी नदियाँ:** सिंधु, झेलम और चिनाब का 80 प्रतिशत पानी पाकिस्तान को आवंटित किया गया था।
- पश्चिमी नदियों में, भारत को संधि में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार सीमित भंडारण (3.6 मिलियन एकड़ फीट या एमएएफ पानी तक) के साथ 'रन ऑफ द रिवर' जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए कुछ कृषि उपयोगों की अनुमति है।
- झेलम की सहायक नदी किशनगंगा या नीलम पर स्थित किशनगंगा जलविद्युत परियोजना (केएचईपी) का उद्घाटन 2018 में किया गया था।
- रैटल हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट (आरएचईपी) का निर्माण चिनाब नदी पर किया जा रहा है।

भारत-अफ्रीका रक्षा संवाद (IADD)

चर्चा में क्यों: हाल ही में भारत-अफ्रीका रक्षा संवाद (IADD) गुजरात के गांधीनगर में DefExpo 2022 के मौके पर आयोजित किया गया था। गांधीनगर घोषणा को IADD 2022 के परिणाम दस्तावेज के रूप में अपनाया गया था।

भारत-अफ्रीका रक्षा संवाद (IADD) के बारे में:

- आईएडीडी को 2020 में क्रमिक डेफएक्सपो के दौरान द्विवार्षिक रूप से आयोजित करने के लिए संस्थागत बनाया गया था।
- यह अफ्रीकी रक्षा बलों के सशक्तीकरण और क्षमता निर्माण, अभ्यास में भागीदारी व प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मानवीय सहायता आदि द्वारा आपसी हित के सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का प्रस्ताव करता है।
- भारत ने रक्षा अध्ययन और विश्लेषण के लिए मनोहर पर्रिकर संस्थान के माध्यम से अफ्रीकी देशों के विशेषज्ञों के लिए फेलोशिप की पेशकश की।

संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन

चर्चा में क्यों: भारत ने दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों के सामने आने वाली सुरक्षा और परिचालन संबंधी चुनौतियों का समाधान करने के लिए सुधार प्रस्तुत किए हैं।

संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के बारे में:

- पहला संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन 1948 में स्थापित किया गया था, जब इजराइल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच युद्धविराम समझौते की निगरानी के लिए पश्चिम एशिया में सैन्य पर्यवेक्षकों को तैनात किया गया था।
- इसका उद्देश्य संघर्ष से प्रभावित देशों में स्थायी सुरक्षा और शांति का निर्माण करना है।
- किसी देश में शांति मिशन भेजने का निर्णय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा किया जाता है।
- संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र की कमान के तहत सैन्य और पुलिस कर्मियों का योगदान करते हैं, जिसके लिए उन्हें संयुक्त राष्ट्र के कोष से भुगतान किया जाता है।

मैंडेट:

- शांति और सुरक्षा बनाए रखना।
- नागरिकों की रक्षा करना और मानवाधिकारों को बढ़ावा देना।
- संवैधानिक प्रक्रियाओं और चुनावों के संगठन का समर्थन करना।
- कानून के शासन को बहाल करने और वैध राज्य प्राधिकरण आदि का विस्तार करने में सहायता करना।

संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में भारत:

- वर्तमान में, भारत सैन्य-योगदान करने वाले देशों में तीसरा सबसे बड़ा देश है।
- यूएन पीसकीपिंग में भारत का योगदान 1950 के दशक में कोरिया में यूएन ऑपरेशन के साथ शुरू हुआ।
- भारत ने वियतनाम, कंबोडिया, लाओस के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए तीन अंतर्राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया, जिसकी स्थापना 1954 में इंडोचाइना पर जेनेवा समझौते द्वारा की गई थी।
- 2007 में, भारत मिशन के लिए पूरी तरह से महिलाओं की टुकड़ी को तैनात करने वाला पहला देश बन गया।
- भारत 2016 में स्थापित यौन शोषण और दुर्व्यवहार पर ट्रस्ट फंड में योगदान करने वाला पहला देश भी था।
- वर्तमान परिस्थितियों में अपनी प्रासंगिकता बढ़ाने के लिए भारत ने समय-समय पर मिशन के लिए सुधारों पर जोर दिया है।

शांति के लिए कार्यवाही (A4P):

- शांति के लिए कार्यवाही (A4P) को 2018 में पारस्परिक रूप से सहमत सिद्धांतों और प्रतिबद्धताओं के एक सेट के रूप में घोषित किया गया था ताकि भविष्य के लिए शांति अभियानों को तैयार किया जा सके।
- यह आठ प्राथमिकता वाले प्रतिबद्धता क्षेत्रों पर केंद्रित है।

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)

चर्चा में क्यों: फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने पाकिस्तान को उसकी ग्रे लिस्ट से हटाने की घोषणा की।

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) के बारे में:

- एफएटीएफ वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग (एमएल) और आतंकवादी वित्तपोषण (टीएफ) प्रहरी है।
- अंतर-सरकारी निकाय अंतर्राष्ट्रीय मानकों को निर्धारित करता है जिसका उद्देश्य इन अवैध गतिविधियों को रोकना है।
- इसकी स्थापना 1989 में पेरिस में आयोजित ग्रुप ऑफ सेवन (जी-7) शिखर सम्मेलन द्वारा की गई थी।
- धन शोधन (एमएल) से उत्पन्न खतरे को खत्म करने में मदद करने के लिए जी-7 शिखर सम्मेलन ने विश्व स्तर पर नीतियों को विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए एफएटीएफ की स्थापना की।
- 2001 में, FATF ने आतंकवादी वित्तपोषण के खिलाफ लड़ाई में मानकों के विकास की जिम्मेदारी ली।
- FATF में वर्तमान में 37 सदस्य क्षेत्राधिकार और 2 क्षेत्रीय संगठन

(खाड़ी सहयोग परिषद और यूरोपीय आयोग) शामिल हैं।

- भारत 2010 में FATF का सदस्य बना।
- एफएटीएफ की ब्लैक एंड ग्रे लिस्ट- ये शब्द आधिकारिक एफएटीएफ शब्दावली में मौजूद नहीं हैं, लेकिन बोलचाल के वाक्यांश हैं जिनका उपयोग एफएटीएफ द्वारा बनाए गए देशों की दो सूचियों का वर्णन करने के लिए किया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन (इंटरपोल)

चर्चा में क्यों: इंटरपोल ने नई दिल्ली में अपनी 90वीं महासभा के दौरान दुनिया भर में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया पहला पुलिस मेटावर्स लॉन्च किया है।

मेटावर्स के बारे में:

- मेटावर्स वास्तविक समय के 3डी वर्चुअल स्पेस को संदर्भित करता है, जहां उपयोगकर्ता मिल सकते हैं, काम कर सकते हैं, सामान और सेवाएं खरीद सकते हैं और अन्य लोगों के साथ इवेंट में भाग ले सकते हैं जो एक ही भौतिक स्थान में नहीं हैं।
- इंटरपोल मेटावर्स पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को फ्रांस के ल्योन में अपने सामान्य सचिवालय मुख्यालय का आभासी दौरा करने, अन्य अधिकारियों के साथ बातचीत करने, फोरेंसिक जांच और अन्य पुलिस कौशल में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम लेने की अनुमति देता है।
- इसे सभी 195 सदस्य देशों द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। यह दूरस्थ कार्य, नेटवर्किंग, अपराध स्थल से सबूत एकत्र करने, संरक्षित करने, प्रशिक्षण देने जैसे लाभ प्रदान करता है।

इंटरपोल के बारे में:

- यह एक अंतर-सरकारी संगठन है जिसमें 195 सदस्य देश शामिल हैं, जो इन सभी देशों में पुलिस बलों को उनके कार्यों का बेहतर समन्वय करने में मदद करता है।
- इसका गठन 1923 में हुआ था।
- भारत 1956 से इसका सदस्य है।
- यह सदस्य देशों को अपराधों और अपराधियों पर डेटा साझा करने व उन तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। यह कई प्रकार की तकनीकी और परिचालन सहायता प्रदान करता है।
- सामान्य सचिवालय संगठन की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों का समन्वय करता है।
- यह सिंगापुर में नवाचार के लिए एक वैश्विक परिसर और विभिन्न क्षेत्रों में कई उपग्रह कार्यालयों के साथ ल्योन (फ्रांस) में अपने मुख्यालय के साथ एक महासचिव द्वारा चलाया जाता है।
- भारत का केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), इंटरपोल के साथ राष्ट्रीय समन्वय एजेंसी है।

आतंकवाद विरोधी समिति (सीटीसी)

चर्चा में क्यों: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की काउंटर टेरर कमेटी की विशेष बैठक हुई।

UNSC की आतंकवाद विरोधी समिति (सीटीसी) के बारे में:

- इसको अमेरिका में 9/11 के आतंकवादी हमलों के मद्देनजर सर्वसम्मति से अपनाए गए सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1373 द्वारा स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य देश और दुनिया भर में आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए देशों की कानूनी तथा संस्थागत क्षमता को बढ़ाना है।

यूएनएससी प्रस्ताव

चर्चा में क्यों: भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में यूक्रेन के चार क्षेत्रों- खेरसॉन, जापोरिज्जिया, लुहांस्क और डोनेट्स्क में रूस द्वारा आयोजित जनमत संग्रह की निंदा करने वाले एक मसौदा प्रस्ताव में अनुपस्थित रहा।

UNSC संकल्प:

- यह संयुक्त राष्ट्र के संगठनों की राय या इच्छा की औपचारिक अभिव्यक्ति हैं।
- अमेरिका और अल्बानिया द्वारा परिचालित मसौदा प्रस्ताव को सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से 10 ने समर्थन दिया, जबकि ब्राजील, चीन, गैबॉन और भारत शामिल नहीं हुए।
- संकल्प ने सभी राज्यों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और एजेंसियों को रूसी कब्जे को मान्यता नहीं देने का आह्वान किया। इसने रूस से अतिशीघ्र, पूरी तरह से और बिना शर्त के अपने सभी सैन्य बलों को यूक्रेनी क्षेत्र से वापस लेने का भी आह्वान किया।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए)

चर्चा में क्यों: भारत में ISA की 5वीं असेंबली की बैठक हुई। भारत आईएसए असेंबली के अध्यक्ष का पद संभालता है जबकि फ्रांस सरकार सह-अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। असेम्बली सदस्यों की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है, जहां प्रत्येक सदस्य देश का प्रतिनिधित्व होता है और संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों के लिए सदस्यता खुली है। असेंबली की बैठक आईएसए के मुख्यालय में सालाना स्तर पर होती है।

आईएसए के बारे में:

- यह एक अंतर सरकारी संगठन है, जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था। आईएसए भारत में मुख्यालय वाला पहला ऐसा अंतर सरकारी संगठन है।
- इसका मिशन 2030 तक सौर ऊर्जा में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश को अनलॉक करना और प्रौद्योगिकी की लागत तथा इसके वित्तपोषण को कम करना है।

आईएसए के तहत महत्त्वपूर्ण परियोजनाएं:

- वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड (OSOWOG)
- ISA सौर प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग संसाधन केंद्र (ISTAR-C)
- भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) योजना

19वां भारत-आसियान शिखर सम्मेलन

चर्चा में क्यों: हाल ही में, 19वां भारत-आसियान शिखर सम्मेलन कंबोडिया में आयोजित किया गया। 2022 को आसियान-भारत मैत्री वर्ष के रूप में मनाया गया तथा शिखर सम्मेलन में भारत-आसियान संवाद की 30वीं वर्षगांठ भी मनाई गई।

शिखर सम्मेलन के प्रमुख बिंदु:

- दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, इंडो-पैसिफिक में परियोजनाओं, साइबर सुरक्षा और डिजिटल वित्तीय प्रणालियों की अंतर-संचालनीयता आदि सहित विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रणनीतिक से व्यापक रणनीतिक साझेदारी (सीएसपी) तक संबंधों को बढाने की बात की।
- भारत ने आसियान-भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी कोष के लिए $5 मिलियन के अतिरिक्त परिव्यय की घोषणा की। 2008 में स्थापित यह फंड, अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं तथा संबद्ध परियोजना विकास गतिविधियों को सहायता प्रदान करता है।
- आसियान-इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट (AITGA) की समीक्षा में तेजी लाने पर बात हुई ताकि इसे व्यवसायों के लिए अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल, सरल और व्यापार सुविधा के साथ-साथ स्थायी व समावेशी विकास के लिए समर्थन मिल सके।

आसियान के बारे में:

- दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) की स्थापना 1967 में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड द्वारा आसियान घोषणा (बैंकॉक घोषणा) पर हस्ताक्षर के साथ की गई थी।
- इसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच संयुक्त प्रयासों के माध्यम से आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना है।
- भारत ने 1992 में आसियान के साथ एक क्षेत्रीय संवाद भागीदार के रूप में औपचारिक जुड़ाव शुरू किया और 2012 में एक रणनीतिक साझेदार बन गया।

ब्लैक सी ग्रेन डील

चर्चा में क्यों: हाल ही में रूस ने ब्लैक सी ग्रेन डील में भागीदारी फिर से शुरू की।

ब्लैक सी ग्रेन डील के बारे में:

- रूस और यूक्रेन के बीच जुलाई, 2022 में संयुक्त राष्ट्र (यूएन) तथा तुर्की द्वारा ब्लैक सी ग्रेन डील की मध्यस्थता की गई थी।
- ब्लैक सी ग्रेन डील काला सागर के प्रभावी रुकावट के कारण आपूर्ति शृंखला व्यवधानों से उत्पन्न होने वाली बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने का प्रयास करता है।
- यह यूक्रेनी निर्यात (विशेष रूप से खाद्यान्न के लिए) के लिए इसके तीन प्रमुख बंदरगाहों अर्थात चर्नोमोर्स्क, ओडेसा और पिवडेनी से एक सुरक्षित समुद्री मानवीय गलियारा प्रदान करना था।

भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष

चर्चा में क्यों: हाल ही में भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष ने दक्षिण-दक्षिण सहयोग के 5 वर्ष पूरे किए।

यूएनडीएफ के बारे में:

- यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के तहत 2017 में स्थापित एक समर्पित सुविधा है।
- भारत सरकार ने 10 वर्षों में भारत-संयुक्त राष्ट्र कोष में $150 मिलियन की प्रतिबद्धता जताई है।
- इसका प्रबंधन दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNOSSC) द्वारा किया जाता है और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के सहयोग से कार्यान्वित किया जाता है।
- 1974 से यूएनडीपी द्वारा होस्ट किया गया यूएनओएसएससी, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया था।

दक्षिण-दक्षिण सहयोग के बारे में:

- दक्षिण-दक्षिण सहयोग वैश्विक दक्षिण में विकासशील देशों के बीच तकनीकी सहयोग को संदर्भित करता है।
- क्रियात्मक रूप से, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक विकासशील देश अपने व्यक्तिगत या साझा राष्ट्रीय क्षमता विकास उद्देश्यों का अनुसरण करते हैं।
- यह अर्जेंटीना में संयुक्त राष्ट्र के 138 सदस्य देशों द्वारा विकासशील देशों (बीएपीए) के बीच तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने और कार्यान्वित करने के लिए ब्यूनस आयर्स योजना को अपनाने से प्राप्त हुआ है।

बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था

चर्चा में क्यों: भारत ने जनवरी 2023 से एक वर्ष के लिए वासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता ग्रहण की।

बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था के बारे में:

- 42-सदस्यीय वासेनार अरेंजमेंट एक स्वैच्छिक बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था (MECR) है जो वासेनार अरेंजमेंट में भाग लेने वाले राज्यों के बीच सूचना साझा करने की सुविधा के साथ ही पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं और प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण में अधिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के लिए है।
- यह पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं तथा प्रौद्योगिकियों के निर्यात नियंत्रण पर मानक स्थापित करता है। भारत 2017 में वासेनार अरेंजमेंट में शामिल हुआ।

चीन-हिंद महासागर क्षेत्र फोरम

चर्चा में क्यों: चीन ने भारत को छोड़कर इस क्षेत्र के 19 देशों और भारत के सभी पड़ोसियों को एक साथ लाने वाला पहला चीन-हिंद महासागर क्षेत्रीय फोरम की बैठक बुलाई।

चीन-हिंद महासागर क्षेत्रीय फोरम के बारे में:

- यह हिंद महासागर क्षेत्र में चीन और अन्य देशों के बीच एक समुद्री आपदा रोकथाम तथा शमन सहयोग तंत्र स्थापित करने का प्रयास करता है।
- यह अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग एजेंसी द्वारा आयोजित किया गया था जो बीजिंग की नई विकास सहायता एजेंसी है।

जी-20

चर्चा में क्यों: भारत ने दिसंबर, 2022 में G-20 की अध्यक्षता ग्रहण की। इसने भारत के G-20 के लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण

किया। लोगो में कमल और ब्लू अर्थ का चित्रण किया गया है।

- **कमल:** भारत का राष्ट्रीय फूल, 7 पंखुड़ियों वाला कमल, विश्व के सात महाद्वीपों और संगीत के सात स्वरों का भी प्रतिनिधित्व करता है।
- **जी-20:** यह भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जीवंत रंग केसरिया, सफेद और हरा है।
- **ब्लू अर्थ:** जीवन के लिए भारत के प्रो-प्लैनेट दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है, जो प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य में है।

जी-20 के बारे में:

- यह 19 देशों के साथ-साथ यूरोपीय संघ (ईयू) से बना एक अंतर-सरकारी मंच है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन शमन और सतत विकास जैसी महत्त्वपूर्ण वैश्विक आर्थिक चुनौतियों का समाधान करना है।
- G-20, जो दुनिया की अधिकांश शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं (विकसित और विकासशील दोनों) से बना है, 1999 में बनाया गया था। यह समूह 2008 से साल में कम से कम एक बार मिलता है।
- इस समूह के पास कोई स्थायी कर्मचारी या सचिवालय नहीं है, प्रत्येक वर्ष दिसंबर में एक G-20 देश अध्यक्षता ग्रहण करता है, जो शिखर सम्मेलन के आयोजन का प्रभारी होता है।

भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (ईसीटीए)

चर्चा में क्यों: ऑस्ट्रेलियाई संसद ने में भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (ईसीटीए) की पुष्टि की।

ईसीटीए के बारे में:

- यह विकसित देश के साथ भारत के लिए इस तरह का पहला समझौता है।
- भारत ने ज्यादातर दक्षिण एशियाई देशों के साथ मुक्त व्यापार सौदे किए हैं और भारत के व्यापारिक हितों को मुश्किल से पूरा किया है।
- इस सौदे में अगले पांच वर्षों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार को लगभग $50 बिलियन तक बढ़ाने और विशेष रूप से स्टार्ट-अप अर्थव्यवस्था में कम से कम 10 लाख नौकरियां सृजित करने की क्षमता है।

न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरल सिस्टम

चर्चा में क्यों: भारत ने वैश्विक व्यवस्था को निर्धारित करने के लिए NORMS (न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरल सिस्टम) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र में सुधारों का प्रस्ताव दिया है जो समकालीन वास्तविकताओं को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है।

नॉर्म्स के बारे में:

- मानक वर्तमान बहुपक्षीय संरचना (शांति, सुरक्षा, विकास और मानवाधिकार) के सभी तीन स्तंभों में सुधार की परिकल्पना करता है, जिसके केंद्र में संयुक्त राष्ट्र है।
- यह एक प्रतिनिधि बहुपक्षीय संरचना की मांग करता है जो आतंकवाद, कट्टरवाद, महामारी, नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के खतरों आदि जैसी उभरती चुनौतियों का समाधान करने के लिए आवश्यक है।
- भारत ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस की अध्यक्षता करते हुए इस विचार का प्रस्ताव रखा।

यूएनएससी के बारे में:

- यह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख संकट-प्रबंधन निकाय है, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों पर बाध्यकारी दायित्वों को लागू करने के लिए अधिकृत है।
- पांच स्थायी सदस्यों (चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए) को वीटो शक्ति प्राप्त है।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दो-तिहाई बहुमत से चुने गए दस गैर-स्थायी सदस्य होते हैं। वे दो साल की सेवा करते हैं। कोई भी देश लगातार दो बार नहीं चुने जा सकते, साथ ही उनके पास वीटो शक्ति नहीं होती है।

इंडिया-यूएस युद्ध अभ्यास का विरोध

चर्चा में क्यों: युद्ध अभ्यास का 18वां संस्करण, वार्षिक भारत-यू.एस. हाल ही में उत्तराखंड में सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ जिसका चीन द्वारा विरोध किया गया।

चीन द्वारा उठाया गया मुद्दा:

- चूंकि यह अभ्यास वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर आयोजित किया गया था, इसलिए चीनी सरकार ने इसका विरोध किया।
- चीन ने दावा किया है कि भारत ने एलएसी पर 1993 और 1996 के समझौतों का उल्लंघन किया है, साथ ही अमेरिका को भारत-चीन संबंधों में हस्तक्षेप न करने की सलाह दी है।
- 1993 के समझौते में, दोनों पक्षों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा का सख्ती से सम्मान करने और उसका पालन करने पर सहमत हुए थे जो इस प्रकार है:
  - वास्तविक नियंत्रण रेखा से सटे क्षेत्रों में सैन्य बलों को न्यूनतम स्तर पर रखना।
  - परस्पर चिन्हित क्षेत्रों में सैन्य अभ्यास नहीं करना।
  - प्रत्येक पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास निर्दिष्ट स्तरों के सैन्य अभ्यास की अन्य पूर्व सूचना देना।
- 1996 के समझौते में, वे इस बात पर सहमत हुए कि कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष के खिलाफ अपनी सैन्य क्षमता का उपयोग नहीं करेगा। वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में दोनों ओर से कोई सशस्त्र बल तैनात नहीं है।

महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग (CSW)

चर्चा में क्यों: संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) ने ईरान को CSW से हटाने के लिए एक संकल्प अपनाया। इसके बाद ईरान को इस ग्रुप से हटा दिया गया।

यूएन-सीएसडब्ल्यू के बारे में:

- यह लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से समर्पित प्रमुख वैश्विक अंतर-सरकारी निकाय है।
- इसकी स्थापना 1946 में ECOSOC द्वारा की गई थी।
- यह बीजिंग घोषणा और कार्यवाही के लिए मंच के कार्यान्वयन में अग्रणी भूमिका निभाता है।
- समान भौगोलिक वितरण के आधार पर ECOSOC द्वारा चुने गए प्रत्येक 45 सदस्य राज्यों में से एक प्रतिनिधि शामिल होता है।
- भारत 2021 से 2025 तक चार वर्षों के लिए CSW के लिए चुना गया था।

भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग

चर्चा में क्यों: राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम (NDDA) को सीनेट और प्रतिनिधि सभा द्वारा पारित किया गया। अधिनियम हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है।

- 2016 में, अमेरिका ने भारत को प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में नामित किया था।
- भारत को विशेष रूप से नागरिक अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्रों में उच्च-प्रौद्योगिकी उत्पाद की बिक्री के लिए 2018 में 'रणनीतिक व्यापार प्राधिकरण टियर 1 का दर्जा' दिया गया था।

भारत-अमेरिका रक्षा समझौते:

- भारत अमेरिका के सभी प्रमुख रक्षा समझौते का हस्ताक्षरकर्ता है।
- सैन्य सूचनाओं के आदान-प्रदान पर सैन्य सूचना सामान्य सुरक्षा समझौता (GSOMIA), 2002 में हुआ।
- लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (LEMOA), 2016 एक दूसरे के सैन्य अड्डे का उपयोग करने के लिए हुआ।
- संचार संगतता और सुरक्षा समझौता (COMCASA) 2018 में दो सेनाओं के बीच अंत:क्रियाशीलता और भारत को उच्च तकनीक की बिक्री के लिए समझौता हुआ।
- बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौता (बीईसीए), 2020 में उच्च अंत सैन्य प्रौद्योगिकी, रसद तथा भू-स्थानिक मानचित्र साझा करने के लिए समझौता हुआ।

सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क

चर्चा में क्यों: आरबीआई ने सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ एक मुद्रा विनिमय समझौते (सीएसए) पर हस्ताक्षर किए हैं।

करेंसी स्वैप समझौते के बारे में:

- दो देशों के बीच सीएसए पूर्व निर्धारित नियमों और शर्तों के साथ मुद्राओं के आदान-प्रदान के लिए एक समझौता या अनुबंध है।
- सार्क करेंसी स्वैप सुविधा 2012 में संचालन में आई थी, जो अल्पावधि विदेशी मुद्रा तरलता आवश्यकताओं या लंबी अवधि की व्यवस्था किए जाने तक भुगतान संकट के संतुलन के लिए बैकस्टॉप लाइन प्रदान करती है।
- आहरण (DRAWAL) अमेरिकी डॉलर, यूरो या भारतीय रुपये में किया जा सकता है।

भारत-मध्य एशिया सुरक्षा बैठक

चर्चा में क्यों: भारत ने अफगानिस्तान में उभरती सुरक्षा स्थिति पर ध्यान देने के साथ कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के एक सम्मेलन की मेजबानी की।

बैठक के मुख्य बिंदु:

- एक शांतिपूर्ण, स्थिर, सुरक्षित अफगानिस्तान के लिए समर्थन, इसकी संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान पर जोर देना तथा इसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का आग्रह करना।
- प्रतिभागियों ने अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन कॉरिडोर के ढांचे के भीतर चाबहार बंदरगाह को शामिल करने के भारत के प्रस्ताव का समर्थन किया।
- विज्ञप्ति में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र व्यापक सम्मेलन (सीसीआईटी) को जल्द अपनाने का भी आह्वान किया गया है, जिसे भारत ने पहली बार 1996 में प्रस्तावित किया था।
- अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (आईएनएसटीसी) भारत, ईरान, अफगानिस्तान, अर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के बीच माल ढुलाई के लिए जहाज, रेल तथा सड़क मार्गों का एक बहु-मोड नेटवर्क है। इसकी स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी।
- अश्गाबात समझौता भारत, ईरान, कजाकिस्तान, ओमान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच एक बहुपक्षीय परिवहन समझौता है, जो मध्य एशिया और फारस की खाड़ी के बीच माल के परिवहन को सुविधाजनक बनाने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय परिवहन तथा पारगमन गलियारा बनाने के लिए है। यह 2011 में ईरान, ओमान, कतर, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान द्वारा लाया गया था।

इजरायल पर यूएनजीए का प्रस्ताव

चर्चा में क्यों: संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) से फिलिस्तीनी भूमि पर इजरायल के लंबे समय तक कब्जे के कानूनी परिणामों पर अपनी राय देने के लिए कहा गया। हालांकि भारत ने वोटिंग में भाग नहीं लिया।

इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष के बारे में:

- इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष यह 20वीं सदी की शुरुआत का है, जब यहूदी फिलिस्तीनी भूमि को पैतृक संपत्ति के रूप में दावा कर रहे थे जबकि अरब बहुसंख्यक थे।
- 1920-40 के बीच, यूरोप में उत्पीड़न के कारण फिलिस्तीन में यहूदियों का प्रवास बढ़ा।
- 1947 में, संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को एक अलग यहूदी और अरब राज्य में विभाजित करने का प्रस्ताव दिया।
- इसे अरब राज्यों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था जिसके कारण 1948 में पहला अरब-इजरायल युद्ध हुआ।

- संघर्ष विराम में, जॉर्डन ने वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया, मिस्र ने गाजा पर कब्जा कर लिया और यरुशलम को इजरायल तथा जॉर्डन के बीच विभाजित कर दिया गया।
- 1967 में अरब और इस्राइल के बीच छह दिन का युद्ध शुरू हुआ। इसके अंत में, इजरायल ने मिस्र से सिनाई प्रायद्वीप और गाजा पट्टी का क्षेत्रीय नियंत्रण प्राप्त किया। वेस्ट बैंक व पूर्वी यरूशलेम जॉर्डन से और गोलान हाइट्स सीरिया से छीन लिया।
- इजराइल का अभी भी वेस्ट बैंक और पूर्वी यरुशलम पर कब्जा है।

17वां प्रवासी भारतीय दिवस

चर्चा में क्यों: 9 जनवरी, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने 'आजादी का अमृत महोत्सव-भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रवासी भारतीयों का योगदान' विषय पर पहली बार डिजिटल प्रवासी भारतीय दिवस प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया।

प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में:

- प्रवासी भारतीय दिवस (पीबीडी) सम्मेलन भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जो प्रवासी भारतीयों के साथ जुड़ने और प्रवासी भारतीयों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में सक्षम बनाने के लिए एक महत्त्वपूर्ण मंच प्रदान करता है।
- वर्ष 2003 से प्रवासी दिवस मनाने की शुरुआत की गई, लेकिन वर्ष 2015 में इसे संशोधित किया गया और हर दो वर्ष पर इसे मनाने का निर्णय लिया गया।
- इस वर्ष सम्मेलन का विषय 'प्रवासी: अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार' है।
- प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में पांच विषयगत पूर्ण सत्र हुए।

वैश्विक दक्षिण शिखर सम्मेलन

चर्चा में क्यों: हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने एक आभासी कार्यक्रम, वॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट का उद्घाटन किया।

शिखर सम्मेलन के बारे में:

- यूक्रेन में महामारी और युद्ध के प्रभावों के बारे में विकासशील देशों के विचारों को स्पष्ट करने के लिए भारत ने शिखर सम्मेलन की मेजबानी की।
- इस कार्यक्रम में वित्त, ऊर्जा, शिक्षा, विदेशी मामलों और वाणिज्य सहित आठ मंत्रिस्तरीय सत्र हुए है।
- यह 'आवाज की एकता, उद्देश्य की एकता' विषय के तहत आयोजित किया गया था। अनिवार्य रूप से वैश्विक दक्षिण के देशों को एक साथ लाने और मुद्दों की एक पूरी श्रृंखला में उनके दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं को साझा करने की परिकल्पना की गई थी।

भारत-श्रीलंका संबंध

चर्चा में क्यों: श्रीलंका को कर्ज पुनर्गठन का आश्वासन देने वाला भारत पहला देश बन गया है।

भारत के वित्तीय आश्वासन कदम का महत्त्व:

- श्रीलंका के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अनंतिम पैकेज श्रीलंका के आधिकारिक लेनदारों (चीन, जापान और भारत) द्वारा पर्याप्त वित्तपोषण आश्वासन प्रदान करने के बाद ही स्वीकृत किया जाएगा।
- भारत का वित्त पोषण आश्वासन का निर्णय भारत के विश्वास का एक पुनर्कथन था, और एक अच्छे भागीदार के रूप को प्रदर्शित करता है।

संयुक्त राष्ट्र एवं उसकी विशिष्ट एजेंसियां

- इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में हुई थी।
- इसके चार्टर पर 26 जून, 1945 को सैन फ्रांसिस्को में हस्ताक्षर किए गए थे और 51 देशों के चार्टर पर हस्ताक्षर करने के बाद यह 24 अक्टूबर, 1945 को लागू हुआ।
- इसका मिशन अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना, सामाजिक प्रगति, बेहतर जीवन स्तर तथा मानवाधिकारों को बढ़ावा देना है।
- मुख्यालय - न्यूयॉर्क
- राजभाषा - अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, रूसी
- सदस्य - 193 (नवीनतम सदस्य दक्षिण सूडान)
- इनमें शामिल हैं: संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा स्थापित प्रमुख अंग, चार्टर के अनुच्छेद-57 में प्रदान की गई विशेष एजेंसियां, चार्टर के अनुच्छेद-22 से प्राप्त अपने अधिकार के तहत महासभा द्वारा स्थापित धन और कार्यक्रम।

संयुक्त राष्ट्र महासभा

- यह मुख्य विचार-विमर्श करने वाला निकाय है जिसमें सभी सदस्य राज्य शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक के पास एक वोट है।
- यूएनजीए का जनादेश अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा, बहस, सिफारिशें करना है जिसमें विकास, निःशस्त्रीकरण, मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय कानून और राष्ट्रों के बीच विवादों की शांतिपूर्ण मध्यस्थता शामिल है।
- यह संयुक्त राष्ट्र के अन्य चार अंगों की रिपोर्ट पर विचार करता है, सदस्य देशों की वित्तीय स्थिति का आकलन करता है और संयुक्त राष्ट्र के बजट को मंजूरी देता है।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद या सदस्यों के बहुमत या सदस्य राज्य के अनुरोध पर विधानसभा नियमित सत्र (सितंबर से दिसंबर तक), विशेष सत्र और आपातकालीन विशेष सत्र (24 घंटे के भीतर) में मिलती है।
- यह सुरक्षा परिषद द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति करता है।
- यह सुरक्षा परिषद के गैर-स्थायी सदस्यों तथा सामाजिक और आर्थिक परिषद के सदस्यों का चुनाव करती है।
- सुरक्षा परिषद के साथ, यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव करती है।
- महासभा के अध्यक्ष प्रत्येक वार्षिक सत्र के साथ बदलते हैं और

स्वयं निकाय द्वारा चुने जाते हैं।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद

- अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव के लिए इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है।
- परिषद में 15 सदस्य हैं: 5 स्थायी-यूएस, यूके, रूस, फ्रांस और चीन, जबकि अस्थायी 10 सदस्य 2 साल के लिए महासभा द्वारा चुने जाते हैं।
- जबकि संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंग केवल सदस्य देशों को सिफारिशें कर सकते हैं। सुरक्षा परिषद के पास सदस्य राज्यों पर बाध्यकारी निर्णय लेने की शक्ति है। सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता हर महीने 15 सदस्यों के बीच वर्णानुक्रम में बदलती है।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली कठोर है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद-27 में कहा गया है कि सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होगा। प्रक्रियात्मक मामलों पर सुरक्षा परिषद के निर्णय 9 सदस्यों के सकारात्मक वोट द्वारा किए जाएंगे। अन्य सभी मामलों पर सुरक्षा परिषद के निर्णय स्थायी सदस्यों के सहमति मतों सहित 9 सदस्यों के सकारात्मक मत द्वारा लिए जाएंगे।

संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद

- यह प्रमुख अंग है जो सतत विकास नीतियों का मार्गदर्शन करता है। यह सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर काम कर रहे कई संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं तथा संगठनों की गतिविधियों का समन्वय करता है।
- यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए प्रमुख निकाय है।
- इसमें 54 सदस्य हैं, जिन्हें महासभा द्वारा तीन साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है।
- परिषद में सीटें भौगोलिक प्रतिनिधित्व के आधार पर आवंटित की जाती हैं। उनमें से 11 एशियाई राज्यों को आवंटित किए गए हैं।
- तीन साल की अवधि के लिए ईसीओएसओसी के सदस्यों के रूप में चुने जाने के लिए राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र महासभा के वोटों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है।
- परिषद के प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होता है और आम तौर पर परिषद में मतदान साधारण बहुमत से होता है।
- अध्यक्ष को एक वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है

संयुक्त राष्ट्र सचिवालय

- इसका गठन 1945 में हुआ था जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है।
- संयुक्त राष्ट्र सचिवालय संयुक्त राष्ट्र (संयुक्त राष्ट्र) के छह प्रमुख अंगों में से एक है। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र की कार्यकारी शाखा है।
- संयुक्त राष्ट्र के विचार-विमर्श और निर्णय लेने वाले निकायों (अर्थात महासभा, आर्थिक और सामाजिक परिषद, सुरक्षा परिषद) के एजेंडे को निर्धारित करने तथा इन निकायों के निर्णयों के कार्यान्वयन में सचिवालय की एक महत्त्वपूर्ण भूमिका है।
- महासचिव, जिसे महासभा द्वारा नियुक्त किया जाता है, सचिवालय का प्रमुख होता है।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय

- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के छह प्रमुख अंगों में से एक है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करता है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मुद्दों पर सलाहकारी राय देता है।
- आईसीजे एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय अदालत है जो राज्यों के बीच सामान्य विवादों का फैसला करती है। इसके फैसले और राय अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्राथमिक स्रोतों के रूप में (अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधान के अनुच्छेद 59 के अधीन) काम करते हैं।
- इसकी स्थापना 1945 में हुई थी जिसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में स्थित है।
- संगठन में कुल 15 जज होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है।

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ)

- संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो भूख को हराने, पोषण और खाद्य सुरक्षा में सुधार के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करता है। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर, 1945 को हुई थी।
- एफएओ में 195 (194 देशों और यूरोपीय संघ सहित) सदस्य हैं जिसका मुख्यालय रोम, इटली में है। FAO के क्षेत्रीय कार्यालय दुनिया भर में हैं, जो 130 से अधिक देशों में काम कर रहे हैं।
- यह सरकारों तथा विकास एजेंसियों को कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, भूमि, जल संसाधनों के सुधार और विकास के लिए उनकी गतिविधियों का समन्वय करने में मदद करता है। यह अनुसंधान भी करता है, परियोजनाओं को तकनीकी सहायता प्रदान करता है, शैक्षिक और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है, कृषि उत्पादन, उत्पादन तथा विकास डेटा एकत्र करता है।
- एफएओ प्रत्येक सदस्य देश और यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले एक द्विवार्षिक सम्मेलन द्वारा शासित होता है, जो 49 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का चुनाव करता है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जिसका काम अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को स्थापित करके सामाजिक और आर्थिक न्याय को आगे बढ़ाना है।
- राष्ट्र संघ के तहत 1919 में स्थापित, यह संयुक्त राष्ट्र की पहली और सबसे पुरानी विशेष एजेंसी है।
- ILO में 187 सदस्य देश हैं। इसमें कुक आइलैंड्स और संयुक्त राष्ट्र 193 सदस्य देशों में से 186 देश शामिल हैं।
- इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है।
- आईएलओ के मानकों का उद्देश्य दुनिया भर में स्वतंत्रता, समानता, सुरक्षा, सम्मान की स्थिति में सुलभ, उत्पादक और टिकाऊ काम सुनिश्चित करना है।

- ILO की एक अनूठी विशेषता इसका त्रिपक्षीय कार्य है। ILO की सदस्यता सदस्य देशों में त्रिपक्षीय प्रणाली के विकास को सुनिश्चित करती है। यह संगठन में हर स्तर पर अर्थात् श्रमिकों और नियोक्ताओं से जुड़ी होती हैं।
- ILO महासभा की बैठक हर साल आयोजित की जाती है।

अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ)

- अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई नेविगेशन के सिद्धांतों और तकनीकों का समन्वय करती है। यह सुरक्षित व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन की योजना और विकास करती है।
- इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। आईसीएओ का मुख्यालय मॉन्ट्रियल, कनाडा में क्वार्टियर इंटरनेशनल में स्थित है।
- आईसीएओ परिषद हवाई नौवहन, इसकी अवसंरचना, उड़ान निरीक्षण, गैरकानूनी हस्तक्षेप की रोकथाम और सीमा पार प्रक्रियाओं की सुविधा से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के लिए मानकों तथा अनुशंसित प्रथाओं को अपनाती है।

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO)

- अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) शिपिंग को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है।
- IMO की स्थापना 1948 में जिनेवा में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में समझौते के द्वारा की गई थी। IMO 1959 में पहली बार अस्तित्व में आया।
- इसका मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। IMO में वर्तमान में 175 सदस्य देश और तीन सहयोगी सदस्य हैं।
- IMO का प्राथमिक उद्देश्य शिपिंग के लिए एक व्यापक नियामक ढांचे का विकास और रखरखाव करना है। इसके दायरे में समुद्री सुरक्षा, पर्यावरण संबंधी चिंताएं, कानूनी मामले, तकनीकी सहयोग, समुद्री सुरक्षा और शिपिंग की दक्षता शामिल है।
- आईएमओ सदस्यों की एक सभा द्वारा शासित होता है जो हर दो साल में एक बार होती है।

यूनिसेफ

- यूनिसेफ आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो दुनिया भर के बच्चों को मानवीय और विकासात्मक सहायता प्रदान करती है।
- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बच्चों को आपूर्ति और सहायता प्रदान करने के लिए 11 दिसंबर, 1946 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 57(I) द्वारा यूनिसेफ बनाया गया।
- यह एजेंसी 192 देशों और क्षेत्रों में उपस्थिति के साथ दुनिया में सबसे व्यापक और पहचानने योग्य सामाजिक कल्याण संगठनों में से एक है।
- यूनिसेफ की गतिविधियों में टीकाकरण और बीमारी की रोकथाम प्रदान करना, एचआईवी वाले बच्चों तथा माताओं के लिए उपचार का प्रबंध करना, बचपन व मातृ पोषण में वृद्धि करना, स्वच्छता में सुधार करना, शिक्षा को बढ़ावा देना एवं आपदाओं के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया शामिल है।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)

- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जिसे देशों को गरीबी समाप्त करने, स्थायी आर्थिक विकास और मानव विकास हासिल करने में मदद करने का काम सौंपा गया है।
- यूएनडीपी दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता और समृद्धि के लिए स्थानीय क्षमता विकसित करने पर बल देता है।
- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की स्थापना 1965 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र का एक सहायक अंग है, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है।
- यह संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी विकास सहायता एजेंसी है, जिसके 177 देशों में कार्यालय हैं।
- यूएनडीपी पूरी तरह से यूएन सदस्य देशों के स्वैच्छिक योगदान से वित्त पोषित है।

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन(यूनेस्को)

- संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की एक विशेष एजेंसी है जिसका उद्देश्य शिक्षा, कला, विज्ञान, संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति तथा सुरक्षा को बढ़ावा देना है।
- इसके 193 सदस्य राज्य और 12 सहयोगी सदस्य हैं, साथ ही गैर-सरकारी, अंतर-सरकारी तथा निजी क्षेत्र के भागीदार हैं।
- इसका मुख्यालय पेरिस (फ्रांस) के वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में है।
- यूनेस्को की स्थापना 1945 में बौद्धिक सहयोग पर राष्ट्र संघ की अंतर्राष्ट्रीय समिति के उत्तराधिकारी के रूप में की गई थी। यूनेस्को का संस्थापक मिशन राष्ट्रों के बीच सहयोग तथा संवाद को सुगम बनाकर शांति, सतत विकास और मानवाधिकारों को आगे बढ़ाना है।
- यूनेस्को सामान्य सम्मेलन द्वारा शासित होता है, जो सदस्य राज्यों और सहयोगी सदस्यों से बना होता है, जो एजेंसी के कार्यक्रमों तथा बजट को निर्धारित करने के लिए द्विवार्षिक रूप से मिलता है।
- यह कार्यकारी बोर्ड के सदस्यों का चुनाव भी करता है, जो यूनेस्को के काम का प्रबंधन करने हेतु हर चार साल में एक महानिदेशक की नियुक्ति करता है, जो यूनेस्को के मुख्य प्रशासक के रूप में कार्य करता है।

संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूनिडो)

- 17 नवंबर, 1966 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (UNIDO) को संयुक्त राष्ट्र के भीतर एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया।
- इसका मिशन विकासशील देशों के औद्योगीकरण को बढ़ावा देना और उसमें तेजी लाना है।

- यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो देशों को आर्थिक और औद्योगिक विकास में सहायता करती है।
- 60 से अधिक देशों में स्थायी उपस्थिति के साथ इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के विएना के संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में स्थित है।
- अप्रैल 2019 तक, UNIDO में 170 सदस्य देश शामिल हैं, जो एक साथ द्विवार्षिक आम सम्मेलन के माध्यम से संगठन की नीतियों, कार्यक्रमों और सिद्धांतों का निर्धारण करते हैं।
- 25 जुलाई 2016 को, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2016-2025 की अवधि को अफ्रीका के लिए तीसरे औद्योगिक विकास दशक के रूप में घोषित करने वाले प्रस्ताव को अपनाया।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनडीआरआर)

- आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनडीआरआर) दिसंबर 1999 में आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय रणनीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था।
- UNDRR (पूर्व में UNISDR) संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का हिस्सा है जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंदाई फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन और समीक्षा का समर्थन करता है।

यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम (यूएनओडीसी)

- यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम (यूएनओडीसी) एक संयुक्त राष्ट्र कार्यालय है जिसे 1997 में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दवा नियंत्रण कार्यक्रम (यूएनडीसीपी) कार्यालय के रूप में स्थापित किया गया था।
- इसका मुख्यालय वियना में स्थित है। 2002 में इसका नाम बदलकर ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय कर दिया गया।
- एजेंसी का ध्यान अवैध दवाओं की तस्करी और दुरुपयोग, अपराध की रोकथाम, आपराधिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और राजनीतिक भ्रष्टाचार है।
- यह संयुक्त राष्ट्र विकास समूह का सदस्य है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है।
- WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी जिसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है जिनके शासनादेश में शामिल हैं:
  - स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर में काम करना।
  - दुनिया को सुरक्षित रखना और कमजोर लोगों की सेवा करना।
- इसका कार्य सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल कवरेज, सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों की निगरानी के साथ जुड़ाव, स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए प्रतिक्रियाओं का समन्वय, स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना है। यह देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानकों को निर्धारित करता है और वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों पर डेटा एकत्र करता है। यह विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट, विश्वव्यापी स्वास्थ्य विषयों का आकलन प्रदान करता है।

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ)

- विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की 15 विशिष्ट एजेंसियों में से एक है।
- विश्व बौद्धिक संपदा संगठन 1967 में बनाया गया जिसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है।
- WIPO को देशों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से सहयोग करके दुनिया भर में बौद्धिक संपदा को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा करने के लिए बनाया गया था।
- डब्ल्यूआईपीओ सामाजिक आर्थिक विकास हेतु आईपी का उपयोग करने के लिए सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और व्यक्तियों के साथ भी काम करता है।
- डब्ल्यूआईपीओ 26 अंतर्राष्ट्रीय संधियों का संचालन करता है जो विभिन्न प्रकार के बौद्धिक संपदा मुद्दों से संबंधित हैं, जिनमें दृश्य-श्रव्य कार्यों की सुरक्षा से लेकर अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट वर्गीकरण की स्थापना शामिल है।
- डब्ल्यूआईपीओ के वर्तमान में 193 सदस्य राज्य हैं, जिनमें 190 संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्य और कुक द्वीप समूह, होली सी और नीयू शामिल हैं। फिलिस्तीन को स्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है।

विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी)

- विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) संयुक्त राष्ट्र के भीतर एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में खाद्य सहायता प्रदान करता है।
- यह दुनिया का सबसे बड़ा मानवतावादी संगठन है जो स्कूली भोजन का अग्रणी प्रदाता है।
- इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। WFP का मुख्यालय रोम में है और 80 देशों में इसके कार्यालय हैं।

अन्य संगठन

गुटनिरपेक्ष आंदोलन:

- गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) की स्थापना 1961 में शीत युद्ध के टकराव के संदर्भ में विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ाने की दृष्टि से की गई थी। इसने औपनिवेशीकरण का विरोध स्वतंत्र राज्यों के गठन और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लोकतंत्रीकरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत NAM का संस्थापक सदस्य है।

ग्रुप-7 (G-7):

- G-7 कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ-साथ यूरोपीय संघ सहित दुनिया की सात उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का एक अनौपचारिक समूह है। इसका गठन 1975 में किया गया था।

ग्रुप-77 (जी-77):

- G-77 15 जून, 1964 को बहत्तर विकासशील देशों द्वारा स्थापित किया गया था। जी-77 समूह की मूल स्थापना 77 देशों ने मिलकर की थी। बाद में बहुत से अन्य देश भी इसके सदस्य बनते गये

और वर्तमान में इसकी संख्या 130 है। यह विकासशील देशों के हितों को आगे रखने वाला संयुक्त राष्ट्र में सबसे बड़ा समूह है।

जी-20:

- G-20 की स्थापना 1999 में कई विश्व आर्थिक संकटों के जवाब में की गई थी। इसमें 19 देश (अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूना किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका) और यूरोपीय संघ शामिल हैं। G-20 सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 85%, वैश्विक व्यापार के 75% से अधिक और विश्व जनसंख्या के लगभग दो-तिहाई का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत इसका संस्थापक सदस्य है।

छोटे द्वीप राज्यों का गठबंधन (AOSIS):

- एलायंस ऑफ स्मॉल आईलैंड स्टेट्स तटीय और छोटे द्वीपीय देशों का एक अंतर-सरकारी संगठन है। AOSIS की स्थापना 1990 में द्वितीय विश्व जलवायु सम्मेलन से पहले की गई थी। गठबंधन का मुख्य उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को संबोधित करने के लिए छोटे द्वीप विकासशील राज्यों की आवाज को मजबूत करना है।

ऑकस (AUKUS):

- ऑकस ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौता है, जिसकी घोषणा 15 सितंबर 2021 को हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए की गई थी। समझौते के तहत अमेरिका और ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां हासिल करने में मदद करेंगे।

उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो):

- उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन 4 अप्रैल, 1949 को स्थापित एक सैन्य गठबंधन है जिसका मुख्यालय ब्रसेल्स में है। यह संगठन सामूहिक सुरक्षा को बढ़ावा देता है, जिसके तहत किसी एक सदस्य पर आक्रमण सभी देशों पर आक्रमण माना जायेगा।

अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी (IRENA):

- अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (IRENA) ऊर्जा परिवर्तन के लिए एक प्रमुख वैश्विक अंतर-सरकारी एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए प्रमुख मंच के रूप में कार्य करती है। यह देशों को उनके ऊर्जा संक्रमण में सहायता करती है और अत्याधुनिक डेटा प्रदान करती है ताकि प्रौद्योगिकी, नवाचार नीति पर विश्लेषण किया जा सके। इसकी स्थापना 26 जनवरी, 2009 को की गई थी।
- IRENA की सदस्यता में 167 देश और EU शामिल हैं। भारत इस संगठन का संस्थापक सदस्य है।

अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी:

- अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी 29 जुलाई, 1957 को बनाई गई थी। वर्तमान में 173 राज्य IAEA के सदस्य हैं। यह परमाणु क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए दुनिया का केंद्रीय अंतर-सरकारी मंच है। यह परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सुरक्षित शांतिपूर्ण उपयोग के लिए काम करता है।

परमाणु ऊर्जा एजेंसी:

- परमाणु ऊर्जा एजेंसी (एनईए) एक अंतर-सरकारी एजेंसी है जो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के तहत आयोजित की जाती है। इसे 1972 में बनाया गया था। वर्तमान में इसके 34 सदस्य हैं।

रासायनिक हथियारों के निषेध संगठन (ओपीसीडब्ल्यू):

- रासायनिक हथियारों के निषेध संगठन (OPCW) रासायनिक हथियार सम्मेलन के लिए कार्यान्वयन निकाय है, जो 29 अप्रैल 1997 को लागू हुआ। OPCW, अपने 193 सदस्य राज्यों के साथ, रासायनिक हथियारों को स्थायी रूप से और सत्यापित रूप से समाप्त करने के वैश्विक प्रयास की देखरेख करता है। भारत इस संगठन का हिस्सा है।

वासेनार व्यवस्था:

- औपचारिक रूप से जुलाई, 1996 में स्थापित वासेनार व्यवस्था, एक स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है जिसके 42 सदस्य पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं तथा प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण पर सूचनाओं का आदान-प्रदान करते हैं। इस तरह के आदान-प्रदान के माध्यम से, वासेनार का उद्देश्य हथियारों के दोहरे उपयोग वाले सामानों के निर्यात में अपने सदस्यों के बीच अधिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देना है। भारत इस संगठन का हिस्सा है।

परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG):

- परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) एक बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है और परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों का एक समूह है जो परमाणु हथियारों के निर्माण के लिए उपयोग की जा सकने वाली सामग्रियों, उपकरणों तथा प्रौद्योगिकी के निर्यात को नियंत्रित करके परमाणु प्रसार को रोकना चाहता है। इसका गठन 1974 में हुआ था और भारत इस संगठन का हिस्सा नहीं है।

ऑस्ट्रेलिया समूह (एजी):

- ऑस्ट्रेलिया समूह एक बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है और 1985 में स्थापित देशों का एक अनौपचारिक समूह है जो सदस्य देशों को उन निर्यातों की पहचान करने में मदद करता है जिन्हें नियंत्रित करने की आवश्यकता है ताकि रासायनिक और जैविक हथियारों के प्रसार में योगदान न हो। वर्तमान में इसमें भारत सहित 43 सदस्य हैं।

मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (एमटीसीआर):

- मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था एक बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है। यह 35 सदस्य देशों के बीच एक अनौपचारिक संगठन है जो मिसाइलों तथा मिसाइल प्रौद्योगिकी के प्रसार को सीमित करता है। इसका गठन 1987 में G-7 औद्योगिक देशों द्वारा किया गया था। भारत इस संगठन का हिस्सा है।

प्रारम्भिक परीक्षा आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न

1. निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार के 'नदियों के अंतर्संबंध प्रोग्राम' का संभावित लाभ हो सकता है?
1. पानी की कमी वाले क्षेत्रों में संवर्धित जल संसाधन।
2. राष्ट्र की बेहतर खाद्य सुरक्षा।
3. बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

2. गन्ने के अधिकतम निर्यात योग्य कोटा (MAEQ) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिये:
1. MAEQ अधिशेष चीनी स्टॉक के निर्यात के लिए एक विपणन सहायता नीति है।
2. MAEQ इथेनॉल की आपूर्ति के साथ जुड़ा हुआ है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

3. प्रधान मंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना (PMSSS) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिये:
1. PMSSS उत्तर पूर्वी राज्यों के छात्रों को सहायता प्रदान करता है।
2. PMSSS को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 न ही 2

4. विश्व बैंक समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिये :
1. पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक (IBRD) दुनिया के सबसे गरीब देशों को ऋण प्रदान करता है।
2. अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA) मध्यम-आय और ऋण-योग्य गरीब देशों को ऋण प्रदान करता है।
3. भारत विश्व बैंक समूह के तहत सभी संगठनों का सदस्य है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से **असत्य** है / हैं?
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 3
(c) उपर्युक्त में से कोई नहीं (d) उपर्युक्त सभी

5. मोरिंगा ओलीफेरा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिये:
1. यह पेड़ भारत का मूल वृक्ष है।
2. इसमें एंटीफंगल, एंटीवायरल, एंटीडिप्रेसेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

6. निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत में खाद्य और कृषि संगठन द्वारा विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली (GIAHS) के रूप में मान्यता दी गई है?
1. कोरापुट
2. रुशिकुल्या
3. कुट्टनाड

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिये:
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

7. न्यूमोकोकल कॉन्ज्यूगेट टीके के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिये:
1. सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने पहला स्वदेशी न्यूमोकोकल कॉन्ज्यूगेट टीका विकसित किया।
2. न्यूमोकोकल कॉन्ज्यूगेट टीका वायरस के कारण होने वाले न्यूमोकोकल रोगों के खिलाफ प्रभावी हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

8. क्वांटम रैंडम नंबर जेनरेटर (QRNG) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिये:
1. QRNG को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद-केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है।
2. QRNG क्वांटम संचार, वैज्ञानिक और वित्तीय सिमुलेशन में मदद करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

9. भारत सरकार की एक पहल, डिजिटल महासागर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिये:
1. इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज (INCOIS) द्वारा विकसित किया गया है।
2. यह 3D और 4D डेटा विजुअलाइजेशन की सुविधा देता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

10. नीचे दिए गए देशों में से कौन सा /से फाइव आईज नेटवर्क का हिस्सा हैं?
1. यूनाइटेड किंगडम
2. कनाडा
3. ऑस्ट्रेलिया
4. चीन
5. न्यूजीलैंड

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
(a) 1, 2, 3, 4 और 5 (b) 2 और 4
(c) 1, 2, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 5

11. ग्रीन प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी (GPT) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिये:
1. GPT में फ्यूल के रूप में ग्लाइसीडाइल एजाइड पॉलिमर (GAP) और ऑक्सीडाइजर के रूप में अमोनियम डि-नाइट्रामाइड (ADN) शामिल है।
2. तरल ऑक्सीजन और तरल मीथेन को GPT में ग्रीन प्रोपेलेंट संयोजनों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

12. राष्ट्रीय सामान्य गतिशीलता कार्ड (NCMC) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिये:
1. NCMC कार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक पहल है।
2. नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता वाली समिति ने NCMC कार्ड के उपयोग की सिफारिश की है।

उपर्युक्त कथनों मे से कौन सा/से **असत्य** है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

13. निम्नलिखित में से कौन सा/से वन्यजीवों में रेडियो टेलीमेट्री के अनुप्रयोग है/हैं?
1. जानवरों की होम रेंज का अध्ययन करना
2. मानव-पशु परस्पर क्रियाओं का अध्ययन करना
3. विभिन्न प्रजातियों के व्यवहार का अध्ययन करना

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिये:
(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 2 (d) 1, 2 और 3

14. भारत सरकार द्वारा कोयला आयात निगरानी प्रणाली (CIMS) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिये:
1. CIMS भारत सरकार द्वारा किसी भी कमोडिटी के लिए पहला ऐसा इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम है।
2. एन्थ्रेसाइट, बिटुमिनस, कोकिंग और स्टीम कोल आयात CIMS के अधीन होंगे।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

15. निम्नलिखित कथनों पर विचार करिये:
1. राष्ट्रीय कैडेट कोर दुनिया का सबसे बड़ा युवा संगठन है।
2. भारत में राष्ट्रीय कैडेट कोर को डिजिटल बनाने के लिए DGNCC डिजिटल फोरम शुरू किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

16. कुष्ठ रोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिये:
1. कुष्ठ रोग एक बेसिलस, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के कारण होता है।
2. महात्मा गांधी ने कुष्ठ रोग के खिलाफ एक योद्धा के रूप में काम किया।
3. कुष्ठ रोग का कोई इलाज अभी तक खोजा नहीं गया है।

उपर्युक्त मे से कौन से कथन सही हैं?
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

17. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

सूची-I (इमारती लकड़ी)	सूची-II (देश)
A. देवदार	1. म्यांमार
B. डग्लस फर	2. कनाडा
C. महोगनी	3. मैक्सिको
D. सागौन	4. होन्डुरास

कूट:
(a) A - 3; B-2; C- 1; D-4
(b) A - 3; B-2; C-4; D-1
(c) A-2; B- 3; C- 4; D-1
(d) A-2; B-3; C-1; D-4

18. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
रुपये की पूर्ण विनिमयता का अभिप्राय हो सकता है:
1. अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राओं के साथ इसका मुक्त प्रवाह।
2. देश के भीतर और बाहर किसी निर्धारित स्थान पर किसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा के साथ इसका सीधा आदान-प्रदान।
3. इसके द्वारा किसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा की ही भाँति कार्य करना।

इनमें से कौन-कौन से कथन सही हैं?
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

19. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. चीनी उत्पादन प्रक्रम में शीरा एक उपोत्पाद है।
2. चीनी कारखानों में चीनी मिलों में से निकली खोई भाप

बनाने के लिए बॉयलरों में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है।
3. कच्ची सामग्री के रूप में केवल गन्ने से ही चीनी का उत्पादन होता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं?

(a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

20. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :

1. प्रर्त्युजता व्यक्ति विशेष की किसी बाह्य पदार्थ के प्रति अतिसंवेदनशील के कारण होती है।
2. एचआईवी एक दुर्बल विषाणु है और इसका संक्रमण आसानी से नहीं होता है।
3. सिफलिस एक जीवाणु जनित रोग है जो संक्रमित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क के कारण फैलता है।
4. सूजाक नेस्सेरिया गोनारोई नामक जीवाणु से होने वाला रोग है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) 1, 2 और 3 (b) 1, 3 और 4
(c) 2, 3 और 4 (d) उपरोक्त सभी

21. चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा/से सत्य है/हैं?

1. चक्रवात तेज गति की हवायें होती हैं जो कि एक केन्द्र के किनारे गोलाई में चक्कर लगाती हैं।
2. ऊष्णकटिबंधीय चक्रवात तभी उत्पन्न हो सकते है जब समुद्र की सतह का तापमान 15^0C से अधिक हो।
3. 'डाइक्स' का निर्माण चक्रवात से होने वाली क्षति को रोकने का एक कारगर तरीका है।

नीचे दिए गये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें :

(a) केवल 1 (b) केवल 1 तथा 2
(c) केवल 1 तथा 3 (d) केवल 2 तथा 3

22. हॉटस्पाट अथवा संवेदनशील स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा/से सत्य है?

1. संवेदनशील स्थल से तात्पर्य उन स्थानों का है जहाँ पर कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या अधिक है।
2. वह स्थान जहां की बड़ी संख्या में विभिन्न वन्यजीवों तथा वनस्पतियों की प्रजातियाँ पायी जाती है पर साथ ही साथ इन स्थानों पर प्रजाति एंडमिज्म भी उच्च स्तर पर देखा जाता है को जैव विविधता के संदर्भ में संवेदनशील स्थल कहा जाता है।

नीचे दिए गये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें :

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

23. गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जिन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है:

1. मेहरगढ़ में एक लोहे के खंभे के शिलालेख से उसके साम्राज्य के प्रसार का संकेत मिलता है।
2. ग्रीक बौद्ध तीर्थयात्री मेगस्थनीज ने इनके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया।
3. पराशर स्मृति गुप्तों की कानूनी पुस्तक है।
4. उन्होंने पूर्वी भारत में शासन करने वाले शक राजाओं को हराया।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से **असत्य** है / हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1, 2 और 3
(c) केवल 1 तथा 2 (d) उपरोक्त सभी

24. ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार महापद्मनंद के उत्तराधिकारियों की संख्या आठ थी। निम्नलिखित में से वे कौन से स्रोत हैं जहाँ इस तथ्य का उल्लेख है?

(a) उपनिषद और ब्राह्मण (b) अरण्यक और जैन ग्रंथ
(c) पुराण और बौद्ध ग्रंथ (d) वेद और उपनिषद

25. अन्तरिक्ष पिण्डों के सन्दर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए:

1. ऊर्ट क्लाउड लम्बे समय तक विचरण करने वाले पुच्छल तारों के जन्मदाता हैं।
2. बौना ग्रह प्लूटो ऊर्ट बादलों में पाया जाता है।

उपर्युक्त दिये गये कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

26. कोविड-19 के दौरान उपयोग किए जाने वाले भारतीय दंड संहिता अनुभागों के संदर्भ में, सही विकल्प का पता लगाएं:

1. IPC की धारा 269 - जो कोई भी संगरोध नियम की अवज्ञा करता है उसे कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।
2. IPC की धारा 271 -नियमों की अवज्ञा से बीमारी के संक्रमण फैलने की संभावना है।
3. IPC की धारा 188- यह उन डिफॉल्टरों के लिए उपयोग किया जाता है जो लॉकडाउन के दौरान लोक सेवकों के आदेशों की अवहेलना करते हैं।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

(a) केवल 1, 2 और 3 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 3 (d) केवल 2 और 3

27. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. संसद ने ग्रामीण जनजातीय क्षेत्रों के लिए अनुसूचित क्षेत्रों (पीईएसए) अधिनियम के लिए पंचायती राज विस्तार और शहरी जनजातीय क्षेत्रों के लिए 1996 में अनुसूचित क्षेत्रों के लिए नगरपालिका विस्तार (MESA) अधिनियम अधिनिर्णय लागू किया है।
2. संविधान की पाँचवीं अनुसूची पंचायती राज अधिनियम और नगरपालिका अधिनियम से अलग कानूनों को शासित करती है ताकि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में गांवों और कस्बों का प्रशासन किया जा सके।

उपर्युक्त दिये गये कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

28. कालानुक्रमिक क्रम में निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को व्यवस्थित करें -
1. मुस्लिम लीग का गठन
2. कानपुर षड्यंत्र का मामला
3. सूरत विभाजन
4. रैले विभाजन

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
(a) 1,4,2,3 (b) 4,1,3,2
(c) 1,3,4,2 (d) 3,1,2,4

29. निम्नलिखित को सुमेलित करिये-

संगम साहित्य	**लेखक**
A. कूरल	1. इलंगो आदिगल
B. शिलप्पादिकारम	2. तिरूवल्लुवर
C. मनिमेखलै	3. चितलाई चतनार
D. तोल्काप्पियम	4. तोल्कापियार

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

	A	B	C	D
(a)	2	1	3	4
(b)	2	3	1	4
(c)	3	1	2	4
(d)	4	1	3	2

30. दक्षिण चीन सागर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. फिलीपींस, वियतनाम, चीन, ब्रुनेई, ताइवान, भारत और मलेशिया इतिहास और भूगोल के विभिन्न तथ्यों के आधार पर समुद्र पर अलग-अलग, कभी-कभी अतिव्यापी, क्षेत्रीय दावे करते हैं।
2. 2016 में, चीन ने UNCLOS आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के फैसले को स्वीकार कर लिया कि चीन ''नाईन-डैश लाइन'' के तहत पानी में संसाधनों के ऐतिहासिक अधिकारों का दावा नहीं कर सकता है, दक्षिण चीन सागर के अधिकांश हिस्से में अगर ये जल अन्य तटीय राज्यों के विशेष आर्थिक क्षेत्र या ईईजेड के भीतर हैं।
3. वैश्विक शिपिंग का दो-तिहाई, या कुल US$6.74 ट्रिलियन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, दक्षिण चीन सागर से होकर गुजरता है।

उपर्युक्त दिये गये कथनों में से कौन-सा/से **असत्य** है/हैं?
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) 1, 2 और 3 (d) केवल 1

31. निम्नलिखित में से कौन सा सही है / जब राज्य विधानमंडल को राष्ट्रपति शासन के तहत भंग या निलंबित किया जाता है:
1. संसद के सत्र में नहीं होने पर राष्ट्रपति राज्य के शासन के लिए अध्यादेश ला सकता है।
2. राष्ट्रपति, जब लोकसभा सत्र में नहीं होती है, तो राज्य की समेकित निधि से व्यय को प्राधिकृत कर सकता है।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

32. निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है?
1. स्टाइरिन का उपयोग एक विशेष तरह के फैब्रिक के निर्माण में किया जाता है।
2. एल. जी. पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्नाटक स्थित संयत्र में इसी गैस का रिसाव हुआ था।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

33. निम्नलिखित में से कौन सा कथन (वास्तुकला) के विजयनगर शैली के मूल तत्वों के बारे में सही है / हैं?
1. मंदिर के स्तंभों में अक्सर घोड़ों या हिप्पोग्रैफ के उत्कीर्णि होते हैं।
2. छोटे मंदिरों में एक गर्भगृह (गर्भगृह) और एक बरामदा होता है।
3. बड़े मंदिरों में चोल शैली में लकड़ी, ईट और प्लास्टर के साथ निर्मित लंबा रायगोपुरम है।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 3 (d) उपरोक्त सभी

34. राज्य आपदा प्रतिकर निधि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :
1. एसडीआरएफ का गठन 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया था।
2. केन्द्र सरकार एसडीआरएफ में 50 प्रतिशत का योगदान देती है और शेष 50 प्रतिशत राज्य सरकार से प्रदान की जाती है।
3. राज्य सरकार प्राकृतिक आपदा के शिकार लोगों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए SDRF के तहत उपलब्ध धन का उपयोग कर सकती है जिसे वे राज्य के स्थानीय संदर्भ में आपदा मानते है।

उपर्युक्त दिये गये कथनों में से कौन-सा/से **असत्य** है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 1 और 3 (d) केवल 2 और 3

35. लोकसभा के विघटन पर निम्नलिखित में से कौन सा बिल चूक जाता है?
1. लोकसभा द्वारा पारित एक विधेयक, लेकिन राज्यसभा में लंबित।
2. राज्यसभा में लंबित एक विधेयक, लेकिन लोकसभा द्वारा पारित नहीं।
3. दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक, लेकिन राष्ट्रपति की लंबित सहमति।

नीचे दिए गए कूट में से सही का चयन करें:

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 1
(c) 1, 2 और 3 (d) केवल 1 और 2

36. कॉलिंग अटेंशन मोशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :

1. यह संसद में एक सदस्य द्वारा तत्काल सार्वजनिक महत्व के एक मामले पर एक मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए, और उस मामले पर उनसे आधिकारिक बयान लेने के लिए पेश किया जाता है।
2. यह प्रक्रिया के नियमों में उल्लिखित नहीं है

उपर्युक्त दिये गये कथनों में से कौन-सा/से **असत्य** है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

37. पारिस्थितिक तुल्यांक (Ecological Equivalent) के सन्दर्भ में सही कथन है/हैं-

1. इनका सम्बन्ध भिन्न भौगोलिक प्रदेशों में समान पारिस्थितिक कर्मता ग्रहण करने वाले जन्तुओं से है।
2. आस्ट्रेलिया के कंगारू, उत्तरी अमेरिका के गौर के पारिस्थितिक तुल्यांक हैं।

नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें-

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

38. जलविभाजक (Watershed) के लाभ होते है/हैं-

1. लघु स्तर पर जल और मृदा का उचित प्रबंध किया जा सकता है।
2. फसलों की विविधता और फसल चक्र के अनुरूप कृषि कार्य किया जा सकता है।
3. स्थानीय संसाधन आधारित रोजगार व्यवस्था का विकास किया जा सकता है।

नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें-

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

39. निम्नलिखित कथनों में कौन से सत्य है/हैं?

1. जेम्स ऑट्रम 1857 की क्रांति को एक 'मुस्लिम षणयंत्र' मानते थे।
2. जे.आर. होम्स के अनुसार 1857 की क्रांति ''सिपाही विद्रोह'' थी।

नीचे दिये गये कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए-

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

40. निम्नलिखित का मेल कराईये-

समाचार पत्र/पत्रिका	**व्यक्ति/प्रकाशक**
A. विजय ऑफ इंद्रा	1. अजीत सिंह
B. कौम	2. आसिफ हसन हसवी
C. परिदसक	3. काज़ी अब्बास
D. रेश्वा	4. बिपिन चंद्र पाल

नीचे दिये गये कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए-

	A	B	C	D
(a)	1	2	3	4
(b)	2	3	4	1
(c)	4	2	3	1
(d)	3	4	1	2

41. सूची-I को सूची-II से मिलान कीजिए तथा नीचे दिये गये कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए-

सूची-I (निर्माण)	**सूची-II (वास्तुकार)**
A. गेटवे ऑफ इंडिया, मुम्बई	1. आर. एफ. चिशोम
B. कलकत्ता का विक्टोरिया मेमोरियल हॉल	2. हर्बर्ट बेकर
C. नई दिल्ली	3. लुटियन्स
D. चम्पा (प्राचीन शहर)	4. महागोविंद

कूट :

	A	B	C	D
(a)	1	2	3	4
(b)	2	1	3	4
(c)	3	4	1	2
(d)	4	1	2	3

42. हाइड्रोथर्मल कार्बोनाइजेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. इस प्रौद्योगिकी का उद्देश्य आर्द्र बायोमास को उचित तापमान और दाब की परिस्थितियों में हाइड्रो-4 में परिवर्तित करना है।
2. कार्बन और उच्च उष्मीय मान से समृद्ध हाइड्रो-4 का उपयोग ईंधन के रूप में किया जा सकता है।
3. इसके उप-उत्पादों में राख शामिल है जिसे इसमें उपस्थित फॉस्फोरस सामग्री के कारण पौधों में पोषक तत्व संवर्धक के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से कथन **असत्य** है/हैं?

(a) केवल 1 (b) 1 और 3
(c) 2 और 3 (d) उपरोक्त में कोई नहीं

43. *सोडियम सल्फर बैटरी* के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक उच्च तापमान वाली बैटरी है, जो लगभग 300 डिग्री सेल्सियस तापमान पर संचालित होती है।
2. इस बैटरी को 50 वर्षों से अधिक समय तक संग्रहित रखा जा सकता है।
3. इसकी लागत कम होती है क्योंकि सोडियम, लिथियम की तुलना में कहीं अधिक सामान्य और व्यापक रूप से उपलब्ध सामग्री है।
4. शीत की स्थिति में यह निष्क्रिय हो जाती है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं।

(a) 1, 2 और 3 (b) 1, 2 और 4
(c) 2, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

44. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. चैन-मेल्टेड स्टेट भौतिक पदार्थ की नई खोजी गई अवस्था है जिसमें परमाणु एक ही समय में ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं में होते है।
2. क्वांटम लीफ वायु में कार्बन डाई ऑक्साइड निर्मुक्त किये बिना सिनगैस का उत्पादन करती है।
3. टोरेफेक्शन तकनीक द्वारा धान के ठूंठ या अपशिष्ट को जैव कोयला में परिवर्तित किया जा सकता है।

उपरोक्त कथनों में कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?
(a) 1 और 3 (b) 2 और 3
(c) 1 और 2 (d) उपरोक्त सभी

45. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-
1. वलयाकार सूर्यग्रहण तब घटित होता है जब चन्द्रमा का कोणीय व्यास सूर्य की तुलना में कम हो जाता है जिससे चन्द्रमा, सूर्य को पूर्णतः आच्छादित नहीं कर पाता है।
2. वलयाकार सूर्यग्रहण की एक प्रावस्था के दौरान बेली बीइस नामक परिघटना दिखाई देती है।
3. वलयाकार सूर्यग्रहण कोरोना के अध्ययन हेतु उपर्युक्त होता है।

उपरोक्त कथनों में कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?
(a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) 1 और 3 (d) उपरोक्त सभी

46. 'द रिव्यू ऑफ मेरीटाइम ट्रान्सपोर्ट रिपोर्ट' प्रकाशित की जाती है :
(a) अंकटाड (b) वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम
(c) वर्ल्ड ट्रेड आर्गेनाइजेशन् (d) इनमें से कोई नहीं

47. सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए-

सूची-I (मिसाइल)		सूची-II (प्रकार)	
A-	निर्भय	1-	सतह से सतह
B-	धनुष	2-	सतह से समुद्र
C-	पृथ्वी	3.	समुद्र से सतह
D-	अस्त्र	4.	हवा से हवा

कूट:

	A	B	C	D
(a)	2	1	4	3
(b)	4	3	2	1
(c)	2	3	1	4
(d)	3	2	4	1

48. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए -
1. बायोसिमिलर्स दवायें बायोथेराप्यूटिक दवाओं का सस्ता रूप होती है जो जेनेरिक मेडिसीन के समान होती है। बायो-सिमिलर्स दवायें वास्तविक दवाओं के समान ही प्रभावशाली होती है।
2. बायो थेराप्यूटिक उन दवाओं को कहते हैं जो संश्लेषित रसायनों की बजाय जैविक तथा सजीव स्रोतों जैसे-कोशिका, रक्त, रक्त कणिकाएँ, उत्तक तथा अन्य पदार्थो से निर्मित की गई हों।

उपर्युक्त दिये गये कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

49. प्राकृतिक वनों से सम्बन्धित मियावाकी सिद्धान्त के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. इस सिद्धांत के अनुसार, पेड़ पौधों के बीच कोई निश्चित दूरी नहीं रखनी चाहिए।
2. वनीकरण से पूर्व भूमि को उपजाऊ बनाने का प्रयास करना चाहिए।
3. बरगद जैसे पेड़ जिनका वितान बहुत बड़ा होता है उन्हे अधिक लगाना चाहिए।

उपर्युक्त दिये गये कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) 1 और 2 (b) 1 और 3
(c) 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

50. निम्नलिखित में से कौन सिनक्लायनोरियम (पंखा वलन) का उदाहरण है?
(a) अरावली पहाड़ियाँ
(b) कश्मीर घाटी एवं उसकी पहाड़ियाँ
(c) तिब्बत पठार की पहाड़ियाँ
(d) विंध्याचल की पहाड़ियाँ

उत्तर

1.	(d)	14.	(b)	27.	(b)	40.	(b)
2.	(a)	15.	(c)	28.	(b)	41.	(a)
3.	(b)	16.	(a)	29.	(a)	42.	(d)
4.	(d)	17.	(c)	30.	(c)	43.	(d)
5.	(c)	18.	(d)	31.	(c)	44.	(d)
6.	(c)	19.	(a)	32.	(a)	45.	(d)
7.	(a)	20.	(d)	33.	(d)	46.	(a)
8.	(b)	21.	(c)	34.	(b)	47.	(c)
9.	(c)	22.	(c)	35.	(b)	48.	(c)
10.	(d)	23.	(d)	36.	(b)	49.	(a)
11.	(c)	24.	(c)	37.	(c)	50.	(b)
12.	(a)	25.	(a)	38.	(d)		
13.	(d)	26.	(c)	39.	(a)		

समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न

1. केल्प वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. केल्प वन उथले पानी में बने पानी के नीचे के पारिस्थितिक तंत्र हैं।
2. केल्प प्राकृतिक बैकवाटर के रूप में काम करते हैं और तटीय कटाव को रोकते हैं।
3. ये जंगल आमतौर पर 300°C से ऊपर के तापमान में गर्म पानी में बनते हैं।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A. केवल 2 B. 1 और 2
C. 2 और 3 D. 1 और 3

उत्तर- B

2. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. CPI-IW को श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय के एक संबद्ध कार्यालय द्वारा संकलित और जारी किया जाता है।
2. CPI-IW का आधार वर्ष 2001 से बदलकर 2012 कर दिया गया।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों D. उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर- A

3. संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट, 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 में विश्व उत्पादन वृद्धि, 2022 के स्तर से कम होने का अनुमान है।
2. रिपोर्ट के अनुसार, महामारी के प्रारंभिक चरण के दौरान महिलाओं के रोजगार में अनुपातहीन नुकसान पूरी तरह से अपने प्रारम्भिक स्तर पर नहीं आया है।
3. सख्त मौद्रिक नीति और कमजोर वैश्विक मांग के कारण संयुक्त राष्ट्र ने 2023 में भारत के लिए सकल घरेलू उत्पाद के पूर्वानुमान में कटौती की है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2 B. केवल 2
C. केवल 1 और 3 D. 1,2 और 3

उत्तर- D

4. निसार उपग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. यह नासा द्वारा लॉन्च किया गया अब तक का सबसे बड़ा रिफ्लेक्टर एंटीना वाला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है।
2. यह नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) की संयुक्त परियोजना है।
3. इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार (SAR) है जो पृथ्वी की सतह में परिवर्तन को मापने के लिए मदद करेगा।

सही विकल्प का चयन करें-

A. कथन 1 और 2 सही हैं।
B. कथन 1 और 3 सही हैं।
C. कथन 2 और 3 सही हैं।
D. सभी कथन सही हैं।

उत्तर- B

5. एवियन इन्फ्लुएंजा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. H5N1 बर्ड फ्लू पैदा करने के लिए जिम्मेदार कम रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा (LPAI) वायरस का एक प्रकार है।
2. यह केवल जंगली पक्षियों को संक्रमित करता है और वायरस का मानव संक्रमण बिल्कुल भी संभव नहीं है।
3. भारत को एवियन इन्फ्लुएंजा (H5N1) से मुक्त घोषित किया गया है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A. 1 और 2 B. केवल 3
C. 2 और 3 D. 1 और 3

उत्तर- B

6. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. बायोलॉजिकल दवाओं का विविध समूह है जिसमें टीके, विकास कारक, प्रतिरक्षा न्यूनाधिक, साथ ही मानव रक्त से प्राप्त उत्पाद शामिल हैं।
2. राष्ट्रीय जैविक विज्ञान संस्थान (एनआईबी), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत, जैविक गुणवत्ता नियंत्रण के प्राथमिक वैधानिक कार्य करने के लिए जिम्मेदार है।

उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं?

A. केवल 1 B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों D. उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर- A

7. प्रयोगशाला में विकसित हीरे (एलजीडी) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. LGD रासायनिक रूप से, भौतिक और वैकल्पिक रूप से हीरा हैं, जो हीरे-उत्तेजक के समान हैं।
2. एलजीडी को उनकी कठोरता और अतिरिक्त ताकत के

कारण कटर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

3. भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा काटने और चमकाने का केंद्र है।

उपरोक्त में से कौन से सही हैं?

A. 1 और 2 B. केवल 2

C. 2 और 3 D. 1, 2 और 3

उत्तर- B

8. जीनोम सीक्वेंसिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. जीनोम एक ब्लूप्रिंट की तरह है या किसी जीव, जैसे पौधे या जानवर को बनाने और चलाने के लिए निर्देशों का एक सेट है।

2. जीनोम अनुक्रमण महत्त्वपूर्ण देशी नस्लों की आनुवंशिक विविधता को संरक्षित करने में मदद कर सकता है।

3. वेचुर दुनिया की सबसे छोटी गाय की नस्ल है जिसकी हाल ही में जीनोम सीक्वेंसिंग हुई है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 B. 1 और 2

C. 1 और 3 D. उपरोक्त सभी

उत्तर- D

9. पेरिस क्लब के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. यह 22 राष्ट्रों का एक समूह है, जिसका उद्देश्य देशों के लिए स्थायी ऋण-राहत समाधान खोजना है

2. सभी 22 समूह के सदस्य हैं, जिन्हें आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) के रूप में जाना जाता है।

3. भारत पेरिस क्लब का सदस्य है।

उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं?

A. केवल 1 B. 2 और 3

C. 1 और 3 D. 1 और 2

उत्तर- A

10. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 2016 में अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) शुरू किया गया था।

2. एआईएम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए स्कूल स्तर पर अटल इन्क्यूबेशन संेटर स्थापित किए गए हैं।

3. नीति आयोग सहकारी संघवाद को प्रोत्साहित करता है, प्रतिस्पर्धी संघवाद को नहीं।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A. 1 और 2 B. 2 और 3

C. 2 केवल D. केवल 1

उत्तर- D

11. अतिरिक्त निगरानी तंत्र (एएसएम) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने निवेशकों को बाजार की अस्थिरता और शेयर की कीमत में असामान्य बदलाव से बचाने के इरादे से 2018 में ेइड लॉन्च किया।

2. एक एएसएम शॉर्टलिस्टिंग निवेशकों को संकेत देता है कि शेयरों में असामान्य गतिविधि देखी गई है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1 B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों D. कोई नहीं

उत्तर- B

12. सिकल सेल एनीमिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. यह प्रकृति में आनुवंशिक है।

2. वर्तमान में इसका निदान बच्चे के जन्म के बाद ही किया जा सकता है।

3. तकनीकी विकास की वर्तमान स्थिति में इस रोग का कोई इलाज नहीं है।

सही विकल्प का चयन करें-

A. कथन 1 और 2 सही हैं।

B. कथन 1 और 3 सही हैं।

C. केवल कथन 1 सही है।

D. सभी कथन सही हैं।

उत्तर- C

13. भारत में पेंशन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत, जो लोग सरकार के लिए काम करते हैं, वे अपने मूल वेतन का 10% योगदान करते हैं, जबकि उनके नियोक्ता 14% तक योगदान कर सकते हैं।

2. एनपीएस पुरानी पेंशन प्रणाली (ओपीएस) के विपरीत गैर-कर योग्य है।

3. ओपीएस के तहत कर्मचारियों को पेंशन अंशदान करने से छूट दी गई है।

दिए गए विकल्पों में से सही कथन का चयन करें-

A. केवल 1 B. 2 और 3

C. 1 और 2 D. 1 और 3

उत्तर- D

14. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है।
2. भारत में डेयरी दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता विश्व औसत से अधिक है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर- C

15. प्रयोज्य आय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. यह वह राशि है जो किसी व्यक्ति या परिवार को आयकर काटने के बाद खर्च या बचत करनी पड़ती है।
2. मुद्रास्फीति, रहने की लागत में वृद्धि और अप्रत्याशित व्यय जैसे कारक डिस्पोजेबल आय की मात्रा को प्रभावित कर सकते हैं।
3. YouGov की रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 12 महीनों में प्रयोज्य आय में कमी आई है।

सही विकल्प का चयन करें:

A. कथन 1 और 2 सही हैं।
B. कथन 1 और 3 सही हैं।
C. केवल कथन 1 सही है।
D. सभी कथन सही हैं।

उत्तर- D

16. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. शारीरिक निष्क्रियता भारत में मौतों का चौथा प्रमुख कारण है।
2. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) 5-17 वर्ष की आयु के बच्चों और किशोरों के लिए प्रति दिन औसतन 60 मिनट की शारीरिक गतिविधि की सिफारिश करता है।

निम्नलिखित में से कौन सा/से गलत है/हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर- A

17. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सौर तूफानों और सनस्पॉट से प्रभावित होता है।
2. प्रवासी पक्षी अपनी आँखों में मैग्नेटो रिसेप्टर्स का उपयोग करके इन चुंबकीय क्षेत्रों को महसूस कर सकते हैं।
3. पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में विकृतियाँ केवल युवा पक्षियों को प्रभावित करती हैं क्योंकि वयस्क पक्षी उनके प्रवास के अनुभव पर निर्भर करते हैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए

A. केवल 1
B. केवल 1 और 2
C. केवल 1 और 3
D. 1, 2 और 3

उत्तर- B

18. फरक्का बैराज पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. इसका निर्माण गंगा के पानी को भागीरथी-हुगली नदी तंत्र की ओर मोड़ने के लिए किया गया था।
2. यह देश में अपनी तरह का सबसे बड़ा बैराज है जिसमें एक फीडर नहर है जिसकी बेड चौड़ाई स्वेज नहर की तुलना में व्यापक है।

निम्नलिखित में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर- C

19. क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज (iCET) पर पहल पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यह भारत और जापान के बीच हस्ताक्षरित एक समझौता है।
2. उभरती प्रौद्योगिकियों में संयुक्त विकास और उत्पादन के अलावा, यह व्यापार बाधाओं, नियामक तंत्र और निर्यात नियंत्रणों को संबोधित करेगा।

निम्नलिखित में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर- B

20. 'ओपन एयर कैंप' से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. ये खुली जेलें हैं जो आत्म-अनुशासन और स्व-शासन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं।
2. देश में सबसे अधिक खुली जेलें मध्य प्रदेश में हैं।

निम्नलिखित में से कौन सा/से गलत है/हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर- B

व्यक्तित्व

शांति स्वरूप भटनागर

डॉ शांति स्वरूप भटनागर एक ऐसे स्वप्नद्रष्टा वैज्ञानिक थे, जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में देश की स्थिति को मजबूत करने का स्वप्न देखा था और उसे साकार करने में जुट गए। उन्हें भारतीय शोध प्रयोगशालाओं के जनक के रूप में याद किया जाता है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), जिसकी देशभर में आज 38 वैज्ञानिक शोध प्रयोगशालाएं विज्ञान के विविध क्षेत्रों में काम कर रही हैं, की स्थापना का श्रेय डॉ शांति स्वरूप भटनागर को जाता है। वह मशहूर भारतीय वैज्ञानिक और अकादमिक प्रशासक थे। उनका जन्म 21 फरवरी, 1894 को शाहपुर में हुआ, जो अब पाकिस्तान में है। डॉ भटनागर के जन्मदिवस के अवसर पर आज देश उन्हें याद कर रहा है।

वर्ष 1913 में पंजाब यूनिवर्सिटी से इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास करने के पश्चात उन्होंने लाहौर के फॉरमैन क्रिस्चियन कॉलेज में दाखिला लिया, जहाँ से उन्होंने वर्ष 1916 में बीएससी और 1919 में एमएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की। स्नातकोत्तर डिग्री पूर्ण करने के उपरांत, शोध फेलोशिप पर, वे इंग्लैंड चले गये, जहाँ उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज, लंदन से 1921 में, रसायन शास्त्र के प्रोफेसर फेड्रिक जी. डोन्नान की देखरेख में, विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। इंग्लैंड प्रवास के दौरान वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग, लंदन की ओर से उन्हें 250 यूरो सालाना की छात्रवृत्ति मिलती थी।

अगस्त, 1921 में वे भारत वापस आए, और उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) में रसायन शास्त्र के प्रोफेसर के तौर पर तीन साल तक अध्यापन कार्य किया। इसके बाद, उन्होंने लाहौर के पंजाब विश्वविद्यालय में 'फिजिकल केमिस्ट्री' के प्रोफेसर के साथ-साथ विश्वविद्यालय की रासायनिक प्रयोगशालाओं के निदेशक के तौर पर भी काम किया। यह समय उनके वैज्ञानिक जीवन की सबसे महत्त्वपूर्ण समय था, जिसमें उन्होंने मौलिक वैज्ञानिक शोध किये. उन्होंने इमल्सन, कोलायड्स और औद्योगिक रसायन शास्त्र पर कार्य के अतिरिक्त 'मैग्नेटो-केमिस्ट्री' के क्षेत्र में अहम योगदान दिया। वर्ष 1928 में उन्होंने के.एन. माथुर के साथ मिलकर 'भटनागर-माथुर मैग्नेटिक इन्टरफेरेंस बैलेंस' का प्रतिपादन किया। यह चुम्बकीय प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे संवेदनशील यंत्रों में से एक था, जिसका बाद में ब्रिटिश कंपनी ने उत्पादन भी किया।

वर्ष 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली तब देश में विज्ञान और तकनीक की नींव रखने का कार्य आरंभ हुआ। इसके लिए डॉ शांति स्वरूप भटनागर ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधारभूत ढांचे और नीतियों को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। उन्होंने कई युवा और प्रतिभाशील वैज्ञानिकों का मार्गदर्शन किया और उन्हें प्रोत्साहित किया। उन्होंने शिक्षा मंत्रालय में सचिव के पद पर कार्य किया, और भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार भी रहे। उनके नेतृत्व में तेल शोधन केंद्र शुरू हुए, टाइटेनियम जैसी नई धातुओं और जिरकोनियम उत्पादन के कारखाने बने तथा खनिज तेल (पेट्रोलियम) का सर्वेक्षण भी शुरू किया गया।

शांति स्वरूप भटनागर ने व्यावहारिक रसायन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने 'नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कारपोरेशन' (एनआरडीसी) की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। एनआरडीसी की भूमिका शोध एवं विकास के बीच अंतर को समाप्त करने से संबंधित रही है. उन्होंने देश में 'औद्योगिक शोध आंदोलन' के प्रवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। उनके नेतृत्व में भारत में कुल बारह राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई। जिस सीएसआईआर की स्थापना उन्होंने की थी, आज वह वैश्विक पटल पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विविध क्षेत्रों में भारत का नेतृत्व कर रहा है। आज सीएसआईआर का संपूर्ण भारत में 38 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, 39 दूरस्थ केन्द्रों, 3 नवोन्मेषी कॉम्प्लेक्सों और 05 यूनिटों के साथ एक सक्रिय नेटवर्क है। सीएसआईआर, रेडियो एवं अंतरिक्ष भौतिकी, महासागर विज्ञान, भू-भौतिकी, रसायन, औषध, जीनोमिकी, जैव प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में कार्य कर रहा है।

वर्ष 1954 में भारत सरकार ने डॉ शांति स्वरूप भटनागर को विज्ञान एवं अभियांत्रिकी क्षेत्र में अहम योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। 1 जनवरी, 1955 को दिल का दौरा पड़ने के कारण डॉ शांति स्वरूप भटनागर की मृत्यु हो गई। उनके मरणोपरांत वर्ष 1957 में सीएसआईआर ने उनके सम्मान में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की घोषणा की। यह पुरस्कार विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले वैज्ञानिकों को दिया जाता है।

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

20 वर्षों का भरोसा
सफलता ही हमारी परम्परा!

DHYEYA IAS®
most trusted since 2003

जुड़िए सर्वश्रेष्ठ टीम के साथ

TARGET

68th BPSC

MAINS SPECIAL BATCH

Hindi & English Medium

Starts from

20 FEBRUARY 11:30 AM

3 CLASSES FREE

BPSC MAINS TEST SERIES

FREE FOR FIRST 200 STUDENTS

A 12, 13, ANSAL BUILDING, DR. MUKHERJEE NAGAR, DELHI

Call: 9205274741 / 42, 9289580074 / 75

ध्येयIAS®

most trusted since 2003

20 वर्षों का भरोसा

सफलता ही हमारी परम्परा!

4500+ SELECTIONS IN IAS & PCS

₹ 55

dhyeyaias.com

Face to Face Centres

North Delhi : A 12, 13, Ansal Building, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 110009, Ph: 9205274741/42/44 I **Laxmi Nagar :** 1/53, 2nd floor, Lalita Park, Near Gurudwara, Opposite Pillar no.23, Laxmi Nagar, Delhi -110092, Ph: 9205212500/9205962002 I **Greater Noida :** 4th Floor Veera Tower, Alpha 1 Commercial Belt., Greater Noida, UP - 201310, Ph: 9205336037/38 I **Prayagraj :** II & III Floor, Shri Ram Tower, 17C, Sardar Patel Marg, Civil Lines, Prayagraj, UP - 211001, Ph: 0532-2260189/8853467068 I **Lucknow (Aliganj) :** A-12, Sector-J, Aliganj, Lucknow, UP- 226024, Ph: 0522-4025825/9506256789 I **Lucknow (Gomti Nagar) :** CP-1, Jeewan Plaza, Viram Khand-5, Near Husariya Chauraha, Gomti Nagar, Lucknow, UP - 226010, Ph: 7234000501/ 7234000502 I **Lucknow (Alambagh) :** 58/1 , Sector-B Opposite Phoenix Mall Gate No. 3, L.D.A Colony , Alambagh Lucknow,, Ph: 7518373333, 7518573333 | **Kanpur :** 113/154 Swaroop Nagar, Near HDFC Bank, Kanpur, UP - 208002, Ph: 7887003962/7897003962 I **Gorakhpur :** Narain Tower, 2nd floor, Gandhi Gali, Golghar, Gorakhpur, Uttar Pradesh 273001, Ph: 7080847474 I **Bhubaneswar :** OEU Tower, Third Floor, KIIT Road, Patia, Bhubaneswar, Odisha -751024, Ph: 9818244644/7656949029

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.com/hindi

ध्येयIAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 9205274741, 9205274742, 9205274744